प्रभात

अंदर के पन्नों में...

★ फडणविस सरकार का एक साल 5
★ छत्तीसगढ़ बजट–2016–17 9
★ रोहित वेमुला की आत्महत्या 15
★ साईबाबा की अवैध हिरासत... 20
★ सोनी सोढ़ी पर हमला 27
★ पत्रकारिता को जकड़ती जंजीरें 30
★ शरणार्थी समस्या 34
★ झूठी मुठभेड़ें 39

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का तिमाही मुख–पत्र

वर्ष–28 अंक–1 जनवरी–मार्च 2016 सहयोग राशि–15 रुपए

बोट्टेम में दुश्मन से लोहा लेते हुए प्राण न्योछावर करने वाले शहीद योद्धा कॉमरेड लच्छन्ना, सोनी, चंदू, मिनको, नवता, अनिता, रोशन, रामे व देवे को लाल–लाल सलाम!

कॉ. लच्छन्ना

कॉ.सोनी

कॉ.चंदु

कॉ.नवता

कॉ. अनिता

केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा मिशन–2016 के नाम पर संघर्षरत जनता व उसका नेतृत्व करने वाली भाकपा (माओवादी) के ऊपर भीषण दमन चलाया जा रहा है. इसके तहत केंद्रीय अर्ध सैनिक बल, छत्तीसगढ़ पुलिस व तेलंगाना के कुख्यात ग्रेहाउंड्स के संयुक्त बलों द्वारा दक्षिण बस्तर डिविजन के पामेड एरिया के बोट्टेम गांव के पास डेरा डाले पीएलजीए बलों पर मार्च 1, 2016 को बड़ा हमला किया गया. दुश्मन के हमले का हिम्मत व साहस के साथ मुकाबला करते हुए नौ प्यारे कॉमरेडों ने अपनी अनमोल जानें कुर्बान की. शहीद हुए कॉमरेडों में डीकेएसजडसी के वैकल्पिक सदस्य कॉमरेड गोट्टिमुक्कला रमेश (लच्छन्ना), दक्षिण बस्तर डिविजनल कमेटी की सदस्या कॉमरेड यूसुफ बी (सोनी), 22 वीं प्लटून का कमांडर कॉमरेड किसके कमलु (चंदु), सीआरसी कंपनी–2 की प्लटून की डिप्युटी कमांडर कॉमरेड नरोटी सनका (मिनको), तेलंगाना राज्य कमेटी के स्टाफ की कॉमरेड सृजना (नवता), दल सदस्या कॉमरेड सारक्का (अनिता), कॉमरेड राजू (रोशन), कॉमरेड सोनी की गार्ड कॉमरेड रामे, ऊसूर दस्ते की सदस्या कॉमरेड देवे हैं. इन कॉमरेडों की हत्या कर दुश्मन ने क्रांतिकारी आंदोलन को एक बड़ा धक्का जरूर दिया है. लेकिन करोड़ों उत्पीड़ित जनता के पक्ष में संचालित किये जाने वाला जन युद्ध इस नुकसान से जरूर उभरेगा. शहीदों के बलिदानों की प्रेरणा से लैस होकर पीएलजीए अवश्य ही जीत की ओर अग्रसर होगी. इन तमाम कॉमरेडों को प्रत्येक के नाम पर प्रभात विनम्र श्रद्धांजलि पेश करता है और अपने पाठकों का आह्वान करता है कि वे इन कॉमरेडों के अधूरे सपनों को साकार करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ें. इन कॉमरेडों की जिवनियां संक्षिप्त रूप से जानेंगे.

कॉमरेड गोट्टिमुक्कला रमेश (लच्छन्ना)

कॉमरेड गोट्टिमुक्कला रमेश का जन्म आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले के अंदुकूरु गांव में लगभग 48 साल पहले हुआ था. वे मां अनसूर्यम्मा व बाप वीराब्रह्म चारी की पांचवी संतान थे. अविभाजित कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवेश के पूर्व से ही कई आंदोलनों की विरासत से लैस गांव में

कॉमरेड रमेश पला–बढ़ा था. कॉमरेड रमेश ने अपनी प्रथामिक शिक्षा गांव में ही हासिल की. इंटरमीडियेट शिक्षा अपने गृह जिले से हासिल करने के बाद वे हैदराबाद के राजेंद्रानगर कृषि महाविद्यालय में बीएससी (अग्रिकल्चर) में प्रवेश लिया. वहीं उनका राडिकल छात्र संगठन (आरएसयू) से परिचय हुआ था. आंदोलनरत गांव की पृष्ठभूमि से आए कॉमरेड रमेश को क्रांतिकारी राजनीति अपनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा. आरएसयू के नेतृत्व में आयोजित हर कार्यक्रम में वे सक्रिय रूप से भाग लेते थे.

1990 में वह पढ़ाई छोड़ कर गुरिल्ला जीवन में आ गए. दक्षिण तेलंगाना के महबूबनगर जिले में एक गुरिल्ला दस्ते का सदस्य बनकर उन्होंने काम किया. बाद में कल्वकुर्ति गुरिल्ला दस्ते के कमांडर की जिम्मेदारी उन्होंने निभायी. वहां उनका नाम कमलाकर था. महबूबनगर जिला तेलंगाना का सबसे पिछड़ा प्रांत है. ऐसे इलाके में काम करते समय उत्पन्न कई कठिनाइयों का उन्होंने दृढ़तापूर्वक सामना किया था. वहां की पीड़ित जनता को कृषि क्रांति में गोलबंद करने उन्होंने अविरल मेहनत की.

शिक्षित व सक्षम होने की वजह से 1995 के बाद उन्हें क्रांति पत्रिका जो तत्कालीन आंध्र प्रदेश राज्य कमेटी का मुख–पत्र था, के विभाग में लिया गया. पहले उन्होंने उस विभाग के प्रिंटिंग आदि तकनीकी काम संभाला. उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए वे अपनी जीवन साथी कॉमरेड यूसुफ बी के साथ महानगरों में रहे थे. महानगरों में व्याप्त साम्राज्यवादी विषैली संस्कृति के प्रभाव से स्वयं को मुक्त रखते हुए उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया था. कुछ दिन के बाद वे डीटीपी व अनुवाद करने लगे थे. दमन व अन्य प्रतिकूलताओं के चलते 2003 के बाद क्रांति प्रेस बंद किया गया था.

2006 में आंध्र प्रदेश राज्य कमेटी, उत्तर तेलंगाना स्पेशल जोनल कमेटी व आंध्रा–ओडिशा स्पेशल जोनल कमेटी के मुख–पत्र के रूप में क्रांति पत्रिका का प्रकाशन गुरिल्ला जोन इलाके से पुनःप्रारंभ हुआ था. उस समय गठित संपादक मंडल के सदस्यों में कॉमरेड रमेश एक थे. क्रांति यूनिट में वे अपना नाम लच्चाल रखे थे. लेकिन कैड़र उन्हें लच्छन्ना पुकारने लगे थे. इससे उनका नाम लच्छन्ना ही स्थिर हो गया. क्रांति संपादक मंडल में वे 2012 तक कार्यरत थे. इस दौरान उन्होंने क्रांति के लिए न सिर्फ कई लेख लिखे थे बल्कि कई लेखों का अंग्रेजी से तेलुगु में अनुवाद भी किया था. किसी भी विषय पर लेख लिखने के लिए वे गहराई से अध्ययन करते थे. समग्रता के लिए कोशिश करते थे. चूंकि उन्होंने कंप्यूटर के हार्डवेयर व साफ्टवेयर संबंधित विषयों में विस्तृत जानकारी हासिल की थी इसलिए लेखन के अलावा उन्होंने उन विषयों में भी अपनी अनमोल सेवाएं दी. कभी–कभी पत्रिका का मेकिंग भी करते थे. कई कॉमरेडों को कंप्यूटर संबंधित विषय सीखने में उन्होंने मदद दी.

लेखन व कंप्यूटर कार्यों तक सीमित न होकर उन्होंने क्रांति यूनिट में काम करने वाले अन्य कॉमरेडों की राजनीतिक व सैनिक क्षमता बढ़ाने में भी अपना योगदान दिया था. उन्होंने कई बार शिक्षक बन कर यूनिट कॉमरेडों के लिए राजनीतिक क्लास चलाया.

2012 के बीच में उनका तबादला बटालियन–1 में हुआ था. 2015 दिसंबर तक वे वहां कार्यरथ थे. बटालियन पार्टी कमेटी के सदस्य की हैसियत से वे बटालियन के राजनीतिक शिक्षक बने. आज की कठिन परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में आंदोलन में आनेवाले उतार–चढ़ाव व ज्वार–भाटा के बारे में बटालियन कॉमरेडों को समझाने में, क्रांति की विजय के प्रति उनका विश्वास बढ़ाने में, उन्हें बोल्शेविक बनाने में कॉमरेड लच्छन्ना का योगदान महत्वपूर्ण रहा.

सैनिक मामलों में भी उन्हें दिलचस्पी रहती थी. मौका मिलने से सैनिक कार्रवाईयों में शामिल होते थे. क्रांति में काम करते समय वे कई बार टीसीओसी में शामिल हुऐ थे. बटालियन में काम करते वक्त बटालियन द्वारा की गयी सभी कार्रवाइयों में उनकी प्रत्यक्ष या परोक्ष भागीदारी थी. उन्होंने कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल किया था. पीएलजीए साथियों को कराटे स्किल्स सिखाते थे.

वे एक गुरिल्ला डॉक्टर भी थे. जरूरतमंदों का इलाज करने वे हमेशा तैयार रहते थे. उनके मेडिकल ज्ञान को बढ़ाने वे अक्सर मेडिकल गाइड्स पढ़ा करते थे. वे जिस किसी भी काम में रहते, उसमें निपुणता हासिल करने की कोशिश करते थे.

जिला कमेटी सदस्य की हैसियत से क्रांति के संपादक मंडल में शामिल होने वाले कॉमरेड रमेश ने 2011 में रीजनल कमेटी सदस्य की हैसियत हासिल की. अक्तूबर 2015 में संपन्न डीके प्लीनम में वे एसजेडसी के वैकल्पिक सदस्य के रूप में चुने गए थे.

लगभग 25 साल की अपनी क्रांतिकारी जिंदगी में दृढ़ संकल्प के साथ काम करते हुए कॉमरेड रमेश ने अपने आप को एक विश्वसनीय नेता के तौर पर साबित किया. आज की कठिन परिस्थिति में उन्हें खोना दंडकारण्य आंदोलन के लिए बड़ा ही नुकसान है.

कॉमरेड रमेश सहित कइयों शहीदों द्वारा स्थापित कम्युनिस्ट मूल्यों व आदर्शों को अपनाकर आगे बढ़ते हुए नुकसानों से उभरेंगे.

कॉमरेड रमेश अमर रहे!

कॉमरेड यूसुफ बी (सोनी)

तेलंगाना राज्य के मेदक जिले के माचिनपल्लि गांव के गरीब अल्पसंख्यक मुसलमान परिवार में लगभग 40 साल पहले कॉमरेड यूसुफ बी पैदा हुई थी. वह हुस्सेन अहमद और खुषुंबी दंपत्ति की संतान थी. 1985 के बाद उस इलाके में तत्कालीन सीपीआई (एम–एल) (पीपुल्सवार) के नेतृत्व में क्रांतिकारी गतिविधियां सक्रिय हो गईं. उस प्रभाव से छोटी उमर में ही कॉमरेड यूसुफ बी क्रांति के प्रति आकर्षित हुई. समाज में खासकर मुसलमान समाज में महिलाओं पर अमल होने वाली पाबंदियों को तोड़ कर वह 1993 में पूर्णकालीन कार्यकर्ता के रूप में गुरिल्ला दस्ते में भर्ती हुई थी. भर्ती होने के बाद उसने अपना नाम भाग्या रखा था. पहले उसने इंदूप्रियाल दस्ते में, बाद में गिरायपल्लि दस्ते में काम किया था. मेदक जिले के भीषण दमन में वह न सिर्फ अडिग रही, बल्कि अपने मिलनसार स्वभाव के चलते जनता में लोकप्रिय हुई थी. अपने दस्ते की जरूरत के अनुसार वह रातों में अकेले गांवों में जाती थी. कई जरूरतें निपटाती थी. क्रांतिकारी सफर के क्रम में उसके व उस दस्ते के कमांडर कॉमरेड मुरली के बीच में प्यार पनपा. पार्टी के अनुमोदन से दोनों की शादी हुई थी. लेकिन कुछ ही दिन बाद एक मुठभेड़ में कॉमरेड मुरली की शहादत हुई थी. झकझोरने वाली इस आघात का उसने हिम्मत से सामना किया था. अपने जीवन साथी के अधूरे सपने को साकार करने वह आगे बढ़ी. 2000 में उसकी शादी कॉमरेड रमेश (लच्छन्ना) के साथ हुई. शादी के बाद अपने जीवन साथी कॉमरेड रमेश के साथ क्रांति स्टाफ में काम करने उसने गुरिल्ला जोन को छोड़ा था. देहाती इलाके में पलने–बढ़ने व बहुत कम ही पढाई करने के बावजूद उसने शहरी इलाके में अपनी जिम्मेदारी सटीक निभाई. जरूरत के अनुसार उसने कई भाषाएं सीखी थी. बाहर क्रांति प्रेस बंद होने के बाद 2006 में उसने सोनी के नाम से दंडकारण्य में कदम रखा था. उसी साल के जुलाई–अगस्त से वह दक्षिण बस्तर डिविजन के पामेड एरिया कमेटी में शामिल होकर उस एरिया के मोबईल पोलिटिकल स्कूल (मोपोस) की शिक्षिका बनी थी. अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए गांव–गांव में घूमते हुए वहां के पार्टी सदस्यों, क्रांतिकारी जनता ना सरकार व जन संगठनों के कार्यकर्ताओं को राजनीतिक शिक्षा देने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

कॉमरेड सोनी की स्वास्थ्य की समस्या थी. वह हमेशा हड्डियों व जोड़ों में असहनीय दर्द के मारे परेशान रहती थी. इसके बावजूद वह अपनी जिम्मेदारियां निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी. महत्वपूर्ण बात यह है कि भीषण दमन में ही उसने अपनी जिम्मेदारियां निभाई थी. उसके मेहनती, मिलनसार व स्नेहिल स्वभाव के चलते उस इलाके में वह एक लोकप्रिय जन नेत्री बनी.

2012 में उसे दक्षिण बस्तर डिविजनल कमेटी में लिया गया था. डीवीसी में शामिल होने के बाद उसकी जिम्मेदारी का दायरा बढ़ गया. मोपोस शिक्षिका के रूप में उसने पूरे डिविजन में अपनी सेवाएं देती रही. कठिन परिस्थिति में भी अडिग रह कर आखिरी दम तक वह अपनी जिम्मेदारी निभाती रही.

अपने 22 साल की क्रांतिकारी जिंदगी में कॉमरेड यूसुफ बी स्वयं को एक आदर्श जन सेविका के रूप में साबित किया.

कॉमरेड यूसुफ बी अमर रहे!

कॉमरेड किसके कमलु (चंदु)

छत्तीसगढ़ राज्य के माड़ डिविजन के इंद्रावती एरिया के ऊत्ला गांव में लगभग 27 साल पहले कॉमरेड कमलु पैदा हुआ था. क्रांतिकारी इलाके में पलने–बढ़ने के चलते सहज ही वह क्रांति के प्रति आकर्षित हो गया. 2002 में वह पूर्णकालीन क्रांतिकारी बन कर पीएलजीए में भर्ती हुआ था. लगभग एक साल किसकोड्डो एलजीएस में काम करने के बाद 2003 में उसका तबादला प्लटून में हुआ था. वहीं उसे पर्टी सदस्यता दी गई. 2007 में उसका तबादला निब कंपनी में हुआ था. 2008 में पीपीसी सदस्य बन कर उसने सेक्शन कमांडर की जिम्मेदारी निभायी. 2013 की आखिरी में उसका तबादला 22 वीं प्लटून में हुआ था. वहां उसने प्लाटून कमांडर की जिम्मेदारी निभायी. वहां उसका नाम चंदू था.

निब कंपनी व 22 वीं प्लटून में काम करते समय वह नेतृत्वकारी कॉमरेडों की सुरक्षा के प्रति हमेशा सावधानी दिखाता था.

2010 में कॉमरेड कमलू की शादी कॉमरेड लच्छी के साथ हुई थी. जनवरी 11, 2016 को हुई एक मुठभेड़ में कॉमरेड लच्छी शहीद हुई थी. इस दर्द से उबरने के पहले ही वह भी शहीद हो गया.

कमलु एक मेहनती, अनुशासित व मिलनसार कॉमरेड था. वह हर कॉमरेड के साथ स्नेहिल रिश्ता बना लेता था.

कॉमरेड कमलु अमर रहे!

कॉमरेड नरोटि सनको (मिनको)

उत्तर गडचिरोली डिविजन के कसनसूर एसी के दायरे में आनेवाले कोयंदूड गांव की लाड़ली बेटी थी, कॉमरेड नरोटी सनको. वह लगभग 30 वर्ष की थी. उस इलाके में क्रांतिकारी आंदोलन के कदम रखने के बाद जन्मी कॉमरेड सनको की जिंदगी अपनी पिछली पीढ़ियों की महिलाओं की तरह की नहीं रही. छोटी उम्र में ही

क्रांतिकारी रास्ता अपनाते हुए वह बाल संगठन में भर्ती हुई थी. बड़ी होने के बाद उसने क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन (केएएमएस) में सक्रिय रूप से काम किया था. कुछ अनुभव हासिल करने के बाद दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संगठन (डीएकेएमएस) में भी अपना योगदान दिया. 2004 में वह पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनकर पीएलजीए में भर्ती हुई थी. पीएलजीए में भर्ती होने के बाद वह अपना नाम मिनको रखा था. कुछ दिन कसंसूर एरिया में ही काम करने के बाद उसका तबदला कसनसूर प्लटून में हुआ था. 2008 में जब सीआरसी कंपनी का गठन हुआ, कॉमरेड मिनको का तबादला उसमें हुआ था. 2009 में उसे सेक्शन कमांडर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. 2011 से लेकर शहदत तक वह प्लटून डिप्युटी कमांडर की जिम्मेदारी निभाती रही.

कॉमरेड मिनको एक विश्वसनीय, मेहनती, अनुशासित व मिलनसार स्वभाव की थी. वह हिम्मत व साहस के साथ दुश्मन से लोहा लेती थी. बोट्टेम में अपनी आखिरी लड़ाई में भी वह नेतृत्वकारी कॉमरेडों को बचाने दुश्मन के साथ आखरी दम तक लड़ती रही. घायल होने के बाद भी लड़ते हुए वह रिट्रीट हुई. थोडी दूर जाने के बाद उसने दम तोड़ा था. इस वजह से उसकी लाश दुश्मन को नहीं मिली.

सैनिक क्षेत्र में उभरती एक महिला कॉमरेड को खोना पीएलजीए के लिए बड़ा ही नुकसान है.

कॉमरेड मिनको अमर रहे!

कॉमरेड सृजना (नवता)

कॉमरेड सृजना तेलंगाना राज्य के वरंगल जिले के पैडिपेल्लि गांव में लगभग 26 साल पहले पैदा हुई थी. पैडिपेल्लि वो गांव है, जिसने अमर शहीद कॉमरेड जन्नु चिन्नालु को जन्म दिया. कॉमरेड जन्नु चिन्नालु की छोटी बहन कॉमरेड शांता की बेटी है, कॉमरेड सृजना. कॉमरेड शांता भी 'अमरा वीरुला बंधु मित्रुला कमेटी' (वीर शहीदों के बंधु व मित्रों की कमेटी) की नेता है. मामा की शहादत से प्रेरित कॉमरेड सृजना ने अपनी इंटरमीडियट की पढ़ाई के बीच में ही पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनने की इच्छा खम्मम–करीम नगर–वरंगल (केकेडब्ल्यू) डिविजन के सामने व्यक्त की. उस कमेटी ने कॉमरेड सृजना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया. बाद में उस कमेटी ने क्रांतिकारी जरूरतों के मुताबिक उसे बाहर भेजा था. जो काम उसे सैंपा गया था, निपटाकर वापस आते समय वह पलिस के हाथों में पड़ी थी. पुलिस ने उसे क्रूर यातनाएं देकर जेल में ठूंस दिया था. वह लगभग एक साल वरंगल केंद्रीय कारागार में रही. जेल में भी वह आवाज बुलंद करती रही. जेल से बाहर आने के बाद 2008 के प्रारंभ में वह गुरिल्ला जोन में चली आई. कुछ महीने के लिए उसने केकेडब्ल्यू डिविजन में ही काम किया. वहीं उसे पार्टी सदस्यता दी गई. 2008 नवंबर में उसका तबादला क्रांति यूनिट में हुआ था. केकेडब्ल्यू डिविजन में वह अपना असली नाम सृजना ही रखा. क्रांति यूनिट में आने के बाद उसने अपना नाम रागो रखा था. लगभग 2013 आखिरी तक कॉमरेड रागो ने उसी यूनिट में अपना योगदान दिया. वह शारीरक रूप से बहुत कमजोर थी. वह बचपन से ही हिमोग्लोबिन की कमी से पीड़ित थी. पुलिस की यातनाएं व जेल जिंदगी ने उसकी तबीयत को और बिगाड़ दिया था. इसके बावजूद टाइपिंग, प्रिंटिंग व स्कॉनिंग आदि कंप्यूटर संबंधित हर काम उसने सीखा और किया. कंप्यूटर संबंधित काम के अलावा उसने यूनिट की सुरक्षा में भी अपना योगदान दिया था. उसके योगदान व चेतना के लिहाज से 2011 में उसे एरिया कमेटी सदस्यता दी गई. 2010 में उसने एक साथी क्रांतिकारी से प्रेम विवाह किया.

2013 की आखिरी में उसका तबादला तेलंगाना राज्य में हुआ था. वहां उसने अपना नाम नवता रखा था. भीषण दमन व इसके चलते उत्पन्न होने वाली कई कठिनाईयों को झेलते हुए तेलंगाना राज्य के स्टाफ सदस्या की हैसियत से वह कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम करते हुए नेतृत्वकारी कॉमरेडों की सहायिका बनी थी. साथ ही साथ तेलंगाना इन्फरमेशन बुलिटेन व प्रजा विमुक्ति जो तेलंगाना राज्य कमेटी के मुख–पत्र है, की तैयारी में भी अपना योगदान दिया. अपनी शहादत के सिर्फ दो दिन पहले उसने प्रजा विमुक्ति के पहले अंक की तैयारी की थी.

कॉमरेड सृजना हमेशा हंसते हुए बिना किसी हिचकिचाहट बड़ों व छोटों के साथ घुल–मिलकर रहती थी. वह खुद बीमार होने के बावजूद अन्य बीमारों के प्रति न सिर्फ संवेदना व्यक्त करती थी बल्कि उन्हें मदद भी देती थी. हालांकि सुदीर्घ काल तक जनता के लिए काम करने का मौका उसे दुश्मन ने नहीं दिया लेकिन कम समय में ही उसने जनता के हृदयों में हमेशा के लिए अपना स्थान सुस्थिर बना गयी.

कॉमरेड सृजना अमर रहे!

कॉमरेड धनसरि सारक्का (अनिता)

कॉमरेड सारक्का का जन्म तेलंगाना राज्य के वरंगल जिले के मडिगुडेम गांव में हुआ था. दो साल पहले ही वह गुरिल्ला दस्ते में भर्ती हुई थी. अनिता के नाम से काम करते हुए उसने पार्टी सदस्यता हासिल की. कुछ दिनों में ही उसने शहादत को पाया. क्रांतिकारी आंदोलन में कुछ ही समय काम करने के बावजूद अपने अनमोल प्राण को न्योछावर करने वाली कॉमरेड सारक्का को जनता कभी नहीं भूल सकती है.

कॉमरेड सारक्का अमर रहे!

फडणविस सरकार का एक साल

फासीवादी दहशत, महंगाई, बदहाली और बेरोजगारी से जनता बेहाल

भारतीय जनता पार्टी के देवेन्द्र फडणविस ने सत्ता में आते ही गो मांस पर प्रतिबंध लगाकर ब्राह्मणत्व का प्रदर्शन शुरु किया. जनवादी नेताओं की हत्या करने का सिलसिला नरेंद्र दाभोलकर से शुरु होकर लगातार जारी है. कॉमरेड गोविंद पानसरे की हत्या इसी की एक और कड़ी है. समाज में अभूतपूर्व रूप से दहशत और असहिष्णुता का माहौल साजिशाना तरीके से फैलाया जा रहा है. देश के जानेमाने बुध्दिजीवी, कलाकार, साहित्यिकार, रंगकर्मी इस माहौल का विरोध करने सड़कों पर उतर आए हैं, अपने पुरस्कार वापस कर विरोध दर्ज करा रहे हैं. महाराष्ट्र में ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी सांस्कृतिक आक्रमण के साथ–साथ असहमति को सहन न करने की समस्या गंभीर रूप धारण कर चुकी है. अभिव्यक्ति की स्वतंत्र को कुचला जा रहा है. किसानों की आत्महत्याएं जारी हैं. पानी के नियोजन के नाम पर भाजपा के फुट सोल्जरों को पालने–पोसने का काम जारी है. राज्य में चारा और पीने के पानी का संकट बरकरार है. मंहगाई चरम पर है, आलू, प्याज, टमाटर 60 रुपये प्रति किलो की दर को पार कर गये हैं तो दाल 200 रुपये तक चढ़ गयी है और आम आदमी की थाली से गायब हो चुकी है. रोजगार शून्य विदेशी पूंजी निवेश के कारण युवाओं का असंतोष फुट पड़ रहा है. स्वार्थी तत्व दलितों और पिछडों के हकों को हड़पने के लिए इस असंतोष को भुना रहे है. महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं. शिक्षा का भगवाकरण और व्यापारीकरण तेजी से किया जा रहा है. राज्य में कुपोषण और पुलिस हमलों के कारण आदिवासियों के अस्तित्व का संकट पैदा हुआ है. चुनाव में कांग्रेस के घोटालों को भुनाकर वोट हासिल करने वाली भाजपा मात्र एक साल में ही दो मंत्रियों पर करोड़ों रुपयों के घोटाले के आरोप से घिर गई है. इस तरह जनता फडणविस सरकार का एक साल देखकर अपने आपको छला हुआ महसूस कर रही है.

महाराष्ट्र में फडणविस सरकार आते ही चिल्लाना शूरु किया कि सरकार के पास धन नहीं है, खजाना खाली है. राजस्व घाटा 26 हजार करोड़ का है. राज्य पर 3 लाख 44 हजार करोड़ का कर्ज है. महाराष्ट्र के हर व्यक्ति पर 28 हजार 660 रु. के कर्ज का बोझ है. इस पर ब्याज के रूप में 23 हजार करोड रु. अदायगी की जाती है. इस तरह जनता को आंकडों के जाल में फंसाकर चुनाव मे किए वादों से पलट गए हैं. चुनाव में एलबीटी रद्द करने और टोल टैक्स बंद करने के दिए आश्वासन को भुलाकर जनता के साथ छल किया है. फडणविस सरकार जनता को अर्थिक और सामाजिक दोनों स्तर पर मार दे रही है. खजाना खाली का बहाना कर कल्याणकारी कार्यक्रमों में और विकास की योजनाओं

कॉमरेड कुंजाम रामे

कॉमरेड रामे का जन्म दक्षिण बस्तर डिविजन के ऊसूर एरिया के नर्सम गांव में हुआ था. वह लगभग 22 वर्ष की थी. पीएलजीए में भर्ती होने के बाद उसे कॉमरेड सोनी की गार्ड जिम्मेदारी सैंपी गई थी. वह एक अनुशासित व जवाबदेह गार्ड थी. अपनी कमांडर को बचाने की कोशिश में वह शहीद हो गई.

कॉमरेड रामे अमर रहे!

कॉमरेड पदाम राजु (रोशन)

कॉमरेड रोशन का जन्म दक्षिण बस्तर डिविजन के पामेड एरिया के पेद्दा बट्टुम गांव में लगभग 20 साल पहले हुआ था. लगभग दो वर्ष पहले ही वह पीएलजीए में भर्ती हुआ था. भर्ती होने के बाद कुछ दिन उसने एक एसजडसी कॉमरेड के गार्ड के तौर पर काम किया था. वह एक मिलिटेंट कॉमरेड था. विगत में तेलंगाना के पीएलजीए बलों के साथ मिल कर वहां के मुखबिरों के उन्मूलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था. इस साल भी तेलंगाना व डीके के संयुक्त पीएलजीए बलों द्वारा काउंटर इंटेलिजेन्स ऑपरेशन संचालित करने की प्लान बनाई गई. उसमें शामिल होने के लिए बोट्टेम गए कॉमरेड रोशन ने वहां शहादत को पाया.

कॉमरेड पदाम राजु अमर रहे!

कॉमरेड देवे

दक्षिण बस्तर डिविजन के पामेड एरिया के मेट्टागूडेम गांव में लगभग 20 साल पहले जन्म लेनी वाली कॉमरेड देवे भी इस मुठभेड़ में शहीद हो गई. उसकी पूर्णकालीन क्रांतिकारी जिंदगी को एक साल भी पूरा नहीं हुआ था. शहदत के वक्त वह ऊसूर एलओएस में कार्यरत थी.

कॉमरेड देवे अमर रहे! ❍

में कटौती कर रही है. दलितों, अल्पसंख्यक धर्मावलंबियों के खान–पान की आदतों पर पाबंदियां लगा रही है. सामाजिक सौहार्द्र को बिगाड़कर जनजीवन को आतंकित किया जा रहा है. यह सारा खेल सुनियोजित है।

फडणविस चाहे जितनी भी डींगें हांके पर उनकी दारोमदार विदेशी पूंजी निवेश पर टिकी हुई है. उनकी नीतियां पूर्व की कांग्रेस सरकार से अलग नहीं हैं. उद्योगों और निवेश को अनुमति देने के लिए रखी गयी 75 शर्तों को 25 तक घटाकर बहुत उछलकूद करते हुए बयान दे रहे हैं. यूरोप, इज्रायल और चीन जाकर देवेन्द्र फडणविस ने विदेशी कंपनियों से कई समझौते किए हैं. इन समझौतों का परिणाम महाराष्ट्र के किसानों और मजदूरों का और ज्यादा शोषण करने में होगा. किसी भी समझौते में रोजगार बढ़ाने के स्पष्ट संकेत नहीं हैं. स्किल इंडिया योजनाओं से कौशल विकास कर नौकरी के बजाय युवाओं को उद्योग लगाने की सलाह दी जा रही है. यह जले पर नमक छिड़कने का काम है. हर साल 1.25 करोड़ युवाओं को रोजगार चाहिए और सरकार की कौशल विकास प्रशिक्षण स्कूलों की क्षमता साल में मात्र 35 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने की है. उसमें भी स्कूलों का स्टैंडर्ड इतना गिरा हुआ है कि वो केवल सर्टिफिकेट देनेवाले कार्यालय जैसे बन गए हैं. ऐसे में स्वरोजगार की बातें खयाली पुलाव पकाने जैसी हैं. सरकारी महकमे में नौकर भारती का 40 प्रतिशत बैकलॉग है. राज्य में 2 लाख 59 हजार मंजूर पदों पर अभी तक भर्ती नहीं की गयी है. इस कारण कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ा है. काम के लिए तरसने वाले युवा दर–दर भटक रहे हैं और ऊपर से यह कहना कि 'सेवा हमी कानून' बनाये हैं, नागरिकों के सरकारी काम जल्दी करायेंगे, जनता के आंखों में खुले रूप से धूल झोंकने के सिवाय कुछ नहीं है. महाराष्ट्र के महसूल मंत्री एकनाथ खडसे ने कहा है कि सरकार के पास चूंकि धन नहीं है इसलिए 40 प्रतिशत विकास कार्य कम किए जायेंगें. इसका सीधा असर शिक्षा, स्वास्थ्य और जनता की आवश्यक जरूरतों पर पड़ रहा है. कर्ज का बहाना करके सरकार निवेश नहीं करेगी, लिहाजा नौकरियां मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है. पर जनता की जान की दुश्मन बनी सरकार केवल पुलिस विभाग में 60 हजार की भर्ती कर रही है। इनके द्वारा राज्य के पंजीकृत 2 लाख 47 हजार युवा बेरोजगार और दसियों लाख ऐसे बेरोजगार युवाओं जो पंजीकृत नहीं हुए हैं, पर लाठी और गोलियां बरसाई जायेगी. इस तरह सरकार पेट और पीठ दोनों पर मार देगी.

रोजगार और विकास का सवाल पूरे राज्य का है. उसमें भी रीजनल पक्षपाती नीति से विदर्भ एवं मराठवाडा की जनता का जीना और भी दुभर हो जाता है. नागपुर समझौते के मुताबिक 23 प्रतिशत की रकम विदर्भ को मिलनी चाहिए. वह कभी नहीं मिली और जो मिली उसको भी विदर्भ में इस्तेमाल करने के बजाय पश्चिम महाराष्ट्र के तरफ टर्न किए गए. पिछले 15 सालों में विदर्भ के 70 हजार करोड़ छिने गए, और बैकलॉग 75 हजार करोड़ का बना हुआ है. इस पर फडणविस कुछ नहीं कह रहे हैं. वह सिलसिला आज भी जारी है. साढ़े चार हजार मेगावॉट बिजली का उत्पादन विदर्भ में होता है और विदर्भ की जरूरत केवल 2200 मेगावॉट है फिर भी विदर्भ के किसान और विदर्भ की जनता अंधेरे में है. विदर्भ में तैयार हो रही बिजली किसानों को देने के बजाय उन्हें सोलर दिखाया जा रहा है और विदर्भ की बिजली को पश्चिम में ले जा रहे हैं. मुख्यमंत्री, आर्थिक मंत्री विदर्भ से होने के बावजूद विदर्भ को हो रहे अन्याय को दूर करने के लिए इन्होंने कोई पहल नहीं की है. अलग विदर्भ राज्य की मांग पर भाजपा ने कन्नी काट ली। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह अब सरासर झूठ कह रहे हैं कि उन्होंने अलग विदर्भ का आश्वासन नहीं दिया था. विधान सभा में जय विदर्भ का नारा देनेवालों पर कार्रवाई की धमकी देना, या युवाओं के लिए 'मी मराठा' वेब पोर्टल (उच्च जाति विशेष के नाम से) खोलना यह स्पष्ट दिखाता है कि मुख्यमंत्री चाहे ब्राह्मण हो या विदर्भ का हो सत्ता मराठा लॉबी की ही जारी है.

मोदी के स्वच्छ भारत की दुहाई फडणविस भी देते हैं, पर महाराष्ट्र की स्कूलों की स्वच्छता या सुविधा की बात तक नहीं की जाती. महाराष्ट्र में आज 1997 स्कूलों में शौचालय नहीं, 6039 में बिजली नहीं, 668 स्कूलों में पीने का पानी नहीं, 14,745 स्कूलों को खेल का मैदान नहीं है, पर बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं. ऐसे में किसकी और कैसी स्वच्छता करने वाले हैं? राज्य में हर पांचवां व्यक्ति खुले मे शौच को जाता है. एक करोड़ लोगों के पास शौचालय नहीं है. फडणविस ने एक साल में ग्रामीण इलाकों में 14 लाख 50 हजार शौचालय बनवायेंगे, ऐसा दावा ठोका. पर उसके लिए मात्र 4000 रु. का अनुदान. क्या केवल 4000 रुपये में शौचालय बन सकता है? और इसके लिए पानी के प्रबंध की कोई व्यवस्था नहीं। जहां पीने के पानी के लिए 19 हजार से भी ज्यादा गांव तरस रहे हों वहां संडास साफ करने पानी कहां से लायेंगे? साल बीत गया पर संडास का

पता नहीं. सरकार के पास स्मार्ट सिटी, मेगा फुड पार्क बनाने के लिए और कुंभ मेले में नंगे साधुओं के नहाने के लिए खर्च करने करोड़ो रुपयों का धन है, पर जनता के स्वास्थ्य पर खर्च करने के लिए नहीं. मुंबई के पास 'नयना' और राज्य में ऐसे ही 30 स्मार्ट सिटी बनाने हजारों करोड़ रुपये खर्च कर रही है. जो मौजूदा सिटी हैं, उनकी यातायात, ड्राइनेज, बसाहट, बिजली, पानी, कचरा निकासी व्यवस्थाएं आज तक कोई सरकार ठीक नहीं कर पायी है. एशिया की सबसे बड़ी झोपडपट्टी और विश्व के सबसे बड़े प्रदूषित शहरों में शुमार हैं, महाराष्ट्र के शहर. वहां स्मार्ट सिटी बनाने का मामला हरामखोरी करने के लिए बनाई गई नई योजना के सिवाय और कुछ नहीं. मेगा फुड पार्क भाजपा की फायनेन्शिअल लाईफ लाईन अदानी, आयटीसी आदि के भरण–पोषण के लिए है. जिसमें वे 850 करोड़ निवेश करने वाले हैं. महाराष्ट्र की जनता स्मार्ट सिटी नहीं, समृध्द गांव और समृध्द खेती चाहते हैं जिस पर 65 प्रतिशत जनता की आजीविका निर्भर है. फडणविस सरकार का ध्यान भी मोदी की तरह कार्पोरेट वर्ग को मुनाफा पहुंचाने, उनकी पूंजी के चक्र को घुमाने की तरफ है.

फडणविस सरकार रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्रों में पिछले एक साल में बुरी तरह फेल हो चुकी है. महाराष्ट्र में 37 प्रतिशत कुपोषित बच्चें और कम वजनी माताएं हैं. इन मामलों में राज्य तमिलनाडू, पश्चिम बंग के बाद देश में तीसरे नंबर पर है. कुछ जिलों में 25 तो कहीं 42 प्रतिशत बच्चें कुपोषित हैं. महाराष्ट्र में महिलाओं पर बलात्कार में 63 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है. अंधश्रध्दा के खिलाफ लड़ने वाले जनवादी बुध्दिजीवी नरेन्द्र दाभोलकर के खूनी को अब तक पकड़ नहीं सके. कॉमरेड़ गोविंद पानसरे के हत्यारों को पकड़ने का जो दावा किया जा रहा है, वह भी जनता के गुस्से को शांत करने के लिए सनातन संगठन के साथ मिलीभगत कर बनायी गयी योजना जान पड़ती है. असली गुनाहगार अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है. जाहिर है, यह राज्य के साथ मिलीभगत से अंजाम दिया गया जघन्य कांड है. हजारों करोड़ रुपये खर्च कर मुख्य शहरों को सीसीटीवी कैमरे के स्कॉनिंग में लाया जा रहा है. सरकार की बद्तमीजी यहां तक है कि जेल में महिला बैरकों में भी सीसीटीवी कैमेरे लगाए गये थे. कॉमरेड एंजेला के नेतृत्व में इसके खिलाफ महिलाओं की भूख हड़ताल के बाद इसे वापस लिया गया. 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' का नाटक करने वाली भाजपा सरकार का महिलाओं के प्रति रवैया क्या है, इससे स्पष्ट होता है. पुलिस नेटवर्क, ऑन लाईन सूचना तंत्र और क्राईम ट्रैकिंग नेटवर्क से लैस पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे हैं, भले ही जनता को दो वक्त की दाल–रोटी नसीब न हो. इरादा स्पष्ट है कि आनेवाले दिनों में जनता पर राज्य की ओर से हमले और बढ़ने वाले हैं. इसीलए राज्य के हर हिस्से को पुलिस राज्य के रूप मे तब्दील किया जा रहा है. जनवादी आंदोलनों पर अघोषित पाबंदी लगाई गई है. एक तरफ परमिशन देते हैं, दूसरी तरफ भारी पुलिस तैनात कर दहशत फैलाते हैं.

पहले ही पुलिस जिले में तब्दील गड़चिरोली जिले में सीआरपीएफ की और बटालियनों की मांग इस सरकार ने केंद्र से की है. बैलाडिला की तरह ही दुनिया का बेहतरीन लौह अयस्क गड़चिरोली के सुरजागढ़ पहाड़ी में है. इसे लूटने के लिए विदेशी कंपनियों के साथ देशी कंपनियों ने सांठ–गांठ की है. देश के दलाल पूंजीपति और नेताओं की नजर इस बहुमूल्य खनिज संपत्ति पर पड़ी है. इसे लूटने के लिए इसके चारों ओर पुलिस कैम्पों का जाल बिछाया जा रहा है. गौरतलब है कि यह क्षेत्र भारत के संविधान के अनुसार पांचवी अनुसूची के तहत आता है. यहां आदिवासी जनता जल–जंगल–जमीन और इज्जत के लिए लड़ रही है. पर फडणविस सरकार सारे कानूनों को ताक पर रखकर और जनप्रतिरोध को बंदूक के बल पर कुचलकर खदानें खोलने जा रही है. सूचना आधारित बड़े पैमाने पर हमले कर माओवादी आंदोलन को खत्म करने की योजना पर काम कर रही है. मार्क्सवादी बुध्दिजीवी और समर्थकों को गिरफ्तार कर माओवादियों के 'शहरी नेटवर्क' को खत्म करने के काम पर विशेष ध्यान दे रही है. अन्य राज्यों की ही तरह माओवादियों के खिलाफ युध्द करने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित यूनिफाईड कमांड की मीटिंग नियमित करने का निर्णय लिया गया है. इसमें केन्द्रीय गृह मंत्रालय, राज्य गृह मंत्रालय, केन्द्रीय फोर्स के अफसर, सेना के अफसर हिस्सा है. आनेवाले दिनों मे माओवादियों के खिलाफ एक साथ देशव्यापी हमलावर अभियान के लिए महाराष्ट्र में भी तैयारी की जा रही है.

दरअसल आदिवासियों की बढ़ती राजनीतिक चेतना से सरकार भयभीत है. इसलिए आदिवासियों में विश्वास गंवा चुकी सरकारी संस्थाओं के वजूद को बरकरार रखने के लिए टीएसपी (ट्राईबल सब प्लान) के अंतर्गत 5 प्रतिशत राशि सीधे 'पेसा' अंतर्गत ग्राम पंचायतों के हवाले करने का निर्णय किया है. इसे 'गांवचा विकास गावाच्या हाती' और 'एक पाऊल विकासाकडे' नाम से

प्रचारित किया जा रहा है. इस तरह के सतही तौर के प्रचार से प्रसार माध्यमों में तो वाहवाही लूटेंगे पर आदिवासियों के दिलों दिमाग पर उन्होंने जो दूरगामी चोट पहुंचाई है, वह इससे भरने वाली नहीं. पिछले एक साल में आदिवासी विषय पर राज्य सरकार खासकर राज्यपाल कभी इतने सक्रिय नहीं हुए थे. आदिवासियों की जमीन हड़पकर कार्पोरेट कंपनियों के हवाले करने हेतु राज्यपाल के मार्फत राजनीतिक साजिशें की जा रही हैं.

आदिवासी की तरह ही दलितों पर अन्याय व अत्याचार जारी हैं. भाजपा एक तरफ डॉ. आंबेडकर के प्रतीकों का इस्तेमाल कर दलितों को बरगलाने की कोशिश कर रही है. वहीं आंबेडकर के विचारों के ठीक उल्टा काम कर रही है. अनावश्यक रूप से करोड़ों रुपये खर्च कर लंडन का वह घर खीरद लिया है जिसमें छात्र जीवन में डॉ. आंबेडकर कभी रहा करते थे. इसे देखने न कोई साधारण दलित जायेगा और ना ही यह दलितों की मांग थी और न इसका कोई उपयोग है. 'प्रतीकों को पूजना और विचारों को दफनाना' भाजपा के इस धूर्त चाल से दलित जनता को वाकिफ करना चाहिए. यह दलितों के उध्दार के लिए नहीं है बल्कि दलितों की लड़ाकू शक्ति को खोखला बनाने के लिए है. साथ ही ब्राह्मणीय हिन्दू फासीवादी आक्रमकता से डॉ. आंबेडकर की प्रतिमाओं को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर रही है. हिंदू धर्म में जबरन शामिल करना ब्राह्मणवादी नीति के अमल का हिस्सा है. वहीं दूसरी तरफ राज्य में दलितों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं.

राज्य में सरकार द्वारा अमल में लायी गयी योजनाओं की वजह से राज्य की जनता पर भारी शोषण और दमन बढ़ने वाला है. लेकिन इस पर कोई राजनीतिक पार्टी दखल तक नहीं ले रही है. इस राजनीतिक परिवेश की वास्तविकता को जनता में ले जाना जरूरी है. इस परिवेश ने सभी राजनीतिक पार्टियों का पर्दाफाश कर दिया है. शिवसेना जो गठबंधन में बड़ी मछली हुआ करती थी, आज छोटी बन गई है और इस खतरे से घबरा गई है कि कहीं भाजपा शार्क उसे निगल न ले. कोंकण के अपने जन आधार को बचाये रखने के लिए जैतापूर प्रकल्प का विरोध कर रही है. शिवसेना का चरित्र ही दोगला रहा है. पहले दाभोल परियोजना का विरोध जताया था और फिर अमरिका के साथ सौदा कर विरोध वापस लिया था. उसके धोखेबाजी चरित्र जनता जानती है. राष्ट्रवादी कांग्रेस तथा कांग्रेस दोनों ही केवल सतही स्तर की टिप्पणी करते हुए सत्ता में बैठी भाजपा–शिवसेना का मूक समर्थन ही दे रही हैं. भाजपा के साथ चुनाव में सहयोगी राजू शेट्टी के शेतकरी संगठन, महादेव जामकर के शिवसंग्राम या रामदास आठवले को हर स्तर पर मुंह की खानी पड़ रही है. गन्ना किसानों को पर्याप्त भाव, मराठा आरक्षण, गोमांस पर पाबंदी से इन तीनों का जनाधार भी सवाल करने लगा है. सत्ता के पल्लू के किनारे बांधकर इन्हें लाचार बना दिया गया है.

कुल मिलाकर महाराष्ट्र में पहले से जारी किसान समस्या, विस्थापन, रोजगार, मजदूरों की सुरक्षा, हक और वास्तविक रोजी की समस्या, स्वास्थ्य और शिक्षा की समस्या और तीव्र हो गई है. सरकारी कर्मचारियों पर काम का बोझ काफी बढ़ा दिया गया है. महिला सुरक्षा का प्रश्न और भी विकराल बना हुआ है. पूरे राज्य को घोर पुलिस राज्य में तब्दील किया जा रहा है. आदिवासी और दलितों को निशाना बनाकर सीधे और मानसिक रूप से दमन और बढ़ाया जा रहा है. जहां–वहां सीसीटीवी कैमरे लगाना, कुंभ मेले में करोड़ो रुपये खर्च करना और विदेशों में जाकर बड़े कार्पोरेट घरानों को राज्य में लूट और शोषण करने के लिए आमंत्रित करना, यही फडणविस के विकास की परिभाषा है. उसे न तो किसानों की आत्महत्याओं से कोई लेना–देना है और न ही रोजगार के लिए दर–दर भटक रहे नौजवानों की परवाह है. जनता की नजर में फडणविस सरकार हर मोर्चे पर विफल है, मात्र झूठा प्रचार करने में अव्वल है. जनता समझ रही है कि कांग्रेस के भ्रष्ट शोषण का जवाब ब्राह्मणीय हिंदू फासीवादी राज नहीं है. दोनों की नीतियां एक ही हैं. एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ. भ्रष्ट कांग्रेसी को हटाने के चक्कर में जनता इन फासीवादियों के विकास के नारे के झांसे में आकर ठगा महसूस कर रही है. इसलिए जनता की इन ज्वलंत समस्याओं पर राजनीतिक पहल करने की जरूरत है. अब तक के अनुभवों से भी यह साफ हो गया है कि संसदीय व्यवस्था में चुनावों से केवल पार्टी बदलती है, राज्य नहीं बदलता, न ही उसका स्वरूप बदलता है. पल–पल सताती इस व्यवस्था को बदलने का एक मात्र रास्ता है, नवजनवादी क्रांति. जमीनी परिस्थिति बता रही है कि भारत को क्रांति की अत्यंत आवश्यकता है. अतः इससे पहले कि फासीवादी हमारे नौजवानों को सांप्रदायिक दंगों के आपसी मार–काट के रास्ते पर ले जाकर बर्बाद करें, उन्हे क्रांति में गोलबंद कर देश को बचाने और नवजनवादी भारत का पुनर्निर्माण करने के कार्य में लगाना होगा। ❍

छत्तीसगढ़ बजट 2016–17
कॉरपोरेट लूट के लिए आधारभूत संरचना पर जोर

विगत 9 मार्च को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमण सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में 73,996 करोड़ रुपए का अपना 10 वां बजट विधान सभा में पेश किया. पिछले वर्ष के 65,013 करोड़ के बजट की तुलना में इस वर्ष का बजट 18 फीसदी बढ़ गया है. अपने बजट को समावेशी बजट करार देते हुए रमण सिंह ने कहा कि इस बजट के माध्यम से आर्थिक विकास की आगामी रणनीति के सात स्तंभों–सुखी अन्नदाता, समावेशी विकास, संचार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और सक्षमता को सुदृढ़ किया जायेगा. रमण सिंह की आम बजट के साथ ही विशेष कृषि बजट पेश करने की नौटंकी दो साल में ही खत्म हो गयी. 2014–15 बजट पेश करते समय बड़े आडंबर के साथ यह कहते हुए कि इससे राज्य का कृषि संकट खत्म हो जायेगा, अलग से कृषि बजट पेश किया गया था. खत्म होना तो दूर की कौड़ी है, उल्टे कृषि संकट गहराता जा रहा है. लेकिन इस बार सात स्तंभों की नयी नौटंकी शुरु की गयी. हमेशा की तरह बजट को सत्ता पक्ष के लोगों ने विकासोन्मुखी बताया तो विपक्ष ने बजट को साधारण व निराशाजनक.

आइए! बजट के आंकड़ों और उनके संभावित नतीजों पर नजर दौड़ाते हैं.

बजट पेश करते हुए रमण सिंह ने कहा कि कुशल वित्तीय प्रबंधन और सही प्राथमिकताओं की एक मजबूत बुनियाद तैयार करने के पश्चात उनके सामने अपनी उपलब्धियों से और आगे बढ़ने की चुनौती है. यह अपनी पीठ खुद थप–थपाने वाली बात है. जबकि वास्तविकता इसके ठीक उल्टा है. छत्तीसगढ़ के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक ने राज्य के वित्तीय प्रबंधन को बदहाल कहा. राजस्व घाटा 1,573 करोड़ रुपए का हो गया है. जबकि 13वें वित्त आयोग और राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन कानून राजकोषीय घाटे को शून्य रखने की जिम्मेदारी तय करता है. 2014–15 के दौरान राजकोषीय घाटा 8,008 करोड़ रुपए रहा. कैग ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 9,500 करोड़ रुपए का गड़बड़झाला पाया. 2015–16 बजट के पुनरीक्षित अनुमान के मुताबिक सकल वित्तीय घाटा 6,832 करोड़ रहा. हर बार बजट में वित्तीय घाटे को काफी कम करके दिखाया जाता है लेकिन अंत में जाकर यानी पुनरीक्षित अनुमान के मुताबिक घाटा बढ़ ही जाता है. चालू वित्तीय वर्ष में भी घाटा 8 हजार करोड़ पार करने का खयास लगाया जा रहा है. राज्य पर जीएसडीपी के अनुपात में 15.2 प्रतिशत ऋणभार है. हालांकि रमण सिंह यह कहते खुश हो रहे हैं कि इतने ऋणभार के साथ भी छत्तीसगढ़ देश में सबसे कम ऋणभार वाला राज्य है. लेकिन एक छोटे राज्य के लिए यह ऋणभार कम नहीं होता है. और यह लगातार बढ़ रहा है. प्रति व्यक्ति कर्जा पिछले वर्ष के 6,632 करोड़ रुपए की तुलना में 74 फीसदी बढ़कर 11,549 करोड़ रुपए हो गया है. कैग ने इसके लिए बजट और वित्तीय कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया. सारा कर्जा गया कहां है? राज्य की जनता का हाल बेहाल है. सभी तबकों की जनता की समस्याएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं. किसानों, मजदूरों, शिक्षकों, सभी विभागों के कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है. इसका सीधा मतलब है, आम आदमी की लूट और खास लोगों को छूट और मुनाफे पर मुनाफा. बजट व वित्तीय कुप्रबंधन का आलम यह है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में सरकार मूल बजट के अलावा चार अनुदान मांगें लेकर आई. इसके बावजूद 833 करोड़ 54 लाख रुपए बजट प्रावधानों के बाहर जाकर खर्च किए गए. इसे नियमित करने के लिए सरकार ने कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई. इतना ही नहीं, पिछले बजट से मिले 12 हजार 848 करोड़ 3 लाख रुपए को खर्च ही नहीं कर पाई. सबसे बड़ी निंदनीय बात यह है कि पिछले पांच वर्षों से सामाजिक, आर्थिक सेवाओं की अनुदान मदों में लगातार बचत देखी गयी है. इससे यह साफ है कि राज्य के गरीब, दलित व आदिवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य कल्याण योजनाओं के अमल पर उस हद तक असर पड़ा था.

इस बार के बजट में आय के स्रोतों में केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से के तहत 27 प्रतिशत, केंदीय सरकार से सहायता 19 प्रतिशत, वाणिज्यिक कर 17 प्रतिशत, शुद्ध लोक ऋण 11 प्रतिशत, खनिज 8 प्रतिशत, राज्य उत्पाद शुल्क 6 प्रतिशत, प्रवेश कर 2 प्रतिशत, विद्युत कर 2 प्रतिशत, स्टाम्प एवं पंजीयन 2 प्रतिशत, वाहनों पर कर 1 प्रतिशत, वानिकी 1 प्रतिशत, भू–राजस्व 1 प्रतिशत, सिंचाई 1 प्रतिशत, अन्य 2 प्रतिशत शामिल हैं. यानी प्रत्यक्ष करों से 41 प्रतिशत प्राप्तियां हासिल करने की संभावना जतायी गयी है. बजट के व्यय के प्रावधानों में शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति 20 प्रतिशत, कृषि एवं संबद्ध सेवाएं 13 प्रतिशत, सड़क एवं पुल 10 प्रतिशत, स्थानीय निकायों को अनुदान 8 प्रतिशत, पेंशन एवं विविध सेवाएं 7 प्रतिशत, जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास 7 प्रतिशत, स्वास्थ्य 6 प्रतिशत, प्रशासनिक सेवाएं 6 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण 1 प्रतिशत, ग्रामीण विकास 1 प्रतिशत, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण 1 प्रतिशत, ऊर्जा 3 प्रतिशत, उद्योग व खनिज 1 प्रतिशत, ब्याज संदाय 4 प्रतिशत, सामाजिक कल्याण 4 प्रतिशत, अन्य 5 प्रतिशत

शामिल हैं. बजट का क्षेत्रवार व्यय इस प्रकार है–42,056 करोड़ रुपए यानी 60 प्रतिशत का आयोजना व्यय, 13,004 करोड़ रुपए यानी 18.5 प्रतिशत का पूंजीगत व्यय. जबकि उपयोजना व्यय में अनुसूचित जनजाति उपयोजना व्यय 36 प्रतिशत और अनुसूचित जाति उपयोजना व्यय 12 प्रतिशत है. बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए कुल 40 प्रतिशत राशि आबंटित की गयी है जिसमें से स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास के लिए 13,086 करोड़ (19 प्रतिशत), स्वास्थ्य के लिए 3,815 करोड़ (5.4 प्रतिशत), महिला एवं बाल विकास के लिए 1,902 करोड़ (2.7 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया है. आर्थिक क्षेत्र के लिए कुल 40 प्रतिशत राशि आबंटित की गयी है जिसमें से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के लिए 4,627 करोड़ (6.6 प्रतिशत), ग्रामीण विकास के लिए 8,319 करोड़ (12 प्रतिशत), लोक निर्माण के लिए 6,804 करोड़ (10 प्रतिशत), सिंचाई के लिए 2,923 करोड़ (4 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया है.

रमण सिंह हमेशा गांव, गरीब, किसान को अपनी सरकार का लक्ष्य बताते नहीं थकते हैं. इस बार के बजट को भी गांव, गरीब, किसान के दिल के करीब बताया जोकि सत्य से परे है. दरअसल वर्तमान बजट में सबसे ज्यादा जोर आधारभूत संरचना पर दिया गया है. रमण सिंह ने बेहिचक यह साफ कहा कि आधारभूत संरचना को विकसित करना बजट का लक्ष्य है. इसके तहत सड़कों, पुलियों, रेल मार्गों, हवाई अड्डों, नेट कनेक्टिविटी, अंडर ब्रिज व ओवर ब्रिजों के निर्माण के लिए बजट में कई प्रावध ाान किये गये हैं. सुदूर वनांचलों से शहरों को जोड़ने की योजना है. 42 हजार करोड़ के निवेश से आगामी तीन वर्षों में 13 हजार किलोमीटर सड़कों का उन्नयन किया जाना है. पीडब्ल्यूडी सड़कों व पुलों के लिए 4,640 करोड़ का प्रावधान है, जो 2015–16 से 56 प्रतिशत अधिक है. जबकि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 2,476 किलोमीटर लंबाई की सड़कों जिसके अंतर्गत 150 नई सड़कें भी शामिल हैं, के निर्माण के लिए 1,062 करोड़. कुलमिलाकर सड़कों के लिए 6,101 करोड़ का प्रावधान है. इनमें वनांचल खासकर बस्तर संभाग के अंदरूनी इलाकों की सड़कें शामिल हैं जिनका मुख्य मकसद संसाधनों की लूट एवं संघर्षरत जनता के दमन के लिए सशस्त्र बलों की आवाजाही को सुगम बनना है. 1,300 किलोमीटर से अधिक रेल नेटवर्क मात्र 5–6 वर्षों में निर्मित करने की योजना है. रावघाट खदान सहित दर्जनों खदानों से खनिज संसाधनों की लूट के लिए उद्देश्यित दल्ली–रावघाट–जगदलपुर रेल लाइन निर्माण व उसके लिए आबंटित राशि अलग है. उसका बजट से कोई लेना–देना नहीं है. इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रायगढ़, जगदलपुर की हवाई पट्टियों के विमानतल में उन्नयन के प्रावधान किये गये हैं. केंद्र से योजना आयोग की सिफारिश के मुताबिक 7,400 करोड़ रुपए अधोसंरचना मद में अतिरिक्त मिलेंगे. मुख्यमंत्री ने बताया कि इसीलिए अधिकांश कार्यों में अधोसंरचना विकास पर फोकस किया गया है. इससे साफ जाहिर है कि संसाधनों की कॉरपोरेट लूट की दूरगामी योजना के मुताबिक ही वर्तमान बजट को तैयार किया गया है. जनता की मूलभूत जरूरतों को दरकिनार करके अधोसंरचना को ही जनता के विकास के रूप में प्रचारित किया जा रहा है और बजट को उसी हिसाब से पेश किया गया है.

रमण सिंह ने विकास की अपनी भावी रणनीति के सात स्तंभों में सुरक्षा को भी जोड़ा है. जाहिर है, सुरक्षा का मतलब नक्सलवाद के विरुद्ध सरकारी रणनीति से संबंधित है. केंद्रीय तथा राज्य सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान और 'विकास' को महत्व देते हुए बजट में सशस्त्र बलों की 4,000 पदों के साथ 4 नई बटालियनों के गठन के लिए प्रावधान किया गया है. साथ ही 70 हजार सुरक्षाकर्मियों के आवास के लिए 1,000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं. केंद्र सरकार द्वारा माओवाद विरोधी अभियान के लिए राज्य को दी जाने वाली सहायता इसके अतिरिक्त है. इससे साफ जाहिर है, राज्य में जारी फासीवादी दमन अभियान में और तेजी आयेगी.

'धान का कटोरा' कहलाने वाला छत्तीसगढ़ पिछले कुछ वर्षों से देश में अन्नदाताओं की आत्महत्याओं के लिए जाना जाने लगा है. 443 आत्महत्याओं के साथ छत्तीसगढ़ 2015 में देश में चौथे स्थान पर खड़ा था. 2016 की पहली तिमाही में ही 70 से ज्यादा किसानों ने राज्य में आत्महत्या की. इतनी विकराल हुई समस्या के हल के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है. यह सर्वविदित है कि किसानों की आत्महत्याओं के पीछे प्रधान कारण है, कर्जा का बोझ. किसानों को दी जाने वाली सब्सिडियों में कटौती, लागत खर्च का बढ़ना, कृषि उत्पादों का समर्थन मूल्य में नाम मात्र की बढ़ोत्तरी आदि के चलते ऋणभार का बढ़ना. कृषि विभाग के बजट में ब्याज अनुदान एवं सूखे के लिए किसानों को ऋण सहायता 223 करोड़, सूखा प्रभावित लघु एवं सीमांत किसानों को 1 क्विंटल तक निःशुल्क प्रमाणित धान बीज 150 करोड़, सूखा–प्रभावित किसानों को बेटियों के विवाह के लिए 30 हजार रुपए देने हेतु 8 करोड़, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. कृषि क्षेत्र के आबंटन में इस बार 26 फीसदी यानी 450 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है. दरअसल कृषि बजट में 2014–15 में उसके पूर्व की तुलना में कमी की गयी थी. पहले कम करना फिर बढ़ोत्तरी दिखाना किसानों के साथ छलावा ही है. किसानों के तमाम कर्ज माफ करने की बजाए सिर्फ ब्याज अनुदान का प्रावधान

ही बजट में किया गया है. इससे किसानों का कर्ज के बोझ से बाहर आना संभव नहीं है. सूखा–प्रभावित किसानों को 223 करोड़ की ऋण सहायता का प्रावधान कहीं से भी वाजिब नहीं है और अपर्याप्त है.

किसानों को मुफ्त बिजली देने की बजाए सिर्फ 1500 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का प्रावधान बजट में किया गया है. यहां भी याद रखना होगा कि सरप्लस बिजली का बखान करने वाले रमण सिंह बिजली की दरें कम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. बहुत कम लागत में बिजली बनाने वाली कंपनियों से महंगी दरों पर बिजली खरीद रहे हैं.

फसल बीमा योजना का 200 करोड़ भी लुभावना भर है और भीषण अकाल पड़ने से यह पर्याप्त नहीं होगा. इसके अमल का अनुभव काफी हताशा पैदा करने वाला है और निराशाजनक है. एक उदाहरण देखें. फसल बीमा लाभ का ख्वाब दिखाकर महासमुंद जिले के 49,362 किसानों से 3 करोड़ 47 लाख 27,886 रुपये की प्रीमियम राशि वसूलने वाली नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस ऑफ इंडिया कंपनी ने सूखे के बाद किसानों को फूटी कौड़ी नहीं दी. इस बीमा कंपनी ने फसल बर्बादी पर किसानों को उनके प्रीमियम के एवज में कुल 27 करोड़ 61 लाख 46,140 रुपए का लाभ देने का दावा किया था. धान का दाना–दाना खरीदने, समर्थन मूल्य 2100 रुपए प्रति क्विंटल करने, धान खरीदी पर बोनस देने, खाद और कीटनाशकों की खरीदी पर सब्सिडी देने का कोई प्रावधान बजट में नहीं है. इतना ही नहीं, कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योगों के लिए भी बजट में कोई प्रावधान नहीं है.

राज्य की अधिकांश खेती आज भी बादल भरोसे है. सिर्फ 17 प्रतिशत भू–भाग ही दो फसली है. सिंचाई योजनाएं कई सालों से अधूरी पड़ी हैं. 2014–15 के बजट में, उसके पहले के बजट से भी कम राशि का प्रावधान किया गया था. इस बार के बजट में हल्की सी बढ़ोत्तरी करते हुए सिंचाई विस्तार के लिए 2,564 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. छत्तीसगढ़ में कुल 248 बड़े बांध हैं जिनमें से 179 बांध 25 साल पुराने हैं जबकि 10 निर्माणाधीन हैं. बजट में दो फसली जमीन में वृद्धि के लिए कुछ नहीं किया गया है. सिंचाई विस्तार के लिए आबंटित राशि बहुत ही कम है. इससे योजनाएं पूरी होने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है. इससे यह अंदाजा लगाना कठिन नहीं होगा कि सरकार किसान के कितनी करीब है.

सामाजिक कल्याण क्षेत्र में पिछड़ी जन जाति को छाता और रेडियो, निशक्त पति–पत्नी को 1 लाख रुपए, एक के निशक्त होने पर 50 हजार रुपए के छोटे–मोटे प्रावधानों सहित 60 लाख परिवारों को सस्ते खाद्यान्न के लिए 3,300 करोड़ आबंटित करके बड़ी चतुराई से रमण सिंह ने अपने बजट को लोक–लुभावन बनाने का असफल प्रयास किया. सत्ता में आते ही सारे रेशन कार्ड जब्त करके सत्यापन के नाम पर करीबन आधे कार्डों को रद्द कर दिया. सस्ती लोकप्रियता की योजना को भी पूरी तरह संचालित करने व उसके लिए आवश्यक राशि प्रदान करने सरकार तैयार नहीं है. दूसरी ओर पिछले साल राज्य में मार्कफेड के जिला विपणन अधिकारी और जिला केंद्रीय बैंकों के बीच 11,729 करोड़ 18 लाख रुपए का धान गायब हो गया है. गैर जरूरी ब्याज, तय दरों से अधिक परिवहन भाड़े का भुगतान, धान की सूखत में, खुले में धान रखने की वजह से धान के खराब होने, 33 चावल मिलों द्वारा चावल जमा न करने की वजह से उपरोक्त नुकसान हुआ है.

महिलाओं व निशक्तों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है.

असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा मंडल श्रमिकों एवं उनके परिवार हेतु छात्रवृत्ति, कौशल विकास, इलाज सहायता आदि कल्याणकारी योजनाओं के लिए मात्र 40 करोड़ की राशि आबंटित की गयी है जोकि किसी भी मायने में अपर्याप्त ही कहा जायेगा.

महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु 1,902 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं जिसमें से एकीकृत बाल विकास योजना हेतु 1,056 करोड़ का प्रावधान है.कुपोषण दूर करने के लिए राज्य सरकार हालांकि समेकित बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, नवाजतन योजना आदि कई तरह की योजनाएं संचालित करने का दावा कर रही है लेकिन राज्य में बाल विकास की वास्तविक स्थिति ऐसी है कि प्रदेश में 6 लाख 52 हजार बच्चे कुपोषण के शिकार हैं.

युवाओं को लुभाने के लिए बजट में कुछेक प्रावधान किये गये हैं लेकिन बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में ये कोई खास मदद नहीं कर पायेंगे. मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एवं स्किल डेवलपमेंट इनिशियेटिव योजना के लिए 144 करोड़ की राशि आबंटित की गयी. लेकिन कई सरकारी विभगों के दसियों हजार खाली पदों को भरने का कोई प्रयास सरकार की ओर से नहीं किया गया है, सिवाय पुलिस भर्ती के. बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने का कोई प्रावधान भी बजट में नहीं है.

बिजली महंगी न हो, इसके लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है. लेकिन बजट प्रावधानों के अमल में आते ही 1 अप्रैल से बिजली महंगी हो गयी है. राज्य में बिजली के नये दाम तय होने के बाद सबसे ज्यादा भार घरेलू उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है. निम्न मध्यम से लेकर उच्च मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को हर 100 यूनिट बिजली खपत पर 44 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे.

बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए किये गये आबंटनों में

स्कूल शिक्षा के लिए 11,144 करोड़ दिए गए हैं. आश्रम शालाओं एवं छात्रावासों के रहवासी छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु स्वामी विवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना प्रारंभ करने हेतु 1,902 करोड़, मिड डे मील के लिए 542 करोड़ आबंटित हैं. शिक्षाकर्मियों को ऑनलाइन वेतन योजना के तहत आगामी वर्ष से सभी शिक्षकों व शिक्षाकर्मियों को नियमित रूप से वेतन भुगतान के लिए जिला स्तर से सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान किये जाने का प्रावधान है. बजट प्रावधानों में ज्यादातर वेतन भत्तों, स्कूलों व महाविद्यालयों का उन्नयन शामिल है. शिक्षा के लिए महत्व देकर राशि आबंटित करने की बात कही जा रही है लेकिन प्रदेश की शालाओं व शिक्षा की स्थिति देखने से यह राशि कितनी कम है, आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है. 70 हजार शिक्षकों के खाली पर भरे जाने के बारे में बजट मौन है. मध्यान्ह भोजन की क्वालिटी में सुधार, ग्रामीण इलाकों की स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार की योजनाएं बजट में नदारद हैं. बजट में शिक्षा के वातावरण व पढ़ाई के स्तर को सुधारने के बारे में कोई चर्चा नहीं की गयी है. राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में मौजूद 32,786 प्राथमिक शालाओं, 13,626 मिडिल और 1859 हाई स्कूलों, 70 हायर सेकंडरी स्कूलों में से 1,073 शालाएं भवन विहीन, 1,008 निर्माणाधीन, 1429 जर्जर हैं. जबकि 2,158 किराए के भवनों में, 476 बगैर किराए वाले भवनों में संचालित हैं. 18,000 शालाओं में बिजली नहीं है. 6,000 से अधिक शालाओं के पास अपना स्वयं का भवन नहीं है. स्वच्छ भारत योजना के शोर के बावजूद हजारों शालाओं में शौचालय नहीं है. शिक्षाकर्मियों की लंबित मांगें–संविलयन व समान वेतनमान का बजट में कोई जिक्र नहीं है. शिक्षा को महत्व देने की बात एक ओर करते हुए ही दूसरी ओर युक्तियुक्तकरण के नाम पर सरकार करीबन 3,000 शालाओं को बंद करने की योजना पर अमल कर रही है. आदिवासी विकास विभाग से स्कूलों का शिक्षा विभाग में हस्तांतरण किया गया है. कई स्कूलों को बंद किया गया है. सरकार बजट बनाने में पांचवी अनुसूची के प्रावधानों का बिल्कुल पालन नहीं किया है. मध्यान्ह भोजन योजना बच्चों को स्कूल में बनाए रखने में पिछले वर्षों में असफल रही है. 2010–11 की तुलना में 2014–15 में बच्चों की संख्या में 22 प्रतिशत की गिरावट देखी गयी है. इसी बीच निजी स्कूलों में 34 प्रतिशत बच्चे बढ़े हैं. 10,000 से ज्यादा स्कूलों में मध्यान्ह भोजन खुले में और अस्वच्छ स्थितियों में पकाया जा रहा है. कुल मिलाकर कहा जाए तो शिक्षा के निजीकरण की ओर सरकार के झुकाव को बजट में भी देखा जा सकता है.

स्वास्थ्य के लिए आबंटनों में राज्य भर में कुछ नये अस्पतालों, कुछेक सूपर स्पेशिलिटी अस्पतालों की स्थापना, स्वास्थ्य बीमा के लिए 250 करोड़, स्मार्ट कार्ड में 50 हजार तक का इलाज, वृद्धों को 80 हजार तक का मुफ्त इलाज मुख्य हैं. लेकिन अस्पतालों में डॉक्टरों, पैरा मेडिकल स्टाफ व अन्य स्टाफ के खाली पदों की भर्ती की कोई योजना बजट में नहीं है. ग्रामीण इलाकों में प्राइमरी केयर को सुदृढ़ करने की भी कोई खास योजना नहीं है.

हालांकि गांवों व शहरों के विकास के लिए बजट में कुछ आबंटन जरूर किए गए हैं लेकिन हर गांव और शहर के सुनियोजित विकास की योजनाएं बजट में नहीं झलकती हैं. मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए 570 करोड़, ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल प्रदाय के लिए 525 करोड़ जिसमें से 16 नगर पंचायतों के लिए 200 करोड़, स्वच्छ भारत के लिए 700 करोड़ जिसमें से शहरी क्षेत्र के लिए 300 करोड़, सबके लिए आवास मिशन के लिए 1900 करोड़ आबंटित किये गये हैं. हजारों गांव अभी भी विद्युत विहीन हैं और शुद्ध पेयजल की सुविधा से वंचित हैं. शहरों में सीवरेज व प्रदूषण मुख्य समस्याओं में से हैं. इनके लिए आबंटित राशि अपर्याप्त है. रायपुर सर्वाधिक प्रदूषित शहर है. झुग्गीवासियों व बस्तियों के विकास के बारे में बजट में कुछ भी नहीं है. इस पर बजट मौन है. नया रायपुर के लिए आकर्षक घोषणाएं व आबंटन किये गये हैं. कुछ योजनाओं की घोषणा तो हुई है लेकिन इन्हें शुरु करने व पूरा करने में वर्षों लग जायेंगे.

राजनेताओं, व्यापारियों, कहीं–कहीं लोगों की मांग पर बहुत सारे नगर पंचायतों का गठन तो किया गया है लेकिन उनकी माली हालत सुधारने का कोई प्रावधान बजट में नहीं है. अधिकांश नगर पंचायतों की आधी से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे है. उनका सालाना राजस्व 20 लाख से भी कम है.

राज्य में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के नाम पर अधोसंरचना पर जोर देने के अलावा भी उद्योगपतियों के लिए कई प्रावधान बजट में किये गये हैं. स्टार्टअप उद्यमियों को बिना ब्याज के कर्ज, औद्योगिक क्षेत्रों के उन्नयन एवं संधारण हेतु 50 करोड़, औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 120 करोड़ आबंटित किये गये हैं. मंदी से राहत देने के लिए स्टील उद्योगों को आयरन ओर, पिग आयरन, स्पंज आयरन, आयरन ओर पैलेट, इंगट, बिलेट तथा फेरो एलायज पर वैट सामान्य दर 5 से घटाकर 2, वायरनेल पर 14 से घटाकर 5, इलेक्ट्रो–फोर्ज्ड ग्रेटिंग पर केंद्रीय विक्रय कर की दर 2 से 1 प्रतिशत की गयी है. लेकिन राज्य के स्पंज आयरन व रोलिंग मिल मालिकों की बहुप्रतीक्षित मांग कि बैलाडीला से दस प्रतिशत आयरन की आपूर्ति की जाए, पर गौर नहीं किया गया है.

औद्योगिक माल के अलावा रोजमर्रा की चीजों के मामले में वैट की दरों को लेकर सरकार ने बजट में

छग सरकार द्वारा 4 नयी बटालियनों के गठन का विरोध करो! पुलिस भर्ती का बहिष्कार करो!

छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपने 2016–17 बजट में चार नयी इंडिया रिजर्व बटालियन बनाने का प्रावधान किया. केंद्र सरकार से पहले ही मंजूरी मिल गयी थी. क्रांतिकारी जनयुद्ध को खत्म करने व विस्थापन विरोधी संघर्षों के बढ़ते तेवर से निपटने के लक्ष्य से जारी पाशविक दमन अभियान ग्रीनहंट को और तेज करने के तहत सशस्त्र बलों की संख्या को बेहिसाब बढ़ाया जा रहा है. इसी सिलसिले में ये नयी बटालियनें खड़ी की जा रही हैं. बजट भाषण में रमण सिंह ने स्पष्ट किया कि संघर्ष इलाकों खासकर बस्तर संभाग से 3,000 युवाओं की भर्ती की जायेगी. भर्ती में उन्हें ही प्राथमिकता एवं महत्व दिया जायेगा. पहले एसपीओ बाद में सहायक आरक्षक की ही तरह अब प्रस्तावित नयी बटालियनों में भी स्थानीय युवाओं की भर्ती करके उन्हें यहीं तैनात करके, युद्ध के मोर्चे पर अग्रिम पंक्ति में रखकर यहां के आन्दोलन को कुचलने में उनका इस्तेमाल किया जायेगा. यानी अपनी ही उंगलियों से अपनी आंखें फोड़वाने की नीति को अमल में लाया जा रहा है. पूरे राज्य एवं खासकर संघर्ष इलाकों के युवाओं को इस साजिश से अवगत होना चाहिए और इन नयी बटालियनों के लिए होने वाली भर्ती प्रक्रिया से दूर रहे और उसका बहिष्कार करें. पुलिस, अर्ध सैनिक या सैनिक बलों में भर्ती का मतलब है, हमारे शोषकों व लुटेरों की सेवा के लिए तैयार होना. देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों द्वारा हमारी सार्वजनिक संपत्ति व संसाधनों की लूट को सुगम बनाना, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेना. अपने जल–जंगल–जमीन के लिए जान की बाजी लगाकर लड़ने वाले हमारे ही वर्गों की जनता का दमन करने तैयार होना. अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना.

दूसरी ओर राज्य में विभिन्न सरकारी विभागों मसलन शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत, सिंचाई, आदि में दसियों हजार रिक्त पद हैं. लेकिन सरकार इन पदों की भर्ती नहीं कर रही है. कभी–कभार कुछेक पदों की भर्ती करते भी हैं तो संविदा नियुक्ति, दैनिक वेतनभोगी या अन्य तरीके में कर रही है लेकिन स्थायी नियुक्तियां कब का बंद हो चुकी हैं. सिर्फ और सिर्फ सशस्त्र बलों में ही स्थायी नियुक्तियां लगातार जारी हैं. इतना ही नहीं हमेशा नये पदों का बेरोकटोक सृजन भी कर रही है. और तो और भगवाकरण के तहत उच्चतर माध्यमिक शालाओं व महाविद्यालयों में आउट सोर्सिंग के नाम पर बाहर के संघीय पृष्टभूमि वालों की भर्ती कर रही है. राज्य के शिक्षित–प्रशिक्षित बेरोजगारों की न केवल अनदेखी कर रही है बल्कि विभिन्न विभागों की नौकरियों में जाने के सारे रास्ते बंद करके उन्हें सिर्फ सशस्त्र बलों में भर्ती होने बाध्य कर रही है. बढ़ती बेरोजगारी, अभाव, गरीबी, पारिवारिक जिम्मेदारी, कृषि संकट आदि के चलते कई युवा बेरोजगार मजबूरी में सशस्त्र बलों में शामिल हो रहे हैं. लेकिन युवा बेरोजगारों को सशस्त्र बलों की नौकरियों में नहीं जाना चाहिए. इज्जत से जीने की नौकरियों के लिए, तमाम विभागों के रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया को तुरंत शुरु करने, भर्ती में स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता देने, सरकार जब तक नौकरियां उपलब्ध नहीं कराती है तब तक तमाम बेरोजगारों को न्यूनतम वेतन के बराबर की बेरोजगार भत्ता निशर्त प्रदान करने की मांग को लेकर आन्दोलन की राह पर आगे बढ़ना चाहिए.

तिकडम किया है. साइकिल तथा साइकिल पार्ट्स पर प्रचलित 5 प्रतिशत वैट समाप्त कर इसे करमुक्त किया गया है. मोबाइल फोन पर वैट की दर 14 से घटाकर 5 प्रतिशत, झाड़ू, पोंछा, ब्रश, वाइपर, इडली तथा डोसा के घोल एवं डेयरी उत्पादों–घी, पनीर, खोवा पर प्रचलित 14 एवं 5 प्रतिशत वैट को समाप्त किया गया है. ये सभी चीजें उनके भाव के मुताबिक नये वित्तीय वर्ष के साथ ही 1 अप्रैल से सस्ती हो गयी हैं. इससे 15 करोड़ की राजस्व क्षति अनुमानित है. इसकी भरपाई के लिए सरकार ने बाकी चीजों पर वैट की सामान्य दर 14 प्रतिशत में आधा प्रतिशत की वृद्धि की यानी 14.5 प्रतिशत. इससे लगभग 75 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व अनुमानित है. यानी पांच गुना अधिक. राज्य और केंद्रीय बजट के प्रावधानों के लागू होने के साथ ही महंगाई बढ़ गयी है. सस्ती हुई कुछेक वस्तुओं को छोड़ बाकी तमाम जन उपयोगी वस्तुएं, बैंक सेवाएं महंगी हो गयी हैं.

कुलमिलाकर कहा जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार के 2016–17 के बजट में गरीबों, किसानों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए कुछ खास नहीं है, उनकी अनदेखी की गयी है. यह देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों द्वारा संसाधनों की लूट के लिए रास्ता सुगम बनाने वाला बजट है. सरकार के लिए यह शर्म की बात है कि एक ओर राज्य के अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सूखे की मार झेल रहे हैं तो उन्हें राहत देने की बजाए राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रियों व विधायकों के वेतन–भत्तों में बेतहाशा वृद्धि की गयी है. जन विरोधी, कॉरपोरेटपरस्त, ब्राह्मणीय हिन्दू फासीवादी भाजपा सरकार के खिलाफ तमाम उत्पीड़ित वर्गों के लोगों को संगठित होकर अपने जायज अधिकारों के लिए जुझारु व व्यापक संघर्ष करना चाहिए. यही उनके सामने मौजूद एकमात्र विकल्प है.

❍

विस्थापन विरोधी संघर्ष सप्ताह का सफल आयोजन!

झूठे गणतंत्र दिवस व फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वां होल्लांद के दौरे का बहिष्कार!

दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के निर्णय के मुताबिक जल–जंगल–जमीन व संसाधनों पर जनता के अधिकार के लिए, केंद्र, राज्य सरकारों द्वारा देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों के साथ किये गये तमाम एमओयु को रद्द कराने 20 से 26 जनवरी, 2016 तक छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र राज्यों के संघर्ष इलाकों में विस्थापन विरोधी संघर्ष सप्ताह का सफल आयोजन किया गया था. इस दौरान 26 जनवरी को झूठे गणतंत्र दिवस का विरोध किया गया था. साथ ही गणतंत्र दिवस के आयोजन के मुख्य अतिथि बनाये गये फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वां होल्लांद के दौरे का बहिष्कार भी किया गया था. दण्डकारण्य में प्रस्तावित बड़े कारखानों, बड़े बांधों, बड़ी खनन परियोजनाओं से होनेवाले विस्थापन के खिलाफ जन संघर्ष, जन प्रतिरोध के साथ–साथ जनयुद्ध को तेज करने का आह्वान करते हुए पर्चा, पोस्टर, सभा, जुलूस के माध्यम से व्यापक प्रचार अभियान चलाया गया था. विस्थापन से आदिवासी अस्तित्व व अस्मिता को होने वाले नुकसान से जनता को अवगत कराया गया है.

सरकारें दरअसल अपनी जन विरोधी व कॉरपोरेट परस्त नीतियों को बेरोकटोक लागु करने के लिए एवं लोगों के ध्यान को जनता के ज्वलंत मुद्दों खासकर विस्थापन, किसानों की आत्महत्याओं से भटकाने के लिए विकास के नाम पर जनाकर्षक या लोकलुभावन योजनाओं को सामने ला रही हैं. उनकी असलियत कुछ और ही है. नौकरियों के सृजन व औद्योगीकरण के नाम पर जबरिया जमीन अधिग्रहण, रोजगार के नाम पर सशस्त्र बलों में भर्ती, बेटी बचाओ के नाम पर सशस्त्र बलों द्वारा सामूहिक बलात्कार, बेटी पढ़ाओ के नाम पर राज्य में तीन हजार शालाओं व देश भर में लाखों शालाओं को बंद करके दलितों, आदिवासियों व गरीबों को शिक्षा से वंचित करने की नीतियां बेरोकटोक जारी हैं. रोजगार के सपने के सच को दसियों लाख युवाओं के पलायन में देखा जा सकता है. बस्तर की युवा प्रतिभाओं को दरकिनार करके आउट सोर्सिंग के नाम पर बाहरी लोगों को नौकरी पर रखकर भगवाकरण का हथकंडा अपनाया जा रहा है. सरकारों की जन विरोधी नीतियों के चलते किसान आत्महत्याएं करने मजबूर हो रहे हैं. श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी बदलाव कर रही हैं. वास्तव में ये सरकारें जन विरोधी हैं.

26 जनवरी, 1950 को संविधान को लागू करते हुए देश को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है. भारतीय संविधान की पीठिका में भारत को संप्रभुतासंपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है. संप्रभुता के नाम पर अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण व अन्य साम्राज्यवादी देशों की लूट के लिए देश को चारागाह बनाना. समाजवादी शब्द तो जनता को भरमाने का कुटिल प्रयास है. अब तो मोदी सरकार संविधान से उक्त शब्द को ही हटाना चाहती है. धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अब देश को हिन्दू राष्ट्र बनाने की साजिश, घर वापसी के नाम पर जबरन धर्मांतरण, मुसलमानों, ईसाइयों, दलितों व आदिवासियों पर हमलें व असहिष्णुता भड़काना जारी है. लोकतंत्र के नाम पर लूटतंत्र व लाठीतंत्र एवं वंशवाद का बोलबाला है. देश राष्ट्रीयताओं का बंदीगृह बना हुआ है. यह आम जनों का गणतंत्र नहीं है. जनता की सही जनवादी राजसत्ता के लिए जारी जनयुद्ध में शामिल होना ही एकमात्र रास्ता है. सही आजादी, सही विकास के एक सही विकल्प के रूप में संघर्ष इलाकों में उभर रही क्रांतिकारी जनताना सरकारों को मजबूत करने व उनका विस्तार करने में हर एक को हर संभव मदद् करनी चाहिए.

दंडकारण्य की जनता खासकर आदिवासी जनता के विस्थापन विरोधी संघर्ष दरअसल राज्य और देश की भावी पीढ़ियों के भविष्य की लड़ाई है. उनके लिए देश की संपदाओं व संसाधनों तथा पर्यावरण को बचाये रखने की लड़ाई है. वह अनगिनत कुरबानियां देते हुए इस लड़ाई को जारी रखी हुई है. उनके विस्थापन विरोधी संघर्ष दरअसल उनके अस्तित्व, अस्मिता व आत्म सम्मान तथा अपने जल–जंगल–जमीन पर अधिकार को कायम रखने की लड़ाई है. वह विकास के एक नये नमूने को पेश कर रही है. एक सही विकल्प को सामने ला रही है. देश, दुनिया की पीड़ित जनता उस पर आशा की नजर लगायी हुई है. इसीलिए दण्डकारण्य की जनता के विस्थापन विरोधी संघर्षों के समर्थन में कदम बढ़ाना चाहिए. उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए. उन पर जारी पाशविक दमन के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी.

फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वां होल्लांद को इस बार के गणतंत्र दिवस के आयोजन के मुख्य अतिथि बनाया गया था. फ्रांस से 36 राफेल युद्ध विमानों की खरीदी से संबंधित 54 हजार करोड़ रुपए के समझौते को फायनल करने के उद्देश्य से होल्लांद का दौरा आयोजित किया गया था. पिछली बार के गणतंत्र दिवस के आयोजन के मुख्य अतिथि ओबामा थे और वह दौरा असल में परमाणु करार को फायनल करने के लिए तय किया गया था. देश की सुरक्षा के नाम पर रक्षा बजट को बेरोकटोक बढ़ाया जा रहा है. साम्राज्यवादियों के युद्ध उत्पादों के लिए देश को बहुत बड़ा एवं सुपर मुनाफे कमाने वाले बाजार में बदला जा रहा है. इन मामलों का भंडाफोड़ करते हुए पार्टी ने होल्लांद के भारत दौरे का बहिष्कार करने का आह्वान किया था. दण्डकारण्य की जनता ने इस आह्वान को सफल बनाया. ❍

रोहित वेमुला की आत्महत्या–
ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवाद द्वारा ली गयी बलि!
एचसीयू व जेएनयू के छात्रों पर दायर राजद्रोह सहित तमाम आपराधिक मामलों को वापस लेने की मांग करो!

केंद्र में भाजपा के सत्तारूढ़ होने के बाद से उसकी मातृ संस्था आरएसएस अपने ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी एजण्डे पर जोरदार ढंग से अमल कर रहा है. षड़यंत्रपूर्ण तरीके से देश में असहिष्णुता को फैलाया जा रहा है. हाल ही में हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोध छात्र रोहित बढ़ते हिन्दुत्व फासीवाद की भेंट चढ़ गये हैं. इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया. देश में और देश की सरहदों के बाहर भी रोहित की आत्महत्या के विरोध में छात्रों व अन्य तबकों के आन्दोलन उमड़ पड़े हैं. इसी सिलसिले में जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार सहित अन्य छात्रों की गिरफ्तारी को समझना होगा.

हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में साइंस, टेक्नोलॉजी एण्ड सोसाईटी स्टडीज शाखा में पीएचडी छात्र रोहित चक्रवर्ती वेमुला ने इस साल 17 जनवरी के शाम को छात्रावास के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या की. रोहित आन्ध्रप्रदेश के गुण्टूर जिले के एक गरीब दलित परिवार में पैदा हुए थे. वो पढ़ाई में शुरु से ही अव्वल थे. अपनी प्रतिभा के बलबूते वो सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ते गये. गरीबों को विशेषकर दलितों को पढ़ाई से वंचित करने वाली अर्ध–सामंती, अर्ध–औपनिवेशिक व्यवस्था जिसके केंद्र में सीढ़ीदार जाति प्रथा है, में यह कोई छोटी बात नहीं है.

रोहित क्लास रूम एवं किताबों तक सीमित नहीं रहे. वे अपनी सामाजिक चेतना को विकसित करते गए. कुछ साल उन्होंने एसएफआई में काम किया. बाद में आंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन(एएसए) के सक्रिय कार्यकर्ता बन गये.

मोदी के सत्ता में आने के बाद से संघ परिवार की ताकतें सभी क्षेत्रों के भगवाकरण के तहत शिक्षा क्षेत्र व शिक्षा संस्थानों के भगवाकरण पर भी विशेष जोर दे रही हैं. भाजपा से संबंध छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्–एबीवीपी को मजबूत करने के प्रयास तेज हो गये हैं. पुराने सड़े–गले विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाली एबीवीपी को किसी भी शिक्षा संस्थान में मजबूत होने के लिए उसे वहां मौजूद प्रगतिशील ताकतों के साथ दो–दो हाथ होना ही पड़ता है. हैदराबाद विश्वविद्यालय में एबीवीपी का कोई खास प्रभाव भी नहीं है. केंद्र में चूंकि भाजपा सत्ता में है इसी घमंड के साथ एबीवीपी गुण्डागर्दी करते हुए अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश में लगी है. इसीलिए स्वाभाविक रूप से विश्वविद्यालय के तमाम प्रगतिशील छात्र संगठनों के साथ एबीवीपी की शत्रुता है. शूद्रों, महिलाओं को शिक्षा से वंचित करने वाली मनु विचारधारा की विरासत लेकर चलने वाली एबीवीपी को दलितों, आदिवासियों व पिछड़ी जातियों के युवाओं द्वारा उच्च शिक्षा ग्रहण करना कतई पसंद नहीं है. इसीलिए वह आरक्षण को पसंद नहीं करती है. आरक्षण के जरिए महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने, पढ़ाई करने वालों को एबीवीपी वाले ऐसे देखते हैं, मानो वे उन्हीं की संपत्ति को चुरा रहे हों. एबीवीपी हमेशा आरक्षण वाले छात्रों को अपमानित करने, उनके आत्मसम्मान को धक्का पहुंचाने की कोशिश में लगी रहती हैं. इसी आरक्षण विरोधी चरित्र के चलते ही एबीवीपी भारतीय संविधान में आरक्षण के प्रावधान को जोड़ने वाले डॉ. आंबेडकर या उनकी विचारधारा के प्रभाव से गठित संगठनों के प्रति नफरत रखती है. इसी के चलते उसे आंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन–एएसए फूटी आंखों नहीं सुहाता है. एएसए के सक्रिय कार्यकर्ता और दलित होना रोहित के प्रति एबीवीपी गुण्डों द्वारा नफरत पालने के पर्याप्त कारण बन गये हैं. इतना ही नहीं, चूंकि ये ब्राह्मणीय हिन्दू धार्मिक कट्टरपंथी ताकतें यह मानती हैं कि प्रतिभा उच्च वर्णों की ही संपत्ति है, इसलिए दलित रोहित का अत्यंत प्रतिभाशाली होना भी वे पचा नहीं पाते हैं.

डॉ. आंबेडकर की विचारधारा से प्रभावित रोहित फांसी की सजाओं का विरोध करता था. 30 जुलाई को जब याकूब मेमन को फांसी दी गयी थी, अपना विरोध दर्ज करते हुए उन्होंने फेसबुक में लिखा, 'रक्त पिपासु राष्ट्रीयता ने एक और सिर कलम कर दिया है. माननीय राष्ट्रपति के खाते में एक और सिर जमा हो गया है. अपराधी साबित होने के बाद कैदियों को दी जाने वाली एक मात्र सजा यदि मौत

की सजा ही है तो हमारे राष्ट्र को हमें जनवादी कहना छोड़ देना चाहिए. हे भारत, तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं.'

इस बात पर कि फांसी एक बर्बर सजा है, अतः उसे रद्द करना चाहिए, दुनिया भर में चर्चा चल रही है. सौ से ज्यादा देशों ने फांसी की सजा को रद्द किया भी. हमारे देश में भी लंबे अरसे से यह मांग की जा रही है. हो सकता है कि यह सभी को मान्य न हो. लेकिन जनवादी देश कहलाने वाले भारत में ऐसी मांग करने का मौका अवश्य रहना चाहिए. रोहित ने जब इन जनवादी भावनाओं को व्यक्त किया, तब एबीवीपी जो स्वयं को देशभक्ति के ब्रांड एंबासडर मानती है, ने रोहित पर देशद्रोही का ठप्पा लगाया. जिन्हें वह पसंद नहीं करती है या जो उनका विरोध करते हैं, उन पर लगाने के लिए एबीवीपी के पास देशद्रोह का ठप्पा हमेशा मौजूद रहता है और वे यह समझते हैं कि उसका पेटेंट उन्हें हासिल है.

इसके दो दिन बाद दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज फिल्म सोसाइटी द्वारा प्रस्तावित 'मुजफर नगर बाकी है' वृत्त चित्र के प्रदर्शन को एबीवीपी ने जोर जबर्दस्ती करके रोक दिया था. यह दरअसल साठ लोगों की मौत, हजारों के विस्थापन का सबब बनने वाले मुजफ्फर नगर के हिन्दू धर्मोन्मादी दंगों से संबंधित वृत्तचित्र है. इसीलिए हिन्दू धर्मोन्मादी गिरोह ने उसके प्रदर्शन को रोका था. इसकी निंदा करते हुए देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे. हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी एएसए के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ था. इसके प्रतिक्रिया स्वरूप विश्वविद्यालय में एबीवीपी के अध्यक्ष सुशील कुमार ने फेसबुक में अपमानजनक व्याख्या लिखी, 'बलवा के बारे में एएसए गुण्डों का उत्तेजनापूर्वक बात करना हास्यास्पद है'. इस व्याख्या के खिलाफ आपत्ति जताते हुए सुशील कुमार को छात्रावास परिसर में रोककर माफी मांगने कहा गया था. हॉस्टल के चीफ वार्डन व चीफ सेक्युरिटी ऑफीसर को पहले ही सूचित किया गया था कि सुशील कुमार से सवाल किया जाएगा. रात में छात्रावास परिसर की सुरक्षा जिम्मेदारी देखने वाले इनचार्ज सेक्युरिटी चीफ के समक्ष ही सुशील कुमार से सवाल किया गया था. सुशील ने न सिर्फ मौखिक रूप से माफी मांगी बल्कि लिखित में भी दिया था. उस पर सेक्युरिटी अधिकारी ने गवाह के रूप में दस्तखत की थी. इस कदर जनवादी तरीके से निपटे मामले को बाद में षड्यंत्रपूर्ण तरीके से तोड़–मरोड़कर पेश किया गया. सुशील कुमार ने उसी रात को एक निजी अस्पताल में भर्ती होकर, यह गलत आरोप लगाते हुए कि उन पर हमला किया गया है, पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी. उक्त शिकायत के समर्थन में हैदराबाद के एक भाजपा नेता ने केंद्रीय मंत्री बंडारु दत्तात्रेय को पत्र लिखकर कहा कि चूंकि एएसए ने याकुब मेमन की फांसी के विरोध में व्याख्या की है, इसलिए वह देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त संस्था है. उक्त गलत शिकायत व पत्र पर आधारित होकर केंद्रीय मंत्री दत्तात्रेय व स्मृति ईरानी द्वारा किये गये हस्तक्षेप से रोहित सहित पांच छात्रों को कुलपति ने निलंबित किया था. यहां निलंबन का मतलब है, ये छात्र कक्षाओं में हाजिर हो सकते हैं, लेकिन छात्रावास में नहीं रह सकते हैं. मेस में खाना नहीं खा सकते हैं. पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकते हैं. छात्रों के साथ बात नहीं कर सकते हैं. विश्वविद्यालय परिसर में सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक ही रह सकते हैं. ये शर्तें मजबूत सामंती व्यवस्था वाले इलाकों में दलितों के प्रति अपनाये जाने वाली अस्पृश्यता जैसी ही हैं. इस अपमान से बुरी तरह आहत इन तमाम छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में ही बहिष्कृत या अछूत बस्ती के नाम पर एक टेंट डालकर करीबन दो सप्ताह तक धरना दिया था. आज के जमाने के विश्वविद्यालयों में अछूत बस्तियों का बनना सभ्य समाज के लिए शर्मनाक दुस्थिति है. निलंबन के सात माह पूर्व से ही रोहित के फेलोशिप को रोक दिया गया था. इससे वो आर्थिक तंगी का शिकार हो गये थे. आत्महत्या के पहले लिखे पत्र के मुताबिक वो कर्जदार बन गये थे. उन्होंने अपने सूसाइड नोट में लिखा था– 'कुछ लोगों के लिए जिंदगी सदा एक श्राप है. मेरी पैदाइश ही मेरे लिए एक जानलेवा खतरा है'. ये वाक्य दरअसल एक दलित के रूप में रोहित की व्यथा, वो जिस विवक्षा से गुजरता आ रहा है, से हमें अवगत कराते हैं. बचपन ही से जाति के कारण जो अपमान उन्होंने सहा, वह विश्वविद्यालय स्तर पर भी जारी रहने के चलते रोहित विचलित व दुखी हो गये थे और उन्होंने आत्महत्या की. कार्ल सागन जैसे विज्ञान के लेखक बनने के उनके सपने को साकार करने के मौके को इस असमान समाज ने खारिज कर दिया था. इस तरह सबसे निचली सीढ़ी से उदित सामाजिक चेतना से लैस एक मेधावी को इस देश ने खोया. हालांकि रोहित की मौत आत्महत्या के रूप में व्यक्त हुई लेकिन यह जाति, धर्म, वर्ग विषमताओं से सड़ी–गली व्यवस्था खासकर ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवाद द्वारा ली गयी बलि ही है. उन सवालों जिन्हें रोहित की मौत ने साधा है, से लोगों का ध्यान भटकाने, उनके फेलोशिप पर लगाई रोक का समर्थन करने के लिए यह कुतर्क सामने लाया जा रहा है कि रोहित दलित नहीं है. इस कुतर्क के साथ मृतक रोहित को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है कि उन्होंने इतने सालों से गलत जाति प्रमाण पत्र द्वारा फेलोशिप पा रहे थे. रोहित की मां अनुसूचित माला जाति की है जबकि बाप वड्डेरा जाति के हैं. अंतर्जातीय विवाहों के मामले में कानून ने यह सहूलियत दी है कि बच्चे मां या पिता जिस किसी की भी जाति को अपना सकते हैं. कानून की बात छोड़ भी दें तो क्या यह तर्क देना कि रोहित को जन्म देने वाली मां की जाति के बजाय पिता जिसने कब का बच्चों को उनके हाल पर छोड़कर चले गये हैं, की जाति से ही बच्चे पहचाने जाएंगे,

सही है? यह कहां तक उचित है? अपने अपराध पर परदा डालने के लिए ही इस तरह की रूढ़िवादी व पितृसत्ता के कवच का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं.

इस विश्वविद्यालय में यह पहली आत्महत्या नहीं है. अब तक बारह छात्रों ने आत्महत्या की. इनमें से दस दलित ही थे. इतने दलित छात्रों की आत्महत्याओं के परिप्रेक्ष्य में ही सही विश्वविद्यालय के पालक मंडल में एक भी दलित प्रोफेसर की नियुक्ति न करना वहां जड़ जमाये जातीय भेदभाव व जातिवाद का ही परिचायक है.

यह कहा जाता है कि देश का भविष्य कक्षा की चार दीवारों में ही निर्मित होता है. ऐसे में शाला हो या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय, शिक्षा संस्थान कैसे होने चाहिए? वैज्ञानिक सोच के स्रोत के रूप में होने चाहिए. समाज के आगे बढ़ने में मदद देने वाले मूल्यों को स्थापित करने वाले केंद्रों के रूप में होने चाहिए. भिन्न–भिन्न विचारों के संघर्ष के मंच के रूप में होने चाहिए. संघर्ष के बिना वैज्ञानिक सोच–विचार उत्पन्न नहीं होते हैं. इस तरह के संघर्ष के लिए पहले शर्त है, जनवादी माहौल का होना.

लेकिन शोषक–शासक वर्ग या उनका प्रतिनिधित्व करने वाली सरकारें शैक्षिक संस्थानों में किस तरह के माहौल चाहते हैं? वे शैक्षिक संस्थाओं को ऐसे मंचों के रूप में ही रखना चाहते हैं जो अवैज्ञानिकता, अज्ञान, भेदभाव, धर्मोन्माद, जातिवाद, पितृसत्ता, केरियरवाद को बढ़ावा देते हों. वहां सामूहिकता न हो. व्यक्ति केंद्रित हो. व्यक्तियों का एकमात्र, प्रधान व अंतिम लक्ष्य हो, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना. पार्टियां जो भी हों, शासकों का लक्ष्य यही है. अपने शोषणमूलक शासन व्यवस्था को हमेशा जारी रखने के लिए जरूरी है कि शैक्षिक संस्थाओं का माहौल वैसा ही रहे. शैक्षिक संस्थाओं को उस दिशा में ले जाने वे हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं. लेकिन उसमें पूरी तरह सफल होने में रोड़ा अटका रहा है, हमारे समाज में लंबे अरसे से जारी वर्ग संघर्ष. उस वर्ग संघर्ष की स्फूर्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली शक्तियां तमाम शैक्षिक संस्थानों में मौजूद हैं और अपनी शक्ति अनुसार शासकों के प्रयासों का मुकाबला कर रही हैं. वहीं ये शक्तियां शासकों का निशाना बन रही हैं.

शोषक–शासक वर्गों द्वारा शैक्षिक संस्थानों को अपने शोषणमूलक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की बुनियाद को मजबूत रखने के अनुरूप प्रतिक्रियावादी अवस्था में रखने हमेशा प्रयासरत रहते हैं. संघ परिवार के सक्रिय कार्यकर्ता रहे मोदी के सत्तासीन होने के बाद से यह स्थिति और बिगड़ रही है. चूंकि आरएसएस के प्रतिक्रियावादी, प्रतिगामी व प्रतिक्रांतिकारी एजेण्डे के अमल में वैज्ञानिक, जनवादी व प्रगतिशील सोच बहुत बड़ी रोड़ा है, इसलिए शैक्षिक संस्थानों में मौजूद ऐसी ताकतों के सफाये में लगे हैं. इसी के तहत तमाम शैक्षिक संस्थानों के महत्वपूर्ण पदों पर संघ परिवार के लोगों को बैठाया जा रहा है. पाठ्यांशों में बदलाव हों, संस्कृत को शामिल करने की कोशिश हो, अपना रास्ता सुगम बनाने के लिए ही है. एक शब्द में कहा जाए तो ये शैक्षिक संस्थानों को पुराने गुरुकुलों में पुनर्स्थापित करना चाहते हैं जिनमें सिर्फ राजकुमारों व ब्राह्मणपुत्रों को ही प्रवेश मिलता है न कि एकलव्य को.

रोहित एवं अन्य छात्रों का निलंबन हो या जेएनयु के कन्हैया कुमार, अनिर्बान, उमर खालिद आदि छात्रों की गिरफ्तारी हो या इन सबसे पहले चेन्नाई आईआईटी में डॉ. आंबेडकर व पेरियार स्टडी सक्रिलों पर स्मृति ईरानी द्वारा प्रतिबंध लगाने का मामला हो अपने ब्राह्मणीय हिन्दुत्व एजेण्डे को आगे बढ़ाने के उद्देश्य का ही हिस्सा है. याकुब मेमन की फांसी का विरोध करने वाले रोहित 'देशद्रोही' बन गया था. वैसे ही अफजल गुरु की फांसी का विरोध करने के चलते कन्हैया कुमार एवं अन्य 'देशद्रोही बन गये हैं. जिन्हें वे सजा दिलाना चाहते हैं, उन पर देशद्रोही का ठप्पा लगा रहे हैं. दरअसल देशभक्त कौन? देशद्रोही कौन? देश की संप्रभुता, सार्वजनिक संपत्ति व संसाधनों को देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों के हवाले करने वाले, लाखों लोगों को अपने जल–जंगल–जमीन व घरों से बेदखल करने वाले, सांप्रदायिक दंगे भड़काने वाले, धार्मिक अल्पसंख्यकों के सामूहिक नरसंहार करने वाले, पुलिस, अर्ध सैनिक व सैन्य बल उतारकर देश की जनता पर युद्ध थोपने वाले, अधिक मुनाफे के लिए पर्यावरण का विध्वंस करने वाले शोषक–शासक वर्ग ही देशद्रोही हैं. लेकिन वे ही स्वयं को देशभक्त ठहरा रहे हैं और उनके जनविरोधी नीतियों का विरोध करने वाले, इनके खिलाफ आवाज उठाने वाले एवं इनसे सवाल करने वाले जनवाद प्रेमियों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, प्रगतिशील ताकतों को देशद्रोही करार दे रहे हैं. इतना ही नहीं, गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं.

यहां गौर करने वाली बात यह है कि जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया था कि 9 फरवरी को विश्वविद्यालय परिसर में अफजल गुरु की फांसी की बरसी पर आयोजित एक कार्यक्रम में देश विरोधी नारे लगाये गये थे. इसी सिलसिले में अनिर्बान और उमर खालिद को भी गिरफ्तार किया गया था. हालांकि कन्हैया कुमार को आंतरिम जमानत मिल चुकी है. दरअसल 9 फरवरी के शाम को बाकायदा विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारियों से पूर्वानूमति लेकर 'द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफीस' शीर्षक से सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया था. विश्वविद्यालय परिसर में लगाए गए इस कार्यक्रम से संबंधित पोस्टरों में स्पष्ट लिखा गया था कि उक्त कार्यक्रम ब्राह्मणीय सामूहिक अंतरात्मा के खिलाफ, मकबूल भट्ट व अफजल गुरु की कानूनी हत्या के खिलाफ, कश्मीरी जनता की जनवादी मांग–स्वयं निर्णय के अधिकार के लिए जारी संघर्ष के समर्थन में आयोजित किया जा रहा है. उक्त आयोजन में एबीवीपी के छात्रों

सहित कुछ बाहरी हिन्दुत्ववादी ताकतें भी घुस आयी थीं और उन्होंने 'भारत माता की जय', 'बजरंग दल जिंदाबाद' आदि नारे भी लगाए और कुछ हिंसक नारे भी लगाए जैसे 'दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे'. इतना ही नहीं उन्होंने आयोजकों व उपस्थित छात्रों के साथ झूमा–झटकी की. दोनों ओर से नारेबाजी, मार–पीट भी हुई. यहां यह जानकर हैरत होगी कि इस मामले में जांच के लिए गठित विश्वविद्यालय की एक उच्च स्तरीय कमेटी ने यह खुलासा किया कि 9 फरवरी के आयोजन में 'भारत को रगडा दो, रगडा दो', 'पाकिस्तान जिंदाबाद', 'भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी' – आदि देश विरोधी नारे छात्रों ने नहीं लगाये थे. चेहरे पर कपड़ा ढके कुछ बाहरी लोगों ने यानी एबीवीपी के गुण्डों ने ही मास्क पहनकर साजिश के तहत ऐसे नारे दिये. मीडिया ने यह भी खुलासा किया कि कन्हैया के भाषण में देश विरोधी बातें नहीं हैं. दिल्ली सरकार की जांच टीम ने भी यह स्पष्ट किया कि आयोजन में आयोजकों ने देश विरोधी नारे नहीं लगाये थे. यह बात भी सामने आयी कि देश विरोधी नारे लगाते हुए जिन छात्रों की वीडियो फुटेज अंतरजाल में पोस्ट किया गया है, वह वास्तविक नहीं है और ओरिजिनल के साथ छेड़छाड़ की गयी है. इतना सब कुछ स्पष्ट होने के बावजूद छात्रों पर केस यथावत चलाया जा रहा है. यहां हमें सरकार की खिलाफत और देश की खिलाफत के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है. अफजल गुरु की फांसी का विरोध हो, याकुब मेमन की फांसी का विरोध हो, वह सरकार, न्यायपालिका या दोनों के विरोध या उनकी आलोचना के रूप में देखना होगा. सरकार या न्यायपालिका का विरोध देश का विरोध नहीं होता है. सरकार के खिलाफ कही गयी बातों को देश विरोधी बातों के रूप में और देशद्रोह के रूप में चित्रित करना, इन्हीं आरोपों में कोर्ट में मामला दायर करना, जेल में डालना जनता को भटकाने व सवाल करने वाली आवाज को दबाने के लिए की गयी साजिश के अलावा कुछ नहीं है. कश्मीर की जनता के स्वयं निर्णय के अधिकार का समर्थन भी एक जनवादी अधिकार है जोकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है. यह संविधान द्वारा प्रदत्त मूलभूत अधिकार है. जनता के हित में सरकार से सवाल करने वाले देशद्रोही नहीं होते हैं. वे ही असली देशभक्त हैं. यहां बात राहुल गांधी की नहीं की जा रही है जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मोदी पर गरज रहे हैं. देश की उत्पीड़ित जनता के हितों की रक्षा के लक्ष्य से सरकार का विरोध करने वालों के बारे में बात की जा रही है. देशभक्ति का मतलब क्या है? पांच साल में एकबार वोट डालना ही देशभक्ति नहीं है. सरकारों से सवाल न करना चाहे सरकारी नीतियां पसंद आए या न आए, यही देशभक्ति नहीं है. देश का मतलब नक्शा नहीं है. देश का मतलब सिर्फ जमीन और सरहदें नहीं हैं. देश का मतलब है, देश की जनता. देश की अत्यधिक पीड़ित आबादी. असली देशभक्त देश की जनता से प्यार करता है. उनकी भलाई के लिए सोचता है, देश की जनता को नुकसान पहुंचाने वाले हर कदम का विरोध करता है. चाहे वह सरकार ही क्यों न हो? जनता पर जारी दमन व शोषण का विरोध करता है. सच्चाई को पहचानते हुए अत्यधिक आबादी के हितों के अनुरूप व्यवस्था को बदलने की कोशिश करता है. बदलाव के कार्याचरण में उतरता है. कम–से–कम उस कार्याचरण का समर्थन करता है. चाहे वह कार्याचरण हथियारबंद ही क्यों न हो. शोषक–शासक वर्गों व उसका प्रतिनिधित्व करने वाली सरकारों का समर्थन करना ही देशद्रोह है.

यहां राजद्रोह पर भी चर्चा करना जरूरी है. यह अंग्रजी साम्राज्यवादियों द्वारा उनके उपनिवेशवादी हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया कानून है. इस 'आजाद' भारत में पिछले करीबन 70 सालों से सरकार का विरोध करने वालों पर बेरोकटोक अमल किया जा रहा है. सरकार के खिलाफ आवाज उठाना, सरकार से सवाल करना भी राजद्रोह माना जा रहा है. अभिव्यक्ति की आजादी का हनन करके उसे राजद्रोह के दायरे में लाया गया है. राजद्रोह के कानून को ही समाप्त करने की जरूरत है. जब राज करने वाले ही जनहित के खिलाफ काम कर रहे हों और वे ही जन विरोधी व देश विरोधी ताकत बन गये हों तब राजद्रोह ही सच्ची देशभक्ति होती है.

मोदी की ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी सरकार संघ परिवार के संगठनों को खुली छूट देकर अपने एजेण्डे पर अमल को तेज कर रहा है. उसके खिलाफ में उठ खड़े होने वालों को लक्ष्य बनाकर वह तेजी से कदम बढ़ा रहा है. चाहे क्रांतिकारी आन्दोलन पर लगातार बढ़ता दमन हो, नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, एमएम कलबुर्गी, अखलाक आदि की जघन्य हत्या हो, रोहित को मौत के मुंह में धकेलना हो, रोहित, कन्हैया आदि पर देशद्रोह का ठप्पा लगाना हो, उसी का हिस्सा है. यहां यह याद दिलाना लाजिमी होगा कि कन्हैया पर दिल्ली के पाटियाला हाउस कोर्ट में भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच ही संघ परिवार के कुछ वकीलों व गुण्डों ने जानलेवा हमला किया था. इतना ही नहीं वहां मौजूद पत्रकारों पर भी उन्होंने हमला किया और कैमरे छीन लिए और तोड़फोड़ किये. यह हिन्दुत्व फासीवाद की खुली व बाजारु अभिव्यक्ति है. सड़क हो या चौराहे, निजी हो या सार्वजनिक स्थान कहीं भी ये ताकतें विरोध करने वालों पर जानलेवा हमले करती हैं. हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के छुट्टी से लौटकर पदभार ग्रहण करने पर उनकी बर्खास्तगी की मांग करने वाले छात्रों पर पुलिस ने न केवल डंडे बरसाये बल्कि 25 छात्र सहित 2 शिक्षकों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया था. हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गयी लेकिन केस तो वापस नहीं लिया गया. इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं की प्रताड़ना के मामले भी सामने आ रहे हैं.

इसे रोकना होगा. वरना इस देश के असंख्य पीड़ित लोगों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, धार्मिक अल्पसंख्यकों, धर्म निरपेक्ष व जनवादी ताकतों का अस्तित्व ही बहुत बड़े खतरे में पड़ जायेगा.

यहां गौरतलब बात एक और है. रोहित एवं अन्य छात्र करीबन दो सप्ताह तक 'बहिष्कृत बस्ती' में रहे. धूप, ठंड में तकलीफों को झेलते हुए. बाहरी समाज से आशानुरूप प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं हुई, समर्थन हासिल नहीं हुआ. रोहित की हताशा का एक कारण यह भी था. प्रगतिशील ताकतों, संगठनों व नागरिक समाज को गहराई से आत्मावलोकन करना चाहिए.

रोहित की मौत के बाद, कन्हैया और अन्य छात्रों की अरेस्ट के बाद देश भर में व्यापक आन्दोलन हो रहे हैं. रोहित की आत्महत्या के विरोध में एवं विश्वविद्यालयों में जातीय भेदभाव के खिलाफ 25 जनवरी को देश भर में 242 जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए थे. रोहित की मौत के विरोध में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों ने दिल्ली के जंतर–मंतर में धरना प्रदर्शन किया जिसमें कई विपक्षी नेताओं सहित जानी–मानी लेखिका अरुंधति राय भी छात्रों का साथ दे रही थी. हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के 25 छात्रों व दो प्रोफेसरों की रिहाई एवं कुलपति अप्पाराव की बर्खास्तगी की मांग को लेकर 28 मार्च को देश भर के विश्वविद्यालयों में बंद का सफल आयोजन किया गया था. इन आन्दोलनों के सामने झुककर रोहित के साथ निलंबित छात्रों का निलंबन वापस ले लिया गया है.

रोहित की आत्महत्या और कन्हैया एवं अन्य पर राजद्रोह के मामले के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों के संदर्भ में देश की शिक्षा एवं छात्र जगत के सामने मौजूद चुनौतियों के बारे में चर्चा करना लाजिमी होगा. सरकार शिक्षा के निजीकरण पर आमादा है. विदेशी विश्वविद्यालय बिल वास्तव में देश की शिक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्यित है. इसी के तहत भारतीय विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–युजीसी द्वारा दिये जाने वाले अनुदान में भारी कटौती की जा रही है. इसका सीधा असर आदिवासी व दलित छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाओं की कटौती के रूप में दिख रहा है. तकनीकी, इंजिनीयरिंग, चिकित्सा, मैनेजमेंट आदि उच्च शिक्षा संस्थानों में हाल ही में ट्यूशन फीज में की गयी बढ़ोत्तरी व छात्रवृत्ति में की गयी कटौती दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को उच्च शिक्षा से वंचित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी. साथ ही आदिवासियों व दलित छात्र–छात्राओं को दी जाने वाली सुविधाओं जैसे फीज में छूट, छात्रवृत्ति, प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं के छात्र–छात्राओं को दिये जाने वाले मुफ्त गणवेश और पाठ्य पुस्तक आदि में भारी कटौती से उत्पीड़ित वर्गों के बच्चें प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा से भी वंचित हो जाएंगे. युक्ति युक्तकरण (रेशनलाइजेशन) के नाम पर देश के एक लाख से भी अधिक शालाओं को बंद किया गया है. छत्तीसगढ़ में ही तीन हजार शाला व आश्रमों को बंद किया गया है. इसका सबसे बुरा असर तो दलितों व आदिवासियों की शिक्षा पर ही पड़ेगा. यह राज्यसत्ता के जन कल्याणकारी योजनाओं या कहे जिम्मेदारियों से हाथ खींचने की योजनाबद्ध साजिश है. विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्मनाक शर्तों के तहत व्यवस्थापन खर्च को कम करने का सुनियोजित तरीका है. शाला व महाविद्यालयों को बड़े पैमाने पर बंद करके शिक्षकों के दसियों हजार पदस्थापनाओं को खत्म करने का जन विरोधी व देश विरोधी कदम है. कुलमिलाकर देखा जाए तो आज देश की शिक्षा क्षेत्र, छात्र व शिक्षक जगत के सामने शिक्षा का देशी, विदेशी कॉरपोरेटीकरण, शिक्षा एवं शैक्षिक संस्थानों का भगवाकरण, आदिवासियों, दलितों व अन्य पिछड़ा वर्गों को शिक्षा से वंचित करना, भयंकर जातीय भेदभाव वाले ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवाद मुख्य चुनौतियों के रूप में मौजूद हैं. इसीलिए ये आज छात्र आन्दोलन की भी चुनौतियां हैं. रोहित की आत्महत्या एवं बाद के परिणामों ने इन चुनौतियों का सामना करते हुए साम्राज्यवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी, वैज्ञानिक नवजनवादी शिक्षा प्रणाली के लिए व्यापक, जुझारु व संगठित छात्र व शिक्षक आन्दोलन का निर्माण करने की आवश्यकता को सामने लाया है. दलित, आदिवासी, जनवादी, प्रगतिशील, आम्बेडकरवादी व वामपंथी छात्र–छात्राओं एवं शिक्षकों को इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए. यह आज के वक्त की मांग है.

देश में बढ़ती असहिष्णुता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जारी अघोषित प्रतिबंध का विरोध करते हुए हाल ही में साहित्यि, संस्कृति, सिनेमा, कला, पत्रकारिता, खेल, विज्ञान, लेखन आदि क्षेत्रों से संबंधित सैकड़ों प्रमुखों ने अपने पुरस्कारों, तमगों, उपाधियों को वापस किया है. हाल ही में रोहित की मौत के विरोध में प्रमुख प्रगतिशील लेखक अशोक बाजपेयी ने अपने डॉक्टरेट उपाधि को वापस किया. देश के इतिहास में ख्याति प्राप्त बुद्धिजीवियों की ओर से इस तरह की प्रतिक्रिया आना अभूतपूर्व है और प्रशंसनीय है, स्वागतेय है. लेकिन यही काफी नहीं है. प्रगतिशील, जनवादी ताकतों से इतिहास और ज्यादा सक्रिय मदद खासकर कार्याचरण की मांग कर रहा है. अलग–अलग घटनाओं के वक्त अलग–अलग रूप से आगे आने वाले या उभरने वाले तमाम आन्दोलनों, अलग–अलग व्यक्तियों की प्रतिक्रियाओं, पीड़ित तबकों की व्यथाओं को मिलकर एक व्यापक, धर्मनिरपेक्ष, जुझारु व संगठित आन्दोलन को विकसित करने की ऐतिहासिक आवश्यकता के मुंहाने आज हम खड़े हैं. इस आवश्यकता को पहचानना, इसे कर्तव्य के रूप में स्वीकार करना हमारी ऐतिहासिक जिम्मेदारी है. आएं! उसे निभाने आगे कदम बढ़ाएं. ❍

कॉमरेड साईबाबा की अवैध हिरासत की कड़ी निंदा करो!

गड़चिरोली पुलिस द्वारा मई 9, 2015 को दिल्ली से अपहरण करके गिरफ्तार किये गये रिवल्यूशनरी डेमोक्रटिक फ्रंट (आरडीएफ) के सह सचिव कॉमरेड जी एन साईबाबा की हिरासत जारी है. कॉमरेड साईबाबा दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद महाविद्यालय में अंग्रेजी पढ़ानेवाले प्रोफेसर हैं. छात्र अवस्था में ही वे रैडिकल आंदोलन से प्रभावित हो गए थे. वे इस विश्वास के साथ कि लूट व शोषण विहीन समाज के निर्माण के लिए क्रांति बिना दूसरा रास्ता नहीं है, कई संगठनों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को स्वीकार कर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. 2005 में उन्होंने कुछ साथियों के साथ मिलकर आरडीएफ का निर्माण किया और उसके अखिल भारतीय सह सचिव की जिम्मेदारी संभाली. उन दिनों में ही तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने ऐलान किया था कि वामपंथी उग्रवाद ही देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है. उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन के खात्मे के लिए जनता खासकार आदिवासियों पर भीषण दमन का सिलसिला प्रारंभ हुआ था. पहले सलवा जुडुम फिर ग्रीनहंट, नाम कुछ भी हो, इन अभियानों का मतलब है, युद्ध. जनता पर थोपा गया युद्ध. देश के संसाधनों को साम्राज्यवादियों व देश के दलाल पूंजीपतियों के हवाले करना ही इस युद्ध का मकसद है.

जनता पर जारी इस नाजायज युद्ध के खिलाफ देश व विदेशों की अनगिनत क्रांतिकारी जनता, जनवादियों, बुद्धिजीवियों, लेखकों, क्रांतिकारी व जनवादी पार्टियों व संगठनों ने न सिर्फ आवाज उठाई बल्कि भारत की क्रांति के प्रति अपना भाईचारा प्रकट किया और कई तरह की मदद भी दी. इस तरह भारत की क्रांति के लिए देश व विदेशों से मदद जुटाने में कॉमरेड साईबाबा की महत्वपूर्ण भूमिका है. इस कोशिश में उन्हेंने देश भर का दौरा किया था. विदेश भी गये थे. अंतर्राष्ट्रीय मंचों से आवज उठाई. जन युद्ध के समर्थन में व साम्राज्यवाद के खिलाफ उन्होंने कई रचनाएं की.

चौंकाने वाली बात यह है कि इतने सक्रिय क्रियाकलाप वाले कॉमरेड साईबाबा 90 फीसदी विकलांग हैं. बचपन में ही पोलियो के संक्रमण से उनकी कमर के नीचे का भाग पूरा अचेतन हो गया. व्हील चाइर के बिना वे एक कदम भी नहीं हिल सकते. बिना दूसरों की मदद के वे अपनी दैनंदिन जरूरतें भी नहीं निपटा सकते. शारीरक निर्बलता के बावजूद उत्पीड़ित जनता के दर्द बांटने के लिए उन्होंने अपने हृदय, मेधा, आवाज व कलम को शोषित जनता के लिए समर्पित किया. यही उनका 'घोर अपराध' बन गया है.

जनता पर थोपे गये युद्ध को जल्द से जल्द खतम करके पूरे देश को लूटने की कोशिशों में लगे शोषक–शासक वर्गों के लिए यह तो बिल्कुल असहनीय होगा ही कि उनके दमन के विरोध में कोई आवाज उठाएं, उनसे कोई सवाल करें. उन विरोधी स्वरों को निर्दयतापूर्वक दबाने की कोशिश करते हैं. इसीलिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान यह दलील दी कि वे बुद्धिजीवी जो प्राकृतिक संसाधनों व श्रम को लूटनेवाली साम्राज्यवादी नीतियों का प्रतिरोध करते हैं, भूमिगत माओवादियों से भी ज्यादा खतरनाक हैं. ऐसे बुद्धिजीवियों और अपनी बुद्धि को व्यवहार के साथ जोड़ने वाले जन आंदोलनकारियों का सरकार दुश्मन मानती है. कॉमरेड गंटी प्रसादम जैसे क्रांतिकारियों की उसने हत्या की. कईयों को जेलों में डाल रही है. प्रोफेसर साईबाबा पर जारी दमन भी उसी का हिस्सा है.

जुलाई 2014 में गड़चिरोली पुलिस द्वारा दिल्ली के हेम मिश्रा नाम के एक छात्र की गिरफ्तारी हुई थी. उनके कथन का हवाला देकर पुलिस ने प्रशांत राही नामक एक मीड़िया कर्मी को गिरफ्तार किया था. साईबाबा के घर पर पुलिस ने दो बार हमलें किये थे. उसके बाद यूनिवर्सिटी कैंपस से उन्हें उठा ले जाकर गिरफ्तारी दिखायी. गिरफ्तारी के वक्त तमाम न्यायिक प्रक्रिया का नजरअंदाज ही नहीं बल्कि घोर उल्लंघन किया गया. चूंकि वे एक प्रोफेसर हैं इसलिए यूनिवर्सिटी की अनुमति लेना, अरेस्ट वारंट दिखाना, परिवार के लोगों को खबर देना, अंतर्राष्ट्रीय न्याय सूत्रों के मुताबिक विकलांगों के लिए मौजूदा नियमों का पालन करना, इन सबका नजरअंदाज किया गया.

उन पर यह आरोप लगाकर गैर कानूनी गतिविधि निरोधक कानून (यूएपीए) के तहत केस दायर किया गया कि वे माओवादी विचारधारा के हैं और माओवादी पार्टी के साथ उनका सांगठनिक संबंध भी है. उन्हें नागपूर जेल के अंडा सेल जिसमें हवा व उजाला नसीब नहीं होती है और काफी जगह भी नहीं होती है, में अकेले डाल दिया गया. दूसरों की मदद के बिना जिन्हें दैनंदिन जरूरतों से निपटना भी असंभव है, उन्हें अकेले कैद करना कितना अमानुषिक है? यहां भी और एक बार अंतर्राष्ट्रीय न्याय सूत्रों की

राजनीतिक बंदियों के समर्थन में संघर्ष व भाईचारा सप्ताह मना!

'साम्राज्यवाद मुर्दाबाद', 'इंकलाब जिंदाबाद' नारों के साथ फांसी के फंदे पर झूल गये भारत के महान देशभक्त व क्रांतिकारी, शहीद–ए–आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के 85 वें शहादत दिवस के मौके पर दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के आह्वान को सफल बनाते हुए 23 से 29 मार्च तक समूचे दण्डकारण्य में राजनीतिक बंदियों के अधिकारों के समर्थन में संघर्ष एवं भाईचारा सप्ताह मनाया गया था.

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर केंद्रीय कारागार में 2007 के मध्य से विचाराधीन बंदियों के रूप में बंद कॉमरेड्स निर्मला एवं पद्मा की तुरंत रिहाई की मांग को लेकर एक अभियान चलाने पार्टी की ओर से देश, दुनिया के मानवाधिकार संगठनों, जनवादी–प्रगतिशील ताकतों का आह्वान किया गया था. इन दोनों का मामला दरअसल राज्य व केंद्र सरकारों, कार्यपालिका व न्यायपालिका की बर्बरता, उनके द्वारा देश के नागरिकों को दिये गये कानूनी एवं संवैधानिक अधिकारों के घोर उल्लंघन का बेमिसाल प्रतीक है. कॉमरेड निर्मला पर लगाये गये डेढ़ सौ से ज्यादा झूठे मामलों में वह बाइज्जत बरी हो गयी है. इसके बावजूद उन पर लगातार नये फर्जी मामलें दायर करते जा रहे हैं. देश के न्यायिक इतिहास में शायद ही किसी और व्यक्ति पर, वह भी किसी महिला पर इतने झूठे मुकदमें दायर किये गये हों. यह छत्तीसगढ़ सरकार और उसकी पुलिस की बेशर्मी का अनोखा व अभूतपूर्व मिसाल है. कॉमरेड पद्मा पर लगाये गये तमाम केसों से वो भी बाइज्जत बरी कर दी गयी. अब तक वो तीन बार जेल से रिहा भी कर दी गयी लेकिन जेल गेट से बाहर निकलते ही उन्हें फिर से गिरफ्तार करके नये केसों में फंसाकर जेल में डाल दिया जा रहा है. कोर्ट द्वारा सजा नहीं दिलवा पाने की स्थिति में यह हथकंडा अपनाया जा रहा है. दोनों ही गंभीर रूप से बीमार हैं.

कॉमरेड मरकाम गोपन्ना का भी यही हाल है. वो भी पिछले 9 सालों से जेल में हैं और उन पर लगाये गये तमाम मामलों में वे जब बाइज्जत बरी हो गये और जेल से रिहा कर दिये गये, उन्हें नये फर्जी मामलों में फिर से जेल में डाल दिया गया है.

धज्जियां उड़ायी गयी. एक साल तक उन्हें पेशी के लिए भी नहीं ले जाया गया.

पहले से ही वे कई बीमारियों से पीड़ित हैं. जेल की अमानवीय परिस्थितियों के चलते उनकी तबियत बुरी तरह बिगड़ गई. जेल प्रशासन ने उन्हें अत्यावश्यक दवाईयां व पौष्टिक आहार नहीं दिया. परिवारजनों द्वारा लाई गई दवाईयों को भी उनतक नहीं पहुंचने दिया. दरअसल सरकार चाहती है कि जेल में ही उनकी मौत हो, ऐसा हम अंदाजा लगा सकते हैं.

सरकार व जेल प्रशासन के तानाशाही रवैये के खिलाफ अप्रैल 2015 में उन्होंने आमरण भूख हड़ताल शुरू की. छह दिनों के बाद जब उनकी तबियत बिगड़ गई थी तब जाकर उन्हें दवाखाना ले जाया गया और जबरन ग्लूकोज चढ़ाया गया. इस हालत में भी उन्हें जमानत नहीं दी गई.

कॉमरेड साईबाबा के प्रति सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ न सिर्फ देश भर में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई आंदोलन उभरे. उनकी रिहाई के लिए कई संगठनों, जनवादियों, जनाधिकार कार्यकर्ताओं व बुद्धिजीवियों के साथ एक भाईचारा कमेटी बनी.

इन प्रयासों के फलस्वरूप जून, 2015 में यानी 14 महीनों की न्यायिक हिरासत के बाद उन्हें छह महीनों की आंतरिम जमानत मिल गयी, वह भी कई शर्तों के साथ. उनका स्वास्थ्य सुधरा ही नहीं, इलाज पूरी हुई नहीं कि बीच में ही उनकी बेल रद्द की गयी. बेल की अवधि को बढ़ाने के लिए दायर पिटिशन को स्वीकार नहीं किया गया था. नतीजतन वे फिर से नागपुर जेल के कैदी बन गये हैं.

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, गुजरात की तत्कालीन भाजपा विधायिका माया कोद्नानी व बजरंगदल का नेता बजरंगी जो गुजरात हत्याकांड के जिम्मेदार हैं (नरोडा पाटिया कत्लेआम मामले जिसमें 97 मुसल्मानों का सामूहिक संहार किया गया था, में दोषी करार देते हुए माया कोद्नानी व भजरंगी को अह्मदाबाद की अदालत द्वारा सजा दी गई. माया को 28 साल की सजा दी गई जबकि बजरंगी को आजीवन कारावास की सजा दी गई) को जमानत देकर, साईबाबा को जमानत देने से इंकार करने वाली अदालतों के अन्यायपूर्ण रवैये पर सवाल उठाते हुए मशहूर लेखिका अरुंधती रॉय ने 'आउटलुक' पत्रिका में एक लेख लिखा था. इसके लिए अरुंधती रॉय पर कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट (अदालत की अवमानना) का मामला दर्ज किया गया. यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात है.

प्रोफेसर साईबाबा की अन्यायपूर्ण व अमानवीय हिरासत व अरुंधती रॉय पर थोपेगये आरोप की 'प्रभात' कड़ी निंदा करता है और प्रोफेसर साईबाबा की तुरंत व बेशर्त रिहाई की मांग करता है. सरकार व सरकार की देख–रेख में ही चलने वाली अदालतों के तानाशाहीपूर्ण रवैये के विरोध में आवाज उठाने जनता, जनवादियों, बुद्धिजीवियों व जन संगठनों का आह्वान करता है. ❍

रायपुर केंद्रीय कारागार में 2008 जनवरी से बंद कॉमरेड मालती की एक केस में जबरन दी गयी सजा खत्म हो गयी और दूसरे केस में दी गयी सात साल की सजा में से साढ़े पांच साल की न्यायिक हिरासत की अवधि को काटने के लिए जेल अधीक्षक तैयार नहीं हैं जबकि कोर्ट के फैसले में इसका स्पष्ट उल्लेख है. इससे स्पष्ट है कि जेल के फैसले न्यायपालिका से अलग भी होते हैं. दरअसल कॉमरेड मालती की दोनों सजाओं को एक साथ अमल करना चाहिए था.

महाराष्ट्र के मुंबई के एक जेल में बंद कॉमरेड एंजेला सोनटके पर भी केसेस खत्म होते ही नये–नये मामले दायर करते जा रहे हैं. दरअसल माओवादी कार्यकर्ताओं को अवैध, असंवैधानिक किसी भी तरीके से जेल से बाहर नहीं आने देने की सरकारों ने ठान ली है.

दिल्ली विश्व विद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर जीएन साईबाबा जोकि 90 प्रतिशत विकलांग हैं, की बेइल जिसे देश, दुनिया के बुद्धिजीवियों की काफी कोशिशों के बाद दी गयी थी, को रद्द करके नागपुर जेल में रखा गया है जिसे हैवानियत भरा कदम कहा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र की तमाम जेलों में क्षमता से कई गुना–दो, तीन, चार गुना अधिक संख्या में बंदियों को रखा जा रहा है और बैठने व सोने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं मिलती है. जेलों में अमानवीय परिस्थितियां व्याप्त हैं. जेल मैनुअल तो पुराना ही है. उसमें सालों से कोई सुधार नहीं हुआ है. इसके बावजूद मौजूदा जेल मैनुअल के मुताबिक भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं. अपनी हर जरूरत के लिए बंदियों के सामने लड़ने के सिवाय दूसरा चारा नहीं है. भ्रष्ट जेल अधिकारियों के अत्याचारों की कोई सीमा नहीं है.

वर्तमान में विस्थापन विरोधी, दमन विरोधी, जनवादी व मानवाधिकार आन्दोलनों, क्रांतिकारी आन्दोलन के कार्यकर्ताओं व संघर्षरत जनता एवं जनपक्षधर पत्रकारों को फर्जी मामलों में फंसाकर जेलों में बंद करके सालों–साल सड़ाया जा रहा है. इनकी संख्या लगभग छह हजार है. इनमें से अधिकांश गरीब आदिवासी हैं. आवश्यक विधिक सहायता के अभाव में ये लंबे समय तक जेल में रहने मजबूर हैं. छह माह की सजा वाले मामलों में बंद कई लोग छह साल से भी ज्यादा समय से बिना फैसले के सड़ रहे हैं. सुकमा के जिलाधीश एलेक्स पॉल मेनन को छोड़ने के एवज में जो समझौता हुआ था, जिसके मुताबिक बुच कमेटी बनी थी, उन समझौता शर्तों को दरकिनार करके धोखा देने वाली छत्तीसगढ़ सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के रूप में लाठी, जेल, गोली को ही एकमात्र रास्ता बनाया हुआ है.

राज्य यंत्र के हिस्से के तौर पर न्यायपालिका तेज होते राज्य दमन के साथ ही साधारण व सहज न्याय सूत्रों की अवहेलना करते हुए, झूठी गवाही के आधार पर या बिना गवाही के ही लंबी सजाएं व आजीवन कारावास की सजाएं दे रही है.

भाईचारा सप्ताह के दौरान पर्चा, पोस्टर, सड़क लेखन, दीवाल लेखन आदि के माध्यम से जेल कॉमरेडों की समस्याओं, राज्य दमन तथा न्यायपालिका की राजनीतिक बंदियों के प्रति उदासीन व नकारात्मक रवैये के बारे में व्यापक प्रचार किया गया था. राजनीतिक बंदियों के परिवारजनों की बैठकें आयोजित की गयी थीं. कुछ जगहों पर परिवारजनों द्वारा पत्रकार वार्ताएं भी आयोजित की गयी थीं. जेल कॉमरेडों के संघर्षों का समर्थन विभिन्न रूपों में किया गया था. जेलों में सामूहिक मुलाकातों के लिए सैकड़ों लोग गये थे. लेकिन दंतेवाडा जेल में सामूहिक मुलाकात के लिए जाने वालों को पुलिस द्वारा तंग किया गया था और मुलाकात देने से जेल प्रशासन ने इनकार किया था. पिछले साल भी राजनीतिक बंदियों के परिवारजनों व जनवादी बुद्धिजीवियों ने दंतेवाडा में एक बड़ी जुलूस निकालने की कोशिश की लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी और दंतेवाडा में घुसने नहीं दिया गया था. पार्टी ने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व देश के जनवादी, प्रगतिशील व जनपक्षधर अधिवक्ताओं से अपील की कि वे जेलों में लंबे समय से बंद विचाराधीन बंदियों के केसों की पैरवी करने आगे आएं और निचली अदालतों में सजा सुनाये गये बंदियों के मामलों को हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर करके पैरवी करें.

हाल ही में जगदलपुर लीगल एइड के वकीलों को आतंकित करने की पुलिसिया कोशिशों व सलवा जुडुम–2 के आतंकी संगठनों जैसे सामाजिक एकता मंच के प्रयासों के विरोध में आवाज उठाने की जरूरत है. छत्तीसगढ़ के तमाम अधिवक्ता संगठनों, बार काउंसिल को चाहिए कि वे छत्तीसगढ़ में मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ व जनवादी माहौल का निर्माण करने में आगे कदम बढ़ाएं. बाहरी वकील के नाम पर देश के अन्य इलाकों से छत्तीसगढ़ में विधिक सेवा उपलब्ध कराने आये अधिवक्ताओं का कुछ स्थानीय अधिवक्ताओं द्वारा सरकारी व पुलिस संरक्षण में विरोध करना न केवल निंदनीय है बल्कि गैर–जनवादी व तानाशाहीपूर्ण रवैया है जिसका हर तरफ से विरोध होना चाहिए.

जनता व जनवाद प्रेमियों को गांवों पर लगातार हो रहे पुलिसिया हमलों व आदिवासी ग्रामीणों की अवैध गिरफ्तारियों को रोकने आवाज बुलंद करनी चाहिए. जेल बंदियों के परिवारजनों की आर्थिक व हार्दिक मदद् करने आगे आना चाहिए. ❍

आदिवासी अधिकारों के योद्धा, उत्पीड़ित जनता के पक्षधर, प्रगतिशील–जनवादी बुद्धिजीवी

डॉ. ब्रह्मदेव शर्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि

आजीवन आदिवासियों के अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करने वाले, उनके हितैषी, उत्पीड़ित जनता के आन्दोलनों के समर्थक व नेता, निस्वार्थ उदारपंथी बुद्धिजीवी डॉ. बीडी शर्मा का दिसंबर 6, 2015 को ग्वालियर में निधन हो गया. वे 85 वर्ष के थे. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की केंद्रीय कमेटी की ओर से प्रवक्ता अभय एवं दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी की ओर से प्रवक्ता विकल्प ने डॉ. बीडी शर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की. उनके परिवारजनों, मित्रों, जन संगठनों व आदिवासी संगठनों के उन साथियों जिनके साथ उन्होंने काम किया, के प्रति गहरी संवेदना व सहानुभूति प्रकट की.

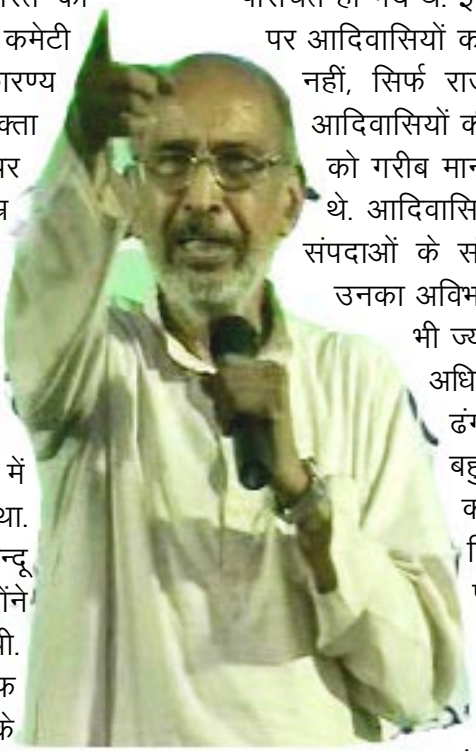

डॉ. बीडी शर्मा का जन्म 1931 में मध्यप्रदेश राज्य के ग्वालियर में हुआ था. उनकी शिक्षा ग्वालियर और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में हुई. गणित में उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की थी. पिलानी स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस में प्राध्यापक के रूप में अपने कॅरिअर की शुरुआत की थी. 1956 में वे आईएएस के लिए चुने गये थे. तब से लेकर 1981 में समय पूर्व स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेते तक उन्होंने अविभाजित बस्तर सहित मध्यप्रदेश के कई जिलों के जिलाधीश के रूप में और केंद्रीय गृह मंत्रालय में विभिन्न पदों पर रहते हुए अपनी सेवाएं दी. वे शिलांग स्थित एनईएचयु (नार्थ–ईस्ट हिल युनिवर्सिटी) के कुलपति के रूप में 1981 से 1986 तक, एक रुपए मासिक वेतन पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग के अध्यक्ष (1986–91) के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके थे. जब वे बस्तर में कलेक्टर की जिम्मेदारी निभाने आये थे तब वे समझ गये थे कि राज्ययंत्र उत्पीड़न का औजार मात्र है न कि जनता के विकास का माध्यम. वे अक्सर आदिवासियों के इस कथन का उल्लेख किया करते थे– 'आदिवासियों का स्वर्ग वह जंगल है जहां मीलों मील महुआ पेड़ हैं और नरक वह जंगल है जहां मीलों मील महुआ पेड़ एक वन रक्षक के साथ.' इस कथन से आदिवासियों के जीवन में राज्य यंत्र की शोषणमूलक व दमनकारी भूमिका को अत्यंत सरल तरीके से समझा जा सकता है. प्रकृति, प्राकृतिक संपदा, जैव संपदा के प्रति आदिवासियों के असीम प्यार व अपनापन से वे भली–भांति परिचित हो गये थे. इसीलिए उन्होंने जल–जंगल–जमीन पर आदिवासियों का जन्मसिद्ध अधिकार को एक नारा नहीं, सिर्फ राजनीतिक कार्य योजना नहीं, उसे आदिवासियों की जीवनशैली माना. वे आदिवासियों को गरीब मानने की सोच का कड़ा विरोध करते थे. आदिवासियों को देश के जंगल व प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षक व मालिक माना. बस्तर से उनका अविभाज्य, आत्मीय संबंध पांच दशकों से भी ज्यादा समय का रहा. एक प्रशासनिक अधिकारी की हैसियत से उन्होंने निस्वार्थ ढंग से जनता की सेवा की. आदिवासी बहुल पलामु जिले में सरकारी भ्रष्टाचार का उन्होंने आंकड़ों सहित भंडाफोड़ किया था. आदिवासी जनता के नाम पर केंद्र से जो निधियां मंजूर होती हैं, उनका 85 प्रतिशत भ्रष्ट अधिकारी ही हड़पते हैं जबकि 15 प्रतिशत निधियां ही आदिवासियों तक पहुंच पाती हैं. उन्होंने बस्तर में विश्व बैंक के 'पाइन प्रोजेक्ट' को रद्द करवाया. ट्राइबल सब प्लान, बंधक श्रमिक मुक्ति कानून जैसी अनेक जनानुकूल कानूनों व योजनाओं के वे सूत्रधार रहे. भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा होते हुए भी डॉ. शर्मा एक ईमानदार व स्वच्छ छवि के अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे. अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के दौरान उनके स्टेटस के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी के सामने निर्भीकता के साथ कहा था कि उन्हें पैसों से कोई नहीं खरीद सकता है. सेवा निवृत्ति के बाद से लेकर आखिरी सांस तक डॉ. शर्मा आदिवासियों के अधिकारों के लिए काम करते रहे एवं उत्पीड़ित जनता के आन्दोलनों में सक्रिय भागीदारी निभाते रहे.

डॉ. बीडी शर्मा ने अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत जन आन्दोलन नामक संगठन की स्थापना की. आदिवासियों के सार्वभौम अधिकारों की वे वकालत

करते थे. पेसा कानून के तहत ग्रामसभाओं को अधिकार दिलाने उन्होंने गंभीर कोशिश की. भूरिया कमीशन रिपोर्ट में उपरोक्त बातों को जुड़वाने में डॉ. शर्मा का काफी योगदान रहा. वे एक गांधीवादी थे और भारत के संविधान में उनकी आस्था थी. पेसा व ग्रामसभा के संदर्भ में उन्होंने नारा दिया था– लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊपर ग्रामसभा. इस सोच के बावजूद वे उत्पीड़ित जनता के तमाम आन्दोलनों में शामिल होते थे, उनका मार्गनिर्देशन करते थे, जरूरतों व परिस्थितियों की मांग पर उनका नेतृत्व भी करते थे. हालांकि उनकी चेतना यात्रा की शुरुआत गांधीवादी विचारों, संविधान पर आस्था, उद्दात हिंदू धर्म से हुई थी लेकिन नए–नए अनुभवों से टकराते हुए वे अपने सरोकारों का फैलाव करते गये अपने दृष्टिकोण को विस्तृत करते गये, समाज के अंतरविरोधों को समझते गये और आखिर में उत्पीड़ित जनता के तमाम किस्म के आन्दोलनों के साथ कदम मिलाकर चलने लगे थे.

1991 में नई आर्थिक नीति के नाम पर साम्राज्यवाद निर्देशित उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीतियों को अपनाते हुए भारत सरकार ने इन नीतियों को ही देश के विकास नमूने के रूप में पेश किया था. इस जन विरोधी विकास नमूने व जन विरोधी नीतियों का विरोध करने के लिए 1992 में देश के प्रगतिशील व जनवादी ताकतों ने अखिल भारतीय जन प्रतिरोध मंच (एआईपीआरएफ) बनाया. क्रांतिकारी लेखक संघ के कॉमरेड़ वरवर राव द्वारा साक्षी तेलुगु अखबार में लिखे गये एक लेख के मुताबिक एआईपीआरएफ के गठन से लेकर अपनी मृत्यु तक के 23 साल डॉ. बीडी शर्मा उक्त जन संगठन में एक नवजवान कार्यकर्ता की तरह काम करते रहे. साम्राज्यवाद के खिलाफ जो असहमति जनता में व्याप्त थी, उसे भी भुनाने की कोशिश में साम्राज्यवाद ने वर्ल्ड सोशल फोरम, एशिया सोशल फोरम जैसे संगठन बनवाये. इसका पर्दाफाश करते हुए मुंबई प्रतिरोध–2004 (एमआर–2004) के नाम पर एक राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें डॉ. शर्मा ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया था. हाल ही में माओवादी पार्टी की दसवीं स्थापना वर्षगांठ के अवसर पर तेलंगाना और आन्ध्रप्रदेश में गठित वैकल्पिक राजनीतिक मंच का हिस्सा बनने जब डॉ. शर्मा को मृत्यु से कुछ समय पूर्व आमंत्रित किया गया था, उन्होंने सहर्ष अपनी स्वीकृति दी थी एवं आम सभा में वक्ता के रूप में शामिल होने की इच्छा भी जताई थी. हालांकि स्वास्थ्य ने उनका साथ नहीं दिया. जन आन्दोलनों में शामिल होने हमेशा तत्पर रहते थे. क्रांतिकारी जनवादी मोर्चा के सह सचिव एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. जीएन साईबाबा की जबरन गिरफ्तारी के समय वे वहीं डटे रहे और पुलिस कार्रवाई का कड़ा विरोध करते रहे. अपने गिरते स्वास्थ्य की परवाह किये बगैर वे नागपुर जाकर डॉ. साईबाबा से मिलने अडिग थे. वे जन आन्दोलनों में जिए. वे कार्यकर्ताओं से बहुत प्यार करते थे. डॉ. शर्मा क्रांतिकारी जनवादी मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में भी कुछ समय तक अपनी सेवाएं दी.

डॉ. बीडी शर्मा आदिवासियों के अधिकारों, पेसा, ग्रामसभाओं, आदिवासियों की जीवन शैली आदि विषयों पर आजीवन लिखते रहे. उन्होंने हिंदी एवं अंग्रेजी भाषाओं में करीबन 100 किताबें लिखी. पहली किताब पगड़ंडी के अलावा वेब ऑफ पॉवर्टी, एग्रेरियन क्राइसिस, दलित बिट्रेड, बेजुबान आदि उनकी चर्चित रचनाओं में से हैं. शोषक–शासक वर्गों के विश्वासघाती जन विरोधी नीतियों के चरित्र का भंडाफोड़ करते हुए 'ब्रोकन प्रॉमिसेज ऑफ अनब्रोकन हिस्टरी' लिखी. उन्होंने पहली हस्तलिखित पत्रिका भूमकाल और बाद में गांव गणराज्य निकालीं.

उनकी संस्था भारत जन आन्दोलन देश के कई राज्यों में खासकर आदिवासी इलाकों में काम कर रही है. महाराष्ट्र के गड़चिरोली जिले में वह पेसा के मुताबिक ग्रामसभाओं का गठन करते हुए, प्रतीकस्वरूप गांवों में किसी निश्चित जगह पर शिला स्थापित करते हैं. इसी कारण से वहां की ग्रामसभाएं 'बंडा सरकार' (शिला सरकार) कहलाती हैं. उक्त संस्था के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं में गांवों के मुखियाओं का प्रभुत्व रहना, नेतृत्व में असामाजिक तत्वों की मौजूदगी आदि पर जब भी उनकी नजर पड़ती, वे उनकी आलोचना करते और उन्हें सुधारने की कोशिश करते. उनके निधन से भारत जन आन्दोलन ने अपने संस्थापक नेता खोया है. यह चिंताजनक है कि देश के क्रांतिकारी व जनवादी आन्दोलनों के प्रति भारत जन आन्दोलन को दोस्ताना रुख अपनाने संबंधित दिशा–निर्देश देने वाले अब नहीं रहे.

डॉ. बीडी शर्मा बस्तर व गड़चिरोली की आदिवासी जनता की हमेशा पहुंच में रहते थे. आखिरी दम तक वे उन जिलों का दौरा करते रहे और वहां की जनता की समस्याओं के हल के लिए कोशिश करते रहे. 83 वर्ष की उम्र में 2012 की तपती गर्मी में उन्होंने 'अबूझ'माड़ का दौरा किया था और पुलिस ऑपरेशन 'विजय' पीड़ितों से मिलकर उनके दुख–दर्द को सुना. पत्रकार वार्ता में पुलिस अत्याचारों की निंदा की. माड़ पर सेना को उतारने एवं वहां सैन्य प्रशिक्षण शाला खोलने का उन्होंने कड़ा

विरोध किया था. 84 वर्ष की उम्र में उन्होंने गड़चिरोली का दौरा किया और बॉम्बे एक्ट 110 को खत्म करने की मांग करते हुए कई सभाओं में शामिल हुए. आखिरी दिनों में वे काफी अस्वस्थ थे. एक सभा में भाषण देते समय वे अचानक गिर पड़े थे. बातें भूल जाने लगे थे. तब भी वे कॉ. वरवर राव से यह मांग करते रहे कि पूरी तरह याददाश्त खोने के पहले एक बार जरूर बस्तर का दौरा किया जाए. यह उनके बस्तर और यहां के आदिवासियों से बेपनाह मोहब्बत का ही द्योतक था. वे 'सादा जीवन, कठोर परिश्रम' की न केवल वकालत करते थे बल्कि स्वयं पालन करते थे. वे दिल्ली के स्लम एरिया में बहुत ही सामान्य परिस्थितियों में रहते थे. कंधे पे झोला, खादी का कुर्ता व धोती, चश्मा यही डॉ. शर्मा की पहचान थी. डॉ. बीडी शर्मा जिन उच्च परंपराओं, आदर्शों, जनपक्षधरता का आजीवन पालन करते रहे, भारत जन आन्दोलन आगे उनका बराबर अनुकरण करेगी, जनता ऐसी आशा व अपेक्षा रखती है.

डॉ. बीडी शर्मा बस्तर में प्रस्तावित बोधघाट बहुउद्देश्यीय बांध परियोजना का प्रारंभ से विरोध करते आये. आदिवासी जन जीवन के तहस–नहस होने व पर्यावरण को होने वाले भारी नुकसान के मद्देनजर उन्होंने बांध परियोजना का विरोध किया. बाद में 1990 के दशक में एनएमडीसी द्वारा बस्तर के माउलीभाटा, हीरानार में इस्पात संयंत्र स्थापित करने की कोशिशों के विरोध में डॉ. शर्मा के मार्गदर्शन में भारत जन आन्दोलन के बैनर तले जनता ने जबर्दस्त आन्दोलन छेड़ा था. इस आन्दोलन के फलस्वरूप 2000 में एनएमडीसी ने अपने प्रस्ताव को वापस लेने मजबूर होना पड़ा. उसी दौरान पुलिस, प्रशासन के संरक्षण व प्रत्यक्ष मदद से कांग्रेस व भाजपा के गुण्डों ने 1993 में डॉ. शर्मा को अधनंगा करके जूतों का माला पहनाकर जगदलपुर शहर में उनका जुलूस निकाला था. आदिवासी जनता के हित में घोर अपमान को आसानी से सहने वाले डॉ. शर्मा बाद के समय में बस्तर के बाहर से बस्तरवासियों के आन्दोलनों का समर्थन करते आये. यह सर्वविदित है कि सुकमा कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन को पीएलजीए की हिरासत से छुड़ाने के लिए मध्यस्तता करने भाजपा की रमण सरकार ने 2012 में उन्हें बाइज्जत बुलाकर बस्तर भेजा था. याद रहे उनका अपमान करने वाली सरकार भी तत्कालीन मध्यप्रदेश की भाजपा की ही सुंदरलाल पटवा सरकार थी. मेनन की रिहाई के समय राज्य सरकार के साथ हुई समझौते के मुताबिक जेलों में बंद आदिवासियों व माओवादी बंदियों की जल्द रिहाई के लिए बनी बुच कमेटी व सरकार ने बाद में किसी की रिहाई नहीं की. सरकार ने वादा खिलाफी की. तब उन्होंने यह महसूस किया कि वे सरकार द्वारा ठगा गये हैं.

डॉ. बीडी शर्मा आदिवासी जनता के हकों, उत्पीड़ित जनता के जायज अधिकारों के लिए जारी तमाम जन संघर्षों व क्रांतिकारी संघर्षों का हमेश समर्थन करते रहे. 2004 में वे चारगांव में आयोजित चारगांव बचाओ समिति की आमसभा में शामिल होकर आदिवासियों के संघर्ष का पुरजोर समर्थन किया था. पहले के सलवा जुडुम, बाद के ग्रीनहंट के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज बुलंद रखी. ऑपरेशन ग्रीनहंट को जनता पर जारी युद्ध के रूप में घोषित करने वाले जनवादी बुद्धिजीवियों में से डॉ. बीडी शर्मा एक थे. देश भर में ग्रीनहंट के खिलाफ आयोजित आमसभाओं व आन्दोलनों में वे शामिल रहे.

डॉ. ब्रह्मदेव शर्मा की सेवाएं अविस्मरणीय हैं. उनके निधन से देश की उत्पीड़ित जनता खासकर आदिवासियों ने एक आत्मीय बंधु, प्रखर पक्षधर, हितैषी को खोया है. देश के जनवादी व क्रांतिकारी आन्दोलन ने एक अच्छे मित्र, साथी व आलोचक को खोया है. उनकी मृत्यु की खबर को सरकारी मीडिया ने जानबूझकर कोई महत्व नहीं दिया था. मेनन की रिहाई में मध्यस्तता करने वाले व्यक्ति के रूप में ही उल्लेख किया गया. शोषक–शासक वर्गों द्वारा ऐसा व्यवहार दरअसल उनके चरित्र के मुताबिक ही है. लेकिन डॉ. शर्मा जनता के दिलों में हमेशा के लिए स्थान बना गये हैं. उच्च शिक्षा प्राप्त एवं उच्च पदों पर कार्यरत रहते हुए भी वे सादा, सरल जीवन लेकिन उच्च मूल्यों व आदर्शों के साथ जिये. सरकारी सेवा में रहते हुए भी और सेवा निवृत्ति के बाद भी, आजीवन आदिवासियों व उत्पीड़ित जनता के लिए उन्होंने समर्पित होकर काम किया. वे यदि जनपक्षधरता को छोड़ दिये होते, शोषकों की सेवा किये होते शायद विश्व बैंक में पहुंच, संसद में या राजभवन में भी पहुंच गये होते. लेकिन तब लोगों के दिलों में कोई जगह नहीं बना पाते. आज के समय में जब भ्रष्टाचार व घोटालों का बोलबाला है, ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवाद देश और समाज को दबोचने की पूरी तैयारी कर रहा है तब डॉ. ब्रह्मदेव शर्मा की कमी हमेशा खलती रहेगी. उच्च शिक्षा प्राप्त एवं उच्च प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत लोगों को उन्हें एक आदर्श नमूने के रूप में स्वीकार करके उनका अनुसरण व अनुकरण करना चाहिए. डॉ. बीडी शर्मा को प्रभात विनम्र श्रद्धांजलि पेश करता है.

संघ परिवार व भाजपा द्वारा प्रायोजित एवं सरकारी संरक्षण में गठित सलवा जुडुम–2 के फासीवादी संगठनों को मात दो!

दरअसल सलवा जुडुम–2 को फिर से संचालित करने की केंद्र, राज्य सरकारों की साजिश के तहत संघ परिवार, भाजपा के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में सलवा जुडूम के जीवित बचे नेताओं व गुण्डों, लंपट तत्वों को सामने रखकर पुलिस नये–नये नामों पर फासीवादी हिंसा फैलाने वाले संगठन बनवा रही है. इसमें भाजपा समर्थित बड़े ठेकेदारों, बड़े व्यापारियों की भी अहम भूमिका है. माओवादी आन्दोलन को जल्द से जल्द खत्म करके बड़े खदानों, बड़े कारखानों को प्रारंभ करवाने में यानी देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों की लूट में ये अपने हिस्से को सुनिश्चित मानते हैं. सामाजिक एकता मंच, नक्सल पीड़ित संघ, महिला एकता मंच आदि सरकारी संरक्षण में पुलिस के प्रत्यक्ष सहयोग व सहभागिता से बनाये गये प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रांतिकारी संगठन हैं. असामाजिक तत्वों, जन विरोधी ताकतों व जनता द्वारा जन अदालतों में दण्डित लोगों व उनके परिवारजनों को पुलिस संरक्षण में उपरोक्त संगठनों में संगठित कर रहे हैं. इन संगठनों द्वारा रैलियां आयोजित की जा रही हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं व महिला संगठनों की कार्यकर्ताओं का घेराव करवाया जा रहा है, उन्हें तंग किया जा रहा है और उन पर हमलें करवाये जा रहे हैं.

दरअसल 1933 में सत्तारूढ़ होने के बाद नाजी हिट्लर ने अपने विरोधियों, यहूदियों, कम्युनिस्टों, मजदूर संगठनों का सफाया करने के लिए इस तरह के संगठनों का इस्तेमाल किया था. ये सड़कों पर हिंसा फैलाते हैं. इनके द्वारा सरकार विरोधी आवाजों को गाली–गलौच, अपमान, मार–पीट, हमलें और भी कई जघन्य तरीकों द्वारा दबाने की कोशिश की जाती है. सरकारों द्वारा पुलिस, प्रशासन के माध्यम से अमल किये जाने वाले दमनात्मक हथकंडों से अलग यह हिंसा होती है. ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी राज्य व्यवस्था की सोची समझी साजिश है, ये फासीवादी संगठन.

सामाजिक एकता मंच के बैनर तले जगदलपुर में 22 दिसंबर, 2015 को 'धिक्कार रैली' एवं सभा आयोजित की गयी. असत्य बात को लेकर कॉरपोरेट मीडिया के सहारे बहुप्रचारित करके माओवादियों की तथाकथित अमानवीयता के खिलाफ यह रैली और सभा आयोजित थीं. पुलिसिया अत्याचारों, दमन, महिला उत्पीड़न के प्रति उभरते जन आक्रोश एवं जन भावनाओं को भटकाने के लिए ही, जनता को डरा–धमकाने के लिए, आतंकित करने के लिए ही जगदलपुर में धिक्कर रैली का आयोजन किया गया था. रैली को पीएलजीए के हाथों में झीरामघाटी में मारे गये जुडूम नेता महेन्द्र कर्मा के पुत्र दीपक कर्मा, सलवा जुडूम के कुख्यात नेतागण चैतराम अट्टामी, सोयम मूका, पी विजय, मधुकरराव, सुखदेव ताती, अवधेशगौतम ने संबोधित किया जबकि भाजपा नेतागण जगदलपुर नगर निगम के सभापति शेषनरायण तिवारी के अलावा आरएसस के नेता राजबहदूरसिंह राणा, महापौर जतिनजयसवाल, एनआर प्रशार, अजयसिंह, मोहम्मद समीम, फारुक, सत्तरअली आदि मंच पर मैजूद थे। एसपी राजेन्द्र नरायणदास, दन्तेवाड़ा एसपी कमलोचन कश्यप आदि पुलिस अधिकारी भी मंच पर मौजूद थे। कुछ ग्रामीणों को डरा–धमका कर रैली में लाया गया था. सलवा जुडूम के नेतागण, संघ परिवार, भाजपा, पुलिस ने ताकत के बलबूते व दबाव डालकर कुछ स्कूली बच्चों को भी रैली व सभा में शामिल कराया था.

दक्षिण बस्तर में पुलिस व अर्ध सैनिक बलों द्वारा महिलाओं पर किये गये अनगिनत व अमानवीय अत्याचारों के विरोध में पदयात्रा निकालने के अपने निर्णय की घोषणा जब सोनी सोढ़ी ने की, तब पुलिस के इशारे पर सामाजिक एकता मंच एवं नक्सल पीड़ित संघ ने बीजापुर में हंगामा मचाया. सोनी का घेराव करके, उनके खिलाफ नारेबाजी से लेकर गाली–गलौच, पत्थरबाजी, धक्कामुक्की की गयी. आखिर उन्हें अपनी पदयात्रा बंद करनी पड़ी. सरकारी सशस्त्र बलों द्वारा बलात्कार पीड़ित महिलाओं की शिकायत दर्ज कराने महिला संगठनों की कार्यकर्ताओं ने जब प्रयास किया, उन्हें थाने में घेरकर बीजापुर और बस्तर छोड़ने काफी दबाव डाला गया. उनके खिलाफ रैली आयोजित की गयी और उन्हें धमकाया गया था. एफआईआर दर्ज करने के लिए भी अधिकारीगण तैयार नहीं थे. यह सब पुलिस की मौजूदगी में उनकी शह पर ही हुआ था.

हाल ही में स्क्रोल इन की स्वतंत्र पत्रकार एवं रेड क्रास की पूर्व कार्यकर्ता मालिनी सुब्रह्मण्यम के घर पर हमला किया गया एवं उन्हें परेशान किया गया. उन्हें बस्तर छोड़ने धमकाया गया. आखिर उनके मकान मालिक पर दबाव डाला गया कि वह मालिनी को अपने घर से खाली कराए. थक हारकर मालिनी बस्तर छोड़ चुकी है. उनका कसूर यही था कि उन्होंने बस्तर में दमन की स्थिति की वास्तविक तस्वीर पेश करने की कोशिश की.

जुलाई, 2013 से शुरू कर, कुछ समय पहले से जगदलपुर में रहकर जेलों में बंद गरीब, दलित व आदिवासियों को कानूनी सुविधा मुहैया कराने वाली चार महिला वकीलों जो जगदलपुर लीगल एइड ग्रुप के नाम से काम कर रही थीं, पर भी एकता मंच के गुण्डों ने हमला किया था. उनके घरों के दरवाजों, खिड़कियों पर पत्थर मारने, गाली–गलौच करने, गंदी नारेबाजी करने, बस्तर छोड़ने वरना गंभीर

सोनी सोढ़ी पर हमले की कड़ी निंदा करो!
ग्रीनहंट के तहत बस्तर में महिलाओं पर जारी पुलिसिया अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद करो

विगत 20 फरवरी की रात को गीदम के पास 'आप' पार्टी की नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोढ़ी पर पुलिस के इशारे पर सलवा जुडुम–2 के गुण्डों ने हमला करके उनके चेहरे पर रसायनयुक्त कालिख पोत दिया था. एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक संसदीय राजनीतिक दल की नेता विशेषकर एक आदिवासी महिला पर खासकर उनके चेहरे पर ज्वलनशील पदार्थ से किये गये हमले से बस्तर में आम आदिवासी जन जीवन की दयनीय स्थिति का हर कोई आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं. यहां यह बताना लाजिमी है कि सरकारी सशस्त्र बलों द्वारा सोनी सोढ़ी पर विगत में अमानवीय यौन अत्याचार किये गये थे. वो फर्जी मामलों में फंसायी गयी थीं. जेलों में भी उन पर अनगिनत अत्याचार किये गये थे. सर्वोच्च न्यायालय से मिली राहत के बाद वे जेल से छूटकर बाहर आयीं. तमाम अत्याचारों का सामना करके वो निर्भीकता के साथ जनवादी तरीके से उत्पीड़ित महिलाओं के लिए आवाज उठा रही हैं. पुलिस–प्रशासन के खफा होने का यही कारण है. अब एक बार और दूसरे रूप में उन पर यह हमला उनकी आवाज बंद करने किया गया है. यह हमला केंद्र, राज्य सरकारों के संरक्षण व संघ परिवार के संगठनों व भाजपा द्वारा प्रायोजित सामाजिक एकता मंच, नक्सल पीड़ित संघ आदि सलवा जुडुम–2 के फासीवादी गुण्डा संगठनों द्वारा पुलिस की शह पर व उनकी सहभागिता से किया गया है. पिछले अक्तूबर से लेकर अब तक बस्तर की आदिवासी बालाओं, महिलाओं पर सशस्त्र बलों द्वारा किये गये अत्याचारों को उजागर करने, पीड़िताओं की शिकायतें थानों में दर्ज करवाने व कोर्ट में मामले दायर करवाने तथा झूठी मुठभेड़ हत्याओं का भंडाफोड़ करने की सोनी सोढ़ी व महिला संगठनों की कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं व मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, जगदलपुर लीगल एइड की वकीलों, जनपक्षधर पत्रकारों की जनवादी कोशिशों पर प्रहार के रूप में ही इस हमले को देखा व समझा जाना चाहिए. पूर्व में महिलाओं पर बस्तर में जारी अत्याचारों के विरोध में सोनी सोढी की प्रस्तावित रैली को भी जबरन रोका गया था. सोनी सोढ़ी

परिणाम भुगतने की चेतावनी देना आदि कुकृत्यों के जरिए उन पर काफी दबाव बनाया गया था. आखिर में ईशा खंडेलवाल, भारद्वाज और एक महिला वकील बस्तर छोड़कर चली गयी. जबकि शालिनी गेरा पुलिस व मंच के तमाम हथकंडों के बावजूद जगदलपुर में डटी हुई है. उन्होंने घोषणा की कि जान जाए पर वो बस्तर नहीं छोड़ेंगी.

सामाजिक एकता मंच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाली प्रोफेसर नंदिनी सुंदर का मंच ने जगदलपुर में पुलिस के समक्ष पुतला जलाया था।

एक और सामाजिक कार्यकर्ता, कैंब्रिज से डॉक्टरेट हासिल बेला भाटिया ने भी जो पिछले साल भर से जगदलपुर में पूर्णकालीन रह रही हैं, घोषणा की कि वे अपनी जान की परवाह नहीं करेंगी और बस्तर नहीं छोड़ेंगी.

इस बात से सभी वाकिफ है कि बस्तर जिले के मारडुम थाना क्षेत्र के गांव टुंडेर के अडमा कश्यप की फर्जी मुठभेड़ मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर करवाकर लौट रही सोनी सोढ़ी पर इन्हीं संगठनों द्वारा हमला करके उनके चेहरे पर विषैली कालिख पोत दी गयी थी.

बीबीसी के रायपुर संवाददाता आलोक प्रकाश पुतुल जब रिपोर्टिंग के लिए बस्तर गये थे, उन पर हमला करने की इन संगठनों की कोशिशों का उन्हें पता लगा, तब वे जान बचाकर रायपुर चले गये थे. उपरोक्त तमाम हमलें पुलिस की मौजूदगी में होने के बावजूद अब तक किसी को पुलिस ने छुआ तक नहीं. छुएगी भी क्यो? आखिर उनके इशारे पर ही वे जो नाच रहे हैं.

केंद्र, राज्य सरकारों द्वारा जारी जनता पर युद्ध ऑपरेशन ग्रीनहंट के हमलों के अलावा इस तरह के संगठनों के जरिए जनवादी, प्रगतिशील व मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, जनपक्षधर वकीलों व पत्रकारों को माओवादी या माओवादी समर्थक कहकर उनकी आवाज बंद करके संघर्ष इलाकों में जारी दमन के खबरों को बाहरी दुनिया में जाने से रोकने के विफल प्रयास किये जा रहे हैं.

जनता व प्रगतिशील–जनवादी जन संगठनों, जनपक्षधर पत्रकारों, वकीलों, मानवाधिकार संगठनों को दमन का मुकाबला करते हुए ही सलवा जुडुम–2 के फासीवादी संगठनों का कड़ा विरोध व प्रतिरोध करना चाहिए. ❍

पर हमले के पहले पत्रकार मालिनी सुब्रह्मण्यम एवं अन्य मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को आतंकित करने की कोशिशें की गयीं. बस्तर सहित तमाम संघर्ष इलाकों में महिलाओं पर सरकारी सशस्त्र बलों के बढ़ते अमानवीय अत्याचारों, सामूहिक बलात्कारों, झूठी मुठभेड़ों के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने व उनका पर्दाफाश करने वालों को आतंकित करने की घृणित कोशिशों का हिस्सा है, यह हमला. बस्तर की आदिवासी अवाम पर सरकारी सशस्त्र बलों द्वारा जारी फासीवादी दमन, पाशविक हमलों की सच्चाई से बाहरी दुनिया अवगत न हो, इसीलिए यह हमला किया गया है.

सोनी सोढ़ी पर यह हमला उस समय हुआ जब वे एक झूठी मुठभेड़ के मामले में बिलासपुर उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अपने घर लौट रही थीं. उन्होंने गीदम एवं रायपुर पुलिस में शिकायत दर्ज करायी थी कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. उनकी जान को खतरा है. पुलिस की ओर से सुरक्षा की बात तो दूर उल्टे सोनी पर पुलिस ने ही हमला करवाया. इस पूरे प्रकरण में बस्तर आईजी शिवराम प्रसाद कल्लूरी केंद्र में हैं और स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि कल्लूरी के ही इशारे पर यह सब हुआ है. बाद के परिणाम इसे ही साबित कर रहे हैं.

हमले के बाद से पुलिस सोनी के परिवारजनों को लगातार परेशान कर रही है. पूछताछ के नाम पर, बयान लेने के नाम पर सोनी की बहन, बहनोई, बच्चों, भतीजा लिंगाराम कोडोपी को बार–बार थाना बुलाकर गाली–गलौच, धमकियां, सोनी पर हमले की जिम्मेदारी थोपना आदि के जरिए काफी तंग करने की बातें मीडिया में सामने आयी हैं. लिंगाराम कोडोपी ने तो सोशल मीडिया के जरिए पुलिस प्रताड़ना की आपबीती लोगों तक पहुंचाते हुए लिखा कि वो कल्लूरी के हाथों मरने की बजाय आत्महत्या कर लेंगे. लिंगाराम को सोनी पर हमले का कसूरवार ठहराने की पुलिसिया कोशिश जोरों पर चल रहा है. सोनी के बच्चों से परामर्श करने आये मुख्य सचिव ने भी सोनी पर किये गये हमले में लिंगाराम का हाथ होने की बात कही थी. सोनी के घर पर पुलिस के पहरे के बावजूद धमकी भरे पत्रों के मिलने की शिकायत पर कल्लूरी के इस कथन से कि अब चूंकि बाहर पहरा है, इसलिए घर के अंदर से ही पर्चे फेंके जा रहे हैं, पुलिस की साजिश का अंदाजा लगाया जा सकता है. कल्लूरी ने सोनी पर हमले के मामले में जेएनयू एंगल को भी जोड़कर जांच करने की बात कहकर सभी को हैरत में डाल दिया. और तो और इसमें माओवादियों के हाथ होने का भी संदेह जताया. वाह! कल्लूरी की अद्‌भुत कल्पना शक्ति की दाद देनी पड़ेगी. झूठा प्रचार करना और बातों को घुमाना, कोई उनसे सीखें.

अब सोनी पर हमले के मामले में जांच के लिए गठित एसआईटी–विशेष जांच दल की कार्यशैली भी कम रोचक नहीं है. सोनी का बयान दर्ज करने आयी एसआईटी जिसमें पुलिस अधिकारी ही शामिल हैं, ने बयान में कल्लूरी का नाम न लेने सोनी पर दबाव डाला था. नामजद बयान देने जब सोनी अडिग रही तब एसआईटी ने बयान तक लेने से इनकार किया और टीम वापस गयी. सोनी ने मीडिया को दिये बयान में साफ कहा कि उन पर हमले में कल्लूरी का हाथ है. उन्होंने एसआईटी पर अविश्वास जताया. सोनी ने कल्लूरी पर यह आरोप लगाया कि उनके पिता एवं अन्य परिवारजनों के सामने कल्लूरी ने उन्हें गंदी–गंदी गालियां दी. मीडिया से बात करते हुए भी कल्लूरी ने सोनी को 'बाजारु औरत' और भी कई अपशब्द कहे. यह न सिर्फ कल्लूरी की सामंती पितृसत्तात्मक अखड़ व पुलिसिया घमंड ही नहीं, भाजपा सरकार के ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी महिला उत्पीड़न का द्योतक है. कल्लूरी के इसी चरित्र से खुश होकर सरकारों ने उन्हें केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव के पद के लिए नामांकित किया है. आश्चर्य की कोई बात नहीं कि शोषक–शासक वर्ग अपनी सेवा करने वालों का बखूबी ख्याल रखते हैं.

ज्ञात रहे, पिछले साल अपने छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रधान मंत्री मोदी ने पूंजी के साथ–साथ सलवा जुडुम–2 को साथ लेकर आये थे. अब की बार सोनी सोढ़ी पर हमले के द्वारा वे सामाजिक कार्यकर्ताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, वामपंथी व विपक्षी पार्टियों एवं संगठनों को यह संदेश देना चाहते हैं कि सरकारों के खिलाफ कोई उंगली नहीं उठा सकते हैं, सवाल की कोई गुंजाइश ही नहीं है. जो सरकार के साथ नहीं है, उसे माओवादी या माओवादी समर्थक ही समझा जायेगा. बस्तर में मानवाधिकारों के घोर हनन का यह एक संकेत है.

दण्डकारण्य ही नहीं पूरे देश के जल–जंगल–जमीन व संसाधनों को बचाने के लिए जारी विस्थापन विरोधी आन्दोलनों, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के नेतृत्व में जारी क्रांतिकारी आन्दोलन, जनवादी, प्रगतिशील व मानवाधिकार आन्दोलनों को खत्म करने के लिए जनता पर जारी नाजायज बहु आयामी युद्ध के तहत ही पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं व जनता पर यह हमलें हो रहे हैं. इसलिए छत्तीसगढ़ सहित देश के तमाम मानवाधिकार संगठनों, महिला संगठनों व मीडिया कर्मियों को आगे आकर सोनी सोढ़ी जो हमले के बाद भी हिम्मत के साथ डटी हुई है, के समर्थन में एवं उन पर हमले के खिलाफ आवाज बुलंद करना चाहिए. महिलाओं पर अत्याचारों को दमन के औजार के रूप में इस्तेमाल करने वाली सरकार के फासीवादी दमन अभियान–ग्रीनहंट के खिलाफ, सरकार द्वारा दी गयी खुली छूट के आधार पर बस्तर में जारी पुलिसिया आतंक के विरोध में सड़क पर उतरना चाहिए. ❍

प्रधान मंत्री रूर्बन मिशन–विकृत शहरीकरण व देहाती भारत में कॉरपोरेट लूट के अड्डों के निर्माण की साजिश

पछले साल 9 मई को कॉरपोरेट लूट के लिए छत्तीसगढ़ का दौरा करते समय मोदी एक हाथ में पूंजी और दूसरे हाथ में सलवा जुडुम–2 को साथ लेकर आये थे. इस बार फिर एक बार वे कॉरपोरेट वर्गों के प्रधान सेवक की अपनी असली भूमिका निभाने 21 फरवरी को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आये थे. इस बार उन्होंने पूरे देश के लिए राजनांदगांव के कुर्राभाठ में बहु प्रचारित प्रधान मंत्री रूर्बन मिशन का उद्घाटन किया. पिछली बार की तरह इस बार भी दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने मोदी जो ग्रामीण इलाकों में कॉरपोरेट लूट के अड्डों के निर्माण की योजना का उद्घाटन करने छत्तीसगढ़ आये थे, के दौरे का बहिष्कार किया था.

यह रूर्बन मिशन है क्या?

छत्तीसगढ़ राज्य में इस मिशन की शुरुआत चार क्लस्टर (संकुल) से करने की घोषणा की गयी जिनमें बस्तर ब्लाक के मडपाल, धमतरी ब्लाक के लोहरसी, डोंगरगढ़ ब्लाक के मुरमंदा, पण्डरिया ब्लाक के कुण्डा को शामिल किया गया है. रूर्बन मिशन के बारे में अधिकारिक तौर पर यह बताया गया है कि यहां के गांवों व शहर को मिलाकर नया रूप दिया जायेगा. शहरी सुविधाओं से समझौता किए बगैर समता व समावेशन पर ग्रामीण जन जीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखकर गांवों के क्लस्टर को रूर्बन गांवों में विकसित किया जायेगा. भौगोलिक रूप से एक–दूसरे के समीप बसे गांवों का एक क्लस्टर ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक तालमेल की इकाई होगी. यह प्रशासनिक दृष्टि से किसी एक ब्लॉक या तहसील के अधीन होगा. योजना की कुल लागत की 70 प्रतिशत राशि कनवर्जेंस से प्राप्त होगी. केंद्र सरकार 30 प्रतिशत राशि देगी. चार क्लस्टरों में से दो ट्राइबल ब्लॉक से और दो नॉन ट्राइबल ब्लॉक से चयनित किये गये हैं. कुल चार क्लस्टर हेतु तीन वर्ष के लिए कुल लागत 120 करोड़ रुपए होगी, जो प्रत्येक वर्ष के लिए चार क्लस्टर हेतु 40 करोड़ रुपए होगी. राज्य स्तरीय सशक्त समिति के अनुमोदन से उपरोक्त चार क्लस्टरों का चयन किया गया है. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से इन क्लस्टरों के लिए प्रारंभिक राशि मिलेगी. चयनित चार में से मुरमंदा संकुल में 16 ग्राम पंचायतें, कुण्डा में 30 गांव, लोहरसा संकुल में 14 गांव, मडपाल संकुल में 23 गांव शामिल हैं. इन चारों क्लस्टर केंद्रों में पहले से कई सुविधाएं मौजूद हैं. मुरमंदा हावड़ा–मुंबई रेल मार्ग और नेशनल हाई वे एनएच–6 से लगा हुआ है. कुण्डा एनएच–130 ए पर स्थित है जबकि मड़पाल एनएच–43 से जुड़ा हुआ है. लोहरसा रायपुर–जगदलपुर राजमार्ग से जुड़ा है. इन क्लस्टरों का चयन उन इलाकों की कुछ विशेषताओं खासकर वहां उपलब्ध होने वाले संसाधनों को ध्यान में रखकर किया गया है. जैसे मुरमंदा संकुल के गांवों में हैंडलूम का काम बड़े पैमाने पर किया जाता है, कुण्डा संकुल में गन्ना उत्पादन एवं गुड़ बनाने का काम बड़े पैमाने पर होता है, मडपाल क्षेत्र में विभिन्न वनोपजों का संग्रहण बड़े पैमाने पर होता है और यह नगरनार स्टील प्लांट के नजदीक है और लोहरसा आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से संपन्न है और नहरों की सुविधा के हिसाब से इलाके की जमीन दो फसली है.

यहां यह याद दिलाना उचित होगा कि देश भर में रूर्बन मिशन के तहत 300 क्लस्टर विकसित करने की योजना है.

प्रधान मंत्री रूर्बन मिशन दरअसल पूंजीपतियों व सामंती ताकतों के हितों को साधने वाली एक देशव्यापी महत्वाकांक्षी योजना है. इसके तहत ग्रामीण भारत में ऐसे क्लस्टर्स का निर्माण किया जायेगा जहां से आस–पास के ग्रामीण इलाकों के कृषि उत्पादों सहित वहां उपलब्ध तमाम प्राकृतिक संपत्ति व संसाधनों को आसानी से देशी, विदेशी बाजारों में ले जाया जा सकेगा. साथ ही उन्हें देशी, विदेशी उत्पादों के भंडारों व उनके बिक्रय केंद्रों में तब्दील किया जायेगा. यहां क्लस्टर का मतलब कुछ गांवों का समूह जिसके केंद्र में ऐसा कस्बा होगा जो आस–पास के गांवों के लिए एक बाजार केंद्र के रूप में काम कर रहा हो और बड़े शहरों से जोड़ने की सड़क पर हो. पहले से कुछ बुनियादी सुविधाएं हो. रूर्बन मिशन के तहत इन क्लस्टरों को विकसित किया जायेगा. इसका यह मतलब नहीं कि क्लस्टर के तमाम गांवों का विकास किया जायेगा. गांवों के समूह के केंद्र के रूप में जो कस्बा रहेगा सिर्फ उसी का विकास होगा. विकास का मतलब उस केंद्र को शहरों से जोड़ने वाली सड़कों का डामरीकरण, चौड़ीकरण, विद्युतीकरण, मार्केट यार्ड, मोबाइल टावरों, इंटरनेट से जुड़ाव, बैंकों की स्थापना, सितारा होटलों (2, 3 या ?), किसान क्लब (जुआ खिलाने..?), व्यावसायिक परिसरों (शापिंग कांप्लेक्स), मल्टी प्लेक्स, शिक्षण संस्थानों, रेल लाइन, आदि का निर्माण. इस कस्बाई केंद्र से क्लस्टर के तमाम गांवों को सड़क मार्ग से जरूर जोड़ा जायेगा ताकि क्लस्टर केंद्र व गांवों के बीच लोगों व कृषि उत्पादों सहित सभी प्रकार के माल की आवाजाही सरल व सुगम बन सके. क्लस्टर केंद्र के रूप में उन्हीं कस्बों का चुनाव किया जा रहा है जहां पहले से कुछ सुविधाएं मौजूद हैं. क्लस्टर्स इन्हीं केंद्रों के नाम से जाने जायेंगे.

पत्रकारों की गिरफ्तारी–क्रांतिकारी आन्दोलन पर बढ़ते राज्य दमन का ही परिचायक है!
पत्रकारिता की स्वतंत्रता को जकड़ती सरकारी जंजीरें

आज की तारीख में समूचे दण्डकारण्य में खासकर बस्तर में भयानक दमन जारी है. हालांकि हमारी पार्टी, जन मुक्ति छापामार सेना, जनताना सरकारें इस दमन के केंद्र में हैं लेकिन तमाम विस्थापन विरोधी आन्दोलनों के कार्यकर्ता, जनता, जनपक्षधर या कहे निष्पक्ष पत्रकार, प्रगतिशील–जनवादी ताकतें, मानवाधिकार संगठनों के कार्यकर्ता सहित तमाम गैर–भाजपाई राजनीतिक पार्टियां–सीपीआई, आम आदमी पार्टी, यहां तक कि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस भी पुलिस के निशाने पर हैं. यहां पुलिस राज चल रहा है. छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस विभाग को सारे अधिकार दिये है. पुलिस किसी को भी, कभी भी, कहीं से भी गिरफ्तार कर सकती है, फर्जी मामलों में फंसाकर जेल भेज सकती है. ईनामी माओवादी कहकर झूठी मुठभेड़ में मार सकती है, आत्मसमर्पण दिखा सकती है, जबरन पुलिस बना सकती है. बस्तर से भगा सकती है. आज–कल बस्तर में यही सब हो रहा है. इन सच्चाइयों को सामने लाने वालों पर राज्य कहर बरपा रहा है.

हाल ही में चार पत्रकारों–सोमारु नाग, संतोष यादव, प्रभात सिंह और दीपक जायसवाल की गिरफ्तारी को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा व समझा जाना चाहिए. उन्हें झूठे मामलों में फंसाकर जेल भेजा गया है. जगदलपुर लीगल एइड के वकीलों, महिला संगठनों के कार्यकर्ताओं, पत्रकार मालिनी सुब्रह्मण्यम को जगदलपुर छोड़ने पर मजबूर किये जाने को भी इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए. निष्पक्ष या कहे जनपक्षधर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को प्रताड़ित करने का सिलसिला बस्तर में फासीवादी सैनिक सांगठनिक दमन अभियान–सलवा जुडुम के साथ ही 2005 से शुरु हुआ. यहां यह बताना वाजिब होगा कि तत्कालीन बस्तर एसपी ने अपने सभी मातहतों को यह वायरलेस संदेश भिजवाया था कि अंदरूनी इलाकों में रिपोर्टिंग करने के लिए कोई भी पत्रकार जाता है तो उन्हें गोली मार दी जाए. बाद के समय में कमलेश पैकरा एवं हिंद सत्ता अखबार के संपादक को प्रताड़ित किया गया था. इस बात से सभी वाकिफ हैं कि विख्यात लेखिका अरुंधति राय ने 2010 में जब बस्तर का दौरा करके आउट लुक पत्रिका में 'वाल्किंग विद कॉमरेड्स' लेख प्रकाशित किया, छत्तीसगढ़ के कई थानों में उन पर झूठे केस दर्ज किये गये.

विगत पांच सालों से जगदलपुर में रहकर पत्रकारिता करने वाली मालिनी सुब्रह्मण्यम को बस्तर छोड़ने विवश कर दिया गया है. सलवा जुडुम–2 का शहरी संस्करण, पुलिस का पालतू संगठन सामाजिक एकता मंच के गुण्डों द्वारा उनके घर पर हमला किया गया था और उनके खिलाफ नारेबाजी, गाली–गलौच की गयी थी. उनके मकान मालिक पर दबाव डालकर उन्हें घर खाली करने मजबूर किया गया था.

बीबीसी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान के छत्तीसगढ़ संवाद्दाता आलोक पुतुल के लिए भी बस्तर से रिपोर्टिंग करना मुश्किल हो गया है और पुलिस से अपनी खैरियत का ख्याल रखते हुए बस्तर से जान बचाकर वापस रायपुर जाना पड़ा. कल्लूरी से मिलने के लिए जब उन्होंने एसएमएस

रूर्बन शब्द को अंग्रेजी शब्द रूरल एवं अर्बन के मिश्रण से बनाया गया है (रूरल+अर्बन=रूर्बन). यानी ग्रामीण व शहरी मिश्रण से रूर्बन क्लस्टर्स बनाये जा रहे हैं. कई गांवों की पूंजीवादी लूट के अड्डों के रूप में ये क्लस्टर्स विकसित होंगे. गांवों की रूपरेखा तो बदल नहीं जयेगी. लेकिन अंदरूनी गांवों सहित समस्त गांवों की लूट संभव हो जायेगी. इसका सीधा मतलब है, देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों व देश के जमींदार वर्ग की लूट, उनकी व्यावसायिक व व्यापारिक जरूरतों के मुताबिक ग्रामीण भारत में बदलाव करना. आदिवासी बहुल वन इलाकों सहित पूरे देश को विश्व बाजार से जोड़ना. सतही तौर पर देखने से यह अच्छा ही लगेगा. विकास जैसा ही दिखेगा. इसे शहरीकरण या पूंजीवादी विकास के रूप में भी प्रचारित किया जायेगा. वास्तव में यह विकृत शहरीकरण ही है. लाखों गांव मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझते रहेंगे. दूसरी ओर इने–गिने कस्बें शहरों का शक्ल अख्तियार करेंगे. इनके विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज घोषित किये जा रहे हैं. यहां प्रस्तावित विकास योजनाओं के अमल के लिए आस–पास के किसानों की जमीनों को अधिग्रहित किया जायेगा. ❍

के माध्यम से समय मांगा तो उन्हें कल्लूरी से धमकी भरा जवाब मिला. कल्लूरी ने लिखा कि उनके पास बाहर के पत्रकारों से मिलने का समय नहीं है. वे तो ऐसे देशभक्त पत्रकारों से ही मिलेंगे जो उनके द्वारा जारी प्रेस रिलीज को छापते हैं. बीबीसी के वात्सल्य राय से फोन पर बस्तर के आईजी कल्लूरी की बातचीत से यह तो जाहिर हो ही गया है कि बस्तर में शासन–प्रशासन किस तरह की पत्रकारिता चाहता है और किस तरह के पत्रकारों को बस्तर में रहने देना चाहता है. उनके मुताबिक जो पत्रकार अंदरूनी इलाकों में जाकर लोगों से बातचीत करके रिपोर्टिंग करते हैं और पुलिस स्टोरी को सही तरीके से कव्हर नहीं करते हैं या सवाल उठाते हैं, वे सभी राष्ट्रद्रोही हैं. टेलीफोनिक बातचीत में कल्लूरी ने वात्सल्य राय के सवालों का जवाब देना तो दूर उल्टे उन्हें ही धमकाते हुए गाली–गलौच करने पर उतारु हो गये थे. ऐसे में बस्तर के साधारण पत्रकारों की स्थिति के बारे में आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है.

हाल ही में पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत में राज्य के मुख्यमंत्री रमण सिंह ने कहा कि निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को बस्तर में पूरी आजादी है. इनकी निष्पक्षता को हमें सही अर्थ में समझना चाहिए. यहां उनकी निष्पक्षता का मतलब है कि कोई भी पत्रकार पुलिस और सरकारी स्टोरी को ही कव्हर करें. यानी सशस्त्र बलों के अत्याचारों, झूठी मुठभेड़ों की सच्चाई को सामने लाने की कोशिश जो कोई भी करेंगे वो सरकार की नजर में माओवादी समर्थक या माओवादी बन जायेंगे. 'या तो हमारे साथ, नहीं तो आतंकवाद के साथ', जार्ज बुश की बातें यहां दोहराये जा रहे हैं. 'या तो सरकार के साथ, नहीं तो माओवादियों के साथ'.

बस्तर के चार पत्रकारों की हाल ही में की गयी गिरफ्तारी के परिप्रेक्ष्य में पत्रकारिता एवं पत्रकारों की स्थिति पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट तैयार की. पत्रकारों पर पुलिस के दबाव व दमन को इसने सही रेखांकित किया है. गिल्ड ने मुख्यमंत्री से मिलकर पत्रकारिता एवं पत्रकारों की समस्याओं पर चर्चा भी की. प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी किया है. पत्रकारों पर दर्ज मामलों की जांच करके उचित निर्णय लेने एक उच्च स्तरीय कमेटी के गठन की रमण सिंह ने घोषणा की लेकिन सरकारी अधिकारियों की कमेटी से कुछ खास उम्मीद नहीं की जा सकती है.

हाल ही में दंतेवाडा के पत्रकारों ने अपनी बैठक में सरकार और माओवादी दोनों के कव्हरेज का बहिष्कार करने का निर्णय लिया जो कि कतई सही नहीं है. समस्या के हल का यह पलायनवादी तरीका है. गलत के खिलाफ डटकर मुकाबला करना चाहिए. यहां इस बात पर गौर करना चाहिए कि अक्सर मीडिया में यह कहा जाता है कि पत्रकार दो पाटों–पुलिस और माओवादियों के बीच पिस रहे हैं. समस्या को देखने व समझने का यह सही नजरिया नहीं है. माओवादी पार्टी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पत्रकारिता की स्वतंत्रता की वकालत करती है. पत्रकारों को चाहिए कि वे सच्चाई को सामने लाएं. सरकारें शोषक–शासक वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं. दमनकारी राज्य यंत्र जिसका मुख्य अंग हैं–पुलिस, अर्ध–सैनिक बल, सेना, कोर्ट, जेल के सहारे अपने शोषण व शासन को बनाये व बचाये रखने की कोशिश करते हैं. खिलाफ लड़ने वाले का दमन करते हैं. इसीलिए पत्रकारिता में शोषण विरोधी, दमन विरोधी, जनपक्षधरता का नजरिया होना चाहिए. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) पत्रकारों के बस्तर में ही नहीं, तमाम संघर्ष इलाकों में स्वेच्छा से काम करने के लिए जरूरी अनुकूल परिस्थितियां जितना संभव हो मुहैया कराने की कोशिश कर रही है. अंदरूनी इलाकों में जो वस्तुस्थिति है, उसे देश, दुनिया के सामने लाने पत्रकारों को संघर्ष इलाकों का दौरा करने बुला रही है. विगत में पत्रकार नेमीचंद जैन एवं साई रेड्डी के मामले में जो चूक हुई थी, उन मामलों को लेकर कुछ बुद्धिजीवी जाने अनजाने में इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं और हमेश इसी बात को दोहराते हैं कि बस्तर में पत्रकारिता को सरकार और माओवादी दोनों से खतरा है. यानी बस्तर के पत्रकार दोनों के बीच पिस रहे हैं. यह अवधारणा सत्य से परे है और लोगों को भटकाने वाली है. क्यों कि उपरोक्त दोनों पत्रकारों पर कार्रवाई उनकी पत्रकारिता को लेकर यानी उनके माओवादी विरोधी कव्हरेज या लेखों या समाचारों के चलते नहीं की गयी है. पुलिस मुखबिरी के शक में कार्रवाई की गयी थी. हालांकि इस बात से सभी वाकिफ हैं कि उक्त दोनों मामलों की गहराई से समीक्षा की गयी, जरूरी सबक लिया गया और सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी गयी थी. माओवादी पार्टी पत्रकार ही नहीं, साधारण जनता से भी उसके कामकाज की रचनात्मक आलोचना का हमेशा आह्वान व स्वागत करती है.

आगे दमन और बढ़ेगा. हाल ही में सरकार ने हवाई फायरिंग व बमबारी का निर्णय लिया है. इससे बड़े पैमाने पर तबाही मचेगी. बढ़े पैमाने पर मूलवासी जनता, प्राचीनतम जनजातियों का हनन होगा. ऐसे में बस्तर के एवं देश, विदेशों के पत्रकारों की जिम्मेदारी भी और बढ़ेगी. पुलिस, अर्ध–सैनिक बलों व सैन्य बलों से खतरे भी बढ़ेंगे. दमन का मुकाबला करते हुए ही पत्रकारों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए. जनपक्षधरता को कायम रखना चाहिए. बस्तर में मानवाधिकारों के हनन व पत्रकारों के ऊपर जारी राज्य दमन के खिलाफ देश भर से आवाज उठनी चाहिए. विरोध दर्ज होना चाहिए. देश, विदेश के पत्रकार संगठनों को इस मामले में आगे आना होगा. ❍

ग्राम सभा की अनुमति के बिना दे दी लौह खदान सरपंचों ने कंपनी से की दस्तावेज दिखाने की मांग

(देशबंधु से साभार यह लेख छोटे डोंगर से लौटकर देशबंधु संवाद्दाता देवशरण तिवारी द्वारा लिखा गया है. दण्डकारण्य के संसाधनों को दलाल पूंजीपतियों के हवाले करने के शासन–प्रशासन की नाजायज कोशिशों को यह बखूबी दर्शाता है. प्रभात के पाठकों के अवलोकन के लिए इसे यथावत प्रकाशित किया जा रहा है.)

नारायणपुर जिले के छोटेडोंगर तहसील की आमदई पहाड़ी में जायसवाल नीको लिमिटेड रायपुर को लौह अयस्क के उत्खनन हेतु माईनिंग लीज प्रदान की गई है। 192.25 हेक्टयर में उत्खनन का विरोध यहां के ग्रामीण कर रहे हैं। नक्सलियों द्वारा भी समय–समय पर खदान में कार्यरत वाहनों को जलाकर, बयान जारी कर इसका विरोध किया जा रहा है।

वर्तमान में इस पहाड़ी पर खड़े करीब 900 सागौन वृक्षों को काटा जा रहा है और यह लकड़ी नारायणपुर स्थित वनमंडल डिपो ले जाया जा रहा है। दो बार यहां हुई नक्सली वारदातों के बाद इस पहाड़ी के पास आईटीबीपी की एक बटालियन तैनात की गई है। आईटीबीपी की सुरक्षा के बीच फिर से काम शुरू किया गया है। गुरूवार को इस पहाड़ी से जुड़े तीन पंचायतों के प्रतिनिधियों ने कंपनी के लोगों से कटाई का काम रोकने कहा और पंचायतों द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र दिखाने की मांग की। इस घटना से नाराज छोटे डोंगर के थाना प्रभारी रोहित मालेकर ने वन सुरक्षा समिति के मजदूरों को एसपी और कलेक्टर नारायणपुर के पास शिकायत दर्ज कराने को भेजा. शिकायत में कहा गया है कि पंचायत प्रतिनिधि खदान में काम करने वालों के राशन कार्ड जब्त करने की धमकी दे रहे हैं. इधर नीको जायसवाल लिमिटेड पर फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र और फर्जी ग्रामसभा के दस्तावेजों के आधार पर माईनिंग लीज प्राप्त करने का आरोप लगाने वाले सरपंचों और अन्य पदाधिकारियों ने थानेदार पर यह अरोप लगाया है कि वे इस माईनिंग कंपनी की तरफदारी कर रहे हैं।

थानेदार ने दी ग्रामीणों को धमकी

इधर छोटे डोंगर थाना प्रभारी रोहित मालेकर द्वारा खदान में वृक्षों की कटाई कर रहे 40–50 ग्रामीणों को शिकायत करने उकसाया गया और एसपी के समक्ष जा कर शिकायत करने दबाव डाला गया। दूसरे दिन इन मजदूरों से यह झूठी शिकायत करवाई गई की सरपंचों द्वारा उन्हें धमकाया जा रहा है कि नीको जायसवाल की खदान में जो भी मजदूर काम करेगा उसका राशन कार्ड जब्त कर लिया जायेगा। साथ ही थानेदार द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों को भी धमकी दी गई है कि यदि यहां किसी पत्रकार को बुलाया तो सभी को नक्सली समर्थक मानते हुए गिरफ्तार कर लिया जायेगा।

पिछले 20 सालों में नहीं हुई कोई ग्राम सभाः सरपंच

छोटे डोंगर के सरपंच सुमन पात्र ने देशबंधु को बताया कि इस पंचायत में बीते 20 सालों में लौह अयस्क उत्खनन के लिये नीको जायसवाल के या राज्य शासन के पक्ष में कोई भी ग्राम सभा आयोजित नहीं की गई। फिर किस आधार पर केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा नीको जायसवाल को यह पूरा पहाड़ लीज पर दे दिया गया है। गत एक मई को आसपास की पंद्रह पंचायतों के करीब पंद्रह हजार ग्रामीणों ने नारायणपुर में रैली निकालकर इस खदान का विरोध किया था। इस दिन राज्यपाल के नाम कलेक्टर नारायणपुर को ज्ञापन भी सौंपा गया था और पंचायती राज अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के उल्लंघन की शिकायत की थी। उसके बाद भी ग्रामीणों की बातों को अनसुना कर दिया गया था।

नीको के लिये तैनात की गई फोर्सः सरपंच, धनोरा

धनोरा की सरपंच सरिता मरकाम ने कहा कि पंचायतों को जानकारी ही नहीं है कि कब यह पूरा पहाड़ नीको को सौंप दिया गया। इस पहाड़ के नीचे एक ऐतिहासिक शिव मंदिर है जिसके जीर्णोद्धार की मांग को शासन प्रशासन द्वारा वन अधिनियम का हवाला देते हुए रोक दिया गया। सिर्फ पचास वर्ग फुट भूमि धार्मिक प्रायोजन के लिये देने मना कर दिया गया, जबकि इसमें तीनों पंचायतों की सहमती थी। फिर सभी की सहमती के बगैर नीको जायसवाल को 200 हेक्टर का इतना बड़ा पहाड़ कैसे दे दिया गया।

प्रशासन ने बात नहीं मानी तो जनहित याचिकाः सरपंच राजपुर

ग्राम पंचायत राजपुर की सरपंच श्रीमती एमपी बाई समरथ ने कहा कि यहां पंचायती राज कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। इस पहाड़ी का क्षेत्र तीनों पंचायतों से जुड़ा हुआ है। किसी एक पंचायत से भी अनुमति ली गई होती तो शासन का यह कदम उन्हें स्वीकार्य था, लेकिन तीनों पंचायतों से अनुमति लिये बगैर अरबों रूपयों की यह संपत्ति निजी कंपनी को सौंप दिया जाना गंभीर मुद्दा है। अगर शासन ने बात नहीं सुनी तो हाईकोर्ट में याचिका लगाई जाएगी।

विरोध करने पर पुलिस ने नक्सली बनाने की दी धमकीः उप सरपंच

ग्राम पंचायत राजपुर के उपसरपंच रामजी दोदी ने कहा कि यहां कानून की बात करना भी एक बड़ा गुनाह है। उन्होंने कहा कि खदान के ठीक सामने बीएसएफ का कैम्प बनाया गया है। यह कैम्प नीको जायसवाल की इस खदान की सुरक्षा के लिये बनाया गया है। यहां के पुलिस अधिकारी उन्हें धमकाते हैं कि इस खदान का विरोध मत करो। विरोध

आह्वान

विस्थापन के विरोध में मई माह भर विरोध–प्रतिरोध तेज करो!

4–5 मई, 2016 को दण्डकारण्य बंद को सफल बनाओ!

दण्डकारण्य के विस्थापन की समस्या की ओर देश, दुनिया की नजर व ध्यान आकृष्ट करने, जनता के जल–जंगल–जमीन व संसाधनों को बचाने, आदिवासियों के अस्तित्व, अस्मिता व आत्मसम्मान को बचाये रखने, पर्यावरण के विनाश को रोकने के लिए मई माह भर विरोध–प्रतिरोध तेज करो. 4–5 मई को दंडकारण्य बंद को सफल बनाओ.

इस विरोध–प्रतिरोध के दौरान छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र की विस्थापन संबंधी विनाशकारी परियोजनाओं–बड़ी खनन परियोजनाओं, बड़े बांधों, बड़े कारखानों, पाइप लाइन, वायु सैनिक अड्डों, सैन्य प्रशिक्षण शालाओं, नेशनल पार्कों, रेल लाइनों आदि के विरोध में सभा–सम्मेलनों, संगोष्ठियों, धरना, प्रदर्शन, जुलूसों को आयोजन करें. देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों की विनाशकारी परियोजनाओं को बंद कराने, उनके उपयोग में आने वाले सार्वजनिक उपक्रमों को बंद कराने प्रतिरोध कार्रवाइयों को अंजाम दें.

इन तमाम परियोजनाओं से देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों जापान स्टील मिल्स, चीन व कोरिया की कंपनियां, वेदांता, डीबियर्स, बीएचपी बिलिटन, रियो टेंटो, अमेरिका की टीपीजी, टाटा, एस्सार, लायड़, आर्सेलर मित्तल, जिंदल, नीको जायसवाल, रायपुर एलायज, गोदावरी इस्पात, पुष्पा स्टील्स, बजरंग इस्पात लिमिटेड्, हरी मिनरल्स, महींद्रा स्पंज एवं पवर लिमिटेड, मां बम्लेश्वरी माइंस एंड इस्पात लिमिटेड, प्रकाश इंडस्टीज, वंदना एनर्जी, आग्रो सिनेर्जी, कुसुम मिनरल्स, मोनेट इस्पात आदि का ही विकास होगा और हो रहा है. बाहरी उच्च व उच्च मध्यम वर्ग के छोटे से तबके को नौकरियां मिलेंगी.

इन तमाम परियोजनाओं के शुरु हो जाने से आदिवासी बहुल दण्डकारण्य की आदिवासी व गैर आदिवासी मूल जातियों की दसियों हजार जनता को खदेड़ा जायेगा, उनका सफाया किया जायेगा. खासकर बड़े पैमाने पर आदिवासी हनन होगा. दसियों हजार एकड़ की कृषि जमीन और जंगल नष्ट हो जायेगा. नदियां बुरी तरह प्रदूषित हो जायेंगी. जल–वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण कुल मिलाकर पर्यावरण की भारी क्षति होगी. मानसूनी बारिश कम हो जायेगी. सूखा व अकाल की स्थिति निर्मित होगी. प्राचीनतम जनजातियों की जीवन शैली, संस्कृति, उनका अस्तित्व सब कुछ ही मिट जायेगा. सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के अधिक मुनाफे के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन होगा. भावी पीढ़ियों के लिए संसाधन नहीं बचेंगे.

आईए! दण्डकारण्य के विस्थापन विरोधी जन आन्दोलनों के समर्थन में, जनताना सरकारों के असली व जनपक्षधर विकास नमूने को बचाने कदम बढ़ायेंगे! ❍

करोगे तो तुम्हें नक्सलियों का समर्थक मानते हुए गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

पूर्वजों की धार्मिक आस्था का मामला है: अध्यक्ष, सर्व आदिवासी समाज

सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष बेदराम पात्र ने कहा कि यह 84 परगना का मुख्य धार्मिक स्थल है। आदिवासी समुदाय के तमाम धार्मिक क्रिया कलापों का यह पहाड़ केंद्र रहा है। यहां प्राचीन शिव मंदिर है और बगल में माड़िन नदी बहती है जो डोंगर वासियों की प्राणदायिनी है। इन सब महत्वपूर्ण तथ्यों को दरकिनार करते हुए बेशकीमती सागौन के जंगल से भरे इस पहाड़ के विनाश के लिए हम लोग किसी भी कीमत पर अपनी सहमती नहीं दे सकते। इस कंपनी द्वारा फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र देकर खदान स्वीकृत करवाई गई है।

अनमोल जड़ी बूटियों का खजाना है, आमदई पहाड़: बैद्यराज

कैंसर और एड्स जैसी लाईलाज बीमारियों का जड़ी बूटियों से इलाज करने वाले बैद्यराज भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि तमाम जटिल बीमारियों के लिये इस आमदई पहाड़ की ही जड़ी बूटियां उनके द्वारा इस्तेमाल की जाती है। इस पहाड़ से कई लोगों की जान उन्होंने बचाई है। उन्होंने कहा कि उनके पूर्वज राजा दलपत देव के जमाने से यहां निवास कर रहे हैं और इस पहाड़ी का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। मैंने कभी भी इस खदान के लिये ग्राम सभा आयोजित होते नहीं देखा और ना ही पूर्व के सरपंचों ने इस पहाड़ को लोहा खदान बनाने कभी सहमति दी है। हम इस खदान का विरोध करते हैं और करते रहेंगे।

ग्राम सभा के बिना नहीं मिल सकती अनुमतिः क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी

बस्तर के प्रभारी क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी हरीश तिवारी का कहना है कि ग्राम सभा की अनुमति के बगैर किसी भी सूरत में पर्यावरण विभाग की स्वीकृति नहीं दी जा सकती। अगर पंचायत प्रतिनिधियों को संदेह है तो वे शासन के पास जमा दस्तावेजों की असलियत जांच सकते हैं।

वन अधिनियम का किया गया पालनः वन मंडलाधिकारी

नारायणपुर वनमंडल के वनमंडलाधिकारी श्री पैकरा ने कहा कि ग्राम सभा की अनुमति के बाद ही वन विभाग आगे की कार्यवाही करता है। पंचायतों को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। इस मामले में वन अधिनियम का पालन किया गया है कोई भी कार्य नियम विरूद्ध नहीं किया गया है. ❍

साम्राज्यवादियों के युद्धोन्माद का अनिवार्य नतीजा है,
शरणार्थी समस्या

हाल के समय में शरणार्थी समस्या को लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है और चिंता जाहिर हो रही है. इसे शरणार्थी संकट भी कहा जा रहा है. युरोप में गंभीर बनी इस समस्या का उल्लेख प्रवासी या पलायन व शरणार्थी समस्या के रूप में किया जा रहा है. हमें इस सच्चाई को पहले समझना होगा कि इन दोनों समस्याओं की असली जड़ें साम्राज्यवादी व्यवस्था में ही मौजूद हैं. प्रवासी व शरणार्थी, दोनों ही शब्दों के अपने स्वभाव अनुसार ठोस अर्थ हैं. साधारणतया आजीविका की तलाश में, आर्थिक जरूरतों के लिए अन्य इलाकों, देश–विदेशों में मेहनतकश जनता पलायन कर जाते हैं. पूंजीपति मुनाफे की चाहत में व्यापारिक प्रवास पर दूसरे इलाकों व देशों में जाते हैं. सरकारें इनमें फर्क किये बगैर सभी को एक समान देखती हैं. हमारे देश में इन्हें प्रवासी भारतीय कहते हैं. लेकिन वर्तमान शरणार्थी समस्या इससे पूरी तरह भिन्न है. शरणार्थी यानी ठोस रूप से युद्ध पीड़ित ही हैं. इन्हें 1951 में आयोजित शरणार्थी सम्मेलन ने असिलम सीकर्स–शरणार्थी कहा है. इसके मुताबिक आक्रमणकारी युद्धों अथवा गृह युद्धों की वजह से अपने देशों में जीवनयापन करने की स्थिति के अभाव में, लाचारी में शरण मांगते हुए दूसरे देशों में जाने वाली जनता को शरणार्थी कहा जाता है.

जिंदगी की तलाश में सरहदों को मिटाते शरणार्थी

इतिहास के पन्नों से हमें यह ज्ञात होता है कि अमेरिकी साम्राज्यवाद एवं उसके पिट्ठुओं का मुकाबला करते हुए वियत्नाम, फिलिस्तीन, इराक आदि देशों में जो लड़ाइयां हुई, उनमें शरणार्थियों की संख्या लाखों में थी. कंपुचिया पर वियत्नाम के हमले के समय के पलायन के बारे में तो अलग से बताने की जरूरत ही नहीं है. सोवियत सामाजिक साम्राज्यवाद एवं अमेरिकी साम्राज्यवाद के बीच के अंतर्विरोध–संघर्ष व सांठगांठ के चलते जो युद्ध हुए हैं, अफ्गानिस्तान, लिबिया, इराक से लेकर आज के सीरिया तक के तमाम युद्धों में शरणार्थियों की समस्या हमेशा से रही और इस सवाल के साथ कि इस समस्या का हल क्या है, वह युरोप को उतल–पुतल कर रही है. आस–पड़ोस के देशों को भी झकझोर रही है.

यूरोप का शरणार्थी संकट दरअसल मध्यपूर्व में अमेरिका एवं यूरोप की दशकों की विदेशनीति की परिणति है. वर्तमान शरणार्थी समस्या को 2011 में प्रारंभ राजनीतिक विद्रोहों से उत्पन्न समस्या के रूप में देखा जा रहा है. अरब वसंत कहलाने वाले इन राजनीतिक विद्रोहों ने पहले तुनीशिया में शुरु होकर समूची अरब दुनिया, करीबन 22 देशों को हिला कर रख दिया है. पश्चिम एशिया, उत्तरी आफ्रिका के इलाके विगत पांच सालों से रावण की चिता समान जल रहे हैं. इसके फलस्वरूप हजारों तुनीशियायी इटली की शरण में गये हैं. सब–सहारा आफ्रिका से विगत में जो लोग लिबिया गये थे, वे कर्नल गद्दाफी के बाद के समय में यानी 2011–12 के दौरान शरणार्थी बनकर इटली पहुंच गये हैं. इस तरह वर्तमान परिस्थितियों में युरोप पहुंचने वाले शरणार्थियों में मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया, आफ्रिका महाद्वीपों के ही लोग हैं. खासकर सीरिया, सूडान, पाकिस्तान, नाइजीरिया, इराक, ईरान, डार्फर, सोमालिया, अफ्गानिस्तान, एरित्रिया, घना आदि देशों की जनता है. इनमें से अधिकांश सीरियावासी हैं जो पिछले साढ़े चार सालों से सैनिक हमलों के शिकार थे.

शरणार्थी समस्या का असली कारण है, साम्राज्यवाद

आज शरणार्थी समस्या का मतलब है, युद्ध पीड़ितों की समस्या. युद्धों की वजह से ही यह समस्या उत्पन्न हो गयी है. युद्ध की जड़ है, साम्राज्यवाद. दूसरे विश्व युद्ध के बाद के समय में इस कदर व्यापक जन समुदायों का शरणार्थी बनकर जाने व साम्राज्यवादी देशों द्वारा अत्यधिक मुनाफे की चाहत में किये जाने वाले आक्रमणकारी युद्धों व अप्रत्यक्ष युद्धों के बीच सीधा संबंध है. लंबे अरसे से विभिन्न देशों में जारी युद्धों व साम्राज्यवादियों के अंतहीन आर्थिक व वित्तीय संकट के बीच सीधा संबंध है. युद्धों व साम्राज्यवादियों के व्यापार के बीच प्रत्यक्ष संबंध है. ये सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं. इसीलिए मार्क्सवाद के महान शिक्षक कॉमरेड लेनिन ने सही कहा–'साम्राज्यवाद का मतलब ही युद्ध है.'

उन युद्धों जो साम्राज्यवादी व्यवस्था की देन हैं, को गहराई से व समग्रता से समझने के द्वारा ही 'आतंकवाद पर युद्ध', पलायन की समस्या एवं शरणार्थी समस्या की जड़ों को पकड़ सकते हैं.

वियत्नाम के युद्ध खत्म होने के बाद से मध्य एशिया की समस्या को महत्व दिया गया था. अपने प्रभाववाले इलाकों का विभाजन करते हुए, एक दूसरे को बाधित करते हुए रूस यानी तत्कालीन सोवियत सामाजिक साम्राज्यवाद और अमेरिकी साम्राज्यवाद दोनों प्रतिद्वंद्विता और सांठगांठ में लगे हुए थे. एक छोटा लेकिन ऐसा समाचार जिसे खुलेआम ऐलान नहीं किया गया था, के मुताबिक अमेरिका के अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन जब 1972 में मास्को का दौरा किया था, सोवियत संशोधनवादियों के साथ एक गुप्त समझौता किया था. उसके अनुसार रूस के व्यापार के अनुकूल किये गये एक समझौते के बदले में रूस हर साल 36 हजार यहूदियों को इज्रायल भेजने सहमत हो गयी. अमेरिका इज्रायल को सैनिक सामग्री की आपूर्ति करेगा जबकि अरब देशों पर युद्ध के लिए आवश्यक मानव शक्ति को रूस मुहैया करेगा. इससे जाहिर है, अमेरिका और रूस के बीच की होड़ में अरब देश छिन्न–भिन्न होते आये हैं. वे एक न हो सके. इज्रायल का मुकाबला करने में यह अत्यंत अननुकूल विषय बना रहा. अल्जीरिया, सिरिया, इराक, लिबिया, जोर्डान, लेबनान एक–दूसरे के साथ लड़ते रहे. आपसी अंतर्विरोध बढ़ा रहे थे. मध्य एशिया के तेल भंडार वाले दो प्रमुख देशों–ईरान व साउदी अरब को कब्जे में लेने हमेशा अमेरिका प्रयासरत रहा. समकालीन दुनिया की जरूरतों में तेल व प्राकृतिक गैस के महत्व के मद्देनजर तब से जारी युद्ध ही शरणार्थी समस्या के तीव्र होने के प्रधान कारण हैं.

पश्चिम व मध्य एशिया के देश जहां से लाखों शरणार्थियों की बाड़ जारी है, युद्ध के केंद्र क्यों बने हुए हैं?

ये देश कच्चे तेल के अकूत भंडार हैं. दुनिया पर प्रभुत्व पाने के लिए प्रयासरत साम्राज्यवादियों के लिए तेल पर कब्जा हासिल करना अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है. इसीलिए इन देशों को अपने अधीन रखने के लिए साम्राज्यवादी देश प्रारंभ से ही कोशिश में लगे हैं. उसके तहत ब्रिटेन, फ्रांस, इटली आदि साम्राज्यवादी देशों ने इन देशों को विगत में अपने उपनिवेश बनाये. 50, 60 के दशकों में इन देशों में उपनिवेशवाद के खिलाफ महान संघर्ष हुए. 1848 तक सिरिया, लेबनान, जोर्डान स्वतंत्र हो गये थे. उसके बाद भी कई देश साम्राज्यवाद के शिकंजे से मुक्त हो गये. तमाम अरब देशों की जनता साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष की महान विरासत से लैस हैं. इस तरह उठी साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षों की लहर को देख ब्रिटेन और अमेरिका ने तेल भंडारों पर अपने प्रभुत्व को कायम रखने के लिए षड्यंत्रपूर्वक फिलिस्तीन को विभाजित करके 1948 में इज्रायल को विश्व पटल पर अस्तित्व में लाये. तब से अमेरिका इज्रायल को सामने रखकर अरब देशों पर आक्रमणकारी युद्ध लड़ता आया है. कुछ देशों में विद्रोहों को हवा देते हुए, कई देशों के आपसी झगड़ों को इस्तेमाल करते हुए अरब देशों के आंतरिक मामलों में अमेरिका का हस्तक्षेप जारी रहा. इस तरह वह साउदी अरब जैसे देशों को अपने वश में कर लिया. अमेरिका के प्रोत्साहन से यमन पर साउदी अरब द्वारा जारी भयानक हमलों की वजह से एक लाख सत्तर हजार बच्चे पौष्टिक आहार के अभाव में कुपोषण के शिकार होकर मौत से झूझ रहे हैं. इराक, अफ्गानिस्तान में यह संख्या लाखों में है. आक्रमणकारी युद्ध के जरिए वह अफ्गानिस्तान, इराक जैसे देशों में अपनी पिट्ठु सरकारों का गठन किया. सीरिया, लेबनान, इरान जैसे देश उससे झूझते आये हैं. सीरिया के तानाशाह बशर अल असद के शासन के खिलाफ उस देश में उभरे आन्दोलन का फायदा उठाते हुए अमेरिका ने वहां हवाई हमला शुरु किया. नतीजतन विगत पांच सालों से सीरिया युद्ध में डूबा हुआ है. इराक व सीरिया पर इस्लामिक राज्य–आईएसआईएस विरोधी मोर्चे के नाम पर अमेरिका की छत्रछाया में 65 देश 2014 से हमलें कर रहे हैं. विगत सितंबर माह से रूस भी आईएस के आतंक को खत्म करने के नाम पर असद सरकार के समर्थन में विरोधी गुटों पर बमबारी शुरु की. इससे 2015 की आखिरी से युद्ध का स्वभाव ही बदल गया है. अमेरिका ने सीरिया के आईएस प्रभुत्व वाले तेल कुओं पर नवंबर में अत्यधिक हमलें किये. रूस ने कोस्तल लताकी एअर बेस पर अपने वायु सेना को तैनात किया. तुर्की–रूस के बीच के अंतर्विरोध का संबंध कुर्दिस्तान–सीरिया के साथ जुड़ा हुआ है. तर्क, वितर्क जो भी हों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार एक बड़े देश के सैन्य विमान को तुर्की जैसे पड़ोसी देश जो नाटो के सहभागी देश है, ने गिरा दिया. यह तेल हितों से जुड़ा हुआ मामला है. अमेरिका ने तो यहा घोषणा की कि उसने आईएस के 40 प्रतिशत से ज्यादा तेल कुओं को नष्ट कर दिया है. उन्होंने कहा कि उनके एक–एक कमांडो आईएस के एक–एक बेस को ध्वस्त करेंगे.

आईएस के आतंक का विरोध करने के नाम पर अमेरिका एवं रूस द्वारा सीरिया पर जारी युद्ध का भारत भी समर्थन कर रहा है. ब्रिटिश संसद ने सर्वसम्मति से अपनी सरकार को सीरिया पर हमले की अनुमति दे दी. इसके बाद दिसंबर 3 से उसने वायु सैनिक बलों द्वारा हमले शुरु किये. पेरिस हमलों के बहाने फ्रांस ने भी हमले शुरु किये. संसद की अनुमति पाकर जर्मनी दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार अपने वायु सैनिक दस्ते को सीरिया विरोधी युद्ध

क्षेत्र में इंटेलिजेन्स के लिए भेजा. तुर्की ने इराकी सरहदों से तोपों का इस्तेमाल करने के लिए भेजा तो इराक ने यह कहते हुए विरोध दर्ज कराया कि वह उसकी संप्रभुता के लिए धक्का है. चीन ने इंटरनेशनल रोड़ मैप का अनुमोदन देकर सीरिया पर हमलों को अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सहमति दी.

अफ्गानिस्तान व इराक जहां अमेरिका की पिट्ठू सरकारें बनी, में युद्ध खत्म नहीं हुए हैं. नाटो देशों के बल, अमेरिकी बल, अफ्गानिस्तान की सेना व पुलिस अत्याधुनिक हथियारों, वैमानिक व ड्रोन हमलों के साथ 30 हजार तालिबानों के साथ भिड़ रहे हैं. दिन–ब–दिन तालिबान ही मजबूत हो रहे हैं. अमेरिका अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पा रहा है. उसी तरह इराक, सीरिया में मौजूद आईएस के 35 हजार बल अमेरिकी गठबंधन के साम्राज्यवादी देशों पर अविराम आत्मघाती बम हमलों द्वारा नयी चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं.

दरअसल 20 वीं सदी के आखिरी तीन दशकों के दौरान आक्रमित अफ्गानिस्तान में रूसी साम्राज्यवादी सैनिकों के खिलाफ लड़ने के लिए, विश्व पर अपना प्रभुत्व कायम करने की महत्वाकांक्षा के तहत अमेरिका ने ही तालिबान व अलखायदा का सृजन किया था. सच्चाई तो यही है कि तालिबान, अलखायदा, ओसामा बिन लादेन, आईएस, कांट्रा जैसे संगठन अमेरिका की ही देन हैं. भारत में सीरिया अरब गणराज्य के राजदूत रियाद कामेल अब्बास के अनुसार इस्लामिक स्टेट को पश्चिमी देशों ने जन्म दिया है और सीरियाई संकट के लिए अमेरिका व उसके मित्र देश जिम्मेदार हैं. शरणार्थी संकट पश्चिम के ही षड्यंत्रों का परिणाम है. पश्चिमी देश इस्लामिक स्टेट के खिलाफ युद्ध को सीरिया की वर्तमान सरकार को अस्थिर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. सीरिया में शरणार्थी समस्या पहले से नहीं थी. इस समस्या की जड़ में साउदी अरब, तुर्की, कतर हैं जिनके द्वारा भेजी गयी आइएस की सेनाओं के लिए तुर्की ने सीरिया से लगी अपनी सीमाओं को खोल दिया है. आइएस को पश्चिम से अनुदान मिलते हैं. तुर्की आइएस से कच्चे तेल का व्यापार करता है. दूसरी ओर तालिबान, अलखायदा, आइएस को आज अमेरिका उग्रवादी के रूप में बड़े पैमाने पर प्रचारित कर रहा है और उसी को उसने दुनिया के देशों के एजेण्डे में तब्दील कर दिया है.

2011–15 के बीच अमेरिका साउदी अरब को सबसे ज्यादा भारी हथियार बेचकर 80 बिलियन डॉलर यानी 5 लाख 20 हजार करोड़ रुपये, मुनाफा कमाया. साम्राज्यवादी देश एक ओर देशों के बीच युद्ध भड़काते हुए उन्हें अपने वश में करते हैं और दूसरी ओर युद्धरत देशों को हथियार बेचकर मुनाफा कमाते हैं. उपरोक्त देशों में 'उग्रवादी' ताकतों को कुचलने के नाम पर जिस बर्बर हत्याकांड को अंजाम दे रहा है उसके लिए एवं दुनिया भर में 'आतंकवाद पर युद्ध' के लिए अमेरिका प्रति घंटा 8.36 मिलियन डॉलर यानी 75 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है. विगत 13 सालों में उसने कुल 1.60 ट्रिलियन (एक ट्रिलियन बराबर एक लाख करोड़ और एक डॉलर बराबर 65 रुपये हैं) डॉलर खर्च किया. चूंकि अमेरिका युद्ध पर इतनी भारी राशि खर्च कर रहा है, इसलिए वह अभूतपूर्व आर्थिक संकट में फंस गया है. 2008 में फूटा वह संकट समूची दुनिया को उथल–पुथल कर दिया. उस संकट का धक्का ही था जिसने अरब दुनिया को हिलाकर रख दिया. सरकारों के परिवर्तन के लिए जारी जन आन्दोलनों का दौर जिसे अरब वसंत के रूप में जाना जाता है, उसी का नतीजा है. उतना ही नहीं, उस संकट ने युरोप के ग्रीस, स्पेन जैसे देशों को अंतहीन ऋण संकट में धकेल दिया. ग्रीस अब भी उस कर्ज के दलदल से बाहर निकलने को छटपटा रहा है. जैसे सिर मुंडाते ही ओले पड़े, अब युरोप में शरणार्थी समस्या का गाज ग्रीस पर ही प्रमुख रूप से गिरा. पश्चिम ने जिस शरणार्थी समस्या सीरिया में खड़ी की वह अब उनकी ओर बढ़ रही है.

शरणार्थी समस्या–युरोप

युरोप में शरणार्थियों की बाढ़ सी आ रही है. इससे वहां कई समस्याएं सामने आ रही हैं. उनमें प्रधान व जटिल है, युरोप का कौन देश कितने शरणार्थियों को व्यवस्थापित करे. इस समस्या के हल के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न देश मिलकर बैठकें आयोजित कर रहे हैं. कुछ तात्कालिक निर्णय ले रहे हैं. लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं कर पा रहे हैं. न ही कर सकते हैं. शरणार्थियों के मामले में 2003 में संशोधित डुब्लिन रेगुलेशन के मुताबिक प्रवासी माइग्रेंट्स जिस देश में पहले कदम रखते हैं, उस पहले देश को ही उन शराणार्थियों की यूनिलेटरल रेस्पॉन्सिबिलिटी – एकपक्षीय जिम्मेदारी लेनी चाहिए. ईयू–यूरोपियन यूनियन के कानूनों के मुताबिक शरण मांगने वालों को उसी देश में रहना होगा जिसमें वे पहले कदम रखते हैं. उनके शरणार्थी आवेदनों का उसी देश को अवलोकन करना चाहिए. यदि वे किसी और देश जाते हैं, तब भी उन्हें पहले देश में वापस भेज दिया जायेगा.

ईयू के सदस्य देशों के बीच कोई सीमा नहीं है. ईयू बॉर्डर फ्री जोन है. यानी एक देश के लोगों को दूसरे देश में जाना हो तो कोई वीजा की जरूरत नहीं होती है. विगत 20 सालों से यह अमल में है. ईयू गठबंधन में चूंकि जर्मनी का प्रमुख स्थान है, इसलिए बाकी देशों ने यह स्पष्ट किया कि उस देश की चांसलर एंजेला मार्केल को शरणार्थी समस्या का ज्यादा भार वहन करना चाहिए. लेकिन एंजेला मार्केल उसके लिए कतई तैयार नहीं है. मार्केल एक तरफ यह कह रही है कि शरणार्थियों का स्वागत करने की ही

नीति पर अमल होगा, साथ ही दूसरी ओर यह भी बोल रही है कि जर्मनी शरणार्थियों की असीमित संख्या का बोझ नहीं उठा सकता है.

अक्टूबर, 2015 में ब्रसेल्स में आयोजित आठ बाल्कन देशों की बैठक में बुल्गेरिया के प्रधान मंत्री बोज्को बोरिसोव ने एंजेला मार्केल से सवाल करते हुए यह स्पष्ट करने कहा कि वह कितने शरणार्थियों को व्यवस्थापित करेंगी. एंजेला मार्केल ने यह कहा कि उनके देश में तब तक शरणार्थियों के 8 लाख आवेदन आ गये हैं. शरणार्थियों की संख्या में बढ़ोत्तरी सीरिया युद्ध पर निर्भर होने की बात भी मार्केल ने कहा. फ्रांस और यूके के पास साढ़े छह लाख के हिसाब से आवेदन आ गये थे. इतनी बड़ी संख्या में शरणार्थियों को व्यवस्थापित करना उन देशों की बस की बात नहीं है, यह कहते हुए मार्केल ने ईयू के बाकी देशों को भी आगे आकर शरणार्थियों की जिम्मेदारी लेने दबाव डाला. यहां यह याद रखना होगा कि यह संख्या नवंबर के पेरिस हमलों के पहले की है. पेरिस हमलों का बहाना करके फ्रांस दूसरे ही दिन से सीरिया पर लगातार बमबारी कर रहा है.

ग्रीस में 50 हजार, मेसिडोनिया, सेर्बिया, क्रोएशिया में 50 हजार लोगों को व्यवस्थापित करने का निर्णय लिया गया है. हालांकि यह तय हुआ कि ग्रीस से एक लाख साठ हजार लोगों को आगामी दो सालों में ईयू के अन्य देशों में भेजने का भी निर्णय लिया गया है लेकिन उन देशों से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं हुई है.

डब्लिन रेगुलेशन के मुताबिक शरणार्थी पहले जिस देश में प्रवेश करते हैं, उसे ही शरणार्थियों का नाम दर्ज करना चाहिए. लेकिन ग्रीस, इटली, क्रोएशिया वैसा न करते हुए शरणार्थियों को उनके देश से दूसरे देशों में जाने की अनुमति दे रहे हैं. ग्रीस प्रधान मंत्री अलेक्सिस सिफ्रास ने यह स्पष्ट किया कि कर्ज में डूबा हुआ उनका देश 50 हजार शरणार्थियों को शरण नहीं दे सकता है. इस स्थिति से निपटने संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थी एजेन्सी के प्रमुख आंटोनियो गुट्टेर्स ने यह राजीनामा प्रस्ताव पेश किया कि ग्रीस में शरणार्थियों को जिन होटलों, अन्य निजी स्थानों में बसायेंगे, उनका किराया युएन वहन करेगा. शरणार्थी ज्यादातर जर्मनी, नार्वे, स्वीडन में शरण लेना चाह रहे हैं.

ज्यादातर शरणार्थियों के लिए प्रवेश द्वार हैं, ग्रीस, इटली. हंगरी, आस्ट्रिया तरफ भी शरणार्थी पार कर रहे हैं. हंगरी से शरणार्थियों के देश में प्रवेश को रोकने सर्बिया ने 175 किलोमीटर की फैन्सिंग अपनी सरहद में लगाया. इस तरह वह शरणार्थियों को क्रोएशिया, स्लोवेनिया की ओर मोड़ दिया. इसके साथ ही वह अपने 'दया गुण' को उजागर करते हुए ईयू देशों से अपील जारी की कि शरणार्थियों को वापस न भेजा जाए. आस्ट्रिया भी स्लोवेनिया की तरफ की सरहद में फेन्सिंग लगाने की बात कही. साथ ही आस्ट्रिया के चांसलर वेर्नर फेमन्न ने यह भी कहा कि शरणार्थियों को बेहतर व युक्तिबद्ध तरीके से नियंत्रित करने के लिए ही फेन्सिंग लगाया जायेगा. युरोपियन कमीशन के अध्यक्ष जीन क्लाडी जंकर ने यह कहा कि ईयू देशों के बीच चूंकि स्वेच्छापूर्वक आने–जाने का समझौता है, इसलिए फेन्सिंग न लगाया जाए, 'युरोप में फेन्सिंग के लिए कोई जगह नहीं है'. इसके बावजूद आर्थिक संकट के पीड़ित ईयू देश अध्यक्ष की बातों की परवाह नहीं कर रहे हैं. दीवारों के ढहाये जाने के जर्मन अनुभव से सबक लेनेवाली मार्केल वैसी राजनीतिक गलती को न दोहराने की बात कह रही है. फिर भी स्लोवेनिया ने यह घोषणा की कि यदि ब्रसेल्स कार्य योजना पर अमल नहीं होता है तो वह क्रोएशिया की सरहदों में फेन्सिंग लगायेगा. शरणार्थी संकट से युरोप देशों के बीच कई नई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं.

शरणार्थियों की मुश्किलें

जान हथेली पर रखकर कई परेशानियों, खतरों, नुकसानों, अनगिनत समस्याओं का सामना करते हुए अरब देशों के शरणार्थी सागरों को पार करते हुए जहां कहीं से भी संभव हो युरोप में प्रवेश कर रहे हैं. साम्राज्यवादियों द्वारा सृजित समस्या एवं उसके साथ ही उत्पन्न होने वाली कई अन्य समस्याओं को उन्हें जबरन झेलना पड़ रहा है. कोई भी अपना घर छोड़ना नहीं चाहता है. अपना देश नहीं छोड़ना चाहता है. शरणार्थियों के इस तरह का पलायन कोई साधारण या सहज बात नहीं है. यह असाधारण स्थिति है. शरणार्थियों की समस्या जीवन–मरण की समस्य है. जान बचाने के लिए वे अपना वतन छोड़ने मजबूर हैं. इस सफर में कइयों को अपनी जान असामयिक गंवानी पड़ रही है.

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी संगठन इंटरनेशनल ऑर्गानाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने कहा कि अत्यंत अशांत मेडिटेर्रेनियन सी पार करना बेहद खतरनाक है. साथ ही शरणार्थियों के लिए पूरे विश्व में सबसे दुर्लभ राह है. फिर भी युद्ध से बचने, जान बचाने, आजीविका की चाह में शरणार्थी इसे पार कर रहे हैं. हजारों तुनीशियायी इटली के लान्सेंडा द्वीप पार किये. कई अन्य युरोपीय देशों की सरहदों में भी समुद्र मार्ग से पहुंच रहे हैं.

महा सागरों का सफर ये शरणार्थी खतरनाक नावों पर कर रहे हैं. विगत साल नाव दुर्घटनाओं में 30 हजार लोग मारे गये. इन नावों में सफर करके युरोप पहुंचने वालों की संख्या 3 लाख से भी ज्यादा थी. दबाव के चलते नाव की क्षमता से दोगुनी संख्या में सफर करते हैं. इससे असंख्य दुर्घटनाएं घट रही हैं. मौसमी प्रतिकूलताओं के चलते भी कई जानें जा रही हैं. ग्रीस व इटली जाने वाले शरणार्थियों में से 2600 नाव दुर्घटना में डूब गये थे.

अगस्त, 2015 में लिबिया के जुवारा से निकले दो नावों के डूब जाने से 500 लोग लापता हो गये हैं. अगस्त में ही आस्ट्रिया में 71 सीरियायी शरणार्थी दुर्घटना में मारे गये. 2015 के प्रारंभ में नाव दुर्घटना में ही 800 शरणार्थियों ने अपनी जानें गंवाईं.

इसी तरह की दुर्घटना के शिकार तीन साल के अलन कुर्दी का शव तुर्की के समुद्री तट पर बहकर आ गया था. रेत में मुंह गढ़ाकर सोने के अंदाज में पड़ी अलन की लाश की तस्वीर ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है. सीरिया के कोबानी शहर के रहवासी अब्दुल्ला अपनी पत्नी रेहान, बेटे पांच व तीन साल के गालिप व अलन कुर्दी सहित देश छोड़ा था. तुर्की आकर वहां से ग्रीस जाने एक नाव पर सवार हुआ था. क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाने के कारण नाव समुद्र में डूब गया था. अब्दुल्ला लाइफ जैकेट के सहारे बच निकला लेकिन बीवी–बच्चों की जल समाधि हो गयी.

इस तरह सफर करने वाले विभिन्न देशों के छोटे–छोटे द्वीपों में पहुंचते हैं. वहां उनकी न्यूनतम जरूरतों की पूर्ति भी नहीं होती है जिससे हजारों शरणार्थियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. लिबिया से इटली पहुंचने का मतलब है, लंबा एवं खतरनाक सफर करना. रास्ते में मानव तस्करों की समस्या गंभीर है. लिबिया की वर्तमान अनिश्चित परिस्थितियां तस्करों को बढ़िया मौका उपलब्ध करा रही हैं. शरणार्थियों को डरा–धमकाकर तस्कर उनसे हजारों डॉलर वसूल रहे हैं.

उपरोक्त समस्याओं के अलावा विभिन्न ईयू देशों में शरणार्थियों को वहां के सरकारी सशस्त्र बलों के साथ भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. हंगरी ने सितंबर, 2015 में एक आपातकालीन कानून बनाया है. उसके अतिक्रमण के नाम पर जुर्माना वसूलना, वापस भेजना, जेल में डालन जारी है. इस तरह सभी देशों में शरणार्थी स्थानीय कानूनों के शिकंजे में फंसकर कई मुसीबतें झेल रहे हैं. नवंबर के पेरिस हमलों के बाद से ये मुसीबतें कई गुना बढ़ गयी हैं.

युद्ध पिपासु साम्राज्यवाद–शरणार्थी समस्या का हल

अमेरिका एक तरफ ईरान, क्यूबा के साथ दोस्ताना रवैया दिखा रहा है जबकि दूसरी ओर उत्तर कोरिया के साथ युद्ध के लिए मैदान सजा रहा है. ईरान के साथ संबंध स्थापित होते ही फ्रांस ने फाइटर जेट विमानों की बिक्री शुरु की. भारत के शासक वर्गों के साथ मित्रवत व्यवहार जारी रखते हुए ही पाकिस्तान को हथियार बेच रहा है. चीन के साथ संबंध जारी रखते हुए ही ताइवान को हथियार बेच रहा है. नवंबर में सीरिया पर बमवर्षा की जबकि बाद में तथाकथित शांति वार्ता के समय रूस ने बमबारी की. तुर्की और रूस के बीच टकराव की स्थिति निर्मित की और कुर्दिस्तान की संघर्षरत संस्था पीकेके पर हमले करवा रहा है. इस तरह के और भी कई उदाहरण दे सकते हैं. इस तरह साम्राज्यवादी ताकतें एक तरफ अपने–अपने सैन्य बलों की एशिया व आफ्रिका में तैनाती कर रहे हैं तो दूसरी ओर अपने उत्पादित हथियारों को खपाने व बेचने युद्धों को संचालित कर रहे हैं. जनता के जान माल के नुकसान की जिम्मेदारी एक दूसरे पर मढ़ रहे हैं और शांति वार्ता की नौटंकी भी कर रहे हैं. साम्राज्यवादियों के इन हथकंडों के चलते एशियाई और आफ्रिकी शरणार्थियों की बाढ़ युरोप को घेर रही है. क्योंकि शरणार्थी युरोप की सरहदों को सुरक्षित मान रहे हैं और इसी आशा के साथ वे युरोप की ओर बढ़ रहे हैं. इस शरणार्थी प्रवाह को रोकना या नियंत्रित करना मुश्किल है. इस समस्या के समाधान के लिए जो भी वार्ताएं हो रही हैं, वो सभी सिर्फ आंसू पोंछ उपाय ही कर सकते हैं. असल में शरणार्थियों को व्यवस्थापित करने के मसले पर ईयु ईमानदार नहीं है. ईयू के सारे देश वास्तव में शरणार्थियों से किसी न किसी तरीके से पिण्ड छुड़ाना चाहते हैं भले ही वे शरणार्थियों की समस्या का हल निकालने कुछ भी कह रहे हों. जो कुछ भी हल निकालेंगे वह अस्थायी तो होगा ही और सम्मानजनक या आदरपूर्वक हल की उम्मीद भी शायद ही की जा सकती है. लेकिन ईयू देशों की युद्ध विरोधी व अमन पसंद एवं मानवतावादी जनता शरणार्थियों का स्वागत कर रही है. बच्चें, बूढ़ें, महिलाएं बड़ी संख्या में प्लॅकार्ड्स सहित सड़कों पर उतरकर, रैलियां निकाल अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही हैं. वर्तमान शरणार्थी संकट का यह एक छोटी लेकिन आशाजनक पहलु है जो स्वागतेय है. लेकिन इतने से नहीं होगा. उन्हें अपनी सरकारों के आक्रमणकारी युद्धों के खिलाफ आक्रामक होना होगा.

चूंकि शरणार्थी समस्या की जड़ साम्राज्यवाद है और साम्राज्यवाद का मतलब ही युद्ध है, इसलिए दुनिया में कोई युद्ध न हो इसके लिए साम्राज्यवाद को ही इस धरती से उखाड़ फेंकना होगा. तभी न युद्ध होंगे और न ही किसी देशवासी को अपने देश छोड़ने की नौबत नही आयेगी. साम्राज्यवादी लूट और शोषण खत्म होगा तो किसी को आजीविका की तलाश में अपनी धरती छोड़कर दर–दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तभी शरणार्थी समस्या का स्थायी हल और शांति संभव होगा. इसीलिए साम्राज्यवादी आक्रमण के खिलाफ साम्राज्यवादियों के पिट्ठुओं के खिलाफ उत्पीड़ित देशों की पीड़ित जनता को संगठित होकर हथियारबंद लड़ाई को तेज करना होगा और उसे हराना होगा. शरणार्थी समस्या का वैश्विक स्तर पर स्थायी समाधान तभी होगा. इस दिशा में आगे बढ़ते हुए साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षों को तेज करना होगा. ❍

झूठी मुठभेड़ें–क्रांतिकारी जनता एवं स्थानीय निर्माणों को आतंकित करने की सरकारी साजिश

दण्डकारण्य के जल–जंगल–जमीन व संसाधनों को जल्द से जल्द देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों के हवाले करने के मकसद से केंद्र, राज्य सरकारें यहां के विस्थापन विरोधी जन आन्दोलनों व उनका समर्थन, मार्गदर्शन व नेतृत्व करने वाले क्रांतिकारी आन्दोलन को खत्म करने ऑपरेशन ग्रीनहंट के पाशविक हमलों में अक्तूबर, 2015 से अभूतपूर्व तेजी लायी हैं. इस वक्त समूचे दण्डकारण्य में सरकारी सशस्त्र बलों द्वारा 'महा अभियान' यानी भयानक दमन अभियान जारी है. मिशन–2016 के नाम से माओवादियों को 2016 में खत्म करने यह अभियान चलाया जा रहा है. गांवों पर हमलें, झूठी मुठभेड़ें, झूठे आत्मसमर्पण, झूठा प्रचार, महिलाओं पर अत्याचार व सामूहिक बलात्कार, लोगों की बेदम पिटाई, संपत्ति की लूट–पाट दण्डकारण्य खासकर बस्तर संभाग में रोजमर्रा की बात हो गयी हैं. बस्तर रेंज के आईजी शिव राम प्रसाद कल्लूरी आये दिन प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिए ईनामी माओवादियों को मुठभेड़ों में मार गिराने, ईनामी माओवादियों के बड़े पैमाने पर आत्मसमर्पण करने के झूठे दावे पेश कर रहे हैं. साथ ही हमारी पार्टी के खिलाफ जहरीले प्रचार कर रहे हैं. केंद्र, राज्य सरकारों द्वारा जारी फासीवादी सैनिक दमन अभियान ऑपरेशन ग्रीनहंट के हिस्से के तौर पर यह सब हो रहा है. शोषक–शासक वर्गों के राज्य यंत्र के एक कलपुर्जे के रूप में, विश्वसनीय एजेण्ट के रूप में काम करते हुए बस्तर आईजी कल्लूरी जनता पर पाशविक दमन अमल कर रहे हैं.

पिछले अक्तूबर से लेकर अब तक बस्तर संभाग के दसियों ग्रामीण युवाओं की निर्मम हत्या करके कल्लूरी ने फर्जी मुठभेड़ कहानियां गढ़कर प्रचारित की. इन फर्जी मुठभेड़ हत्याओं में साधारण जनता से लेकर ग्रामीण पार्टी इकाइयों, जनताना सरकारों, जन संगठनों के नेतृत्व सहित साधारण सदस्य, पीएलजीए के निहत्थे सदस्य एवं पार्टी कमेटियों के सदस्य भी शामिल हैं. जनता व स्थानीय निर्माणों में दहशत फैलाने के मकसद से सरकारों ने झूठी मुठभेड़ों को बड़े पैमाने पर अंजाम देने का निर्णय लिया है.

25 मार्च, 2016 को कोंडागांव जिले के मर्दापाल थाना क्षेत्र के कुदूर पंचायत के सहपदर गांव के आदिवासी किसान व कुदूर जनताना सरकार कमेटी के सदस्य सुदराम को घर से पकड़कर 26 की अलसुबह डीआरजी गुण्डों ने उनकी निर्मम हत्या की और कल्लूरी ने अखबारों में यह वक्तव्य जारी किया कि जिला पुलिस बल, एसटीएफ एवं डीआरजी के संयुक्त बलों पर माओवादियों ने हमला किया था. पुलिस द्वारा किये गये जवाबी हमले में 3 लाख का ईनामी माओवादी मारा गया.

फरवरी 17, 2016 को कोंडागाव जिले के मर्दापाल थाना क्षेत्र के कोडेनार गांव से 25 वर्षीय युवक बलदेव कोर्राम को घर से उठा ले जाकर जिला पुलिस बल एवं डीआरजी के गुण्डों ने 18 फरवरी को उसकी नजदीक से गोली मारकर हत्या की और कल्लूरी ने यह घोषणा की कि 5 लाख का ईनामी माओवादी को मार गिराया गया है.

2016 फरवरी 16 से 20 तक बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र के पिडिया, दोड्डि तुकनार, हण्ड्री, गुंपूर पंचायतों के गांवों पर बीजापुर, दंतेवाडा, सुकमा जिलों से आए एसटीएफ, सीआरपीएफ, डीआरजी के सैकड़ों बलों ने बर्बर हमले किए. पुलिस की गोलीबारी में पिडिया पंचायत के हर्रा गांव के 8 साल का अबोध बालक सोढ़ी सन्नु जो अपने घर के आंगन में खेल रहा था, की मौत हो गयी. बच्चे की लाश पुलिस अपने साथ ले गयी और जंगल में दफना दी. इस फर्जी मुठभेड़ को बाहर आने नहीं दिया गया था. इसी हमले के दौरान जंगल में वनोपजों का संग्रहण करने वाले कुहडम गंगाल की भी गोली मारकर हत्या की गयी.

13 फरवरी, 2016 को बीजापुर जिले के फर्सेगढ़ थाना क्षेत्र के कोकेरा गांव के ग्रामीणों जो तालाब में मछली पकड़ रहे थे, पर महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ के संयुक्त बलों ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर तीन ग्रामीणों–पल्लो सुक्कु, पोडियाम सुखराम, कुम्मा सोमाल की पाशविक हत्या की.

फरवरी के पहले सप्ताह में सुकमा जिले के गोल्लापल्ली थाना क्षेत्र के वंजलवाया में सिंगारम के जनताना सरकार अध्यक्ष कुरसाम धर्मन्ना और सदस्य वट्टि राजाल को निहत्थे पकड़कर, अमानवीय यातनाएं देकर गोली मार दी गयी थी.

5 फरवरी, 2016 को बस्तर जिले के मारडुम थाना क्षेत्र के ग्राम टुंडेर के आदिवासी किसान अडमा कश्यप की घर से उठा ले जाकर गोलियों से भूनकर हत्या की गयी. हत्या के एक सप्ताह पूर्व ही अडमा जेल से रिहा होकर घर आया था. उसे झूठे केस में फंसाकर जगदलपुर जेल में डाला गया था. ढाई साल बाद बाइज्जत बरी होकर छूटा था. यहां यह याद दिलाना वाजिब होगा कि इस मुठभेड़ हत्या के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करवाकर लौटते समय ही आप पार्टी की नेता सोनी सोढ़ी पर हमला करके चेहरे पर रासायनयुक्त कालिख पोत दिया गया था. अडमा की हत्या के बाद अखबारों में यह कहानी छपवायी गयी कि एक भीषण मुठभेड़ में वर्दीदारी व ईनामी माओवादी

को पुलिस ने ढेर कर दिया.

सुकमा जिले के चिंतागुप्पा के ग्रामीण कुंजामी लिंगा की घर के सामने व जनता के सामने ही गोली मारकर हत्या की गयी.

सुकमा जिले के पोलमपल्ली थाना क्षेत्र के पालेमडुगु गांव की वंजाम शांति, सरियम पोज्जे को गांव के नजदीकी जंगल से 30 जनवरी 2015 को पकड़कर अत्याचार करने के बाद उनकी हत्या की गयी एवं मुठभेड़ में दो महिला माओवादियों के मारे जाने की खबर मीडिया को दी गयी. जनवरी महीने में ही बासागुडा थाना क्षेत्र के ईकुम गांव के सोढ़ी सोवाल, सुकमा जिले के गोल्लापल्ली थाना क्षेत्र के सिंगारम, इत्तमपारा के मडकाम राजु, मडकाम मुड़ा को घरों से उठा ले जाकर फर्जी मुठभेड़ में उनकी हत्या की गयी.

27 जनवरी 2015 को दंतेवाडा जिले के कट्टेकल्याण थाना क्षेत्र के लखापाल गांव में आराम करने वाले जन संगठन के सदस्य कॉमरेड्स बालसिंह, कनकी, मासा की निर्मम हत्या की गयी.

18 जनवरी 2015 को बीजापुर जिले के कुटरु क्षेत्र के तुम्मिरगुण्डा गांव पर हमला करके जरीना नामक युवती जो पहले दस्ते में काम कर रही थी, और घर भेज दी गयी थी, को पकड़कर रात भर यातनाएं देकर, सामूहिक अत्याचार करके दूसरे दिन यानी 19 जनवरी को उनकी पाशविक तरीके से हत्या की गयी. इस फर्जी मुठभेड़ के खिलाफ हर तरफ से आवाज उठी थी जबकि कल्लूरी का दावा है, मुठभेड़ में महिला कमांडर मारी गयी.

15 जनवरी 2015 को बीजापुर जिले के पेद्दा जोजोड़ गांव में भूमि समतलीकरण अभियान के तहत खेतों में कार्यरत जनता पर की गयी पाशविक गोलीबारी में ओयाम मुन्ना, मज्जि बुधराम, मडकाम पांडु, ओयाम तुलसी की मौत हो गयी. गांव की जनता ने मीडिया के सामने इस झूठी मुठभेड़ का खुलासा किया था और थाने जाकर लाशें लाकर अंतिम संस्कार किया. लेकिन कल्लूरी ने ईनामी माओवादियों को मार गिराने का दावा ठोंकना जारी रखा.

11 जनवरी 2015 को छत्तीसगढ़–महाराष्ट्र के सरहदी गांव सन्ड्रा में गोटा विनोद नामक एक ग्रामीण युवक को पकड़कर लोगों के सामने ही गोलियों से भूना गया और मुठभेड़ में ईनामी नक्सली के मारे जाने की कहानी अखबारों में प्रकाशित करवायी गयी.

11 जनवरी 2015 के ही दिन गांव कोकेरा के पास पीएलजीए कार्यकर्ता कॉमरेड हेमला लच्छी को गोली मारकर घायल आवस्था में पकड़कर खूब यातनाएं देकर उनकी जघन्य तरीके से हत्या की गयी. बीजापुर जिले के ही आवापल्ली थाना के अंतर्गत गांव गोटुम के पास 6 जनवरी को हमारे कार्यकर्ता कॉमरेड कुडियम कमला को पकड़कर मुठभेड़ के नाम पर उनकी बर्बर हत्या की गयी.

4 जनवरी 2015 को कुन्ना गांव पर हमला करके पुलिस जवानों ने 30 से अधिक ग्रामीण महिला, पुरुषों की बेदम पिटाई की थी जिससे लालू सोढ़ी नामक युवक की मौत हो गयी.

4 जनवरी, 2016 को कोंडागांव जिले के कुदूर साप्ताहिक बाजार से वेड़मा गांव के आदिवासी किसान जैत कोर्राम व कुदूर गांव के ही युवक बोटी कश्यप को डीआरजी द्वारा सैकड़ों लोगों के सामने से पकड़कर ले जाया गया एवं 5 जनवरी की अलसुबह गोली मारकर उनकी हत्या की गयी. कल्लूरी ने अखबारों में यह कहानी प्रकाशित करवाया कि 5 लाख के ईनामी एलजीएस डिप्टी कमांडर जैत और 3 लाख का सदस्य बोटी को पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद मार गिराया है. माओवादियों के तगड़े एंबुश को तोड़कर पुलिस बैच निकली थी और इसी दौरान दो ईनामी माओवादी मारे गये.

1 जनवरी, 2016 को नारायणपुर के माड़ क्षेत्र के कुतुल साप्ताहिक बाजार को चारों ओर से घेरकर पुलिस ने पीएलजीए के दो निहत्थे सैनिक कॉमरेड्स लक्कु (पैवेर) एवं मुन्ना (आंगमेट्टा) की क्रूरतापूर्वक हत्या की.

बस्तर जिले के पखनार थाना क्षेत्र के कोप्पेम गांव में 25 दिसंबर को छिंदरस निकालने गये युवक लखमु की गोली मारकर हत्या की गयी. बाडंगपाल के युवक सैनु को घर से उठा ले जाकर गोली मार दी गयी.

17 दिसंबर, 2015 को नारायणपुर जिले के धनोरा थानांतर्गत गांव मडमनार गांव से सन्नारु कचलाम को डीआरजी द्वारा घर से उठा ले जाकर 18 तारीख को कोंडागांव जिले के वयानार थानांतर्गत केज्जुम के पास उनकी गोली मारकर हत्या की गयी और 8 लाख के ईनामी बेनूर एलओएस कमांडर रनादेर को मार गिराने का झूठा दावा कल्लूरी ने किया. सच्चाई यह है कि सन्नारु कचलाम मूलतया आदेहवेडा गांव का रहने वाला था. उसने 2007 तक रनादेर के नाम से बेनूर एलओएस कमांडर के रूप में काम किया था. 2007 के मध्य में उसने पार्टी छोड़ी एवं 2012 तक आदेहवेडा में खेती काम करके जीवन बिताया. बाद में मड़मनार के ग्रामीणों की मांग पर वह वहां जाकर गायता (भूमि पूजारी) का काम करते हुए जीवन बिता रहा था.

2 नवंबर, 2015 को धनोरा थानांतर्गत गांव कोडेली के आदिवासी युवा किसान बामन पोयामी को खेत से उठा ले जाकर नारायणपुर पुलिस लाइन में 15 दिनों तक यातनाएं देकर उसकी निर्मम हत्या की गयी एवं पुलिस लॉक अप में 17 नवंबर को माओवादी बामन द्वारा आत्महत्या किये जाने की घोषणा की गयी. जन आन्दोलन के बाद

कार्य में लापरवाही का कारण बताकर पुलिस के 4 जवानों को निलंबित किया गया था. ज्ञात रहे, इस लॉकअप हत्या के विरोध में ओरछा में हजारों लोगों ने विशाल रैली निकाली थी.

3 नवंबर 2015 को सुकमा जिले के दोरनापाल थाना क्षेत्र के अरलमपल्ली गांव के तीन ग्रामीणों की निर्मम हत्या की गयी जब वे छिंदरस निकालने बाड़ी मे जा रहे थे. दरअसल तीनों युवक–दूधी भीमा, वेट्टी लच्छू और सोढ़ी मूया जब छिंदरस उतारने जा रहे थे तभी पुलिस उन्हें घेरकर दो युवकों की पिटाई करने लग गयी थी. इसे देख सोढ़ी मूया डर के मारे भागने की कोशिश की थी. पुलिस ने दोनों युवकों के सामने ही पीछे से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी. मारे गये युवक की लाश को थाने तक ले जाने में बाकी दो युवकों की मदद ली गयी थी. बाद में फर्जी मुठभेड़ की पोल खुलने की आशंका से बाकी दोनों युवकों की भी नजदीक से गोली मारकर हत्या कर दी और मुठभेड़ में तीन माओवादियों के मारे जाने की खबर फैलायी. इस फर्जी मुठभेड़ के चश्मदीद गवाह हैं, मृतक के परिजन दूधी हिडमे, दूधी देवे, दूधी जोगी. इस जघन्य हत्याकांड के विरोध में हजारों लोग सड़क पर उतरे.

नवंबर 2015 के पहले सप्ताह में ही दोड्डि अर्जुन नामक ग्रामीण युवक की पुलिस ने झूठी मुठभेड़ में हत्या की.

13 नवंबर 2015 को बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक के तूडेम गांव के पास हुई मुठभेड़ में घायल अवस्था में पकड़ाने के बाद कॉमरेड्स वचामी रुकनी, मडकाम जुन्नी की यातनाएं देकर हत्या की गयी.

27 नवंबर, 2015 को माड़ पर हमला करने वाले सशस्त्र बलों ने आलवेडा के आदिवासी किसान मोटु और वेडमामेट्टा के आदिवासी युवक रेंगु को रास्ते से पकड़कर उनकी जघन्य हत्या की एवं ईनामी माओवादियों को मार गिराने का झूठा दावा पुलिस ने किया.

26 सितंबर, 2015 को बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र के पुंबाड गांव के आदिवासी नेता मंगु पोट्टावी को निहत्थे पकड़कर पाशविक तरीके से यातनाएं देकर उनकी हत्या की गयी एवं ईनामी माओवादी के मुठभेड़ में मारे जाने का दावा किया गया. दरअसल पुलिस ने पहले गांव पर हमला करके घरों में आग लगायी थी और अंधाधुंध गोलीबारी करके 15 वर्ष की नाबालिग लड़की रुकनी की निर्मम हत्या करके लाश को रास्ते के किनारे डालकर पास में एंबुश बैठी थी. गांव की बालिका की हत्या, फिर शव के रास्ते में पड़े होने की खबर पाकर मंगु निहत्थे ही लाश लाने गया था. तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ा, उनकी बेदम पिटाई की, हाथ जला दिये, जीभ काट डाले, आखिर में और भी बर्बर यातनाएं देकर उनकी जघन्य हत्या की.

19 सितंबर को छत्तीसगढ़–उड़ीसा सरहद के मलकानगिरी जिले के माथिली पुलिस थाना क्षेत्र के बेजागुडा गांव से कांगेरघाटी एसी सचिव कॉमरेड सोनाधर, एसीएम कॉमरेड लक्ष्मण एवं पंचायत सचिव घासीराम मुचाकी को निहत्थे पकड़कर अमानवीय यातनाएं देकर उनकी क्रूरतापूर्वक हत्या की गयी. बड़ी मुठभेड़ में माओवादी नेता सहित तीन को मार गिराने का दावा पुलिस ने की.

इन तमाम मामलों में कल्लूरी ने स्वयं ईनाम की घोषणा की. अवार्ड, रिवार्ड, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन एवं लाखों की नकदी का लालच देकर पुलिस खासकर डीआरजी गुण्डों को यह खुली छूट दे रखी है कि वे किसी को भी, कहीं से भी पकड़कर गोली मार सकते हैं. डीआरजी वालों को लाइसेन्सड् किल्लर बनाते हुए उनमें लंपट प्रवृत्ति को योजनाबद्ध तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं. जनता पर आतंक व दरिंदगी ढ़ाने उकसा रहे हैं. यह सरकारी दमन अभियान का ही हिस्सा है. झूठी मुठभेड़ों के विरोध में जनता, जनवादियों, मानवाधिकार संगठनों, आदिवासी, गैर–आदिवासी सामाजिक संगठनों को आगे आकर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए. जनपक्षधर मीडिया कर्मियों व मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को संघर्ष इलाकों का दौरा करके सच्चाई का पता लगाकर जनता के सामने रखना चाहिए. उपरोक्त मामलों में से कुछ के संदर्भ में सीडीआरओ (मानवाधिकार संगठनों की समन्वय समिति), छत्तीसगढ़ महिला अधिकार मंच, मध्यप्रदेश महिला मंच आदि महिला संगठनों, सर्व समाज, आदिवासी समाज, जगदलपुर लीगल एइड ग्रुप, सीपीआई, सोनी सोढ़ी आदि ने सराहनीय कार्य किये हैं. फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां बनाकर सच्चाई को जनता के सामने लाने की कोशिशें की. तथाकथित कानूनी व संवैधानिक अधिकारों के तहत थानों में एफआईआर व न्यायालयों में केस दर्ज करवाने की जनवादी कोशिशें की गयीं. अपने चुनावी स्वार्थ के चलते ही सही कांग्रेस पार्टी की ओर से भी फर्जी मुठभेड़ों का भंडाफोड़ करने की कोशिश की गयी. हालांकि कांग्रेस सहित उपरोक्त तमाम लोगों व संगठनों पर पुलिस की ओर से काफी दबाव डाला गया एवं उन्हें परेशान किया गया. बढ़ते राज्य दमन के दौर में दमन का मुकाबला करते हुए ही जनता पर जारी पाशविक हमलों, महिलाओं पर सरकारी सशस्त्र बलों द्वारा जारी अत्याचारों के खिलाफ उन्हें अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए व पुलिसिया आतंक के शिकार गांवों का दौरा करके सच्चाई को देश, दुनिया के सामने लाना चाहिए. पीड़ित जनता को चाहिए कि वह विभिन्न तथ्यान्वेषण कमेटियों व मीडिया साथियों के दौरों के समय खुलकर उनका साथ देना चाहिए एवं उन्हें अपनी आपबीती, व्यथा, पीड़ा से अवगत कराते हुए सबूत उपलब्ध कराने चाहिए.

❍

जन आन्दोलन व जन युद्ध के जरिए आमदाई पहाड़ को बचाने की कोशिशों के समर्थन में सभी को आगे आना चाहिए!

अवैध तरीके से यानी ग्राम सभाओं की अनुमति के बगैर ही आमदाई लौह अयस्क पहाड़ की लीज प्राप्त करने के बाद 2009 से नीको जायसवाल कंपनी खदान शुरु करने एडी–चोटी का जोर लगा रही है. 2010 में पहली बार अवैध रूप से पेड़ कटाई का काम प्रारंभ किया था. तब आस–पास की हजारों जनता व पीएलजीए ने काम रुकवाया था. कंपनी के एक प्रबंधक झा सहित वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों को हिरासत में लेकर जन अदालत में पेश किया गया था. उनकी गाड़ियों को जब्त करके, गंभीर चेतावनी देकर सभी को छोड़ दिया गया था. कंपनी तथा वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने जनता के सामने गलती मानकर दोबारा खदान काम शुरु न करने व पहाड़ की तरफ न झांकने की जन हिदायत को स्वीकार करके चले गये थे.

दोबारा 2014 में तेलंगाना के एक ठेकेदार के जरिए पेड़ कटाई का कार्य शुरु करवाया गया था. पर्चे, पोस्टर के माध्यम से काम बंद करने की चेतावनी, जनता द्वारा कार्य बंद करने की मांग की अनदेखी की गयी. उसके बाद जनता व पीएलजीए ने 31 दिसंबर, 2014 को कार्यस्थल पर धावा बोलकर खदान पर जाने के लिए बनायी जाने वाली सड़क कार्य व पेड़ कटाई में लगे वाहनों को आग के हवाले किया गया था एवं ठेकेदार की पिटाई भी की गयी थी. काम बंद करने की चेतावनी के साथ उसे भी छोड़ दिया गया था. उसके बावजूद काम जारी था. आमदाई बचाने की मांग को लेकर व भूमि अधिग्रहण अधिनियम के खिलाफ छोटे डोंगर परगणा के 12 पंचायतों की 10 हजार से भी ज्यादा जनता ने 1 मई, 2015 जिला मुख्यालय नारायणपुर में जोरदार रैली निकाली थी. इसके बावजूद अक्तूबर, 2015 में खदान प्रारंभ करवाने छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार की मदद से छोटे डोंगर के नजदीक नयापारा में आईटीबीपी का नया कैंप बैठाया. तब से आमदाई घाटी के गांवों पर निरंतर हमलें, फर्जी मुठभेड़ें, अवैध गिरफ्तारियां आदि दमनात्मक हथकंडे जारी हैं. सरकारी सशस्त्र बलों के सख्त पहरे में खदान खोलने की कोशिशों के तहत पेड़ों की कटाई एवं पहाड़ पर जाने के लिए सड़क बनाने के काम जारी हैं. खदान खोलने की इन जबरिया कोशिशों को नाकाम करने 10 दिसंबर, 2015 को पीएलजीए ने नयापारा कैंप पर हमला किया जिसमें एक जवान मारा गया था.

उसके बाद नीको जायसवाल के लिए आमदाई पहाड़ पर जाने के लिए सड़क बनाने का कार्य शुरु किया गया था. पेड़ कटाई एवं सड़क बनाने का कार्य मां कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा जारी था. जनता के विरोध के बावजूद व पार्टी द्वारा दी गयी चेतावनी को दरकिनार करके यह कंपनी पुलिस सुरक्षा में काम करवा रही थी. संसाधनों की लूट को रोकने के लिए पीएलजीए ने 6 मार्च, 2016 को आमदाई घाटी में सड़क सुरक्षा में तैनात पुलिस जवानों पर हमला किया था जिसमें दो जवान घायल हुए थे और मां कंस्ट्रक्शन कंपनी के दो सूपरवाइजरों ने भी दम तोड़ा. ये दोनों सूपरवाइजर दरअसल पुलिस के लिए भी काम कर रहे थे. पुलिस के सामने, उनकी सुरक्षा के लिए पायलट व स्काउट यानी पुलिस के लिए रूट क्लियर करने का कार्य कर रहे थे. पुलिस उन्हें अपने बचाव के लिए ढ़ाल की तरह इस्तेमाल कर रही थी. दलाल पूंजीपति कंपनी नेको व पुलिस के लिए दोनों सूपरवाइजरों को अपनी जान गंवानी पड़ी. मुठ्ठी भर रुपयों के लालच में शोषकों व लुटेरों के लिए बेरोजगार युवाओं को अपनी जानें नहीं गंवानी चाहिए. खदान कार्यों के लिए नीको कंपनी की नौकरी के चक्कर में युवा न रहे. क्यों कि नीको के लिए काम करने का मतलब है, अपने पैरों पर ही कुल्हाडी मारना. अपनी ही आजीविका के साधनों को तहस–नहस करना.

जनता के जबर्दस्त विरोध के बावजूद कंपनी पुलिस दमन के सहारे खदान खुलवाने की कोशिशों में अब भी लगी है. आमदाई घाटी के गांवों पर लगातार पुलिस हमलें जारी हैं. 11 मार्च को भी घाटी के तोंडावेडा, ईकनार, मूसनार, वेच्चा, घुमटेर, आदेहवेडा, तोयवेडा, हितुलवाडा आदि गांवों का गश्त करके लौटते समय पुलिस बल और पीएलजीए बलों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई जिसमें पांच जवान घायल हुए. घायलों को लेकर पुलिस जवान कैंप लौट गये. पुलिस की बंदूकों की संगीनों के साये में आमदाई खदान खोलने के नीको जायसवाल एवं छत्तीसगढ़ सरकार की कोशिशों को नाकाम करने में बुद्धिजीवियों, मानवाधिकार संगठनों, मीडिया कर्मियों एवं आदिवासी, गैर–आदिवासी सामाजिक संगठनों को जनता एवं पीएलजीए की हर संभव मदद करनी चाहिए. ❍

जन–आंदोलन में कार्य करने वाले हर कम्युनिस्ट को चाहिए कि वह आम जनता का मित्र बने, उस पर हुक्म चलाने वाला नहीं; कभी न थकने वाला शिक्षक बने, नौकरशाह राजनीतिज्ञ नहीं। *–माओ*

भगत सिंह की विरासत को सगर्व ऊंचा उठाये रखने वाले नयी पीढ़ी के वीर योद्धा कॉमरेड्स विवेक, श्रुति, विद्या सागर, सूर्यम की कुरबानियों की राह में आगे बढ़ो!

कॉ. विवेक

कॉ.श्रुति

कॉ. विद्या सागर

कॉ.सूर्यम

'साम्राज्यवाद मुर्दाबाद', 'इंकलाब जिंदाबाद' नारों से देश के युवाओं के दिलों में उफान पैदा करने वाले भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु व सुखदेव की शहादत को 85 साल पूरे हो गये हैं. गोरों व उनकी गुलामी करने वाले कालों को सिर्फ भगत सिंह के भौतिक अस्तित्व ही नहीं, उससे कहीं ज्यादा उनके विचारों की ताकत ने भयभीत किया था. उन्हें फांसी पर चढ़ाने के पीछे उनका सफाया ही एक मात्र मकसद नहीं था. बल्कि उनके विचारों व उन विचारों से प्रेरित उस जमाने की युवा पीढ़ी को उसका प्रतिनिधित्व करने वाले नेतृत्व से वंचित करना था. लेकिन वे बुरी तरह विफल हुए. वे व्यक्ति को मिटाना चाहते थे लेकिन वो शक्ति का रूप धारण कर लिया. काल बार–बार अनेक भगत सिंह को जन्म दे रहा है. भगत सिंह अब एक संज्ञा नहीं रह गया है. वह एक सर्वनाम बन गया है. विवेक, श्रुति, सागर, सूर्यम एवं कुरबानियों की राह में खूनी बीज बोने वाले कइयों नवजवान कॉमरेड अब वो सर्वनाम बन गये हैं.

कौन था ये विवेक?

सिर्फ 19 साल का मासूम था. उम्र से ज्यादा परिपक्व था, वह. परिपक्वता के मुताबिक सटीक व्यवहार को चुना था. विवेक नल्लागोंडा जिले के सूर्यापेट जो हैदराबाद के सामंती शासक निजाम के खिलाफ डटकर मुकाबला करने में आगे था, की संघर्ष विरासत को आत्मसात करने वाला नवजवान था. उसने तेलंगाना के लिए संघर्ष किया था. पृथक तेलंगाना से वह संतुष्ट नहीं हुआ था. जनवादी तेलंगाना का सपना संजोया था. पोलावरम बांध में डूबते आदिवासी जिंदगियों की मदद में खड़ा था. वकालत की पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर उत्पीड़ितों को उनके जायज हक दिलाने हथियार उठाया था.

ये श्रुति कौन थी?

काकतीया सामंती राजाओं के खिलाफ विद्रोह करने वाली सम्मक्का, सारलम्मा एवं निजाम व उसके पिट्टु जमींदारों को धिक्कारने वाली धोबिन आइलम्मा के ओरुगल्लु की संघर्ष विरासत की आज की पीढ़ी की प्रतिनिधि थी, श्रुति. उसकी उम्र मात्र 23 साल थी. जिंदगी के बारे में सुंदर सपने देखने की उम्र. उन सपनों को साकार करने लायक इंजिनीयरिंग की डिग्री. लेकिन उसने जो सुंदर सपना देखा था, वह सामूहिक था. इस धरती से शोषण व उत्पीड़न को मिटाने का सपना. वो यह जानती थी कि उसके सपने को इंजिनीयरिंग डिग्री पूरा नहीं कर सकती. इसीलिए उसने अपने सपने को साकार करने के हथियार के रूप में मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद को अपनाया. इस सैद्धांतिक हथियार के अध्ययन के लिए उसने उत्पीड़ित जनता की जिंदगियों को पढ़ने उनके बीच में गयी. जनता को अपने शिक्षक स्वीकार किये.

ये विद्या सागर कौन था?

कॉमरेड श्रुति के ही समान ओरुगल्लु की संघर्ष विरासत को सागर ने ऊंचा उठाये रखा था. नशाखोरी एवं अन्य लतों के खिलाफ जनता में उसने जागरूकता पैदा की थी. विवेक के बलिदान से प्रज्वलित स्फूर्ति से लैस होकर क्रांतिकारी परचम को फिर से लहराया था. शहीदों की कुरबानियों को भौतिक शक्ति में तब्दील करने के महान कार्य में स्वयं को झोंका था.

कौन था, ये सूर्यम?

नल्लामला की लड़ाकू विरासत से लैस प्रकाशम जिले का प्यारा लाल था. नल्लामला में ढलने वाले सूरज को ढूंढते हुए पूर्वी घाट पहुंच गया था. मन्यम पहाड़ों में अल्लूरी

सीता रामराजु के कदमों के छाप को चूमा था. कुई जनता के दिलों में बस गया था.

कम्युनिज्म–साम्यवाद के उज्वल सपने को साकार करने कुरबानियों की राह में साहस के साथ सफर करने वाले ये कॉमरेड्स आज हमारे बीच में नहीं हैं. पच्चीस साल के भी नहीं हुए थे. साल भर से भी कम का क्रांतिकारी जीवन था, इनका. सर्वोच्च बलिदान देकर इन्होंने शहादत की ऊंचाइयों को छू लिया.

2015 जून 12 को छत्तीसगढ़–तेलंगाना के सरहदी गांव लंकापाकला के पास पुलिस द्वारा की गयी एकपक्षीय गोलीबारी में कॉमरेड्स सोनी, कमला के साथ विवेक भी शहीद हो गया था. 2015 सितंबर 15 को वारंगल जिले के ताडवाय जंगल में छापामार दस्ते पर की गयी गोलीबारी के दौरान ग्रे हाउण्ड्स ने कॉमरेड्स श्रुति, सागर को पकड़ लिया था. पाशविक यातनाएं देकर बर्बर तरीके से उनकी हत्या की गयी. कॉमरेड सूर्यम एओबी के पूर्वी डिविजन में हुई मुठभेड़ में शहीद हो गये.

इन कॉमरेडों ने अपनी शहादत से यह साबित किया कि माओवादी सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है. उन्होंने इस गलत धारणा को भी तोड़ दिया कि अब पढ़े–लिखे लोग पार्टी में भर्ती नहीं होते हैं. हालांकि शोषक–शासक वर्ग युवाओं में केरीरवाद को बढ़ावा देते हुए उनकी सामाजिक चेतना को खत्म करने की काफी कोशिशें कर रहे हैं लेकिन सही राजनीति से जहां कहीं भी युवाओं को लैस करते हैं तो वे आन्दोलन में कूदने तैयार रहते हैं.

इनकी शहादत के मौके पर समाज खासकर युवा पीढ़ी ने विशेष प्रतिक्रिया व्यक्त की. कॉमरेड विवेक की वाट्स एप पीढ़ी के युद्ध गीत के रूप में प्रशंसा की. कॉमरेड श्रुति, सागर की हत्या के संदर्भ में अभूतपूर्व प्रतिक्रिया आयी. 370 जन संगठनों व दस से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाकर तेलंगाना सरकार की दमन नीति की कड़ी भर्त्सना की एवं जोरदार विरोध किया था. पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद, दमन को धत्ता बताते हुए क्रांतिकारी परंपराओं के मुताबिक हजारों लोगों ने इन प्यारे योद्धाओं को अंतिम विदाई दी. कवियों और लेखकों ने अपनी कलमों के जरिए अभूतपूर्व ढंग से इनकी शहादत को लाल सलाम पेश किये.

ये सभी समाज में व्याप्त क्रांतिकारी आकांक्षाओं को दर्शाते हैं. नयी पीढ़ी के इन नवजवान कॉमरेडों की शहादत को प्रभात गर्व के साथ ऊंचा उठाये रखता है. उनकी कुरबानियों की राह में आगे बढ़ने युवाओं का आह्वान करता है. ❍

टाटा के बाद एस्सार की भी बस्तर से वापसी

धुरली–भान्सी में प्रस्तावित एस्सार स्टील प्लांट का निर्माण अब खटाई में पड़ गया है. बस्तर के औद्योगीकरण के नाम पर दरअसल बस्तर की संपदाओं को दलाल बड़े पूंजीपतियों के हवाले करने के लिए टाटा और एस्सार कंपनियों को बैलाडीला लौह अयस्क खदानों में खनन परियोजनाएं शुरु करने व वहां की आपूर्ति के आधार पर लोहण्डीगुडा में टाटा स्टील प्लांट एवं धुरली–भान्सी में एस्सार स्टील प्लांट लगाने के करार 2005 में हुए थे. खनन कार्य शुरु करने के पहले सर्वेक्षण हेतु दोनों कंपनियों को पूर्वेक्षण हेतु प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस जारी किये गये थे. साथ ही स्टील प्लांट लगाने के लिए दोनो ही कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण की जोर आजमाइश भी शुरु हो गयी थी. पिछले दस सालों से लोहण्डीगुडा के दस पंचायतों एवं धुरली–भान्सी सहित चार गांवों की जनता अपनी जमीनों की रक्षा के लिए जी जान से लड़ रही है. पुलिस, प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद जनता से जमीन अधिग्रहण संभव नहीं हो सका. हालांकि लोगों को डरा–धमकाकर, लालच देकर लोहण्डीगुडा के कुछ किसानों की जमीनों को अधिग्रहित किया गया है लेकिन अभी भी किसान ही खेती कर रहे हैं. जनता के जबर्दस्त विरोध के चलते दस सालों में भी प्लांट लगाने का काम एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा. धुरली–भान्सी की जनता से तो एक इंच जमीन का सौदा भी नहीं कर सकी, सरकार. दोनों ही कंपनियां बैलाडीला में खनन सर्वेक्षण से संबंधित काम पूरा करने पांच साल का समय दिया गया था. लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद भी गैर–कानूनी तरीके से दो–तीन बार समय सीमा बढ़ा दी गयी थी. उसके बावजूद दोनों कंपनियां कोई काम नहीं कर पायी हैं. पिछले साल अक्टूबर में आखिरी समयावधि समाप्त हो गयी थी. छत्तीसगढ़ सरकार को मजबूरी में दोनों कंपनियों की लाइसेंस रद्द करना पड़ा. इससे दोनों कंपनियों द्वारा प्रस्तावित स्टील प्लांटों का लगना भी बंद हो गया है. यह जनता की जीत है. फिर भी धुरली–भान्सी की जनता को सतर्क रहना पडेगा और अपनी एकता को कायम रखनी पड़ेगी. सरकार किसी नयी कंपनी के साथ या एस्सार के साथ ही नये सिरे से समझौता कर सकती है. लोहण्डीगुडा के जिन लोगों ने मुआवजा लेकर अपनी जमीनें सरकार को दे दी, उन्हें अपनी जमीनें वापस पाने संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा. ❍

मानवाधिकारों के नेता कॉमरेड़ कनकैया मास्टार को लाल–लाल जोहार!

मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अविराम संघर्ष करने वाले जन पक्षधर, राजनीतिक बंदियों की रिहाई कमेटी, आन्ध्रप्रदेश व तेलंगाना चाप्टर के उपाध्यक्ष कॉमरेड कृष्णमशेट्टी कनकैया मास्टार (79) का 10 सितंबर, 2015 को हृदयाघात से निधन हो गया था.

कॉमरेड कनकैया मास्टार का जन्म आन्ध्रप्रदेश के प्रकाशम् जिले के परचूर गांव में हुआ था. श्रीकाकुलम के अमर शहीद कॉमरेड चागण्टि भास्कर राव को जन्म देने वाला गांव है, वह. उनकी प्रेरणा से बचपन से ही कॉमरेड कनकैया कम्युनिस्ट आन्दोलन की ओर आकर्षित होकर बाल संगठन के सदस्य बन गये थे. हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी कई गुटों में बंट गयी थी लेकिन चागण्टि की संघर्ष विरासत को ऊंचा उठाये वे आखिरी दम तक क्रांतिकारी आन्दोलन के साथ डटे रहे. श्रीकाकुलम संघर्ष के धक्का खाने, चागण्टि सहित कई मुख्य नेताओं के शहीद होने के बावजूद उनकी स्फूर्ति से लैस होकर कइयों को उन्होंने प्रेरित किया. गांव के रैडिकल युवा संगठन में सक्रिय रूप से काम करते हुए कॉमरेड़ चागण्टि भास्कर राव के स्मारक निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई थी. चागण्टि के शहादत दिवस 22 नवंबर को हर साल स्मारक के पास खेल–कूद व सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करते थे. आपातकाल के दौरान वे गिरफ्तार होकर जेल जीवन बिताये.

पेशे से वे पहले शिक्षक थे. सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने पीड़ित जनता के लिए वकालत का पेशा अपनाया था. उनका क्रांतिकारी सफर बाल संगठन से शुरु होकर रैडिकल युवा संगठन, क्रांतिकारी लेखक संगठन, नागरिक अधिकार संगठन, राजनीतिक बंदियों की रिहाई कमेटी तक जारी रहा. हालांकि वे कई संगठनों में काम करते रहे लेकिन मानवाधिकार क्षेत्र में उन्होंने व्यापक सेवाएं दी.

नल्लामला के सरहदी वन गांवों पर जब राज्यसत्ता ने कहर ढाया, उसका डटकर विरोध करके दलितों व चेंचु आदिवासियों व पिछड़े वर्गों की जनता का बड़ा सहारा बन गये थे. ऐसे मौकों पर जब वन विभाग के अधिकारियों द्वारा हत्याएं की गयी और महिलाओं पर अत्याचार किये गये तब पीड़ितों से मिलकर स्वयं के खर्च पर न्यायालयों में केस दायर करवाते थे. पेशियों में आने वालों के आने–जाने व खाने–पीने की व्यवस्था वे अपने दम पर करते थे.

क्रांतिकारी आन्दोलन के नेतृत्व में 2005 में प्रकाशम जिले के तत्कालीन एसपी लड़हा पर हमले के बाद जिले में दमन तेज हो गया था. एक तरफ पुलिस, दूसरी ओर पुलिस के पालतू हत्यारे गिरोहों की हिंसक कार्रवाइयों से वहां के जन संगठन व जन आन्दोलन के सामने कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हो गयी थी. झूठी मुठभेड़ें, अवैध गिरफ्तारियां, कई दिनों व महीनों तक अवैध हिरासत में रखकर अमानवीय यातनाएं देना आम बात हो गये थे. माओवादी मामलों में बंद लोगों के केसेज की पैरवी न करने वकीलों पर दबाव डाला जाता था व धमकियां दी जाती थी. ऐसे कठिन दौर में कॉमरेड कनकैया मास्टार आरोपियों की मदद में खड़े होते थे और उनके मनोबल घटने नहीं देते थे. उस दौर में हत्या के शिकार कई कॉमरेड़ों के शवों को लेने परिवारजन भी डरते थे. ऐसी स्थिति में शहीदों के पार्थिव देहों को लाकर क्रांतिकारी परंपराओं के मुताबिक अंतिम संस्कार कराने में वे खासा ध्यान देते थे.

क्रांतिकारी आन्दोलन के ज्वार–भाटा में वे हमेशा क्रांतिकारी आन्दोलन व क्रांतिकारी जनता के पक्ष में डटे रहे. कॉमरेड़ कनकैया मास्टार को उनकी शहादत के मौके पर 'प्रभात' विनम्रतापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता है. ❍

''जब भी हम किसी चीज का अध्ययन करें, तो हमें उसकी अन्तर्वस्तु को परखना चाहिए, उसके बाहरी रुप को अन्तर्वस्तु की देहरी तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शक भर मानना चाहिए, तथा एक बार देहरी पार कर लेने पर हमें उस चीज की अन्तर्वस्तु को मजबूती से पकड़ लेना चाहिए; विश्लेषण की यही पद्धति एक विश्वसनीय और वैज्ञानिक पद्धती है.''

''वर्ग समाज में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वर्ग के सदस्य के रुप में ही जीवन व्यतीत करता हैं, तथा प्रत्येक प्रकार के विचार पर, बिना किसी अपवाद के, किसी न किसी वर्ग की छाप होती हैं.''

–माओ

तेलंगाना संघर्ष के नेता कॉमरेड़ मद्दिलेटि अमर रहे!

तेलंगाना प्रजा फ्रंट (तेलंगाना पीपुल्स फ्रंट) के अध्यक्ष कॉमरेड़ पुलिमामिडि मद्दिलेटि (49) का 14 अक्तूबर, 2015 को हृदयाघात के चलते निधन हो गया. कॉमरेड मद्दिलेटि का जन्म 1967 में तेलंगाना राज्य के महबूबनगर जिले के लिंगनवाय गांव के एक दलित परिवार में हुआ था. गद्वाला हाई स्कूल में पढ़ते समय वे क्रांतिकारी विचारधारा की ओर आकर्षित होकर रैडिकल छात्र संगठन में शामिल हो गये थे. 1989 में वे शिक्षक बने और गरीब बच्चों को शिक्षा के नजदीक लाने अनवरत कोशिश करते रहे. आन्ध्रप्रदेश टीचर्स फेडरेशन–एपीटीएफ नामक शिक्षक संगठन में काम करते हुए उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष किया. दूसरी ओर दलितों के आत्मसम्मान के संघर्षों को संचालित किया. मानवाधिकारों के आन्दोलन में भी वे शामिल हुए थे. पृथक जनवादी तेलंगाना लक्ष्य के साथ गठित तेलंगाना जन सभा की राज्य कमेटी के सदस्य बनकर उन्होंने काम किया. बाद में गठित तेलंगाना प्रजा फ्रंट में सक्रियता से काम करते हुए 2014 में उसके अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली. समूचे तेलंगाना का दौरा करते हुए तेलंगाना की आकांक्षा को जनता में प्रज्वलित करने में प्रमुख भूमिका निभाई. तेलंगाना संघर्ष व तेलंगाना शहीदों की विरासत के प्रतीक के तौर पर अपनी बेटी का बेल्लि ललिता नाम रखा. तेलंगाना के पृथक राज्य के रूप में गठित होने के बाद सत्ता में आयी तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरकार जन आकांक्षाओं को रौंदते हुए राज्य हिंसा को तेज किया. इस राज्य हिंसा के खिलाफ संघर्ष करते हुए ही जनवादी तेलंगाना के संघर्ष के लिए जनता को तैयार करने की कोशिश की. देश को हिलाने वाली किसानों की आत्महत्याओं के मामले में तेलंगाना दूसरे स्थान पर है. यह तेलंगाना के जनवादियों को हमेशा खलती है. किसानों की आत्महत्याओं से विचलित कॉमरेड मद्दिलेटि ने किसान समस्याओं को लेकर संघर्ष किया.

कॉमरेड मद्दिलेटि अच्छे लेखक थे. तेलंगाना की जनता पर जारी शोषण के खिलाफ एवं किसानों की समस्याओं पर उन्होंने मार्क्सवादी समझ के साथ कई रचनाएं की.

छात्र अवस्था से ही दमित जनता के पक्ष में संघर्ष करते आये कॉमरेड मद्दिलेटि शुरु से तीव्र दमन को भुगतते रहे. सरकार ने उन्हें कई झूठे मामलों में फंसाया. उनके मनोबल को गिराने की नीच कोशिशें की. फिर भी उनके भीतर के क्रांतिकारी को झुका न सकी. तब के आन्ध्र शासकों के तीव्र दमन के शिकार कॉमरेड मद्दिलेटि को पृथक तेलंगाना के शासकों के दमन के भी शिकार होना पड़ा.

तेलंगाना की प्यारी संतानें कॉमरेड्स श्रृति एवं सागर की टीआरएस सरकार द्वारा की गयी जघन्य हत्याओं का तेलंगाना समाज ने अकल्पनीय व अभूतपूर्व ढंग से विरोध जताया. करीबन 400 संगठन एकजुट होकर 'चलो विधान सभा' का आह्वान किया था. गंभीर रूप से अस्वस्थ होने के बावजूद कॉमरेड मद्दिलेटि आन्दोलन में शामिल हुए. इस आन्दोलन पर भी सरकार ने तीव्र दमन का प्रयोग किया. राज्य की कइयों जगह कइयों को हिरासत में लिया गया था. कॉमरेड मद्दिलेटि भी अरेस्ट किये गये थे. उनकी गंभीर अस्वस्थता की परवाह किये बगैर उन्हें 36 घंटे बंद रखा गया था. इससे उनका स्वास्थ्य और बिगड़ गया था. इसके एक सप्ताह बाद उन्होंने अंतिम सांस ली.

तीव्र दमन के बीच ही आखिरी सांस तक जनता के पक्ष में निस्वार्थ ढंग से संघर्ष करने वाले कॉमरेड मद्दिलेटि को 'प्रभात' विनम्रतापूर्वक श्रद्धासुमन अर्पित करता है. ❍

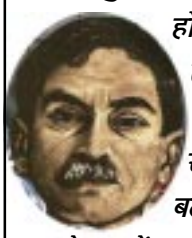

'बहुत कम हिंदू ऐसे हैं, विशेषकर उन लोगों में जो गो–हत्या के सबसे बड़े विरोधी हैं, जिन्होंने कभी गाय पाली हो, या गोशाला में चंदा देते हों या कभी किसी गाय को एक रोटी या एक गट्ठा चारा खिलाया हो. ऐसे लोग जब गो–हत्या पर बावेला मचाते हैं तो क्यों न मुसलमानों को संदेह हो? हमें इस विषय में भाव की जगह बुद्धि से काम लेना चाहिए. गो कितनी ही पवित्र हो, लेकिन मनुष्य की तुलना नहीं कर सकतीं. मुसलमान कितने ही गए गुजरे हों, फिर भी आदमी हैं. क्या अंधेर है कि हम अपने खाने के बर्तनों में कुत्ते को ग्रास खिलाते हैं, लेकिन किसी मुसलमान को पानी पिलाना हो तो कुल्हड़ तलाश करते हैं!!! कुत्ते के मुख का स्पर्श मांजने से साफ हो जाता है लेकिन मुसलमान के मुख का स्पर्श अमिट है! क्या ऐसी स्थिति में भी हम आशा कर सकते हैं कि कोई आत्माभिमानी मुसलमान हमसे भाईचारा का बर्ताव करेगा?'

विख्यात हिंदी लेखक प्रेमचंद, सितंबर 1924

पहली पीढ़ी की महिला क्रांतिकारी
कॉमरेड द्रोणवल्लि अनसूयम्मा को लालसलाम!

नवंबर 5, 2015 को अपने निवासस्थान विजयवाड़ा में कॉमरेड द्रोणवल्लि अनसूयम्मा (75) का निधन हो गया. वे अविभाजित कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में आंध्रा प्रांत में गठित पहले सशस्त्र गुरिल्ला दस्ते की पहली महिला सदस्या थीं. अविभाजित कम्युनिस्ट पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुआ उनका क्रांतिकारी सफर सीपीआई (एम–एल) (पीपुल्सवार) के नेतृत्व वाले रैतु कूली संघम (किसान मजदूर संगठन) तक चलता रहा.

कॉमरेड अनसूयम्मा 1930 में तत्कालीन मद्रास राज्य के आंध्रा प्रांत के कृष्णा जिले के मेडूर गांव के एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में पैदा हुई थीं. दस, ग्यारह साल की उम्र में ही उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति अपनी दिलचस्पी बढ़ा ली. चौदह साल की उम्र में वे कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति आकर्षित हो गयीं. अपने गांव के ग्रंथालय में रूसी सहित्य पढकर, उत्तेजित हो सपना देखती थीं कि रूस में उस समय जिस तरह की सरकार थी उसी तरह की सरकार हमारे देश में भी हो. उस सपने को साकार करने वे कम्युनिस्ट पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता बन गईं. दहेज प्रथा एवं हिन्दू धार्मिक रीति–रिवाजों को खारिज करते हुए उन्होंने कॉमरेड द्रोणवल्ली सत्या प्रसाद जो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता थे, से शादी की. शादी के बाद उन्होंने और सक्रिय रूप से काम करके पार्टी सदस्यता हासिल की थी. नवजवान लोगों को संगठित किया. नौ महीनों की गर्भावस्था में भी वे आंदोलनों में भाग लेती थीं. सोलह दिन के मासूम को छोड़ कर वे जेल गई थीं. जेल में भी अपनी आवाज बुलंद रखी थी. जेल से छूट जाने के तुरंत बाद यानि घर कदम रखे बिना ही वे भूमिगत हो गई थीं. कृष्णा जिले में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में गठित सशस्त्र गुरिल्ला दस्ते में जिद्द करके शामिल होकर उन्होंने उस इलाके में पहली महिला गुरिल्ला के तौर पर अपने स्थान को इतिहास के पन्नों में सुस्थिर बना लिया. वे कई सैनिक गतिविधियों में शामिल हुई थीं. पुलिस द्वारा किए गए हमलों से बचने में उन्होंने कुशलता दिखाई. इस क्रम में उनके जीवनसाथी कॉमरेड सत्या प्रसाद के शहीद होने के बावजूद वे लड़ाई में डटी रही. सशस्त्र संघर्ष विराम के बाद कॉमरेड अनसूयम्मा ने महिला संगठन में सक्रिय रूप से काम किया. सीपीआई में हुए आंतरिक संघर्ष के चलते जब सीपीआईएम बनी, कॉमरेड अनसूयम्मा सीपीआईएम के पक्ष में खड़ी थीं. कॉमरेड सत्या प्रसाद के निधन के बाद वे कोंडपल्ली सीतारामय्या की जीवन साथी बन गई थीं. बाद में कुछ समय के लिए वे सक्रिय राजनीति से दूर रही थीं. संशोधनवादी राजनीति व संसदीय रास्ते को धुत्कारते हुए भारत की क्रांति का सही मार्ग निर्देशन देते हुए पहले सीपीआई (एम–एल), बाद में 1980 में कोंडापल्ली सीतारामय्या के नेतृत्व में सीपीआई (एम–एल) (पीपुल्सवार) जब बनी, तब कॉमरेड अनसूयम्मा उस राजनीति के नजदीक आ गयी. पीपुल्सवार पार्टी के व्यवहार का श्रद्धापूर्वक अध्ययन करने के बाद कॉमरेड अनसूयम्मा 1984 से सीपीआई (एम–एल) (पीपुल्सवार) के नेतृत्व वाले रैतु कूली संघम में सक्रिय रूप से काम करने लगी थीं. उन्होंने ऐलूरु, गुरुविंदापल्ली, पेदावेंगी गांवों में जमींदारों के खिलाफ हुई लड़ाईयों का नेतृत्व किया था. इस क्रम में वे कृष्णा जिले के रैतु कूली संघम की अध्यक्षा बनी थीं. उन्होंने रैतु कूली संघम की राज्य उपाध्यक्षा की जिम्मेदारीं भी निभायी थी.

जब कोंडापल्ली सीतारामय्या ने पार्टी में संकट पैदा किया था, कॉमरेड अनसूयम्मा ने सीतारामय्या का कड़ा विरोध किया और बहुमत का पक्ष लेकर अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व का मजबूती से परिचय दिया. उसके बाद कैन्सर से झूझती बेटी का साथ देने के लिए वे अमेरिका चली गई थीं. इस तरह यद्यपि सक्रिय राजनीति से उनका निष्क्रमण तो हुआ था, लेकिन वे सदा क्रांतिकारी आंदोलन का सघन अवलोकन किया करती थीं. उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन को सहयोग दिया, कई क्रांतिकारियों को मां का प्यार बांटा. 2003 में महिला मार्गम पत्रिका को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, एक दिन इस देश में नव जनवाद क्रांति जरूर सफल होगी. यह विश्वास ही उन्हें जीने की इच्छा शक्ति प्रदान कर रहा है. ये बातें क्रांति की विजय के प्रति उनके दृढ़ विश्वास के प्रतीक हैं. एओबी महिला शहीदों की जीवनियां किताब के लिए 2006 में लिखी गई भूमिका में भी उन्होंने यही विश्वास व्यक्त किया. इस तरह क्रांतिकारी आंदोलन और अपने निजी जीवन में आये उतार–चढ़ावों को दृढतापूर्वक सामना करती हुई आखरी सांस तक क्रांतिकारी राजनीति को ऊंचा उठाए रखने वाली कॉमरेड अनसूयम्मा को 'प्रभात' भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है. ❍

शोषन विहीन समाज के लिए अपनी अनमोल जानें कुर्बान करने वाले वीर शहीदों को कोटि–कोटि लाल सलाम

कॉमरेड सोढ़ी देवे

मार्च 2, 2015 को दक्षिण बस्तर डिविजन के तुमिड़ गांव के पास पुलिस के साथ आमने–सामने लड़ते हुए कॉमरेड सोढ़ी देवे ने अपनी जान कुर्बान की. शहादत के वक्त वह सिर्फ 20 साल की थी. जबकि उसकी पेशेवर क्रांतिकारी जिंदगी केवल दो महीने की थी.

कॉमरेड सोड़ी देवे सुकमा जिले के इत्तगुड़ा गांव के एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी. वह बाल संगठन में काम करते हुए बड़ी हो गई. बाद में उसने सीएनएम में काम किया. 2015 जनवरी में वह गुरिल्ला बनी. मगर दुश्मन के साथ जारी जंग की वजह से इस नव जवान कॉमरेड को नव जनवादी क्रांति के लिए काम करने का उतना मौका नहीं मिल पाया जितना उसने चाहा था. भर्ती होने के दो महीने ही पूरे नहीं हुए कि उसने शहादत को पाया.

गोलीबारी में खुद घायल होने के बावजूद उसने अपने दर्द की परवाह किए बगैर कांटों में फंसनेवाले दूसरे कॉमरेडों का ख्याल रखा था. कांटे निकालने में उन्हें मदद दी. उसकी मदद के चलते बाकी कॉमरेड़ सुरक्षित रिट्रीट हो सके.

कॉमरेड देवे अमर रहे!

कॉमरेड कुंजाम केशा (मल्ला)

2015 मई 17 को लगभग 1500 पुलिस बलों का डटकर मुकाबला करते हुए पीएलजीए ने तीन पुलिस जवानों को मार कर, दो को घायल किया. लेकिन इस घटना में कंपनी–2 के कमांडर कॉमरेड मासा के साथ कॉमरेड केशा भी अपनी जान न्योछावर की.

दरभा डिविजन के कांगेरघाटी एरिया के चांदामेट्टा गांव में वह पैदा हुआ. इस इलाके में सीपीआई (माओवादी) के नेतृत्व में क्रांतिकारी आंदोलन का विस्तार 2007 में हुआ था. तभी से कॉमरेड केशा ने बाल संगठन में काम करना शुरू किया. 2014 में वह पीएलजीए में भर्ती हुआ था. कुछ दिन बाद उसका तबादला कंपनी–2 में हुआ था. छोटी क्रांतिकारी जिंदगी में उसने कुछेक सैनिक कार्रवाईयों में शामिल होकर अपना योगदान दिया. अपनी आखिरी लड़ाई में उसने घायल कंपनी कमांडर कॉमरेड मासा को बचाने के लिए जान की परवाह न करते हुए आगे बढ़ कर दुश्मन से लोहा लिया. इसी कोशिश में वह शहीद हो गया. इस तरह कॉमरेड़ केशा एक आदर्श गुरिल्ला योद्धा के रूप में जनता के दिलों में सुस्थिर स्थान बना लिया.

कॉमरेड केशा अमर रहे!

कॉमरेड लिंगे

जून 2, 2015 को पश्चिम बस्तर डिविजन के वेच्चम गांव के पास हुई गोलीबारी में घायल हुई कॉमरेड लिंगे को पुलिस ने पकड़कर खूब यातनाएं देकर अत्याचार करके उसकी निर्मम हत्या की.

पश्चिम बस्तर डिविजन के भैरमगढ़ एरिया के वेश्रारम गांव में कॉमरेड लिंगे पैदा हुई थी. बचपन में उसने बाल संगठन में काम किया था. जबकि बड़ी होने के बाद केएएमएस में काम करने लगी थी. 2013 जुलाई–अगस्त में आयोजित पीएलजीए के भर्ती अभियान के दौरान वह पूर्णकालीन सदस्या बनी. लगभग दो साल जनता की मुक्ति के लिए अविराम काम करते हुए उसने शहादत को पाया.

कॉमरेड लिंगे अमर रहे!

कॉमरेड मड़कम देवे (कमला)

जून 12, 2015 को छत्तीसगढ़–तेलंगाना के पुलिस बल के संयुक्त आपरेशन के दौरान बीजापुर जिला, उसूर ब्लॉक, लंकापल्ली गांव के पास एक गुरिल्ला टीम पर घात लगाकर की गई आंधधुंध गोलीबारी में कॉमरेड कमला, जोगी व विवेक ने शहादत को पाया.

कॉमरेड कमला का जन्म बीजापुर जिले के चिन्नातर्रेम गांव में 25 साल पहले हुआ था. कमला ने पहले बाल संगठन में काम किया. बड़ी होने के बाद केएएमएस में काम करते हुए केएएमएस की गांव कमेटी अध्यक्षा की जिम्मेदारी भी संभाली. सलवा जुडुम के दौरान मिलिशिया में शामिल होकर प्रतिरोध में सक्रिय रूप से शामिल हुई थी. 2008 में वह पूर्णकालीन क्रांतिकारी बन कर जगरगुंडा एरिया के बासागुड़ा एलओएस सदस्या बनी. 2010 में उसकी तबादला उत्तर तेलंगाना में हुआ था. 2011 तक कंबैट प्लाटून में काम करने के बाद उसका तबादला केकेडब्ल्यू (खम्मम–करीमनगर–वारंगल) के एसजीएस (विशेष गुरिल्ला दस्ता) में हुआ था. वहां एक साल काम करने के बाद उसे उसी डिविजन के एटूरनागारम–महदेवपुर दस्ते में भेजा गया था. 2012 में उसे एसी सदस्यता दी गई

भीषण दमन का सामना करते हुए वह उस इलाके में डटी रही.

कॉमरेड कमला अमर रहे!

कॉमरेड कुहड़म जोगी (सोनी)

कॉमरेड कुहड़म जोगी ने पूर्वी गोदावरी जिले के चिंतूर मंडल जगारम गांव में 21 साल पहले जन्म लिया था. गांव के महिला संगठन में काम करते हुए 2010 में शबरी गुरिल्ला दस्ते में भर्ती हुई थी. बाद में उसका तबादला राज्य कमेटी स्टाफ में हुआ था. वहां उसकी जिम्मेदारी सटीक निभाते हुए एसी सदस्यता हासिल की.

कामरेड जोगी अमर रहे!

कॉमरेड नंदाल

29 जुलाई 2015 को शहीद सप्ताह को विफल करने आए पुलिस बल द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में कॉमरेड मुचाकी नंदाल व पोड़ियामी उंगाल शहीद हो गए.

दरभा डिविजन के हिरोली के मध्यम वर्गीय परिवार में 27 सालों पहले कॉमरेड नंदाल पैद हुआ था. इस इलाके में 2004 में क्रांतिकारी आंदोलन ने कदम रखा. गांव–गांव में संगठन बनने लगे, तो कॉमरेड नंदाल भी संगठन में शामिल हुआ था.

2008 में वह पूर्णकालीन कार्यकर्ता बन कर दरभा डिविजन के मलिंगेर दस्ते में शामिल हुआ था. कुछ दिन के लिए उसने जन मिलिशिया में काम किया था. 2009 में कॉमरेड नंदाल को नेतृत्व के गार्ड की जिम्मेदारी सौंपी गई. 2012 में वह कांगेरघाटी एलजीएस का डिप्टी कमांडर बना था. उसी साल वह गंभीर बीमारी का शिकार हुआ था. दो बार आपरेशन होने के बाद वह ठीक हो गया. बाद में उसका तबादला कटेकल्याण के पेद्दारास एलओएस में हुआ था. जिसमें उसने डिप्टी कमांडर का दायित्व उठाया था.

2014 में उसे एरिया कमेटी सदस्य के रूप में पदोन्नति देकर एरिया मिलिशिया कमांडर इन चीफ बनाया गया था.

कोकावाड़ां, गट्टाम नाईट एंबुश, टाहकावाड़ा आपर्चुनिटी एंबुश, बैलाडीला सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस पर किये गये एंबुश, इन सभी कार्रवाईयों में उसकी सक्रिय भागीदारी रही.

2014 में एक बूबीट्राप दुर्घटना में कॉमरेड विज्जा व हिड़मा की दर्दनाक मौत हुई थी जबकि कॉमरेड नंदाल गंभीर रूप से घायल हो गया था. ठीक होने के बाद वह दुबारा युद्ध भूमि में कूद पड़ा.

कॉमरेड नंदाल अमर रहे!

भेजागुड़ा शहीदों को लाल सलाम!

सितंबर 19, 2015 को उडिशा–छत्तीसगढ़ के सरहदी गांव भेजागुड़ा के पास कॉमरेड सोमा, लक्ष्मण, गासी को पुलिस ने निहत्थे पकड़कर, जनता की मौजूदगी में ही उन्हें क्रूर यातनाएं देकर उनकी निर्मम हत्या की और मलकनगिरी जिले के एक थाने में तीनों की लाशें ले गई.

जनता सैकड़ों की संख्या में जाकर तीनों कॉमरेडों के शव ले आयी. कॉमरेड गासी के शव का उनके गृह ग्राम में अंतिम संस्कार किया गया. कॉमरेड सोमा, लक्ष्मण को एक अज्ञात स्थान पर हजारों लोगों की मौजूदगी में क्रांतिकारी परंपराओं के मुताबिक अंतिम विदाई दी गयी.

भेजागुड़ा शहीदों की यादगार सभा में हजारों जनता ने उनके अधूरे सपने को साकार करने का संकल्प लिया.

कॉमरेड सोनाधर

जिला बीजापुर, बासागुड़ा क्षेत्र, पेदागेलूर ग्राम के एक आदिवासी मध्यम वर्गीय परिवार में 26 वर्ष पहले किशोर व सोनाधर के नाम से लोकप्रिय कॉमरेड़ सोमा का जन्म हुआ था. वह कारम लखमु, लखमी की तीसरी संतान था. मां–बाप के प्रोत्साहन से सोमा ने चौथी क्लास तक सारकेगुड़ा बालक आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी. छोटी उम्र में ही क्रांतिकारी बाल संगठन, छात्र संगठन का सदस्य बनकर क्रांतिकारी राजनीति के संपर्क में आ गया. क्रांतिकारी गीतों–बातों से प्रेरित होकर बीच में ही पढ़ाई छोड़कर गांव की मिलिशिया प्लाटून में भर्ती हुआ था. पीएलजीए में भर्ती होने के पार्टी आह्वान से प्रभावित होकर सोमा उत्साह के साथ भर्ती हुआ था. भर्ती होने के बाद उसे डीवीसीएम के गार्ड के रूप में सुरक्षा जिम्मेदारी दी गयी थी. 2004 में कॉमरेड सोमा का दरभा डिविजन में तबादला किया गया था. दरभा आन्दोलन की जरूरत अनुसार बनायी गयी 24 वीं प्लाटून का डिप्टी कमांडर का दायित्व कॉमरेड सोमा को सौंपा गया था. दरभा डिविजन में जितनी भी मिलिटरी कार्यवाहियां हुईं, सभी में सोमा प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर अनुभव हासिल किया था. उसने बैलाडीला नाइट एंबुश, माड़के, नकुर, नेतानार, बोडेम, ऐतिहासिक झीरम घाटी हमला, टाहकावाड़ा, दूधीरास एंबुशों में जांबाज योद्धा की तरह लड़ते हुए कार्यवाहियों को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभायी. इन सभी सैनिक कार्यवाहियों में सोमा सदस्य, सेक्सन

कमांडर, प्लाटून कमाण्डर की जिम्मेदारी निभायी. इसके अलावा एक्शन टीम का सदस्य बनकर दुश्मन को खत्म करके बन्दूक लाने में अपना योगदान दिया. माड़ेक एंबुश में खुद जख्मी होने के बावजूद शहीद लोकेश की लाश को फायरिंग जोन से उठाकर लाने में विशेष पहलकदमी दिखायी थी. पीएलजीए सदस्यों को हिम्मत से काम करने के लिए प्रेरित करता था. कॉमरेड सोमा पार्टी की पत्र–पत्रिकाओं का गंभीरतापूर्वक अध्ययन करता था. दूसरों को भी समझाता था. कॉमरेड सोमा कठोर मेहनत करता था.

2011 में जब कांगेर घाटी एसी का निर्माण हुआ था तब कॉमरेड सोमा को एरिया कमेटी सचिव जिम्मेदारी दी गयी थी. वह जनता के बीच में रहकर धुर्वा, हल्बी, भतरा, ओड़िया व हिन्दी भाषाओं को सीखा था. स्थानीय जनता की मूलभूत समस्याओं का अध्ययन कर हल करने में, साथ–साथ जनता को आन्दोलनों में गोलबन्द करने में कॉमरेड सोमा की कोशिशें बेमिसाल थीं. आत्मालोचना–आलोचना के जरिए गैर–सर्वहारा रूझानों से मुक्त होने हमेशा प्रयासरत रहता था. कॉमरेड सोमा शादी–शुदा था. वह अपनी जीवन साथी से स्नेहपूर्वक रहते हुए उसे राजनीतिक–सैनिक मामलों में मदद करता था.

दरभा डिविजन खासकर कांगेरघाटी संघर्ष के लिए कॉमरेड सोमा की शहादत एक बहुत बड़ी क्षति है. इसे भरने के लिए हम शपथ लेंगे.

कामरेड सोनाधर अमर रहे!

कॉमरेड माड़वी लक्ष्मण

कॉमरेड लक्ष्मण का जन्म दरभा डिविजन के मलिंगेर एरिया के पेड़का गांव के एक गरीब आदिवासी परिवार में हुआ था. 2004 में जब क्रांतिकारी आंदोलन उस इलाके में विस्तार हुआ था, तब आंदोलन के साथ कॉमरेड लक्ष्मण का परिचय हुआ था. 2007 में वह डीएकेएमएस सदस्य बना था. 2008 में उस संगठन की कमेटी में उसे लिया गया था.

2009 जुलाई में वह पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनकर पीएलजीए में भर्ती हो गया. कुछ दिन मलिंगेर एलजीएस में काम करने के बाद उसे गार्ड की जिम्मेदारी दी गई. उसके बाद उसे कांगेरघाटी में जन मिलिशिया कमांडर की जिम्मेदारी सौंपी गई. बढ़ती उसकी राजनीतिक व सांगठनिक क्षमता के अनुसार उसे एरिया कमेटी सदस्यता देने के अलावा एरिया कमांडर–इन–चीफ जिम्मेदारी भी सौंपी गई. डिविजन में संचालित कई सैनिक कार्रवाईयों में वह भाग लिया. नेतानार व टाहकावाड़ा एंबुशों में घायल होने के बावजूद उसने हिम्मत से लड़ते हुए उन एंबुशों को सफल बनाने में योगदान दिया. ऐतिहासिक झीरमघाटी हमले में भी उसकी सक्रिय भागीदारी थी.

कॉमरेड लक्ष्मण अमर रहे!

कॉमरेड मड़कम मूका (भास्कर)

दक्षिण बस्तर डिविजन के कोंटा एरिया के डब्बाकोंटा गांव के नजदीक गुरिल्ला दस्ते पर 19 नवंबर 2015 को दुश्मन द्वारा किए गए हमले का हिम्मत व साहस के साथ मुकाबला करते हुए कोंटा एलओएस कमांडर कॉमरेड भास्कर व कोंटा एरिया कमेटी की सदस्या व एरिया एमआई इंचार्ज कॉमरेड जोगी ने अपनी जान को न्योछावर किया.

दक्षिण बस्तर डिविजन के कोंटा एरिया के दरभागुड़ा के आदिवासी मध्यम वर्गीय किसान परिवार में कॉमरेड भास्कर पैदा हुआ. पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनने के पहले ही उसकी शादी हुई थी. चार बच्चों का बाप था, वह. बचपन में ही क्रांतिकारी आंदोलन के प्रति आकर्षित होनेवाला कॉमरेड भास्कर 1999 में डीएकेएमएस कमेटी के सदस्य बनकर आंदोलन में सक्रिय हुआ था. 2004 में परिवार को छोड़कर कोंटा दस्ते में भर्ती हुआ. चंद दिनों के बाद उसे कोंटा जन मिलिशिया कमांडर की जिम्मेदारी सौंपी गयी. 2006 में उसे पदोन्नति देकर एरिया कमेटी में लिया गया था व कोंटा एलओएस कमांडर की जिम्मेदारी सैंपी गई. इसके कुछ ही समय बाद बोट्टेम गांव के नजदीक पुलिस के साथ हुई गोलीबारी में कॉमरेड भास्कर बुरी तरह घायल हुआ था. इलाज के बाद दोबारा उसी एलओएस की जिम्मदारी अपने कंधों पर उठायी.

कॉमरड भास्कर अमर रहे!

कॉमरेड जोगी

कामरेड जोगी दक्षिण बस्तर डिविजन, कोंटा विकास खंड, मराईगुड़ा के बिलपारा में जन्म ली. बालक संगठन के जरिए उसने क्रांतिकारी आंदोलन में कदम रखा था. बड़ी होने के बाद वह केएएमएस में काम करने लगी थी. 2001 में उसे गांव के केएएमएस की अध्यक्षा बनी थी. 2000 में वह केएएमएस एरिया कमेटी में शामिल हुई थी. 2005 में उसे ग्राम पार्टी कमेटी सचिव व आरपीसी अध्यक्षा की जिम्मेदारियां सौंपी गई.

2006 में वह घर छोड़कर पूर्णकालीन कार्यकार्ता बनकर भेज्जी गुरिल्ला दस्ते में भर्ती हुई थी. 2011 में उसे एरिया कमेटी सदस्या की हैसियत दी गई और कोंटा एरिया पड़ियोरा (योद्धाओं) परिवार कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी गयी थी. 2013 में उसे एरिया खुफिया विभाग की जिम्मेदारी दी गई.

उसी जिम्मेदारी को संभालते हुए उसने शहादत को पाया.

कॉमरेड जोगी अमर रहे!

नांगलगुड़ा मुठभेड़ में शहीद हुई चार महिला साथियों को कोटि–कोटि लाल सलाम!

22 नवंबर 2015 को मुखबिर की सूचना पाकर आए पुलिस बल द्वारा दरभा डिविजन के नांगलगुड़ा में गुरिल्ला दस्ते पर की कई गोलीबारी में दरभा डिविजन की सप्लाई टीम कमांडर कॉमरेड रामे व सदस्या मासे, डिविजन समन्वय दस्ते की सदस्या कॉमरेड सन्नी व मलिंगेर दस्ते की सदस्या कॉमरेड पांडे शहीद हो गईं.

कॉमरेड रामे

कॉमरेड रामे का जन्म दक्षिण बस्तर डिविजन के किस्टारम एरिया के पालोड के मध्यम वर्गीय परिवार में 32 वर्ष पहले हुआ था.

छोटी उम्र में ही वह चेतना नाट्य मंच में शामिल हुई थी. 2003 में गांव की केएएमएस कमेटी की अध्यक्षा बनी. महिलाओं को गोलबंद करने पर वह विशेष ध्यान देती थी.

2005 में कॉमरेड रामे गुरिल्ला दस्ते की सदस्या बनी. किस्टारम एरिया में कुछ महीने काम करने के बाद उसका तबादला दरभा डिविजन में हुआ था. 2009 में उसे एरिया केएएमएस अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई. 2013 में उसका तबादला सप्लाई दस्ते में हुआ था. 2014 में उसे एसी सदस्यता देकर सप्लाई दस्ते की कमांडर की जिम्मेदारी दी गई थी.

उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए वह शहीद हो गई.

कॉमरेड रामे अमर रहे!

कॉमरेड मुचाकी सन्नी

कॉमरेड मुचाकी सन्नी (20) दरभा डिविजन के कुकानार से सटे पुसगुना के दुनामपारा निवासी थी. उसने पहले बाल संगठन में अपना योगदान दिया. 2014 में वह पेशेवर क्रांतिकारी के रूप में आंदोलन में दाखिल हुई. डिविजन समन्वय दस्ते में काम करते हुए वह शहीद हुई.

कॉमरेड सन्नी अमर रहे!

कॉमरेड माड़वी पांडे

दरभा डिविजन के मलिंगेर एरिया के तेनेली के आदिवासी गरीब किसान परिवार में 17 साल पहले कॉमरेड पांडे का जन्म हुआ था. छोटी उमर में ही क्रांति के प्रति उसमें आकर्षण पैदा हुआ था. नतीजतन 2014 जुलाई में 17 साल की उम्र में ही उसने प्रतिबद्धता के साथ जन युद्ध में कदम रखा था. उसका दाखिला मलिंगेर दस्ते में हुआ था. वहीं काम करते हुए वह शहीद हो गई.

कॉमरेड पांडे अमर रहे!

कॉमरेड मासे

दरभा डिविजन के चोलनार के एक गरीब परिवार में 25 वर्ष पहले कॉमरेड मासे पैदा हुई थी. बाल संगठन में शामिल होकर छोटी उम्र से ही क्रांति के लिए अपना योगदान देने लगी. 2008 में उसने केएएमएस अध्यक्ष की जिम्मेदारी ली.

2013 में वह पूर्णकालीन क्रांतिकारी बनकर पीएलजीए में भर्ती हुई थी. कुछ दिनों तक एरिया में काम करने के बाद उसका तबादला सप्लाई दस्ते में हुई थी. वहीं काम करते हुए उसने शहदत को पाया.

कॉमरेड मासे अमर रहे!

कॉमरेड पोड़ियाम कोसा (दूला)

27 नवंबर 2015 को माड़ डिविजन के कुतुल एरिया के कोडिलेर गांव के पास सर्चिंग पर आई पुलिस पर पीएलजीए ने हमला किया. इस दौरान कुछ देर तक हुई मुठभेड़ में कॉमरेड पोड़ियाम दूला ने दुशमन से हिम्मत के साथ लड़ते हुए शहादत को पाया.

कॉमरेड पोड़ियाम दूला का जन्म बीजापुर जिले के भैरमगढ़ एरिया में स्थित पोटेनार गांव के टिटोपारा में हुआ था. छोटी उम्र में उसने बाल संगठन में काम किया था. बाद में सीएनएम में सक्रिय भूमिका निभायी थी. 2009 में वह पार्टी में पूर्णकालीन कार्यकर्ता के रूप में भर्ती हुआ था. 2012 तक डिवीसी सदस्य का गार्ड रहा. नवंबर 2012 में उसका तबादला कंपनी–2 में हुआ था. कंपनी–2 में रहकर वह कई सैनिक कार्रवाइयों में भाग लिया था. वहीं काम करते हुए वह शहीद हो गया.

कॉमरेड दूला अमर रहे!

कॉमरेड कुड़ाम कोसा (बुधरा)

शुगर बीमारी के चलते तीव्र अस्वस्थता के शिकार होकर जगरगुंडा इलाके के वरिष्ट एसी सदस्य कॉमरेड बुधरा ने दिसंबर 3, 2015 को शहादत को पाया.

दक्षिण बस्तर डिविजन के जगरगुंडा एरिया के कुमोड़तोंग गांव के गरीब आदिवासी परिवार में 50 वर्ष पहले कॉमरेड कुड़ाम कोसा का जन्म हुआ था. 1980 के बाद जब क्रांतिकारी आंदोलन ने उस गांव में कदम रखा तभी से कॉमरेड कोसा का जीवन क्रांति के साथ जुड़ गया. डीएकेएमएस में शामिल होकर गांव के जन विरोधी मुखिया व फारेस्ट विभाग वालों के खिलाफ लड़ने में आगे थे. कुछ दिन के बाद उसी कमेटी के अध्यक्ष बने थे. 1998–99 में जब जगरगुंडा एरिया में रेंज कमेटी का गठन हुआ था,

कॉमरेड कोसा ने उसके अध्यक्ष की जिम्मेदारी ली. 2001 जून में वे पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनकर बासागुड़ा दस्ते में शामिल हुए थे. आंदोलन की जरूरत के मुताबिक बाद में उन्होंने उसूर व पामेड़ गुरिल्ला दस्तों में काम किया था. 2004 में उन्हें एरिया कमेटी की सदस्यता दी गई और पामेड़ एरिया के डीएकेएमएस के अध्यक्ष का पदभार सौंप दिया गया. बीमारी के बावजूद वे पार्टी द्वारा सौंपे गये कार्यों को तन मन लगाकर पूरा करते थे.

क्रांतिकारी आंदोलन ने एक अनुभवी कॉमरेड को खोया.

कॉमरेड बुधरा अमर रहे!

कॉमरेड दूधी पीसो

दरभा डिविजन के कांगेरघाटी एरिया के चांदामेट्टा गांव में जनता की मीटिंग संपन्न करके जा रहे दस्ते पर, रास्ते में घात लगाकर बैठे पुलिस बल ने अंधाधुंध गोलीबारी की. जिसमें कॉमरेड पीसो (24) नेतृत्वकारी कॉमरेडों को बचाने दुश्मन के साथ हिम्मत से लड़ते हुए शहादत हासिल की.

दरभा डिविजन के कनकापाल पंचायत के झीरम गांव की निवासी थी, कॉमरेड पीसो. 2007 में जब क्रांतिकारी आंदोलन की गतिविधियां उस इलाके में शुरु हुई थी, तभी से कॉमरेड पीसो गुरिल्ला दस्ते के पास आना–जाना करती थी. 2009 में उसने गांव के जीआरडी में भर्ती होकर गांव की सुरक्षा में योगदान दिया. ऐतिहासिक झीरमघाटी हमले जिसमें कुख्यात व खुंखार सलवा जुडुम सरगना महेंद्र कर्मा का सफाया किया गया था, में उसने संपूर्ण मदद दी.

2014 जून में वह पीएलजीए में भर्ती हुई थी. 2015 जून में उसे पार्टी सदस्यता दी गई. बाद में कांगेरघाटी एलओएस में उसका तबादला भी हुआ था. उसी दस्ते में अपना कार्यभार संभालते हुए वह शहीद हो गई.

कॉमरेड पीसो अमर रहे!

कॉमरेड कुड़ियम कमला

पश्चिम बस्तर डिविजन के मद्देड एरिया के गोट्टम गांव के पास जनवरी 6, 2016 को सरकारी भाड़े के सशस्त्र बलों के साथ लड़ते हुए कॉमरेड कुड़ियम कमला शहीद हो गई.

कॉमरेड कमला बीजापुर जिले के मोदोकपाल पंचायत के पगनपल्ली गांव की निवासी थी. 2006 में पूर्णकालीन कार्यकर्ता के रूप में वह पीएलजीए में भर्ती हुई थी. मद्देड एरिया में काम करते हुए वह शहीद हुई.

कॉमरेड कमला अमर रहे!

कॉमरेड हेमला लच्छी

छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व केन्द्रीय अर्ध–सैनिक बलों द्वारा जनवरी 11, 2016 को बीजापुर जिले के नेशनल पार्क एरिया के कोकेरा गांव के नजदीक पीएलजीए की एक टीम पर की गई अंधाधुंध गोलीबारी में कॉमरेड लच्छी घायल हुई थी. पुलिस ने उसे पकड़कर खूब यातनाएं देकर उसकी निर्मम हत्या की. कॉमरेड हेमला लच्छी 22 वीं प्लाटून की पीपीसी स्तर की कामरेड थी.

वह बीजापुर जिले के गंगालूर एरिया के सावनार गांव की निवासी थी. छोटी उम्र में उसने बाल संगठन में काम किया था. बड़ी होने के बाद वह केएमएस व मिलिशिया की सक्रिय कार्यकर्ता बनी.

वह 2008 जनवरी में पीएलजीए में भर्ती हुई थी. कुछ दिन गंगालूर एरिया में काम करने के बाद 2009 में उसका तबादला कंपनी–9 में हुआ था. तब से 2014 मार्च तक उसने जाटालूर, भामरागढ़ एरिया में काम किया था. 2014 मार्च में उसका तबादला 22 वीं प्लाटून में हुआ था. वहीं काम करते हुए उसने शहादत को पाया.

कॉमरेड लच्छी अमर रहे!

कॉमरेड बेगाम लक्ष्मी (रोशनी)

3 मार्च 2016 को नारायणपुर जिला, माड़ डिविजन, कुतुल एरिया के होकपाड़ गांव के के पास पीएलजीए द्वारा पुलिस बैच के ऊपर किए गए हमले में दुश्मन के साथ मुकाबला करते हुए कॉमरेड रोशनी ने शहादत को पाया.

बीजापुर जिले के भैरंगढ़ ब्लॉक के मिरतुल एरिया के पेदम गांव में कॉमरेड रोशनी पैदा हुई थी. शोषण विहीन समाज का सपना देखते हुए जन युद्ध में शामिल होकर अपनी अनमोल प्राण न्योछावर करने वाली कॉमरेड रोशनी जनता की स्मृतियों में हमेशा जिंदा रहेगी.

कॉमरेड रोशनी अमर रहे!

कॉमरेड होड़ी लालु (सुनिल)

माड़ डिवीजन कमेटी सदस्य व डिवीजनल कमांडर–इन–चीफ कॉमरेड सुनिल एक एंबुश के लिए

माईन कनेक्शन देते समय दुर्घटनावश माइन के विस्फोट हो जाने के चलते शहीद हुआ. 17 मार्च 2016 को इस दुःखद घटना घटी. 2001 से पार्टी में कई जिम्मेदारियां निभाते आ रहे कॉमरेड सुनिल की शहादत उत्तर सब जोनल ब्यूरो आंदोलन, विशेषकर माड़ डिवीजन आंदोलन के लिए बहुत बड़ा नुकसान है.

इंद्रावती एरिया डुंगा गांव के सोरी परिवार में कॉमरेड सुनिल का जन्मा हुआ. उसका क्रांतिकारी सफर बाल संगठन से शुरू हुआ.

2000 में पार्टी में भर्ती होकर कॉमरेड सुनिल ने माड़ डिवीजन में काम किया. पहले नेलनार एलओएस में कुछ दिन काम किया. जब पीएल–1 का गठन हुआ तब कॉमरेड सुनिल का तबादला उसमें हुआ था. उसने सात साल यानी 2010 तक उसी प्लटून में काम किया. उसकी सक्रियता व राजनीतिक चेतना को देख कर उसे पीपीसी सदस्यता दी गई. उसे पहले उस प्लटून के डिप्टी कमांडर व बाद में कमांडर की जिम्मेदारी भी दी गई. 2003 में गीदम रेड में व 2004 में कोरापुट रेड में वह शामिल हुआ था।

2009 मार्च में कॉमरेड सुनिल को डीवीसी सदस्य की पदोन्नति दी गई। उस समय इंटिलिजेंस काम शुरू किया गया था. तब कॉमरेड सुनिल को कमेटी ने यही जिम्मेदारी दी थी. 2012 में संपन्न डिवीजन प्लीनम के बाद से उसे एमआई की पूर्णकालिक जिम्मेदारी दी गई थी.

सैनिक काम, इंटिलिजेंस काम के साथ–साथ सांगठनिक कामों पर भी वह विशेष ध्यान देता था. वह किसी के साथ, कहीं भी रहने पर गांव के पार्टी संगठन, सरकार, मिलिशिया, जन संगठन आदि निर्माणों की मीटिंग करता था. मीटिंग संचालित करने की योजना बनाता था. जनता के साथ रहते हुए, राजनीतिक प्रचार का काम संचालित करता था. निर्माणों में आने वाली समस्याओं की चर्चा करके हल करता था और साथी कॉमरेडों को मार्गदर्शन देता था.

कॉमरेड सुनिल ने माड़ आंदोलन को आगे ले जाने के लिए 16 साल तक खूब मेहनत की. कॉमरेड सुनिल अपने क्रांतिकारी जीवन में जनता से सीखना, जनता को सिखाना, कठिन परिश्रम करना, हिम्मत व साहस के साथ काम करना, बलिदान के लिए हमेशा तैयार रहना आदि कम्युनिस्ट मूल्यों पर अमल किया था.

कॉमरेड सुनिल अमर रहे।

तिरका शहीदों को लाल सलाम

29 मार्च 2016 की सुबह के 11.30 बजे पूर्व बस्तर डिवीजन के वयानार इलाके के तिरका व सुलेंगा के जंगल में जिला पुलिस बल, आईटीबीपी, सीएएफ, एसटीएफ व पुलिस के पालतू कुत्ता गैंग डीआरजी के 700 सरकारी सशस्त्र बलों के साथ हुई जबरदस्त मुठभेड़ में हिम्मत व साहस के साथ लड़ते हुए वयानार एलओएस कमांडर, पीएलजीए का जांबाज योद्धा कॉमरेड अजय, एसी सदस्य कॉमरेड लादेन, एलओएस सदस्या कॉमरेड रणिता ने शहादत को पाया.

कॉमरेड सोनारु कोर्राम (अजय)

कॉमरेड सोनारू कोर्राम (अजय) ने माड़ डिवीजन के कोहकामेट्टा एरिया, नारायणपुर जिला, इर्कभट्ठी गांव में 31 साल पहले जन्म लिया था. वह गांव के स्कूल में पढ़ते समय ही मिलिशिया में भर्ती हुआ. गांव के चेतना नाट्य मंच–सीएनएम में भी उसने काम किया. सैनिक व राजनीतिक ज्ञान हासिल करते हुए ही वह पेशेवर क्रांतिकारी के रूप में भर्ती हुआ. पार्टी में भर्ती होने के बाद एक साल तक सीएनएम में काम किया. बाद में एसजडसीएम के गार्ड की जिम्मेदारी देकर उसका तबादला किया गया था. 2008 में उसका तबादला कंपनी–1 में हुआ था. कंपनी–1 में रहते हुए वह कई मिलिटरी कार्रवाइयों में शामिल हुआ था. मिलिटरी कामों में उसकी सक्रियता को देखते हुए 2009 में उसे पूर्व बस्तर मिलिशिया के लिए तबादला किया गया था. मिलिशिया को संगठित व प्रशिक्षित करते हुए उसने बहुत सारी प्रतिरोध कार्रवाइयों में मिलिशिया को शामिल किया था. 2011 के जारा फ्रंटल अटैक में उसने अपने साहस का परिचय दिया। उसने वयानार कैंप के ठीक सामने बैठे पुलिस जवानों पर अकेले हमला किया था जिसमें एक जवान को खत्म करके दो को घायल किया था. इसी हमले में खुद भी घायल हुआ था. उसके बावजूद वह हिम्मत के साथ रिट्रीट हुआ था. हाथ में गोली लगने व अपनी बंदूक हाथ से छूट जाने के बावजूद उसने दुश्मन की एक बंदूक लेकर आया था.

हाथ ठीक होने के बाद वह फिर से अपनी जिम्मेदारी निभाने में लग गया था. डिवीजन के वयानार एरिया के एरिया कमाण्डर–इन–चीफ की जिम्मेदारी उसने ली. मिलिटरी में बहुत ही अनुभवी कॉमरेड अजय ने सांगठनिक काम भी सीख लिया था. हाथ पूरी तरह ठीक न होने के बावजूद वह हमेशा पार्टी द्वारा सौंपी गयी जिम्मेदारी को चाहे वह सांगठनिक हो या सैनिक, स्वीकार करने में आगे–पीछे नहीं होता था. पार्टी जरूरतों को वह पहली प्राथमिकता देता था. समस्याओं, तकलीफों, बीमारी, लगातार बढ़ता दमन आदि का डटकर सामना करते हुए आखिरी

पीएलजीए प्रतिरोध

पश्चिम बस्तर डिवीजनः जुलाई से दिसंबर तक डिवीजन में भाड़े के सरकारी सशस्त्र बलों पर जनता के सहयोग से पीएलजीए के तीनों बल मिलकर हमला करके 9 पुलिस जवानों को खतम करके 12 जवानों को घायल किया था.

नेशनलपार्क एरिया के कुटरु क्षेत्र में जुलाई 12 को पकड़कर, 13 को चार अत्याचारी व आततायी एसपीओ जो वर्तमान में सहायक आरक्षक के नाम से काम कर रहे थे, को जनता की मांग पर मौत की सजा दी गयी. ये जुडुम के समय जनसंगठन के कार्यकर्ताओं एवं पीएलजीए के सदस्यों की हत्या में शामिल थे.

अगस्त 19 को मद्देड़ एरिया के गांव गोटुम के पास पीएलजीए द्वारा गश्त पर आए पुलिस संयुक्त बल पर हमला किया गया था. इसमें एक सीआरपीएफ जवान खत्म हुआ और तीन जवान घायल हुए. आवापल्ली, मुरकीनार, मुरदोण्डा, बीजापुर घाटी में बुबीट्राप्स के विस्फोटों में 5 जवान घायल हुए और एक जवान मारा गया.

भैरमगढ़ में 28 अक्टूबर को पण्डेमुरगा के पास प्रेशर बम फटने से एक सीएएफ जवान मारा गया. नेशनलपार्क एरिया में फरसेगढ़ में पदस्थ एक एसपीओ को मार दिया गया था. अगस्त में जुडूम नेता कोरसा पीडू को पीएलजीए द्वारा बीजापुर कैंप में मार डाला गया. इसके अलावा भैरमगढ़ के पास बट्टूम गांव में जन दुश्मन रहे दो जुडूम नेताओं को मौत की सजा दी गयी. गंगालूर के गांव तोड़का के भूतपूर्व सरपंच ताती सोमलू को जनादालत में रखकर उनकी पार्टी विरोधी, जनविरोधी गतिविधियों के लिए मौत की सजा दी गई. चेरपाल में पुलिस मुखबिरी कर रहे एक पूर्व एसपीओ को दिसंबर के पहले सप्ताह में मार दिया गया था. गश्त पर आए पुलिस जवानों पर इतवार, नेण्ड्रा

सांस तक आन्दोलन में खड़ा होकर जनता के लिए जान देने वाले कॉमरेड अजय की बोल्शेविक स्फूर्ति से सभी को सीख लेनी चाहिए.

कॉमरेड अजय अमर रहे!

कॉमरेड गांडो (लादेन)

कॉमरेड लादेन पूर्व बस्तर डिवीजन के वयानार एरिया के मुंड़पाल गांव के थे. उनका घर का नाम गांडो था. कॉमरेड लादेन डीएकेएमएस से अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत की थी. अपने गांव के आस–पास के गांवों की जनता को संगठित करके उनकी समस्याओं के हल के लिए आन्दोलनों में उन्हें गोलबंद करते थे. जनता पर जारी सरकारी जुल्म, अत्याचार के खिलाफ राजनीतिक प्रचार करते थे. इलाके के डीएकेएमएस नेता की हैसियत से उनका काम काफी सराहनीय था. दूसरी तरफ दुश्मन उन्हें बहुत खतरनाक समझता था. उनके लिए लगातार गांव और इलाके पर हमले करता था. इन परिस्थितियों में कॉमरेड लादेन ने पार्टी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में भर्ती होने का निर्णय लिया. वे भर्ती के बाद 2011 से एरिया के जनपक्षधार सियानों को संगठित करने की जिम्मेदारी बढ़िया संभाल रहे थे. गांव–गांव में कमेटी निर्माण कर एरिया स्तर तक कमेटी का विस्तार किया. बहुत सारे जन आंदोलनों में जनता को गोलबंद करने व उनका स्थानीय नेतृत्व विकसित करने में कॉमरेड लादेन की सराहनीय भूमिका रही. गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को लेकर, राज्यहिंसा व विस्थापन के खिलाफ, मुठभेड़ों में शहीद हुए साथियों व जनता की लाशों को लाने संबंधी आन्दोलनों, रैलियों, सभाओं में जनता को गोलबंद करने में कॉमरेड लादेन का महत्वपूर्ण योगदान रहा. सेना के खिलाफ भी विशाल जन आंदोलन खड़ा करने में कॉमरेड लादेन का ठोस योगदान रहा. कॉमरेड लादेन की उम्र 45 वर्ष से भी अधिक थी. डयाबिटीज (सुगर), हाई बीपी आदि स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करने के बावजूद उनके मन में जनता के प्रति जो सेवा भावना, असीम प्यार था, वह बहुत ही आदर्शनीय था. उनकी दृढ इच्छा शक्ति, सादगी, जनता के ही लिए जीने और मरने की उच्च चेतना हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेगी.

कॉमरेड लादेन अमर रहे!

कॉमरेड जानकी हलामी (रनिता)

कॉमरेड रनिता 25 वर्ष की थी. गांव एहरा, उसिरी पंचायत, कोण्डागांव जिले के अंर्तगत आता है. गांव में आते–जाते दस्ते के साथ पहले धीरे–धीरे परिचय हुआ. उसके बाद मिलिशिया में भर्ती हुई. मिलिशिया में काम करते हुए राजनीति सीखी, वर्ग संघर्ष के बारे में समझी व 2009 में पार्टी में भर्ती हुई थी. पार्टी में भर्ती होने के बाद कुछ दिन तक टेलर टीम में रही. एकदम नया काम होने के बावजूद लगन के साथ सीखने की कोशिश करती रही. वहां से तबादला होकर केशकल एरिया में मौजूद प्लाटून–17 में काम करती रही. बाद में उसे डीवीसीएम की गार्ड की जिम्मेदारी दी गयी. गार्ड ड्यूटी से रिलीव होकर वयानार एलओएस की सदस्या बनी. कॉमरेड रनिता शारीरिक रूप से कमजोर रहने के बावजूद पार्टी के द्वारा दिये गए हर काम करने में आगे रहती थी. बढ़ते दमन में रोज चलने वाले गश्त अभियानों के बीच हिम्मत न हारते हुए कॉमरेड रनिता मजबूती से खड़ी थी. दुश्मन के प्रति वर्गीय नफरत उसमें इस कदर मजबूत थी कि उसका समाचार मिलते ही वह एंबुश टीम में जाने के लिए छटपटाती थी. ❍

के पास हमला करके दो पुलिस कमाण्डों को घायल किया गया था.

बंद, हड़ताल के समय एनएमडीसी के 76 वाहन, रोड़ निर्माण में लगी 36 गाड़ियों को जला दिया गया था. रेल रिपेर करने वाली एसी गाड़ी को भी ध्वस्त किया गया था.

दक्षिण बस्तर डिवीजनः जुलाई से लेकर दिसंबर तक के प्रतिरोध में पीएलजीए ने 4 पुलिस जवानों को खत्म किया और 25 जवानों को घायल किया. अगस्त माह में डल्ला के पास संयुक्त गश्ती दल पर हमला करके 2 पुलिस जवानों को घायल किया. अक्टूबर 8, 2015 को भेज्जी के पास बुबीट्राप विस्फोट में सीआरपीएफ के 3 जवान घायल हुए. इसी दिन चिंतागुफा के पास पुलिस पर की गई फायरिंग में 3 जवान घायल हुए. 19 अक्टूबर को सारकेनगुड़ा के पास बुबीट्राप विस्फोट में 2 जवान घायल हो गए. अक्टूबर 26 को मराईगुड़ा के पास रात में गश्त पर आई पुलिस पर पीएलजीए ने हमला किया जिसमें एक जवान वहीं खतम हुआ जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ था. नवंबर में सरकेनगुड़ा के पास एक पुलिस जवान, चिंतालनार के पास एक पुलिस जवान को पीएलजीए ने घायल किया. 8 दिसम्बर को पीएलजीए स्थापना सप्ताह के मौके पर कुंबिंग अभियान पर आई पुलिस के संयुक्त गश्ती दल पर टेटेमड़गु के पास हमला करके 5 पुलिस कमाण्डो को घायल किया था. दिसंबर 9 को आरनपुर–जगरगुंड़ा सड़क निर्माण की सुरक्षा में तैनात 2 जवान बुबीट्राप के फटने से घायल हो गये. इनमें से एक असिस्टेंट कमाण्डेंट था. इसके अलावा 2 दफे दोरनापाल–चिंतलनार के बीच हमला करके पीएलजीए ने पुलिस की सप्लाई जब्त की. अगस्त 21 को पोलेमपल्ली में पदस्थ पीलादास नामक एक एसपीओ को भी हमारी पीएलजीए ने खत्म किया. इसी दौरान 4 पुलिस मुखबिरों, 21 अगस्त को जगरगुण्डा, कुण्डेर के पास जुडूम नेता उईके लखमा को जनता की मांग पर मौत की सजा दी गयी.

दरभा डिवीजनः जुलाई से लेकर दिसंबर तक पुलिस पर हमले करके पीएलजीए ने 3 पुलिस जवानों, दो गोपनीय सैनिकों को खत्म करके 7 पुलिस जवानों को घायल किया है. एक पिस्तौल जब्त की है.

कट्टेकल्याण एरिया में पीएलजीए ने चार दिन तक एक ही दफा खाना खाते हुए, बिना नींद, भूखे पेट पुलिस पर दिन–रात एंगेज होकर 3 दफे फायरिंग की जिसमें एक पुलिस जवान मारा गया और एक जवान घायल हुआ. जनता द्वारा खोदे गए गड्ढों में गिरकर तीन पुलिस जवान घायल हुए.

अगस्त में कुंबिंग के लिए आ रहे कमाण्डो फोर्स पर पीएलजीए ने हमला किया जिसमें एक प्लाटून असिस्टेंट कमाण्डर खत्म हुआ और एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ. सितंबर 4, 2015 को मलिंगेर एरिया के पालनार साप्ताहिक बजार में पुलिस के असिस्टेंट कमाण्डेंट पर चाकू, फरसा से वार कर, उनके गार्ड के आंखों में मिर्च पाऊडर डालकर पीएलजीए योद्धाओं ने उसकी पिस्तौल छीनकर लायी थी. पुलिस के चौतरफा पहरे के बीच पीएलजीए द्वारा सृजनात्मक ढ़ंग से हमला करके पिस्तौल जब्त करके लाना एक शानदार मिसाल है. इसके अलावा सितंबर माह में एक गोपनीय सैनिक को, दिसंबर में एक गोपनीय सैनिक को, तीन मुखबिरों को पीएलजीए, जनता ने मिलकर सजा दिया था.

कुल मिलकर पूरे दक्षिण सब जोन में जुलाई से दिसंबर तक के हमलों में पीएलजीए ने सरकारी सशस्त्र बलों के 16 जवानों को खत्म करके 44 जवानों को घायल किया था.

2016 में हुई कुछ घटनाएंः

पखंजूर एरिया के संगम गांव के साप्ताहिक बाजार में 2016 फरवरी 13 की सुबह पुलिस जवानों पर पीएलजीए की एक छोटी टुकड़ी ने हमला किया जिसमें बीएसएफ के खुफिया विभाग का एक जवान मारा गया. बीएसएफ कैंप से महज सौ मीटर दूरी पर पीएलजीए ने सूझ–बूझ व दमखम के साथ यह हमला किया था.

अरनपुर–जगरगुंडा मार्ग पर अरनपुर के अटामीपारा के नजदीक 2016 फरवरी 21 की सुबह रोड़ ओपनिंग पार्टी पर पीएलजीए द्वारा की गयी आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के एक असिस्टेंट कमांडेंट सहित दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गए.

बोट्टेम में पीएलजीए पर हमला करके हमारे 9 प्यारे कॉमरेडों की हत्या करके वापस जाते सारकारी सशस्त्र बलों की सूचना पाकर पीएलजीए ने मार्च 3, 2016 को सुकमा जिले के डब्बामरका में उन पर जबर्दस्त हमला बोला था. इस़में कोबरा बल के 3 जवान मारे गए व 17 जवान घायल हो गए. इस बड़े व साहसिक हमले के दौरान पुलिस जवानों को पीएलजीए ने काफी दूर तक खदेड़ा था. दिन भर चली इस मुठभेड़ में पीएलजीए ने करीबन सौ पुलिस जवानों की घेराबंदी कर रखी थी. दूसरे दिन मौका–ए–वारदात पर 700 की संख्या में पहुंचे अतिरिक्त बलों के सहारे घेराबंदी में फंसे जवान हमारे इलाके से जान बचाकर भागने में सफल हुए.

2016 मार्च 30 को दंतेवाडा जिले के मैलावाड़ा के पास पीएलजीए द्वारा की गई बारूदी सुरंग विस्फोट व गोलीबारी में सीआरपीएफ के सात जवान मारे गए जिनमें एक एएसपी भी शामिल है.

❍

दमन को धत्ता बताते हुए संघर्ष की राह में आगे बढ़ती जनता प्रतिरोध की अग्रिम पंक्ति में महिला

दिन–ब–दिन बढ़ते दमन की परिस्थिति में जनता के सामने प्रतिरोध के बिना कोई रास्ता नहीं बचा है. इस प्रतिरोध में महिलाओं की भागीदारी सराहनीय है. कुछ घटनाओं में महिलाएं अपने वर्ग सहोदरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष के रास्ते में अगे बढ़ रही हैं. जबकि कुछ अन्य घटनाओं में अपने वर्ग सहोदरों का नेतृत्व कर रही हैं. मिली खबरों के अनुसार विगत साल भर में दण्डकारण्य के विभिन्न डिविजनों में जनता व खासकर महिलाओं का प्रतिरोध काफी जोशीला व प्रेरणादायक रहा. प्रभात के पाठकों के लिए हम यहां प्रतिरोध की कुछ रपटें संक्षेप में दे रहे हैं.

दक्षिण बस्तर

पामेड एरिया

9 जून 2015 को लच्छू नाम के एक ग्रामीण को चेरला पुलिस ने पकड़ा था. इस खबर पाकर जारापल्ली की महिलाएं करीब 10 किलो मीटर पैदल चलकर, बहादुरी का परिचय देते हुए दुश्मन के साथ निहत्थे जूझकर लच्छू को छुड़ा लायी.

12 जुलाई 2015 को पामेड़ पुलिस ने दिनदहाड़े धरमारम गांव का घेराव कर लिया था. 18 निर्दोष ग्रामीणों को गिरफ्तार करके बेरहमी से मार–पीट कर उन्हें पुलिस अपने कब्जे में रखा था. घरों में घुसकर जनता की संपत्ति को लूटा था. इसे देख दसियों की तादाद में इकट्ठी महिलाओं ने हाथ लगे डंडे व पत्थर लेकर पुलिस का प्रतिरोध करती हुई पकड़े गए सभी ग्रामीणों को उनके चंगुल से छुड़ा लायी.

अगस्त माह में बासागुड़ा–सारकेगुड़ा कैंप की पुलिस रात में गुंडाम गांव को घेरकर 17 किसानों को पकड़कर बासागुड़ा थाना ले गयी थी. इस घटना से गांव में दहशत फैल गयी. जनता का डर यह था कि कितने लोगों को जेल भेजेंगे, कितने लोगों की झूठी मुठभेड़ में हत्या करेंगे. गांव के तकरीबन 200 महिलाएं व 14 पुरुष बासागुड़ा थाना पहुंच गए. सभी लोग एक ही स्वर में जोरदार प्रतिरोध करने लगे. उन्होंने पुलिस से कई सवाल करते हुए थाने के समाने प्रदर्शन किया. जनता के बढ़ते आक्रोश को देखकर आखिर सभी 17 लोगों को पुलिस ने छोड़ दिया था.

27 अगस्त 2015 को गश्त पर निकली बासागुड़ा पुलिस ने डल्ला गांव पर हमला कर एक ग्रामीण को पकड़ा था. उसे बासागुड़ा थाने में रखकर मार–पीट करने लगी. पुलिस के पीछे–पीछे थाने जाकर महिलाओं ने लड़–भिड़कर उसे छुड़ा लायी.

18 अक्तूबर 2015 की आधी रात में सैकड़ों पुलिस जवानों ने पोलमपल्ली गांव पर हमला किया था. उस दौरान एक व्यक्ति को जो घर में सो रहा था, उठाकर ले जाने की कोशिश की. यह खबर लगते ही रात ही रात महिलाओं ने इकट्ठी होकर दुश्मन के साथ बहादुरी से लड़कर उसे बचा लिया.

कोंटा एरिया

16 फरवरी, 2015 को भेज्जी, कोत्ताचेरू, गोरखा बेस कैंप से आए सीआरपीएफ, कोबरा व डीआरजी के 300 से अधिक जवानों ने भंडारपदार गांव पर धावा बोलकर गादी पंडुम मना रही जनता से मार–पीट की. मुचाकी हिड़मा, मुचाकी आयते, मुचाकी कोसी, वंजम हड़मा, सोडी देवा, व पोड़ियम मासा को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वे कई दिन चल न सके. बाद में पुलिस सभी को भेज्जी थाना ले गयी. जनता पर जुल्म ढ़ाने के अलावा दुश्मन जनता के कपड़े, 23,000 रुपए, परंपरागत हथियार व अन्य समान लूटकर ले गया. मार खाने के बावजूद गांव की महिलाएं पुलिस के पीछे–पीछे जाकर सभी को छुड़ा लायीं.

चिंतागुफा में तैनात सीआरपीएफ, कोबरा जवान 31 मार्च, 2015 को जब रोड़ ओपनिंग के लिए निकले थे तब पीएलजीए ने उन पर हमला कर एक जवान को खत्म किया था. इससे भयभीत पुलिस ने जंगल में अंधाधुंध गोलीबारी की. इसके अलावा अपने खेत में महुआ बिन रहे चिंतागुफा के निवासी कवासी कोसा की हत्या करके उसकी लाश को सुकमा ले जाकर ऐसा दावा किया कि एक नक्सलवादी मुठभेड़ में मारा गया. इस खबर सुनकर न सिर्फ कोसा के परिजनों बल्कि आस–पास के गांवों की जनता, जिनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा थी, ने सुकमा जाकर अपना कड़ा विरोध दर्ज किया.

बाद में लाश को चिंतागुफा थाने के सामने रखकर घेराव किया. आक्रोशित महिलाएं डंडे व पत्थर के साथ पुलिस पर टूट पड़ी जिसके चलते दो जवान घायल हो गये.

3 नवंबर, 2015 को दोरनापाल व पोलमपल्ली से आए पुलिस बल ने अरलमपल्लि गांव पर हमला करके अपने खेतों में काम कर रहे तीन बेकसूर ग्रामीणों को पकड़ कर उनकी निर्मम हत्या करके यह दावा किया कि मुठभेड़ में तीन माओवादियों को मार दिया गया.

पुलिस के इस अमानवीय करतूत के विरोध में सौ

लोग जिनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा थी, ने दोरनापाल में जुलूस निकाल कर यह मांग की कि दोषी जवानों को सजा दी जाए.

इसी एरिया के डब्बाकोंटा गांव के नजदीक गुरिल्ला दस्ते पर 19 नवंबर, 2015 को दुश्मन द्वारा किए गए हमले का हिम्मत व साहस के साथ मुकाबला करते हुए कोंटा एलओएस कमांडर कॉमरेड भास्कर व कोंटा एरिया कमेटी सदस्या व एरिया एमआई इंचार्ज कॉमरेड जोगी ने अपनी जान न्योछावर की. पुलिस इनके शवों को सुकमा ले गयी थी. इलाके की जनता सुकमा जाकर पुलिस के साथ जमकर लड़ाई करके लाशें लायीं थीं. हजारों लोगों की मौजूदगी में उन्हें अंतिम विदाई दी गई थी.

जगरगुंडा एरिया

मार्च 16, 2015 की अलसुबह 4 बजे चिंतलनार चौकी की पुलिस ने तोंगुड़ा गांव का घेराव कर 4 जन से मार–पीट की जबकि माड़वी देवा नाम के ग्रामीण को अपने साथ पोलमपल्ली कैंप ले गयी. गांव की 40 महिलाएं व तीन पुरुष पोलमपल्ली जाकर भूखे पेट ही दिन भर पुलिस से लड़कर अपने गांववासी को बचाने में कामयाब हुए.

31 मार्च, 2015 को बुरकापाल में अपने खेतों में मछली पकड़ रहे 9 लोगों को पुलिस जबरदस्ती उठा ले जाकर दोरनापाल थाने में रखा था. नक्सली समर्थक बताकर उन्हें कई यातनाएं दी गई. 90 महिलाएं दोरनापाल पुलिस के साथ लड़कर हिरासत से 9 जन को छुड़ा लायीं.

5 अगस्त, 2015 को चिंतलनार साप्ताहिक बाजार गए लोगों को पुलिस ने घेर कर पकड़ा था. पकड़े गऐ लोगों में सुरपनगुड़ा, मोरपल्ली, सिलंगेर और पेदा बोड़केल के लोग शामिल थे. उन सभी लोगों पर किसी को संगठन नेता, किसी को मिलिशिया वाले, किसी को नक्सली समर्थक कहकर सरेंडर के लिए दबाव डाला. ऐसी धमकी भी दी गई कि अगर वे आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो मारे जाऐंगे या जेल भेजे जायेंगे. पलिस की इस तरह की हरकतों को देख महिलाएं जो बाजार करने गयीं थीं, पुलिस के साथ भिड़ गयी. उन्होंने थाने को भी घेर कर प्रदर्शन किया. महिलाओं के गुस्से के नतीजतन 5 जन को जेल भेज दिया गया. जबकि बाकी लोगों को छोड़ दिया गया.

19–20 अगस्त 2015 को बासागुड़ा–सारकेगुड़ा पुलिस ने बुड़गीचेरू, पिसेपारा, चिनागेलूर, कोत्तागुड़ा, गुंडाम, पूसबाका व चिपुरभट्टी गांवों पर हमलें किए. इस दौरान डरा धमकाकर जनता के हजारों रुपये व अन्य सामानों को लूटा था. बड़े पैमाने पर सामाग्री ध्वस्त की थी. वापस जाते समय पुलिस मिलिशिया सदस्य कॉमरेड हेमला रामसू, सोड़ी बिच्छेम की हत्या कर शवों को बीजापूर ले गयी थी. यह खबर लगते ही आस–पास के गांवों की महिलाएं इकट्ठी होकर बीजापूर जाकर शवों को लायी.

पुलिस बल ने 20 सितंबर, 2015 को कोरसागुडा के तीन ग्रामीणों को खेतों से पकड़ कर बेरहमी से पिटाई की. बाद में उन्हें सारकेगुड़ा कैंप में ले जाया गया. खबर लगते ही 40 महिलाएं इकट्ठी होकर कैंप जाकर पुलिस के साथ लड़कर तीनों ग्रामीणों को छुड़ा लाई.

14 अक्तूबर, 2015 को सुरपनगुड़ा के सोड़ी रमेश को नरसापुरम जाते समय रास्ते में ही पुलिस ने दबोचा. कैंप में ले जाकर उसे खूब यातनाएं दी. इसके विरोध में पंचायत की जनता जिनमें करीब 120 महिलाएं, 70 पुरुष थे, नरसापुरम कैंप का घेराव कर रमेश को छुड़ा लायी.

20 से 24 अक्तूबर, 2015 तक बीजापूर जिले के सभी कैंपों व थानों से निकले सैकड़ों पुलिस बल ने पेदागेलूर, चिनागेलूर, पेगड़पल्ली, सुटबायगुंडम, कोत्तागुड़ा, बुड़गीचेरू और जीरागुड़ेम पर हमलें किये. इस दौरान 40 महिलाओं के साथ बेरहमी से मारपीट की. 4 महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. जिनमें एक गर्भवती महिला व 14 वर्षीय नाबालिग लड़की भी थी. इसके अलावा पुलिस कोत्तागुड़ा के 10 ग्रामीणों को पकड़कर थाना ले गयी.

पेदागेलूर में पुलिस ने क्रांतिकारी जनताना सरकार के नेतृत्व में चल रही स्कूल पर भी हमला करके उसे नुकसान पहुंचाया था. जनता की संपत्ति को भी बड़े पैमाने पर ध्वस्त किया था. 15,800 नकदी के अलावा कई सामान, मुर्गों व सुअरों को भी लूट लिया था.

इस क्रूर हमले के खिलाफ 400 जनता जिनमें महिलाएं ज्यादा थीं, ने बीजापुर जिला कलेक्टर से शिकायत करके दोषी पुलिस अधिकारियों व जवानों को सजा देने की मांग की.

10 नवंबर, 2015 की रात को चिंतलनार थाने की पुलिस मुकरम गांव पर धावा बोलकर 10 ग्रामीणों को गिरफ्तार कर थाना ले गयी. उन्हें छुड़ाने के लिए गांव की सभी महिलाओं ने थाना जाकर आंदोलन किया. लेकिन पुलिस ने उन्हें नहीं छोड़ा. झूठे केस लगाकर उन्हें दंतेवाड़ा जेल भेज दिया.

तेलंगाना–छत्तीसगढ़ के सरहदी इलाके के मद्देड एरिया के लंकापल्लि गांव के पास तेलंगाना के एक गोरिल्ला दस्ते के ऊपर 14 जुलाई 2015 को दुश्मन द्वारा की गई एकतरफा गोलीबारी में कामरेड कमला, सोनी और विवेक शहीद हुए थे. ग्रे–हाउंड्स बल शवों को भद्राचलम ले गये थे. खबर पाते ही कमला के परिजन व इलाके की जनता जिनमें महिलाएं ज्यदा थी, ने भद्राचलम पहुंचकर पुलिस–प्रशासन से कमला की लाश की मांग की. लाश देते तक लड़कर वे तेलंगाना से शव को लाये.

सन् 2015 में दमन के विरोध में जगरगुंडा एरिया के

बासागुड़ा, सारकेगुड़ा, चिंतलनार, बुरकापाल गांवों की जनता ने 23 बार रोड–पुलियाओं को ध्वस्त कर दिया. इस तोड़ फोड़ कार्यक्रम में लगभग 2000 पुरुष व एक हजार महिलाएं भाग ली.

केरलापाल एरिया

7 नवंबर, 2015 को दोरनापाल, मिसमा, केरलापाल, पुलबगड़ी, रामवरम और गादीरास के बेस कैंप से सीआरपीएफ, कोबरा, डीआरजी बलों के करीबन 500 जवानों ने केरलापाल एरिया के चार पंचायतों के गांवों पर हमला किया. लोगों से मार–पीट की. माडोम में अमर शहीदों के स्मारक को भी ध्वस्त किया. इसके विरोध में भूमकल मिलिशिया, मिलिशिया प्लाटून और जनता ने अपने परंपरागत हथियारों के साथ प्रतिरोध किया. इस प्रतिरोध के चलते हैरान परेशान होकर पुलिस बल भाग गए.

किस्टारम एरिया

इत्तनपारा के निवासी मुचाकी रामा को जून 19, 2015 को तुंगवागु के पास पकड़कर पुलिस ने उसकी निर्मम हत्या की थी. बाद में लाश को पुलिस किस्टारम थाना ले गयी. लाश को लाने के लिए 100 से अधिक महिलाएं किस्टारम थाना जाकर लड़ी. पुलिस महिलाओं को न सौंपकर लाश को कोण्टा ले गयी. महिलाएं वहां भी जाकर रामा की क्रूरूतापूर्ण हत्या की निंदा करते हुए लाश के लिए जमकर लड़ी. उमड़ती जनाक्रोश को देखकर आखिर पुलिस ने लाश को सौंप दिया.

तेलंगाना–छत्तीसगढ़ पुलिस ने 30 सितंबर, 2015 को टेट्टेबंडा, दोरमंगूम, पुसगुड़ा गांवों पर हमला करके 21 ग्रामीणों को पकड़कर उन्हें एडुराल्लापल्ली थाना में रखा था. 82 महिलाएं पुलिस के पीछे–पीछे जाकर, पुलिस के साथ लड़कर पकड़े गये लोगों को छुड़ा लायीं.

दरभा डिविजन

29 जुलाई, 2015 की सुबह 400 पुलिस बल के 4 बैचों ने गोंडेम, पोटाली व नहोडी गांवों पर हमला किया था. गोंडेम गांव में पुलिस बल जब गांव वालों के मुर्गों को पकड़ कर खाने लगे थे, तब महिलाओं ने इसका कड़ा विरोध किया. विरोध करने वाली 45 महिलाओं के साथ पुलिस ने बुरी तरह मार–पीट की.

जबकि दूसरी बैच नहोडी गांव में घुसी थी, जहां शहीदी सप्ताह मनाने की तैयारी हो रही थी. उस तैयारी में व्यस्त पंचायत सीएनएम के कलाकारों पर पुलिस ने अंधाधुंध गोलीबारी की. इस गोलीबारी में हेमला पोदियाल नामक कलाकार शहीद हुआ था. पुलिस ने बाकी 19 कलाकारों को एक घर में ठूंस कर घर को आग लगाने की कोशिश की थी. लेकिन उन लोग किसी तरह दर्वाजा फोड़कर बाहर निकलने में कामयाब हुए. बाद में पुलिस जब लाश व 19 लोगों को साथ में ले जाने लगे तब बच्चे–बूढ़े सहित सभी गांव वाले कलाकारों को छुड़ाने पुलिस के साथ भिड़ गये. आंदोलनरत जनता के साथ पुलिस ने बुरी तरह मार–पीट की जिसमें 45 महिलाएं घायल हुई थीं. जनता के इस कदर प्रतिरोध करने के बावजूद पुलिस लाश व कलाकारों को साथ में ले गयी थी. पुलिस पिटाई के बावजूद जनता भी पीछे नहीं हटी. पुलिस के पीछे–पीछे दंतेवाड़ा जाकर 300 लोगों ने कलाकारों की रिहाई की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ा. दंतेवाड़ा एसपी पकड़े गए 19 लोगों पर आत्मसमर्पण करने का दबाव डाला जिसे कलाकारों ने ठुकरा दिया. बाद में कुछ लोगों को छोड़ने तैयार हुआ था. लेकिन जनता सभी लोगों को छोड़ने की अपनी मांग पर अडिग रही. जनता के साथ–साथ पकड़े गऐ लोग भी लड़ रहे थे. आखिर जन आन्दोलन के सामने पुलिस ही हार गई. पकड़े गए सभी लोगों को छोड़ने व लाश देने वह विवश हो गयी.

इसी तरह अगस्त माह के दूसरे सप्ताह में मापाड़ गांव के कनकीपारा के 18 ग्रामीणों को पकड़ कर पुलिस उन्हें वारंटी नक्सली बताकर थाने में रखा था. इसके विरोध में जनता 48 घंटे तक थाने का घेराव करके पुलिस के चंगुल से ग्रामीणों को छुड़ा लायी.

18 सितंबर, 2015 को पालनार साप्ताहिक बाजार में ग्रामीणों पर पुलिस ने हमला किया था. इस हमले में जनता, कर्मचारी व व्यापारी तक पुलिस की लाठी का शिकार होकर घायल हुए थे. इस घटना के विरोध में व्यापारी, शिक्षक व सरपंच सहित लगभग हजार की संख्या में जनता ने पुलिस थाने के सामने धरना दिया. इस आंदोलन के चलते दो पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया था.

गुडरा खंकीपारा के 5 ग्रामीणों को माओवादी बताकर कुआकोंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इसके विरोध में करीबन 27 पंचायतों की हजारों जनता ने अपने परंपरागत हथियारों से लैस होकर कुआकोंडा थाने का घेराव किया था. जनता की मांग यह थी कि निर्दोष ग्रामीणों को छोड़ दिया जाए या न्यायालय में पेश किया जाए. जनता ने पुलिस बलों पर यह आरोप लगाया कि माओवादी के नाम से वे आम जनता को गिरफ्तार कर रहे हैं.

पश्चिम बस्तर

सितंबर, 2015 में मद्देड एरिया के बंडारुपल्ली गांव पर हमला कर पुलिस ने महिलाओं से मार–पीट की व घरों को लूटा. इसके विरोध में जनता ने बीजापुर जाकर अपनी शिकायत दर्ज की थी.

नवंबर 19, 2015 को चेरपाल के पोटाकेबिन में 8 वीं

पढ़ने वाला ताती सोहन जब अपने गांव सावनार जा रहा था, बीच में रेगड़गट्टा गांव के पास पुलिस ने उसकी बुरी तरह पिटाई की थी जिसके चलते उसका कान फट गया, उसके मुंह से खून निकला और वह बेहोश हो गया. इस घटना का पता चलते ही चेरपाल के पोटाकेबिन के 550 छात्रों ने स्कूल का बहिष्कार किया. रेगड़गट्टा की स्कूल व आश्रम के छात्र–छात्राओं ने भी शाला का बहिष्कार किया था. सभी छात्रों ने कलेक्टर से पुलिस की शिकायत की. 2 दिसंबर, 2015 को बीजापुर में बड़ी तादाद में छात्रों ने रैली निकालकर पुलिस के विरोध में अपनी आवाज उठाई.

पूर्व बस्तर डिविजन

17 अक्टोबर, 2015 को बेनूर से आई पुलिस की संयुक्त टीम कुव्वानार इलाके के छिनारी गांव से पांच हजार के इनामी नक्सली होने की बात कहते हुए शादी के मंडप से राजेश बघेल नामक युवक को उठाकर ले गयी थी. समारोह में शामिल दो अन्य युवक आशू बघेल तथा विजय रावत को भी गिरफ्तार कर शादी के कपड़े, गहने सहित तमाम साजो सामान को भी साथ ले गयी. पुलिस की इस करतूत से नाराज छिनारी, आदपाल, बॉगझर, छोटे फरसगांव, बैलापाड़, दण्डवंड, कलेपाड़ व मड़ागांव के ढ़ाई सौ ग्रामीण नेतानार की ओर से रैली के शक्ल में थाना पहुंचे थे. लेकिन डीएसपी देवनारायण पटेल सहित पुलिस बल ने ग्रामीणों को थाने से 100 मीटर दूरी पर यात्री मंडली के पास ही रोक दिया.

1 नवंबर, 2015 को कुव्वनार एरिया के कडियामेट्टा गांव से पुलिस 3 ग्रामीणों को उठा ले जाकर अपने साथ रात भर जंगल में ही रखा था. इसके विरोध में कडियामेट्टा व बेच्चा की महिलाएं तुरंत इकट्ठी हो गईं. अगले दिन पुलिस और कुछ लोगों को पकड़ा, तो महिलाएं पुलिस का घेराव कर झगड़ा करने लगी. डीआरजी वालों के ऊपर भी महिलाएं टूट पड़ी थी. महिलाओं ने इस तरह झगड़ा करते हुए एक घंटे तक पुलिस वालों का रास्ता रोक दिया था. महिलाओं के प्रतिरोध के चलते पुलिस को पकड़े गए सभी 22 लोगों को छोड़ना पड़ा.

कुदुर, कोटमेट्टा व वेड़मा गांवों पर 11 अक्टूबर, 2015 को पुलिस ने हमला किया. इस दौरान जनता के साथ मार–पीट की. कोटमेट्टा गांव के लछुन कश्यप व कुलदेर कश्यप को गिरफ्तार कर जेल में ठूंसा था. इसी महीने की 17 तारीख को पुलिस ने वेडमा गांव पर हमला करके घरों में घुसकर सामान का तोड़फोड़ किया था. खेतों में काम कर रही जनता पर गोलीबारी करके आतंक मचाया. इन दो घटनाओं के विरोध में दो पंचायत की जनता इकट्ठी होकर शिकायत करने जब कलेक्टर के पास जा रही थी, तब पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोकने की कोशिश की. लेकिन पुलिसिया कोशिशों को नाकाम करती हुई जनता किसी प्रकार मौका पाकार कलेक्टर से शिकायत की और मीड़िया को भी खबर पहुंचा दी.

दमन के विरोध में दंडकारण्य में जारी जन प्रतिरोध खासकर महिलाओं के बहादुराना प्रतिरोध से संबंधित अनगिनत घटनाओं में से कुछेक को ही हम यहां प्रकाशित कर पा रहे हैं. प्रतिरोध का यह सिलसिला एक बार और इस सच्चाई को साबित कर रहा है कि दमन प्रतिरोध को और बढ़ावा देता है.

माड़ डिविजन

नेलनार एरिया

27 अगस्त, 2015 को पोकनार गांव के 7 ग्रामीणों को पुलिस ने पकड़ कर अपने साथ ले जाने की कोशिश की तो महिलाएं लड़ती हुई पीछे–पीछे जाकर बीच रास्ते से ही सभी को छुड़ा लायी.

11 अक्तूबर, 2015 को ओरछा से आई पुलिस बटवेड़ा व ओयंगेर के बीच के जंगल से जैमन नामक ग्रामीण को पकड़ कर अपने साथ ले गयी. इसके विरोध में ग्रामीण महिलाओं ने ओरछा थाने का घेराव किया व रैली भी निकाली. बाद में महिलाएं नारायणपुर तक जाकर लड़ी थी. लेकिन पुलिस ने जैमन को नहीं छोड़ा. उसे जेल भेज दिया गया.

17 नवंबर, 2015 को रायनार गांव के 9 लोगों को पुलिस पकड़ कर ओरछा ले गयी. गांव की महिलाएं पुलिस के पीछे–पीछे थाना जाकर लड़ी. रैली भी निकाली. महिलाओं की लड़ाई के नतीजतन पुलिस ने सभी लोगों को छोड़ दिया.

26 नवंबर, 2015 को आसनार गांव के 3 ग्रामीणों को पुलिस रास्ते से पकड़ कर ले गयी. इस खबर को सुनते ही गांव की दसियों महिलाएं व पुरुष ओरछा थाने में जाकर दिन भर लड़ते रहे. पुलिस ने यह बताया कि पकड़े गये लोगों को नारायणपुर ले जाया गया. इसके बाद महिलाएं नारायणपुर भी गयी थी. वहां थाने में घुसकर लड़ी थी. लेकिन पुलिस पकड़े गये लोगों को नहीं छोड़ी. ❍

हम कम्युनिस्ट बीज के समान होते है और जनता भूमी के समान होती है। हम लोग जहां कहीं भी जाएं, वहां जनता के साथ एकता कायम करें, उसमें अपनी जड़े जमा लें, और उसके बीच फलें–फूलें।

–माओ

कल्लूरी का झूठा प्रचारः सच्चाई को हमेशा के लिए दबा नहीं सकता है!

बस्तर आईजी शिवराम प्रसाद कल्लूरी द्वारा क्रांतिकारी आन्दोलन व उसका नेतृत्व करने वाली पार्टी को बदनाम करने व उन पर कीचड़ उछालने की घृणित व नीच कोशिशें लगातार जारी हैं. यह सिर्फ बस्तर या दण्डकारण्य ही नहीं समूचे देश में जारी है. बस्तर में कल्लूरी तो दूसरे राज्य में कोई और चेहरा, कोई और नाम. कल्लूरी जैसे लोग दमनकारी राज्य यंत्र के एक कलपुर्जे मात्र हैं. दरअसल यह झूठा प्रचार क्रांतिकारी आन्दोलन को खत्म करने के लिए जारी बहुआयामी युद्ध का हिस्सा है. असत्य, अर्धसत्य एवं सत्य को तोड़–मरोड़कर बार–बार परोसने से उसे सत्य माना जायेगा, शोषक–शासक वर्ग इसी अवधारणा पर विश्वास करके झूठा प्रचार अभियान को रणनीतिक महत्व देते हैं. लेकिन झूठ हमेशा के लिए सच्चाई पर परदा डाले नहीं रख सकता है. कुछ समय के लिए और कुछ जगहों के लिए वह सच के रूप में प्रचारित हो सकता है. देर सवेर उसका भंडाफोड़ हो ही जाता है. इसके बावजूद शासक वर्ग झूठ का ही सहारा लेने मजबूर होते हैं. क्यों कि सच्चाई हमेशा उनके खिलाफ ही होती है. सच्चाई पर टिके रहना उनके लिए संभव ही नहीं है. जबकि क्रांतिकारी आन्दोलन हमेशा सच पर खड़े होकर सच्चाई के लिए आगे बढ़ती है. यह झूठा प्रचार क्रांतिकारी आन्दोलन और पार्टी तक ही सीमित नहीं है. राज्य दमन का विरोध करने वालों, तमाम जनवादी, प्रगतिशील, मानवाधिकार संगठनों के नेताओं व कार्यकर्ताओं, देशभक्त ताकतों, जनवाद प्रेमियों, जनपक्षधर पत्रकारों, वकीलों आदि के खिलाफ भी झूठा प्रचार का इस्तेमाल करते हुए उन्हें बदनाम करने की विफल कोशिशें जारी हैं.

वर्तमान में मुठभेड़ों, झूठी मुठभेड़ों के तमाम मामलों में कल्लूरी ही प्रेस को बयान जारी करते हैं. वो एक से बढ़कर एक नित–नयी कहानियां गढ़ते हुए प्रचारित कर रहे हैं. ऐसे मामलों जहां घरों से उठा ले जाकर हत्याएं की जा रही हैं, में भी वह पुलिस और माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ होने, माओवादियों की तगड़ी एंबुश को तोड़कर निकलने आदि सफेद झूठ कहते हुए अपने जवानों की बहादुरी का बखान करते नहीं थकते हैं. ऐसी घटनाओं जिनमें पुलिस जवान मारे जाते हों, में बड़ी संख्या में माओवादियों के मारे जाने या घायल होने की बात वे बेशर्मी से मीडिया को परोसते हैं. इतना ही नहीं, उन घटनाओं में शामिल जवानों को नकद पुरस्कार के अलावा आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी देते हैं.

8 दिसंबर, 2015 को जब सशस्त्र बलों ने सुकमा जिले के टेट्टेमड़गु गांव पर हमला किया था, हमारी पीएलजीए ने जवाबी कार्रवाई करके 5 जवानों को घायल करके 3 किलो मीटर दूर तक खदेड़ दिया था. इस घटना की जानकारी देते हुए कल्लूरी ने अखबार व टीवी चैनल वालों को एकदम सफेद झूठ बताया कि मुठभेड़ में 15 से 20 माओवादी मारे गये. हद तो यह है कि कल्लूरी ने उक्त घटना में शामिल व मुठभेड़ के दौरान मैदान छोड़कर भागने वाले अपने 'बहादुर' जवानों को ईनाम व प्रमोशन भी दिया था. जबकि इस घटना में हमारे कोई भी कॉमरेड़ शहीद नहीं हुए हैं. इस तरह के ढेरों उदाहरण हैं.

कल्लूरी के झूठे आत्मसमर्पणों की कहानियां अखबारों के पन्नों में रोज सजती हैं. साप्ताहिक बाजारों, बस स्टैंडों, रेल्वे स्टेशन से लोगों को पकड़कर, रिश्तेदारों के पास आने–जाने वालों, कूली आने–जाने वालों को पकड़कर, डरा–धमकाकर, लालच देकर, बहला फुसलाकर, थानों की रिकॉर्डों से नाम हटवाने का बहाना बनाकर सामूहिक आत्मसमर्पण दिखा रहे हैं और मीडिया में जोर–शोर से प्रचारित कर रहे हैं. जनता को झूठे आत्मसमर्पणों का कड़ा विरोध करना चाहिए तथा आत्मसमर्पण से तीखा नफरत करना चाहिए.

आत्मसमर्पित गद्दारों द्वारा कीचड़ उछलवाने की पुलिसिया कोशिशें लगातार जारी हैं. पत्रकार वार्ताएं आयोजित करके पार्टी नेताओं के बीच मतभेद होने, तेलुगु और कोया या स्थानीय और बाहरी नक्सलियों के बीच मतभेद होने की काल्पनिक कथाएं प्रकाशित करवायी जा रही हैं. पार्टी में शादी के पहले ही जबरन नसबंदी कराने, बच्चे पैदा न करने देने आदि मामलों में भी झूठा बयान दिलवाकर पार्टी को बदनाम करने की नाकाम कोशिशें की जा रही हैं. चूंकि इन तमाम मामलों से संबंधित सच्चाइयों से जनता एवं कैडर बखूबी वाकिफ है, इसलिए इन पर विस्तार से लिखने की जरूरत नहीं है.

कल्लूरी अभूतपूर्व कल्पनाओं के साथ दुष्प्रचार करने में माहिर हैं. दिसंबर, 2015 के पहले सप्ताह की घटना थी. बीजापुर जिले के गंगालूर थाना के गांव तोड़का के एक जन विरोधी परिवार की महिला ने पी हुई हालत में बगल में सो रहे अपने 4 माह के मासूम पर लड़खड़ाकर गिर गयी जिसकी वजह से मासूम की मौत हो गयी. इस सच्चाई को दफन करके कल्लूरी ने अखबारों को यह वाहियात बयान जारी किया कि माओवादियों ने 4 माह के मासूम की पीट–पीटकर हत्या की. दल बल को गांव में भेजकर मासूम की गढ़ी लाश को मंगाकर कॉरपोरेट मीडिया द्वारा जोर–शोर से पार्टी के खिलाफ प्रचारित किया. इस घटना के विरोध में विगत 22 दिसंबर, 2015 को बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर के हाता ग्राउण्ड में समाजिक एकता मंच के बैनर तले कल्लूरी ने धिक्कार रैली के नाम पर एक घिनौनी

रैली आयोजित करवायी। इस रैली के आयोजक ही नहीं बल्कि मंच के प्रवक्ता थे, कल्लूरी. रैली को संघ परिवार, भाजपा नेता, सलवा जुडुम के जीवित बचे गुण्डों ने संबोधित किया था। कुछ ग्रामीणों व स्कूली बच्चों को डरा–धमका कर रैली में लाया गया था.

कल्लूरी ने मार्च, 2016 की शुरुआत में मीडिया को एक सनसनीखेज झूठ परोसा कि माओवादियों ने सिर्फ पिछले 15 दिनों के भीतर ही नारायणपुर जिले के 'अबूझ' माड़ इलाके के गांवों के 20 ग्रामीणों की मुखबिरी के संदेह में हत्या की है. इसके बाद पुलिस–प्रशासन की गलियारों में अफरा–तफरी मच गयी.मीडिया पशोपेश में पड़ गयी. लेकिन दो दिन के अंदर ही कल्लूरी की झूठी कहानी का पर्दाफाश हो गया था. पर्दाफाश करने वाले स्वयं पुलिस–प्रशासन के आला अधिकारी ही थे. जनता के बीच में शासन–प्रशासन की बुरी तरह फजीहत होने से बचाने के लिए नारायणपुर के एसपी अभिषेक मीणा, राज्य के स्पेशल डीजी नक्सल ऑपरेशन डीएम अवस्थी एवं गृह सचिव ने अलग–अलग बयान जारी करके स्पष्ट किया कि माओवादियों ने चार ग्रामीणों की हत्या की है. अखबार पत्रिका ने भी सच्चाई को सामने लाया था. पार्टी की ओर से माड़ डिविजनल कमेटी के सचिव राजमण मंडावी ने भी प्रेस को जारी बयान में स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि पिछले छह महीनों में पुलिस मुखबिरी करने, माड पर हमले करवाने, कुतुल, वेडमामेट्टा हमलों में दो ग्रामीणों व पीएलजीए के दो निहत्थे सदस्यों की हत्या के लिए जिम्मेदार आलवेडा के चैतु, परपा के आयतु, कुंदला के सुकराम और मेटवेडा के मंगलु को जनता की मांग पर जन अदालत में सजा दी गयी.

कल्लूरी एक और झूठ प्रचारित करवा रहे हैं कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों खासकर नारायणपुर, कोंडागांव जिलों के संघर्ष इलाकों से माओवादी ग्रामीणों को भगा रहे हैं. जबकि सच्चाई यह है कि पिछले छह महीनों में गंभीर चेतावनी के बावजूद न सुधरने वाले मुखबिरों, जन विरोधियों, जनता की नफरत के शिकार 6–8 परिवरों को ही जन अदालत लगाकर जनता की मांग पर गांव से भेज दिया गया था. दूसरी ओर पुलिस–प्रशासन चोर, लंपट, गुण्डा तत्वों, जन विरोधियों, पुलिस नौकरी करने वालों, हत्या जैसे संगीन अपराध करने वालों के परिवारों को जिला केंद्रों में बुलवाकर, घर व जमीन देने का लालच देकर प्रेस वार्ताएं आयोजित करके पार्टी पर कीचड़ उछलवाने की कोशिशें की जा रही हैं.

सोनी सोढ़ी पर हमला करवाने व कालिख पोतवाने वाले कल्लूरी ने उस घटना का संबंध जेएनयु, उमर खालिद से भी होने की बात कही. माओवादियों के भी हाथ होने का दुष्प्रचार किया. जबकि सोनी खुद चीख–चीख कर कह रही है कि उन पर हमले के पीछे कल्लूरी का हाथ है. इस बात से तो देश, दुनिया ही वाकिफ हो गयी है कि सोनी सोढ़ी को माओवादी समर्थक होने के झूठे आरोप में अरेस्ट करके पहले पुलिस हिरासत, बाद में जेल में अमानवीय यातनाएं व यौन अत्याचार करवाने वाले कल्लूरी ही हैं.

दण्डकारण्य खासकर बस्तर में राज्य दमन, महिलाओं पर जारी पुलिसिया अत्याचारों को उजागर करने की कोशिश करने वाले महिला संगठनों की कार्यकर्ताओं, जेलों में बंद आदिवासियों, माओवादी मामलों में बंद निर्दोष ग्रामीणों को विधिक सेवा उपलब्ध कराने वाली वकीलों जो जगदलपुर लीगल एइड ग्रुप से संबंधित हैं, पर माओवादी या माओवादी समर्थक होने का ठप्पा लगाने में कल्लूरी ने कोई कसर नहीं छोड़ी. इतना ही नहीं, उन्हें माओवादियों के फंड्स से चलने वाले संगठनों के रूप में भी दुष्प्रचारित करने की असफल कोशिश कर रहे हैं. संघर्ष इलाकों में जारी सरकारी दमन की सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करने वाले पत्रकारों को राष्ट्रविरोधी के रूप में प्रचारित कर रहे हैं.

कॉरपोरेट मीडिया खासकर कुछ अखबार अपने निहित स्वार्थ के चलते सरकारी या पुलिसिया खबरों का लाउड़ स्पीकर बने हुए हैं. इन्हें सच्चाई से कोई लेना–देना नहीं है. ये माओवादी विरोधी दमन अभियान में सरकार का खुलकर साथ दे रहे हैं. पुलिस या सरकार की झूठी कहानियों को ये बढ़ा–चढ़ाकर परोसते हैं. कल्लूरी इनका बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं.

लगता है, झूठा प्रचार करने में कल्लूरी नाजी हिट्लर के प्रचार मंत्री गोएबल्स को पछाड़ने का ठान लिया है. हमारी पार्टी को नीचा दिखाने व बदनाम करने के लिए वे रोज नये पैंतरे खोजते हैं. लेकिन कल्लूरी की झूठी बातें लोगों को सच्चाई से हमेशा के लिए दूर नहीं रख सकती हैं. सच पर हमेशा के लिए परदा डालना कल्लूरी, रमण सिंह या मोदी किसी की भी बस की बात नहीं है. आखिरी जीत सच की ही होती है. ❍

कृपया प्रभात के लिए डिविजनों से सही समय पर निम्नांकित रिपोर्ट्स जरूर भेजें!

- ★ ***अमर शहीदों की जीवनियां जिनके साथ तस्वीरें जरूर संलग्न करें.***
- ★ ***पीएलजीए प्रतिरोध***
- ★ ***जन प्रतिरोध विशेषकर महिला प्रतिरोध***
- ★ ***जन संघर्ष की रपटें***
- ★ ***सभा सम्मेलनों की रपटें***

– संपादक मंडल

(...आखरीं पेज का शेष)

इस लोह अयस्क के परिवहन के लिए बिछाए गए बैलाडीला–जगदलपुर–विशाखापट्नम रेल मार्ग ने सैकड़ों एकड़ जमीन हड़प ली. हाल ही में इसके विस्तार के लिए और एक बार जमीनें छीनी गयीं. बैलाडीला खुदाई के चलते बस्तर की सभी नदियां प्रदूषित हो गईं. पानी लाल रंग में बदल गया. इस पानी की वजह से इस इलाके में बीमारियां बढ़ रही हैं. फसलें बरबाद हो रही हैं. पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है. बैलाडीला से सालाना 80 लाख टन लौह चूर्ण को पाइपलाइन द्वारा एस्सार कंपनी विशाखापट्णम ले जा रही है. इसके लिए यहां की नदियों का पानी इस्तेमाल किया जा रहा है. जिसके चलते यहां की नदियां सूख रही हैं. जबकि चूर्ण को बहा ले जाने में इस्तेमाल होने वाला पानी व्यर्थ हो रहा है.

यहां की जनता को विस्थापित करके, उनकी जिंदगियों को तितर–बितर करके, प्रदूषण से यहां की जैविक विविधता को बरबाद करके, यहां की नदियों के पानी को बर्बाद करते हुए निकालने वाले लौह अयस्क किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? हमारे देश की छोटी कंपनियों के लिए कतई नहीं. जापान, कोरिया व चीन की बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए यह निर्यात किया जा रहा है. इस निर्यात से हमरे देश को मिलने वाला फायदा भी कुछ नहीं है. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक टन के लौह अयस्क की दर दस हजार रुपये है, तो जापान को रु.160 की दर पर बेचा जा रहा है. इस निर्यात के जरिए हर टन पर रु. 50 भी सरकार को नहीं मिलते हैं. जबकि लौह अयस्क के पहाड़ों को अपने गर्भ में छिपाने वाले छत्तीसगढ़ में 150 से ज्यादा स्पंज आयरन उध्योग, लौह अयस्क की कमी के कारण बंद पड़े हैं. इन्हें सालाना 12 मिलियन टन लौह अयस्क की जरूरत है. जबकि एनएमडीसी सिर्फ तीन मिलियन टन ही दे रही है. इन उद्योगों की यह मांग कि बैलाडीला से उत्पादित माल का दस प्रतिशत दिया जाए, एनएमडीसी द्वारा खारिज कर दी गयी. यह बात अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि किसके फायदे के लिए किसकी बलि चढ़ायी जा रही है. इन खदानें द्वारा इतनी तबाही होने के बावजूद इनका विस्तार करने की कोशिशें जारी है. इन कोशिशों को यहां के जनांदोलन रोक रहे हैं. इस खदान के चलते प्रदूषित लाल पानी के खिलाफ यहां की जनता लगातार लड़ रही है. इस लड़ाई में महिलाएं अग्रसर हैं.

इस तरह बैलाडीला खदान के खुलने से बस्तरियों का विकास नहीं बल्कि विनाश ही हुआ है. जमीनें गईं. जंगल कटी. गांव–घर उजड़ गये. स्थानीय जनता विस्थापित हुई. जिंदगियां सड़क पर आ गईं.

इतने विनाश के बावजूद अब पूरे दंडकारण्य में यानि छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव व बस्तर के सात जिलें और महाराष्ट्र के गड़चिरोली जिलों में कईयों छोटी, बड़ी खनन परियोजनाओं, बहु उद्देश्यीय बड़ी बांध परियोजनाओं, बृहत् औद्योगिक परियोजनाओं के लिए लगातार एमओयू किये जा रहे हैं. 'अबूझ'माड़ के बीचों–बीच एक तिहाई भूभाग पर सैनिक प्रशिक्षण शाला की स्थापना के लिए निर्णय किया गया है. ये सभी योजनाएं वास्तव रूप लेती हैं, तो बड़े पैमाने पर यहां की जनता विस्थापित हो जयेंगी जिसके चलते यहां की प्राचीनतम माड़िया जनजाति सहित कई आदिवासी व गैर–आदिवासी जातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ेगा. कई विलक्षण जीव व वृक्ष जातियों, अमूल्य औषधीय संपदाओं का नामोनिशान मिट जायेगा. पर्यावरण की बात कहने की जरूरत नहीं है. चूंकि आदिवासियों द्वारा जंगलों व पहाडों को बचाया जा रहा है इसीलिए मानव जाति को अभी तक प्राण वायु–ऑक्सीजन खरीदने की दुर्दशा नहीं आई. वरना पीने के पानी व ठंडी हवा (एसी) के ही समान प्राण वायु को खरीदने की नौबत कब की आ जाती. समाज की जरूरतों को ध्यान में रखने के बजाए सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के लिए ही प्राकृतिक संपदाओं व संसाधनों का अंधाधुंध दोहन व उनका विनाश करने वाले लुटेरे इस विषय को जान बूझकर भुला रहे हैं कि प्रकृति की सृष्टि हम नहीं कर सकते हैं.

इस विनाश को रोकने क्रांतिकारी आंदोलन के नेतृत्व में यहां की जनता लड़ रही हैं. इस लड़ाई के चलते कुछ परियोजनाएं शुरू भी नहीं हो सकी. कुछेक शुरू होने के बाद बंद हो गईं. और कुछ धीमीगति से चल रही हैं. इन आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी सक्रिय है. कुछ आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी ही महत्वपूर्ण है. सशस्त्र बलों को तैनात कर बोधघाट बांध के निर्माण के मकसद से उस इलाके के कुदुर व हर्राकोडेर गांवों में पुलिस कैंप लगाने की कोशिशों को लड़ कर अस्थायी तौर पर विफल करने में महिलाओं ने सराहनीय भूमिका निभाई. हालांकि विस्थापन की समस्या सभी लोगों की है, लेकिन महिलाओं पर इसका असर अधिक होता है. हालांकि यहां की खेती पिछड़ी हुई दशा में है, इसलिए यहां की जनता जंगल पर ही ज्यादा निर्भर होती है. वनोपजों के संग्रहण में महिलाओं की भूमिका ही महत्वपूर्ण होती है. चूंकि वन संपदा व संसाधनों के दोहन के चलते जंगल घट जयेगा, इसलिए जनता की आजीविका पर तीव्र असर पड़ेगा. महिलाओं पर बोझ और बढ़ेगा. आजीविका की तलाश में

पलायन कर रही महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं. कुछ महिलाएं वेश्यावृत्ति में कदम रखने मजबूर हो रही हैं. इसीलिए विस्थापन विरोधी आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है.

देशी, विदेशी कार्पोरेट कंपनियों के मुनाफे की प्यास बुझाने के लिए जरूरी है सभी परियोजनाओं का शीघ्र प्रारंभ होना. सलवा जुडुम, सलवा जुडुम–2, ग्रीनहंट, ग्रीनहंट की दूसरी दशा, तीसरी दशा व मिशन–2016 के नाम पर लगातार भीषण दमन अभियान जनता पर थोपे जा रहे हैं. मोदी के 'मेक इन इंडिया' हो, रमण सिंह के 'मेक इन छत्तीसगढ़' हो, या फडणविस के 'मेक इन विदर्भ' हो शासक यह मान कर चल रहे हैं कि दमन के जरिए ही ये वास्तव रूप ले सकती हैं. सशस्त्र बलों के निरंतर पहरे में दल्ली–रावघाट–जगदलपुर रेल मार्ग बनाया जा रहा है. पल्लामाड़ सहित राजनांदगांव–कांकेर–बालोद के सरहदी इलाके में स्थित दर्जनों खदान, रावघाट, आमदाई व तुलाड़ खदानों को शुरू करने अर्ध सैनिक बलों के दसियों कैंप लगाकर सशस्त्र बलों द्वारा जोर आजमा रहे हैं.

दंडकारण्य में फिलहाल एक लाख बीस हजार पुलिस व अर्ध सैनिक व कमांडो बल तैनात हैं. इस साल इस संख्या में और बढ़ोत्तरी होनेवाली है. फोर्टिफैड–किलेबंदी पुलिस थानें व अर्ध सैनिक बलों के कैंप दंडकारण्य भर में फैला दिए गए हैं. जहां परियोजनाओं की प्लानिंग हुई है, वहां इनकी संख्या और अधिक हैं. नये कैंप लगाने का सिलसिला लगातार जारी है. हवाई व वायुसैनिक अड्डों, हेलीपैडों का निर्माण हो रहा है. हाल ही में हवाई हमलों के लिए योजनाएं तैयार की गईं. परियोजनाओं के इर्द–गिर्द के इलाकों में गश्त के नाम पर लगातार गांवों पर हमलें किये जा रहे हैं. ग्रामीणों की बेदम पिटाई जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, घरों में लूट–पाट, घरों को जलाना, संपत्ति को नष्ट करना, खाद्यान्न को बर्बाद करना आदि आम बात है.

इस परिप्रेक्ष्य में जनता पर खासकर महिलाओं पर दमन बढ़ गया है. जिंदगियां दूभर हो गईं. घरों में, गांवों में, खेतों में व जंगलों में हर जगह सरकारी सशस्त्र बलों का डर उनका पीछा कर रहा है. आहार व वनोपजों के संग्रहण में प्रधान भूमिका निभानी वाली महिलाओं के लिए यह जीवन्मरण सी समस्या बन गई है.

गाली–गलौच, मारपीट, यातनाएं, बलात्कार, गिरफ्तारियां, आखिर हत्याएं यहां आम बात हो गई. लेकिन इनमें से कुछ ही घटनाएं उजागर हो रही हैं. सशस्त्र बलों के अमानवीय करतूतों के बारे में क्रांतिकारी आंदोलन की ओर से जारी होने वाली प्रेस विज्ञप्तियों के लिए सरकार के इशारों पर काम करने वाले अखबारों में जगह न के बराबर ही होती है. इस तरह की घटनाओं को उजागर करने की जनता की कोशिशों जैसे पुलिस थानों का घेराव, नजदीकी कस्बों या शहरों में रैलियां आदि को पुलिस द्वारा जबरन रोक दिया जाता है. जन पक्षधर जन संगठनों, महिला संगठनों, मानवाधिकार संगठनों या जनवादियों के संकल्प से ही कुछ घटनाएं उजागर हो रही हैं. महिलाओं पर बढ़ते दमन का विरोध करते हुए पीड़ितों के पक्ष में खड़े होने वालों पर ही सरकार टूट पड़ती है. गौरतलब है कि माओवादियों से संबंध रखने का गलत आरोप लगाते हुए पुलिस ने 2011 में सोनी सोढ़ी को गिरफ्तार करके, हिरासत में न सिर्फ उन्हें अमानवीय व अकथनीय यातनाएं दी गयी बल्कि उन पर बर्बर यौन अत्याचार किये गये. झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दिया गया. रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी में शामिल होकर वो आदिवासियों पर जारी सरकारी दमन पर उंगली उठाती आ रही हैं. उन्हें सरकार अभी भी सता रही है. उनके घर पर हमला किया गया. उन्हें पोस्टर के जरिए धमकाया गया कि वे बीजापुर में कदम रखेंगी, तो मारी जायेंगी. हाल ही में पुलिस के पालतू कुत्तों ने उनके चेहरे पर केमिकल युक्त कालिख पोत दिया. अपने पेशे को निभाते हुए पुलिस की अमानवीय करतूतों को उजागर करने वाली पत्रकार मालिनी सुब्रह्मण्यम के घर पर सामाजिक एकता मंच जो सरकार व पुलिस का पालतू संगठन है, द्वारा हमला करवाया गया और उन्हें जगदलपुर छोड़ने मजबूर किया गया. उनसे मार–पीट भी की गयी थी. छत्तीसगढ़ खासकर बस्तर संभाग की जेलों में झूठे आरोपों में बंद आदिवासियों विशेषकर महिलाओं को मुफ्त में विधिक सेवा उपलब्ध कराने वाले जगदलपुर लीगल एड की महिला वकीलों, बेला भाटिया जैसी महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं को डरा–धमकाया गया एवं उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया. यह सब सरकारी संरक्षण में पुलिस के समर्थन व सहयोग से सलवा जुडुम–2 संगठनों व पुलिस के गुण्डों द्वारा किया जा रहा है.

इस तरह के सरकारी जुल्म का सामना करते हुए ही पीड़ित व आंदोलनकारी इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं. इस हिंसा की ओर बाहरी दुनिया की नजर खींच रहे हैं. ऐसे मामलों में भी जहां पुलिस की करतूतें उजागर हुई हैं, किसी को सजा नहीं मिली. विगत में सोनी सोढ़ी पर यौन अत्याचार करने वाले दंतेवाड़ा एसपी अंकित गार्ग को पदोन्नति दी गई. बस्तर के आईजी एसआरपी कल्लूरी जिसने सोनी सोढ़ी पर अनगिनत अत्याचार किये और

करवाये व उन्हें 'बाजारू महिला' कहा, परिवारजनों के सामने गंदी गालियां दी, पत्रकारों को धमकियां दी, को भी पदोन्नति देकर केंद्र में संयुक्त सचिव पद पर बैठाने की कोशिश चल रही है.

विगत साल पुलिस द्वारा कई अमानवीय हरकतें की गई. अक्टूबर 2015 में पेद्दा गेल्लूर, चिन्ना गेल्लूर, पेगिड़ेपल्लि, गुंडम आदि गांवों पर पुलिस ने हमलें करके कई लोगों से मार–पीट की जिनमें 40 महिलाएं भी शामिल हैं. चार महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया जिनमें 14 साल की एक नाबालिग लड़की व एक गर्भवती महिला भी शामिल हैं. तालाब में उस गर्भवती महिला को डुबोते व निकालते उनके साथ बलात्कार किया गया. इसके अलावा महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाना, स्तनों को निछोड़कर दूध निकालना आदि घृणित हरकतें की गईं. इस घटना के विरोध में कई महिला संगठनों, आदिवासी संगठनों व राजनीतिक पार्टीयों द्वारा आंदोलन किया गया जिसके चलते इस घटना रोशनी में आई. नहीं तो यहां पर हो रही कई घटनाओं की तरह यह घटना भी इतिहास की अंधेरी गर्त में समा जाती.

कुन्ना गांव की पीड़ित महिलाएं आप नेता सोनी सोढ़ी के सात

50 वर्षीय पीड़िता

पुलिस की अमानवीयता का निशान

सितंबर 2015 में सशस्त्र बल ने कोंडागांव जिले के छिंदखड़क गांव पर हमला करके दो घंटों तक महिला व पुरुषों की जमकर पिटाई की. महिलाओं के कपड़ें फाड़ दिए. दरवाजा तोड़ कर घरों में घुसकर तोड़फोड़ किया. बाद में ग्राम पटेल को जबरन हिरासत में लेने की कोशिश की. पुलिस द्वारा मार–पीट के बावजूद गांव की जनता जिसमें महिलाएं अग्रसर थीं, ने पुलिस का रास्ता रोक दिया. पुलिस ने गोलीबारी की धमकी दी. इसके बावजूद पीछे नहीं हटी. पुलिस के हाथों से बंदी को छुड़वाया. इसके बाद पुलिस के जुल्म के सबूत रहे फाड़े गए कपड़ों, टूटी चूड़ियों, हरे घावों, ज्वलित हृदयों के साथ महिलाओं के नेतृत्व में गांव की जनता ने एसपी कार्यालय में जाकर पुलिस जुल्म के विरोध में शिकायत की.

जनवरी 12, 2016 को सुकमा जिले के कुन्ना व पेद्दा गांवो पर पुलिस ने हमला करके उत्पात मचाया. गांव में आते ही एक महिला, जिन्होंने रास्ता दिखाने से इंकार किया था, को जमकर पीटा. गांव में घुसने के बाद कई महिलाओं पर इसी तरह जुल्म ढाया. महिलाओं के कपड़े फाड.कर, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया. नौ महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया. अत्याचार पीड़ितों में से 50 वर्षीय एक महिला एवं 22 वर्षीय एक युवती को सोनी सोढ़ी के नेतृत्व में जगदलपुर मेड़िकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया. शिकायत करने के बावजूद पुलिस अधिकारियों ने मामला दर्ज नहीं किया.

2016 जनवरी 11 से 15 तक सरकारी सशस्त्र बलों ने बीजापुर जिले के पुनूर, नेंड्रा व गोटोड आदि गांवों पर हमले कर उत्पात मचाया. इस दौरान सात महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया. कई महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया. इन नीच हरकतें करने वाले पुलिस जवानों पर मामले दर्ज कराने सोनी सोढ़ी द्वारा की गई कोशिशें तब विफल रही जब एएसपी ने महिलाओं की शिकायतों को खारिज किया. पुलिस वालों को जनता पर कहर बरपाने की खुली छूट देने वाला प्रशासन उन पर कैसे मामले दर्ज कर सकता है?

मई 2015 में गड़चिरोली जिले के उडेरा गांव में महुआ बिनने वाली मां–बेटी को पकड़ कर, यातनाएं देकर पुलिस ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और उन्हें डराने हवा में गोली चलाईं. कांकेर जिले के गुंदुल गांव में महुआ बिनने वाली 20 साल की रमोती व रुक्मई को पकड़ कर जेल में डाला. बाद में इन दोनों को दस वर्ष की सजा सुनाई गई. अगर पुलिस ने किसी पर तरस खाकर उसकी मुठभेड़ हत्या किए बगैर छोड़ दिया तो उस कमी को पूरा करने के लिए यहां क्रूर कानून, कड़ी सजा देने वाले जज एवं क्षमता न होने के बावजूद लोगों को जबरन ठूंस–ठूंस कर, उन्हें शारीकि व मानसिक रूप से कई तरह की यातनाएं देकर जिंदा लाशों में तब्दील करने के लिए जेलें मौजूद हैं.

पुलिस द्वारा इस साल कई महिलाओं की हत्याएं भी की गईं. जनवरी 15, 2016 को बीजापुर जिले के चिन्ना जोजूर व पेद्दा जोजूर गांवों के बीच पुलिस द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में चार आदिवासी ग्रामीण मारे गए जिनमें ओयम तुलसी नाम की 14 वर्षीय आदिवसी बालिका

भी है. गुरिल्ला महिलाओं पर तो अंतहीन हत्याकांड चल रहा है. पुलिस ने जनवरी 6, 2016 को बीजापुर जिले में कुड़ियम कमला पर अंधाधुंध गोलीबारी करके उसकी निर्मम हत्या की. जनवरी 11, 2016 को एक गुरिल्ला दस्ते पर अचानक किए गए हमले में कॉमरेड हेमला लच्छी घायल हुई थी. घायल अवस्था में उसे पकड़कर पुलिस ने कई यातनाएं देकर उसकी निर्मम हत्या की. मुठभेड़ों के दौरान घायल अवस्था में पकड़ी गईं महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार करना आम बात हो गई है. 2015 सितंबर में वरंगल जिले की गुरिल्ला कॉमरेड श्रुति को पकड़कर उसे अमानवीय यातनाएं देकर, बलात्कार करके उसकी निर्मम हत्या की गयी. 2014 अक्टूबर में बीजापुर जिले के पोट्टेम गांव के पास गुरिल्ला दस्ते को घेर कर की गई अंधाधुंध गोलीबारी के दौरान कॉमरेड जमली, रामबत्ती व लक्ष्मी घायल अवस्था में पुलिस के हाथलग गयीं. पुलिस ने उन्हें कई यातनाएं देकर, उनके साथ बलात्कार करके उनकी निर्मम हत्या की. दंतेवाडा, सुकमा, बीजापुर जिलों के तूडेम, कोल्लाईगूडा व नांगलीगूडेम गांवों के पास हुई अलग–अलग मुठभेड़ों में कॉमरेड रुक्नी, जोगी, रामे, मासे व पांडे निहत्थे पकड़ी गई थीं. पुलिस ने यातनाएं देकर, बलात्कार करके उन लोगों की हत्या की. जनवरी 2016 में छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र के सशस्त्र बलों की संयुक्त टीम द्वारा किये गये अभियान में बीजापुर जिले के तुमिरीगुंडा के पास जरीना नाम की भूतपूर्व गुरिल्ला पकड़ी गई. पुलिस ने उसके साथ बलात्कार करके बाद में हत्या की.

जिंदा पकड़ी गई कॉमरेड ही नहीं, महिला कॉमरेडों की लाशों के साथ भी सरकारी बलों का व्यवहार अनैतिक, शर्मनाक, घृणित व बर्बर होता है. महिला गुरिल्ला योद्धाओं की लाशों को नंगा करके वे अपने मोबाइल फोनों से फोटो व वीड़ियों खींचते हुए विकृतानंद उठाते हैं. ये बातें गुरिल्ला बलों द्वारा किए गए हमलों में जब्त पुलिस वालों की मोबइल फोनों द्वारा उजागर हो रही हैं. क्रांतिकारी व राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों के इलाकों और देश की सीमावर्ती इलाकों में तैनात सरकारी सशस्त्र बलों को सरकारों द्वारा महिलाओं के साथ मनमर्जी व्यवहार करने व यौन उत्पीड़न करने का पूरा अधिकार–लाइसेंस दिया गया है. हम यह कह सकते हैं कि सरकारें अपने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती को प्रोत्साहित करने महिलाओं की देह कोचारे के तौर पर उपयोग कर रही हैं. अपनी घृणित करतूतों पर परदा डालने के लिए माओवादियों पर उल्टे प्रचार कर रहे हैं कि माओवादी अपनी लैंगिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं गुरिल्ला दस्तों में भर्ती होने युवाओं को आकर्षित करने के लिए ही महिलाओं की भर्ती करते हैं. महिलाओं पर पुलिसिया हिंसा व दुष्प्रचार के पीछे सरकार का मकसद साफ है कि आंदोलानों में महिलाओं की भूमिका को कम किया जाए.

सरकार नें एक तरफ यह कहते हुए निर्भया कानून को लाया कि बलात्कार के दोषियों को फासी देंगे, दूसरी तरफ बलात्कार को दमनकारी हथियार बनाया हुआ है. ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादियों के शासन में यह हथियार धार्मिक अल्पसंख्यक व दलित महिलाओं पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है.

मोदी ने कहा था कि इस 8 मार्च को संसद में सिर्फ महिलाओं को ही बोलने का मौका दिया जाए. इसका मतलब यही निकलता है कि नाम के वास्ते कुछ सीटें महिलाओं को दी जाती हैं लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है. प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति का यह कहना कि माहिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाना चाहिए, उनकी शक्ति को पहचानना चाहिए आदि कोरी लफ्फाजी मात्र है क्यों कि देश की प्रगतिशील राजनीति एवं आन्दोलनों में अपनी सक्रिय भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रयासरत महिलाओं के लिए वे सौगात में दे रहे हैं–गिरफ्तारियां, यातनाएं, अत्याचार, बलात्कार, जेल की सजाएं व हत्याएं.

लेकिन इस ऐतिहासिक सच्चाई कि दमन से प्रतिरोध बढ़ता है, को साबित करते हुए जन युद्ध व जन आंदोलनों में दण्डकारण्य की महिलाएं सक्रिय भूमिका निभा रही हैं. इस तरह 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की संघर्ष विरासत को सगर्व बुलंद कर रही हैं. ❍

भूल सुधार

'प्रभात' के पिछले अंक में पीएलजीए की 15 वीं स्थापना वर्षगांठ के अवसर पर प्रकाशित एसजडसी संदेश में एक भूल थी. उसमें छपा कि पिछले 11 महीनों में पीएलजीए द्वारा संचालित कार्यनीतिक प्रत्याक्रमण अभियान व प्रतिरोधी कार्रवाइयों में पीएलजीए ने 11 स्वचालित/अर्ध स्वचालित हथियारों को जब्त किया. दरअसल सिर्फ कस्सलपाड हमले में ही 11 स्वचालित/अर्ध स्वचालित हथियार जब्त किए गए. इस भूल के लिए हमें खेद है. हम उस कॉमरेड जिसने इस भूल की ओर हमारी नजर खींची, का क्रांतिकारी आभार व्यक्त करते हैं.

– संपादक मंडल

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस – 8 मार्च के मौके पर

दण्डकारण्य की महिलाओं ने सरकारी दमन व विस्थापन के विरोध में अवाज बुलंद की

हर साल की तरह इस साल भी दंडकारण्य की संघर्षरत महिलाओं ने 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को क्रांतिकारी स्फूर्ति के साथ मनाया. क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन (केएएमएस) द्वारा आह्वान दिया गया था कि इस बार इस ऐतिहासिक दिन को सरकारी दमन व विस्थापन के विरोध में मनाया जाए. इस आह्वान को महिलाओं ने सफल बनाया. पूरे दंडकारण्य में लगातार बढ़ते दमन व विस्थापन के बारे में, यहां की महिलाओं की जिंदगियों पर इनके बुरे असर के बारे में, इस परिस्थिति के विरोध में महिलाओं की लड़ाई को और तेज करने की आवश्यकता के बारे में, 8 से 14 मार्च तक गांव–गांव में सभा, बैठक, जुलूस के जरिए; पर्चा, पोस्टर व बैनर के जरिए विस्तार से प्रचार किया गया. यह अलग से बाताने की जरूरत नहीं है कि भीषण दमन के बीच में ही, उस दमन का मुकाबला करते हुए ही इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया.

किसी देश अथवा प्रांत में क्रांतिकारी आंदोलन व जनांदोलन को कुचलने शासक वर्गों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाली दमनात्मक हथकंडों का एक अभिन्न भाग होती है– महिलाओं पर हिंसा. यह हिंसा, आंदोलनों में प्रत्यक्ष भाग लेनेवाली महिलाओं पर भी और आंदोलनों का सहयोग देनेवाली महिलाओं पर भी अमल में लायी जाती है. प्रत्यक्ष संबंध न रखनेवाली, सहयोग न देनेवाली उन महिलाओं पर भी यह हिंसा अमल की जाती है जो आंदोलनों में भाग लेने वाले व सहयोग देने वाले पुरुषों से संबंधित होती हैं. ऐसा कोई संबंध न होने पर भी सिर्फ इस कारण कि आंदोलनरत इलाके में रह रही हैं, से भी महिलाओं पर हिंसा अमल हो रही है. दंडकारण्य जहां सालों से क्रांतिकारी आंदोलन जारी है, में महिलाओं पर हिंसा दिन ब दिन बढ़ रहा है. यही विगत कई सालों से यहां की महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली प्राथमिक समस्या है. इसीलिए विगत कई सालों से यहां की संघर्षरत महिलाएं सरकारी हिंसा के विरोध में 8 मार्च को मनाते हुए बाहरी दुनिया को अपनी आवज सुनाने की कोशिश कर रही हैं. इस बार महिलाओं ने सरकारी दमन के साथ विस्थापन समस्या जो उनके अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है, को भी जोड़ दिया. अब यहां ये दोनों समस्याएं जुड़ गई हैं. अब विस्थापन के लिए ही दमन चल रहा है.

दंडकारण्य संसाधनों का भंडार है. इन संसाधनों को लूटने व लुटाने की सरकारी कोशिशों एवं बचाने के लिए चल रही जनता की लड़ाई ने अब युद्ध का रूप ले लिया है. सिर्फ बैलाडीला के उदाहरण के जरिए यहां जारी संसाधनों की लूट को समझ सकते हैं. उस लूट के चलते आदिवासियों की जिंदगियों में हो रही तबाही को भी समझ सकते हैं.

बैलाडीला के पहाड़ों में तीन हजार मिलियन टन का लौह अयस्क है. 1968 से यहां खुदाई शुरू हुई थी. इसके लिए 22 आदिवासी गांवों का नामोनिशान मिटा दिया गया. 22 हजार आदिवासी विस्थापित हो गये. मुआवजा व नौकरी के आश्वासन झूठे साबित हो गये. पेट भरने के लिए कई लोग अंदरूनी जंगलों में जा बसे जबकि बाकी लोग शहरों में रोजी मजदूरी करने, होटलों में काम करने, रिक्शा चलाने, कुछेक तो भीख मांगने मजबूर हो गए. महिलाओं की स्थिति तो और भी दयनीय हो गयी. कुछ महिलाओं ने वेश्यावृत्ति में कदम रखा. इस विषाद के बारे में ''बैलाडीला में ठगी गयी बहनें'' नामक अपनी पुस्तक में बीडी शर्मा ने विस्तार से लिखा था.

आज एनएमडीसी के नौ हजार कर्मचारियों में बस्तरवासी सिर्फ 127 हैं. खदान में उत्पादन प्रारंभ होते तक मिट्टी की खुदाई, सड़क व भवन निर्माण, ईंटा ढुलाई आदि कामों के लिए सस्ती मजदूरी के तहत स्थानीय आदिवासियों को ठेका मजदूरों के रूप में इस्तेमाल किया गया था. बाद में जब स्थाई नियुक्ति की मांग को लेकर ठेका मजदूरों ने 1978 में आंदोलन छेड़ा, पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण तरीके से आंदोलनरत मजदूरों पर गोलीबारी की गई जिसमें दो दर्जन से ज्यादा मजदूर मारे गये थे. मजदूरों की सारी झोपड़ियों को आग के हवाले किया गया था.

(शेष 62 पेज में ...)